दैनिक भास्कर नई दिल्ली 30-08-2025

प्रेरणा

अपनी कामयाबी को इससे मापो कि उसे पाने के लिए तुमने क्या खोया है! - दलाई लामा

संपादकीय

गैर-जरूरी कानूनों को सरल बनाना जरूरी है

जन विश्वास (संशोधन) बिल, 2025 दो साल के भीतर सरकार का उन गैर-जरूरी लेकिन सख्त कानूनों को बदलने और उन्हें गैर-आपराधिक बनाने का दूसरा प्रयास है, जिनकी भरमार के कारण अदालतों में अहम मामले वर्षों लम्बित रहते हैं। पहला संशोधन 2023 में किया गया था, जिसके तहत 42 केंद्रीय कानूनों के प्रावधानों को खत्म किया गया था। नए बिल में 16 कानूनों में जेल की सजा के प्रावधानों को खत्म कर पहले दोष पर चेतावनी और दूसरे पर आर्थिक दंड का प्रावधान लाया गया है। स्वच्छ ऊर्जा आज भी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, न केवल पर्यावरण के लिहाज से बल्कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के लिए भी। लेकिन एक ताजा अध्ययन को देखें तो लगता है कि उदारीकरण से 25 साल में विकास ने जो गति पकड़ी थी, शासकीय मकड़जाल और भ्रष्टाचार ने उसे फिर गिरफ्त में ले लिया है। इसके अनुसार अगर कोई उत्तर भारत की कंपनी महाराष्ट्र में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाती है तो उसे हर साल केंद्रीय, राज्य या स्थानीय निकायों के नियमों, कानूनों और उपबंधों की कुल 2735 शर्तों का अनुपालन करना होगा। इनमें से 83 ऐसी शर्तें हैं, जिनके उल्लंघन पर जेल की हवा खानी पड़ेगी। ऐसे में कोई उद्यमी कैसे इस सिस्टम में उद्यम लगाने की हिम्मत करेगा। ऐसे में जन विश्वास (संशोधन) बिल एक अच्छा प्रयास है।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

जितने विचार-स्मृतियां मन में होंगे, उतनी ही अशांति होगी

आजकल किसी से कोई बात करो, उसकी पुष्टि के लिए लोग मोबाइल खोलते हैं और डिजिटल माध्यमों से जानकारी निकालते हैं। जानकारी निकलती भी है। फिर जीवन इतना अधिक जानकारी-केंद्रित हो जाता है कि ज्ञान खो जाता है। जैसे शास्त्रों में मन पर बहुत काम हुआ है। ऐसा लिखा गया है- माया मरी ना मन मरा, मर-मर गए शरीर। आशा-तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो अब मन को मारना नहीं है। मरेगा भी नहीं। लेकिन फिर भी हमारे यहां मृत्यु की व्यवस्था मनुष्य को स्मृतियों से मुक्त कर देती है। जितने विचार और स्मृतियां मन में होंगे, मनुष्य उतना अशांत होगा। विज्ञान भी मेमोरी एडिटिंग को मानता है। शास्त्रों ने इसे ही ध्यान कहा है। मनुष्य के मस्तिष्क में हिप्पोकैम्पस और कॉर्टिक्स होते हैं। ये स्मृतियों को सहेजते हैं। और एमिग्डेला, नापसंद और पसंद को रजिस्टर करता है। इन तीनों को व्यवस्थित करने का काम ही योग है। इसलिए विज्ञान को योग से लड़ना नहीं चाहिए और योग को विज्ञान से वैर नहीं रखना चाहिए।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

विश्लेषण • भारत-पाकिस्तान हमेशा एक ग्रुप में क्यों?

पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का यह सही समय नहीं

एशिया कप

राजदीप सरदेसाई
वरिष्ठ पत्रकार
rajdeepsardesai52@gmail.com

पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते और ऐसा कहते हुए उन्होंने सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया था। बहरहाल, पानी भले ही खून के साथ नहीं बह सकता, लेकिन खेल जरूर उसके साथ हो सकता है। कुछ ही दिनों बाद एशिया कप शुरू होगा और सभी की निगाहें भारत-पाकिस्तान के अहम मुकाबले पर टिकी होंगी। सरकार ने इन मैचों को यह कहते हुए हरी झंडी दे दी है कि द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुकाबलों में फर्क है।

देखें तो सरकार 2012 से चले आ रहे उन अलिखित दिशानिर्देशों का ही पालन कर रही है, जिनके चलते दोनों देशों के बीच केवल वैश्विक टूर्नामेंटों में ही क्रिकेट मुकाबले हुए हैं। भारत-पाक खेल संबंधों का एक लंबे समय से समर्थक होने के नाते मुझे तो बिना किसी हिचकिचाहट के सरकार के रुख का स्वागत करना चाहिए। आखिर क्रिकेट का खेल ही तो है, जो उपमहाद्वीप के देशों को आपस में जोड़ता है। इसमें भी भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मुकाबलों ने खेलप्रेमियों को कई यादगार लम्हे दिए हैं।

और इसके बावजूद, इस बार की बात अलग है। मैदान में वो दो टीमें आमने-सामने होंगी, जिनके देश अभी कुछ महीने पहले परमाणु युद्ध की कगार पर थे। आप कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों का पाकिस्तान की हुकूमत और फौज की साजिशों से क्या लेना-देना? क्या खेलों की शुचिता को पाकिस्तान के उस सत्ता-प्रतिष्ठान से अलग नहीं रखा जा सकता, जो भारत को 'हजार घाव' देने पर तुला रहता है? सैद्धांतिक रूप से हां, लेकिन वास्तव में नहीं। पहलगाम हमले के बाद, पाकिस्तानी क्रिकेट की किसी भी जानी-मानी आवाज ने भारत के लोगों के प्रति सहानुभूति का बयान नहीं दिया था। शाहिद अफरीदी ने तो उलटे भड़काऊ बयान देते हुए भारतीय सेना को ही आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया था। वे अकेले नहीं थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी- जो शाहबाज शरीफ सरकार में मंत्री भी हैं- ने कहा था कि भारत में हमसे क्रिकेट खेलने से इनकार करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं इसके क्या परिणाम होंगे।

पीसीबी प्रमुख के भड़काऊ बयानों से पता चलता है कि पाकिस्तानी सत्ता-प्रतिष्ठान में नई दिल्ली के प्रति दुश्मनी की भावना कितनी गहरी है। ठीक है कि हमारे देश में भी कुछ उग्र लोग हैं, जो पाकिस्तान के 'खात्मे' की चाहत रखने वाले एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा के दोनों ओर मीडिया द्वारा जो दुष्प्रचार अभियान चलाया गया, वह संस्थागत आचार-संहिता के पतन को दर्शाता है। हमारे एक टीवी एंकर ने तो गरजते हुए कह दिया था कि 'अमन की आशा को ब्रह्मोस की भाषा ने दफना दिया है!'

लेकिन युद्धोन्माद के इस दौर में क्या भारत-पाक क्रिकेट मैच मरहम का काम कर सकता है? दुर्भाग्य से नहीं। मुझे याद है कि 2004 में मैं पाकिस्तान गया था। तब भारत ने न केवल पहली बार पाकिस्तान को उसी की धरती पर टेस्ट श्रृंखला में हराया था, बल्कि उस समय पाकिस्तान के लोगों में भारतीय टीम के प्रति गर्मजोशी का भी संचार हुआ था। मुझे याद है मैं लाहौर में उन्मादी पाकिस्तानी प्रशंसकों से घिरा था, जो 'बालाजी, जरा धीरे चलो' गा रहे थे। मुझे यह भी याद है कि 1999 में एक टेस्ट मैच में भारत को मामूली अंतर से हराने के बाद चेन्नई की भीड़ द्वारा कैसे पाकिस्तानी टीम का खड़े होकर अभिवादन किया गया था। लेकिन सद्भाव के वो पल क्षणभंगुर साबित हुए।

सच तो यह है कि आज भारत-पाकिस्तान के रिश्ते बिल्कुल भी सामान्य नहीं हैं। ऐसे में क्रिकेट सामान्यता

आज भारत-पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य नहीं रह गए हैं। ऐसे में क्रिकेट सामान्यता का बनावटी एहसास दिलाने का जरिया भर बनकर रह जाएगा। खिलाड़ियों से अपेक्षा की जाने लगती है कि वे योद्धा बनकर बल्ले और गेंद से 'युद्ध' छेड़ें।

का बनावटी एहसास दिलाने का जरिया भर बनकर रह जाएगा। खिलाड़ियों से अपेक्षा की जाने लगती है कि वे योद्धा बनकर बल्ले और गेंद से 'युद्ध' छेड़ें, जबकि दर्शक इन मुकाबलों पर फलने-फूलने वाले क्रिकेट के इकोसिस्टम द्वारा राष्ट्रीय उन्माद के अकल्पनीय दौर में धकेल दिए जाते हैं। यह अकारण नहीं है कि लगभग हर वैश्विक टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान को हमेशा एक ही ग्रुप में रखा जाता है। भारत-पाकिस्तान का मैच दो हफ्ते तक चलने वाले एशिया कप के बाकी सभी मैचों की तुलना में ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा और इसी के साथ विज्ञापन-राशि बढ़ेगी।

आम भारतीय और पाकिस्तानी पहलगाम में हुई हिंसा के बाद एक-दूसरे के परिवारों से मिलने के लिए वीसा तक नहीं पा सकते, लेकिन दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड के वीवीआईपी अधिकारी एयर-कंडीशंड कमरों में खुशी-खुशी एक-दूसरे से मिलते रहेंगे। खून और पानी भले ही साथ-साथ नहीं बह सकते हों, लेकिन पैसों का रंग तमाम सीमारेखाओं को लांघ जाता है!

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

नजरिया • घुसपैठियों-प्रवासियों के मुद्दे को तूल क्यों?

बिहार में और भी कई जरूरी मसले और समस्याएं मौजूद हैं

सियासत

पवन के. वर्मा
पूर्व राज्यसभा सांसद व राजनयिक
pavankvarma1953@gmail.com

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वहां 'अवैध घुसपैठियों और प्रवासियों' का मुद्दा चर्चाओं में है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह राष्ट्रीय चिंता की अभिव्यक्ति है या चुनावी माहौल में ध्रुवीकरण या ध्यान भटकाने का प्रयास? एक हद तक यह वास्तविक मुद्दा है। क्योंकि कोई भी देश अवैध प्रवासियों की घुसपैठ को अनुमति नहीं दे सकता। लेकिन बिहार के गया में हाल ही में एक भाषण के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा इस चिंता को जताने का समय और इसके कारण उत्सुकता जगाते हैं। यदि घुसपैठिये सही में चिंता का कारण हैं तो यह पूछना लाजिमी है कि बीते 11 सालों से केंद्र सरकार क्या कर रही थी? खासकर तब, जब बिहार में बीते 8 वर्षों से डबल इंजन वाली एनडीए सरकार है। इस मसले पर कोई नीतिगत प्रस्ताव, सांख्यिकी आकलन और सतत प्रशासनिक कार्रवाइयां क्या कहीं नजर आई हैं?

सीमा की सुरक्षा, निगरानी और अवैध प्रवास रोकने का जिम्मा केंद्र का है। ऐसे में यह तय है कि प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर पर अपनी विफलता की स्वीकारोक्ति तो नहीं ही कर रहे थे। सरकार के अधिकांश कार्यकाल के दौरान बिहार के राजनीतिक विमर्श में यह मुद्दा दबा ही रहा। संसदीय बहस या नीतिगत पहलों में शायद ही इसका जिक्र हुआ। अब चुनाव नजदीक आते ही भाषणों और सुर्खियों में यह मुद्दा छा गया है।

यह सवाल भी उठता है कि इस चिंता के साक्ष्य कहां हैं? निर्वाचन आयोग ने एक सामान्य-सा बयान दिया है कि 'बिहार में बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग हैं।' लेकिन एसआईआर के नाम पर जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम आयोग हटा चुका, उनमें अधिकतर- जैसा कि वह खुद दावा करता है- या तो मृत हैं या कहीं और रहने चले गए हैं। उनके नाम कई निर्वाचन क्षेत्रों में हैं या उनका अता-पता नही है। कितने मतदाताओं को आयोग या किसी अन्य सरकारी अधिकारी ने रोहिंग्या या बांग्लादेशी के तौर पर चिह्नित किया, इसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाने चाहिए।

बिहार असम की तरह बांग्लादेश से एक लंबी और घुसपैठ के लिए जोखिमभरी सीमा नहीं साझा करता है। बिहार ऐतिहासिक रूप से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवास का केंद्र भी नहीं रहा है। इसकी समस्याएं अंदरूनी हैं : गरीबी, पलायन, खराब बुनियादी ढांचा, व्यापक बेरोजगारी, कृषि संकट और जनस्वास्थ्य व शिक्षा का चरमराया हुआ ढांचा। यह अबूझ पहेली है कि जब इतने बड़े मुद्दे मुंह बाए खड़े हैं, तो अचानक अवैध प्रवासियों के मसले को इतनी प्राथमिकता क्यों दी जा रही है?

ध्यान भटकाने के राजनीतिक कौशल में इसका जवाब छिपा हो सकता है। जब सरकारें खुद को राजकाज में पिछड़ते देखती हैं तो वे मतदाताओं का ध्यान दूसरे मुद्दों की ओर भटकाने की कोशिशें करती हैं। इस खतरे को दिखाकर अकसर चुनाव को सरकार के प्रदर्शन पर होने वाले जनमत-संग्रह से भटकाकर देश बचाने की नैतिक मुहिम में बदलने का प्रयास किया जाता है। यह एक जांचा-परखा फॉर्मूला है, जो भारत के लिए अनोखा नहीं। नीतिगत चिंताओं से परे ऐसे भाषणों की भाषा अकसर पहचान की सियासत के दायरे में चली जाती है। अवैध घुसपैठियों को अकसर परोक्ष रूप से किसी समुदाय विशेष से जोड़ दिया जाता है। जानबूझकर किए गए इस घालमेल से डर, आक्रोश और अंततः साम्प्रदायिक विभाजन पनपता है। यह पड़ोसी को पड़ोसी के खिलाफ कर देता है और जहां विचारधाराओं की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए थी, वहां सामुदायिक पहचान का मुकाबला

असम के उलट बिहार बांग्लादेश से एक लंबी और घुसपैठ के लिए जोखिमभरी सीमा नहीं साझा करता है। बिहार ऐतिहासिक रूप से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवास का केंद्र भी नहीं रहा है। इसकी वास्तविक समस्याएं तो अंदरूनी हैं।

हावी हो जाता है।

लंबे समय से धर्म-जाति के नाम पर बिहार की जनता के हितों की बलि दी जाती रही है। ऐसी राजनीति महज चुनावी खेल नहीं, बल्कि यह भारत के सामाजिक ताने-बाने में जहर घोलना है। सदियों से बिहार सांस्कृतिक मेलजोल की भूमि रहा है, जहां हिंदू और मुस्लिम, ऊंची और नीची जातियां न केवल अपनी जमीन बल्कि विरासत भी साझा करते रहे हैं।

बौद्ध धर्म का केंद्र और महात्मा गांधी के चम्पारण सत्याग्रह की भूमि रहा यह राज्य कभी विविधता में सामंजस्य का प्रतीक रहा था। इस परिवेश में विभाजनकारी नैरेटिव घुसाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

इसमें भी बड़ा खतरा तो स्वयं भारतीय लोकतंत्र को है। चुनाव जनता के लिए शासन का मूल्यांकन करने, प्रतिस्पर्धी नजरियों पर बहस करने और नेताओं को जवाबदेह ठहराने का अवसर होना चाहिए। जब यह 'हम' और 'वो' के दृष्टिकोण में बदल जाता है, तो लोकतंत्र भीतर से खोखला हो जाता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

30 अगस्त के अंक से विशेष अनुबंध के तहत सिर्फ दैनिक भास्कर में
इकोनॉमिस्ट की कवर स्टोरी अमेरिकी टैरिफ से भारत को चुनौतियों पर केंद्रित है। मैगजीन ने नई टेक्नोलॉजी में भारी निवेश से चीन को होने वाली मुश्किलों का जायजा लिया है।
The Economist
दैनिक भास्कर — अब आप इकोनॉमिस्ट के सभी आर्टिकल DB एप पर हर शनिवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

बिजनेस — भारत के पास अपनी क्षमता को साबित करने का अच्छा मौका, अर्थव्यवस्था पर ज्यादा नकारात्मक असर भी नहीं

अमेरिकी टैरिफ भारत के लिए आपदा में अवसर की तरह

अमेरिका के टैरिफ ने भारत के सामने दुविधा की स्थिति पैदा की है। ट्रम्प ने पाकिस्तान को गले लगाकर भारत-अमेरिका के रिश्तों को ताक पर रख दिया है। भारतीय पीएम मोदी ने टैरिफ के जवाब में आत्मनिर्भर देश का रास्ता पेश किया है। वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं। भारत को अलग कर अमेरिका ने भूल की है। इन स्थितियों में भारत के महाशक्ति बनने के दावे की परीक्षा है। वह टैरिफ के झटकों को संभालने की स्थिति में है।

ट्रम्प ने दो तरह से भारत को अपमानित किया है। भारत रूसी तेल खरीदता है इसलिए 27 अगस्त से 25% सरचार्ज लगाया है। यह 25% टैरिफ से अलग है। चीन सहित कई देश रूसी तेल खरीदते हैं। लेकिन भारत को दंडित किया गया है। दूसरा घटनाक्रम पाकिस्तान से ट्रम्प का प्रेम है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत-पाक के बीच मई में चार दिन तक लड़ाई चली थी। फिर भी ट्रम्प पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो करंसी व माइनिंग पर करार की संभावनाएं खोज रहे हैं।

अमेरिका के रवैये से भारत का भरोसा टूटा है। 2004 के बाद अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने एशिया में चीन का विरोध करने वाली लोकतांत्रिक ताकत के रूप में भारत का समर्थन किया है। भारत की अर्थव्यवस्था 351 लाख करोड़ रु. की है। स्टॉक मार्केट 439 लाख करोड़ रु. है। दूसरी ओर चीन पर निर्भर पाक अस्थिरता, कर्ज, आतंकवाद के कारण ध्वस्त हो चुका है। भारत के मामले में ट्रम्प का रुख अमेरिकी हितों के खिलाफ सेल्फ गोल है।

इन हालात में बहुत लोग भारत की महाशक्तियों से अलग रहने की नीति को सही मानते हैं। भारत कुछ हथियारों के लिए रूस पर निर्भर है तो कुछेक के लिए यूरोप, इजराइल व अमेरिका पर। मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन से सप्लाई होती है। पश्चिमी देशों का मार्केट और टेक्नोलॉजी उसके काम आती है। 2020 में चीन से सीमा पर झड़प के बाद वॉशिंगटन को उम्मीद थी कि यह अमेरिका से अर्द्ध गठजोड़ का मौका है। 2024 में मजबूत रक्षा संबंधों के लिए सामरिक करार हो गया। बहरहाल पिछले कुछ महीनों की घटनाओं से ग्लोबल गठबंधनों पर संदेह करने वाले भारतीयों की आशंकाओं की पुष्टि हुई है। उन्होंने हमेशा अमेरिका पर निर्भरता को खतरनाक बताया है। मोदी की आगामी चीन यात्रा से संकेत मिलता है कि भारत के पास विकल्प हैं।

अमेरिका के फैसलों से भारत की क्षमताओं और ताकत की परीक्षा का मौका अब आ गया है। पिछले 11 साल से मोदी राष्ट्र निर्माण, आधुनिकीकरण, केंद्रीकरण के रास्ते पर चल रहे हैं। औद्योगीकरण अभियान के मामूली नतीजे मिले हैं। नए जॉब पैदा नहीं हुए हैं। लेकिन कई कामयाबियां भी हैं। नई सड़कों, विमानतलों, डिजिटल पेमेंट्स और टैक्स प्लेटफार्म के कारण सिंगल मार्केट बना है। फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत है। इन कारणों से भारत को टैरिफ के धक्के से उबरने में मदद मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष का कहना है, 2028 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अमेरिका के आक्रामक रुख से भारत में पश्चिम विरोधी भावनाएं पैदा हो सकती हैं।

अगले माह मोदी-ट्रम्प की मुलाकात संभव

- अटकलें हैं कि नरेंद्र मोदी सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के समय अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं।
- पूर्व विदेश सचिव निरूपमा राव का कहना है, राष्ट्रहित में भारत का रुख कायम रहेगा। व्यापार में कुछ रियायतें दे सकता है।
- ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की तन्वी कहती हैं, लगता है ट्रम्प चाहते हैं, वे कह सकें कि उन्होंने भारत को कुछ करने को मजबूर किया है।
- तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के नितिन पई का कहना है,टैरिफ के जवाब में भारत को नए आर्थिक सुधार करना चाहिए।

कई क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों की जरूरत

विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिकी टैरिफ के नुकसान को सीमित करने के लिए भारत कई रियायतें दे सकता है। भारत रूसी तेल की खरीद कम करके अमेरिकी गैस का आयात बढ़ा सकता है। ब्रिटेन, यूएई से हुए समझौतों के समान कुछ नए व्यापार करार किए जा सकते हैं। बिजनेस, खेती, जमीन और बिजली सहित कई क्षेत्रों में बड़े सुधार वर्षों से नहीं हुए हैं।

भारत निर्यात पर ज्यादा निर्भर नहीं

भारत माल निर्यात पर कम निर्भर है। वियतनाम के 85% की तुलना में जीडीपी में भारत के निर्यात का हिस्सा केवल 11% है। स्मार्टफोन, फार्मा जैसे बड़े निर्यात को ट्रम्प के नए टैरिफ से छूट मिली है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अजय श्रीवास्तव मानते हैं, आने वाले महीनों में भारत की अर्थव्यवस्था हिलेगी नहीं बल्कि उसमें थोड़ी बहुत हलचल होगी।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

वर्ल्ड इन ब्रीफ

इजराइल में सेना- सरकार के बीच मतभेद और बढ़े

इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और सेना के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। 24 अगस्त को इजराइली डिफेंस फोर्सेस के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने सरकार से मतभेदों का जिक्र किया। नौसैनिक अड्डे की यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि डिफेंस फोर्स ने गाजा में अपने पिछले अभियान में बंधकों की रिहाई के लिए स्थितियां निर्मित कर दी थीं। उन्होंने ऐसा कहकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू को तल्ख संदेश दिया है। जमीर ने गाजा पर कब्जे के आदेश का विरोध किया है।

फ्रांस में खर्च में कटौती पर सरकार गिरने की नौबत

फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बेराउ देश पर कर्ज का बोझ कम करने के लिए अपनी सरकार को दांव पर लगाने का इरादा रखते हैं। फ्रांस पर जीडीपी का 114 प्रतिशत कर्ज है। अल्पसंख्यक सरकार चला रहे बेराउ बजट खर्च में 2.6 प्रतिशत की कटौती करना चाहते हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां तैयार नहीं हैं। बेराउ ने गतिरोध तोड़ने के लिए 8 सितंबर को संसद में विश्वास मत हासिल करने का निर्णय लिया है। विश्वास मत में उनके हारने की संभावना है। यदि ऐसा होता तो एक साल से कम समय में फ्रांस के तीसरे प्रधानमंत्री को पद से हटना पड़ेगा।

अमेरिका में विदेशी पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई

अमेरिका में पिछले साल के मुकाबले 2025 में विदेशी पर्यटकों की संख्या में 3.8 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। लगभग 13 लाख विदेशी कम आए हैं। सबसे अधिक गिरावट मई और जुलाई के बीच हुई है। अमेरिकी विमानतलों पर अब तक इस वर्ष कनाडा से आने वाले लोगों की संख्या 7.4 प्रतिशत कम रही। यह सबसे ज्यादा है। बोस्टन लोगान और शिकागो ओ हारे एयरपोर्ट्स पर अंतरराष्ट्रीय आवक पिछले साल से 8 प्रतिशत कम रही है। न्यूयॉर्क के जेएफके विमानतल पर 7 प्रतिशत कम लोग उतरे।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

ओपिनियन — विदेशी टेक पर रोक की जरूरत

यूरोप अरबों रुपयों के डेटा सेंटर्स तो बना रहा है किंतु हार्डवेयर में पिछड़ा

क्रिस्टियन क्लीन
जर्मन टेक कंपनी एसएपी के प्रमुख

दुनिया में तनाव और टेक्नोलॉजी की होड़ के दौर में हर देश अपनी डिजिटल किस्मत खुद लिखना चाहता है। विशेषज्ञ सवाल उठाते हैं क्या यूरोप इस मामले में आत्मनिर्भर है? दुर्भाग्य से यूरोप ने गलत तरीका अपनाया है। बड़े डेटा सेंटर बनाने और हार्डवेयर पर अरबों रुपए का निवेश इसका हल नहीं है।

यूरोपियन यूनियन की योजना पांच बड़े एआई डेटा सेंटर के निर्माण पर 23 अरब डॉलर निवेश करने की है। लेकिन अकेले सर्वर्स और प्रोसेसर्स से यूरोपीय संप्रभुता सुरक्षित नहीं होगी।

हार्डवेयर में यूरोप पिछड़ चुका है। यूरोप में चलने वाले डेटा सेंटर्स के प्रोसेसर, नेटवर्क टेक्नोलॉजी अमेरिका में डिजाइन हुए हैं। निर्माण एशिया में हुआ है। पूर्ण तकनीकी आत्म-निर्भरता हासिल करने के लिए विदेशी हार्डवेयर पर रोक की जरूरत है। हालांकि यह कदम नुकसानदेह है। बाहरी इनोवेशन से यूरोप का नाता टूट जाएगा। यूरोप को अपना रास्ता पकड़ना होगा। उसे खुलेपन, जल्द फैसलों और अहम इन्वेस्टमेंट की नीति पर चलना होगा। यूरोप की खासियत उत्कृष्ट रिसर्च और मजबूत औद्योगिक बुनियाद है। यह मॉडल प्राइवेसी के सम्मान, डेटा सुरक्षा और लोकतांत्रिक जवाबदेही से जुड़े मूल्यों पर टिका हो।

अफसरशाही बोझ बन गई है

यूरोपियन यूनियन के डेटा एक्ट में सुधार की जरूरत है। कंपनियों पर अफसरशाही का बोझ है। लालफीताशाही नहीं बल्कि इनोवेशन को अहमियत देना जरूरी है। यूरोप का डिजिटल भविष्य सर्वर रूम में नहीं फैक्ट्रियों, बड़ी, छोटी कंपनियों और उसके सार्वजनिक प्रशासन से तय होगा।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

समस्या

टेक कंपनियों के मुनाफे पर बिजली से ब्रेक लगेगा

आने वाले वर्षों में कंप्यूटिंग की दुनिया को आगे बढ़ने में मुश्किल हो सकती है। आधुनिक कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में बिजली की ज्यादा खपत होती है। बर्नस्टीन कंपनी का अनुमान है, यदि चिप्स कम बिजली का इस्तेमाल करने वाली होंगी तो 2030 तक अमेरिका में 17 गीगॉवाट बिजली की कमी होगी। यदि वे किफायती नहीं होंगी तो कमी 62 गीगावॉट होगी। मोर्गन स्टेनले बैंक ने 2028 तक 45 गीगावॉट की कमी का हिसाब लगाया है। चिप कंपनी एनवीडिया जुलाई में दुनिया में 350 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की पहली कंपनी बनी। उसकी तेजी पर बिजली से ब्रेक लग सकता है। 2010-20 के बीच इंटरनेट ट्रैफिक से दुनिया के डेटा सेंटर्स पर वर्क लोड नौ गुना बढ़ा था। लेकिन बिजली की खपत एक जैसी रही। गैर एआई डेटा सेंटर की कंप्यूटिंग यूनिट को चलने के लिए 12 किलोवॉट बिजली की जरूरत पड़ती है। इतने बड़े एआई मॉडल को ट्रेनिंग में 80 किलोवॉट बिजली लगती है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

बदलाव — सब्सिडी से जीडीपी कम हो गई

ईवी, एआई, क्लीन एनर्जी में आगे रहने की चीनी नीति के कई नुकसान

ज्यादा वक्त नहीं बीता है, जब पश्चिमी देश चीन को नकल करने वाला देश कहते थे। इलेक्ट्रिक वाहनों, क्लीन एनर्जी और एआई जैसे हाइटिक उद्योगों में बढ़त से चीन को प्रशंसा और भय की नजर से देखा जाने लगा है। अब पश्चिमी देशों की कुछ सरकारें उसकी नीतियां अपना रही हैं। लेकिन चीनी नीति के नुकसान भी सामने आ रहे हैं। सरकार को दिक्कत महसूस होने लगी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्वयं औद्योगिक नीति की आलोचना की है।

इंडस्ट्रियल सब्सिडी से चीन की जीडीपी एक साल में 1.7 प्रतिशत कम हो गई थी। देश में दो हजार से अधिक सरकार नियंत्रित इन्वेस्टमेंट फंड हैं। इनका लक्ष्य 123 लाख करोड़ रुपए से अधिक धन जुटाने का है। ये फंड्स तो बढ़ते रहे, पर प्राइवेट वेंचर कैपिटल सूख गई है। बेकार खर्च और धोखाधड़ी से भी नुकसान हुआ है। सेमीकंडक्टर के लिए बना बिग फंड भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात हो चुका है।

शी जिनपिंग ने जुलाई में कहा कि स्थानीय अधिकारी हमेशा एआई, कंप्यूटिंग पावर, इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश करते हैं। इससे ऐसे उद्योगों की भीड़ हो गई है। कीमतों पर युद्ध शुरू हो गया है। कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए मूल्य कम कर रही हैं। प्रतिद्वंद्वी भी ऐसा करते हैं। इस कारण कंपनियों का मुनाफा घटा है। किसी का मार्केट शेयर नहीं बढ़ पाया है। औद्योगिक नीति के समर्थकों का कहना है कि यह सरकार की योजना का हिस्सा है। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों, रोबोट्स, क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देती है। उसे उम्मीद है कि प्रतिस्पर्धा से सुधार होगा। लेकिन इससे इनोवेटिव या सक्षम कंपनियों को हमेशा नतीजे नहीं मिलते हैं। इससे सरकारी संरक्षण वाली कंपनियों को बढ़ावा मिलता है। बहुत बड़ी कंपनियां भी फायदे में हैं। चीन की औद्योगिक नीति सभी लक्ष्य पूरे नहीं कर पाई है। सिविल एविएशन, आधुनिक चिप मेकिंग में अब तक कामयाबी नहीं मिली है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

विचार बिन्दु

निरन्तर बदलने की इच्छा रखना एक ताकत होती है, चाहे इसकी वजह से कंपनी का एक बड़ा हिस्सा कुछ देर के लिए पूरी तरह से अव्यवस्थित क्यों ना हो जाए। –जैक वेल्व

जल के बिना जीवन असंभव है, जल संरक्षण केवल विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है

जल जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। यह केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के अस्तित्व का आधार है। मानव सभ्यता का इतिहास गवाह है कि जहां पानी है, वहीं समृद्धि है। किंतु विडंबना यह है कि जिस संसाधन के बिना जीवन असंभव है, उसी का सबसे अधिक दुरुपयोग हम कर रहे हैं। विश्व स्तर पर जल संकट एक गंभीर चुनौती बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2050 तक विश्व की आधी से अधिक आबादी जल संकट का सामना कर सकती है। भारत जैसे कृषि प्रधान और जनसंख्या बहुल देश के लिए यह स्थिति और भी भयावह हो सकती है। बढ़ती जनसंख्या, अनियंत्रित औद्योगिकीकरण, शहरीकरण की तेज़ रफ्तार और जल संसाधनों का अंधाधुंध दोहन इस संकट को गहरा कर रहा है। भारत में औसतन प्रतिवर्ष 1170 मिलीमीटर वर्षा होती है, परंतु वर्षा का वितरण असमान है। राजस्थान जैसे राज्य, जो शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्र में आते हैं, वहां यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है।

भारतीय संस्कृति में जल को देवता का स्थान दिया गया है। हमारे ठांथों में जल को अमृत, जीवन और शक्ति का प्रतीक माना गया है। प्राचीन भारत में जल संचयन और संरक्षण के अनेक अनूठे तरीके विकसित किए गए। गांव-गांव में तालाब, कुएं, बावड़ियां और जोहड़ जैसी संरचनाएं केवल जल का स्त्रोत नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन का केंद्र हुआ करती थीं। यह व्यवस्थाएं हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वजों ने कितनी दूरदर्शिता के साथ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया। दुर्भाग्यवश, आधुनिक विकास की दौड़ में इन परंपराओं की उपेक्षा हुई। नदियों के किनारे कचरा डालना, तालाबों पर अतिक्रमण, वर्षा जल को व्यर्थ बहने देना और कंक्रीट के जंगल खड़े करना-इन सबने जल संकट को बढ़ावा दिया।

यदि भारत में जल संकट की गंभीरता को समझना है, तो राजस्थान का उदाहरण सबसे उपयुक्त है। यह राज्य भौगोलिक दृष्टि से मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहां औसत वार्षिक वर्षा मात्र 100 से 500 मिलीमीटर के बीच होती है। इसके बावजूद राजस्थान के लोगों ने जल संरक्षण के अद्भुत और टिकाऊ उपाय अपनाए। बावड़ी, जोहड़, टांका, नाड़ी जैसी पारंपरिक संरचनाएं केवल जल भंडारण के साधन नहीं, बल्कि जीवनरेखा थीं। बावड़ियां सीढ़ीनुमा कुएं होते थे, जिनमें वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता। इनका उपयोग पीने के पानी के साथ-साथ गर्मियों में ठंडक के लिए भी होता था। जोहड़ गांवों में बनाए गए छोटे जलाशय होते थे, जो वर्षा जल को रोककर भूजल स्तर को बनाए रखते थे। टांके और नाड़ियां मरुस्थल क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन के ये प्रमुख स्त्रोत थे, जो पशु और मानव दोनों के लिए उपयोगी रहे। सदियों तक इन पारंपरिक प्रणालियों ने राजस्थान को जल संकट से बचाए रखा। किंतु आधुनिकता के दबाव, जनसंख्या वृद्धि और अंधाधुंध भूजल दोहन ने स्थिति को बदतर बना दिया। भूजल स्तर कई क्षेत्रों में 400 फीट से भी नीचे चला गया।

छोटे-छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। नलों को खुला न छोड़ना, स्नान, कपड़े और वाहन धोने में अनावश्यक पानी खर्च न करना, रीसायकल और री-यूज को जीवनशैली का हिस्सा बनाना-ये आदतें हमें आज ही अपनानी होंगी। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि यदि समय रहते जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया, तो भविष्य में पानी को लेकर संघर्ष और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

जब जल संकट चरम पर था, तब राजस्थान ने फिर से अपनी जड़ों की ओर लौटने का प्रयास किया। इसका सबसे प्रेरक उदाहरण है अलवर जिले का तरुण भारत संघ और अरवरी नदी का पुनर्जीवन। 1985 में राजेंद्र सिंह, जिन्हें आज जलपुरुष कहा जाता है, ने जोहड़ों के पुनर्निर्माण का अभियान शुरू किया। सामूहिक प्रयास से सैकड़ों जोहड़ पुनर्जीवित हुए और परिणामस्वरूप अरवरी नदी, जो वर्षों से सूखी थी, फिर से बहने लगी। आज यह नदी लगभग 90 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। इस प्रयास से 1000 से अधिक गांवों में भूजल स्तर बढ़ा, कृषि उत्पादन सुधरा और पलायन रुका। यह उदाहरण बताता है कि सामूहिक प्रयास और पारंपरिक तकनीकों का मेल असंभव को संभव कर सकता है।

राजस्थान सरकार ने जल संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान इस दिशा में एक उल्लेखनीय प्रयास है। इस योजना के तहत लाखों जल संरचनाएं बनाई या पुनर्जीवित की गईं। इससे भूजल स्तर में सुधार हुआ और ठाामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट कम हुआ। अटल भूजल योजना और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से ठाामीण घरों तक पाइपलाइन से पानी उपलब्ध कराने और भूजल पुनर्भरण पर जोर दिया जा रहा है। 2003 में राजस्थान हाईकोर्ट ने भवन निर्माण में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य किया था, लेकिन इसका पालन अपेक्षित स्तर तक नहीं हो सका। अब समय आ गया है कि इसे कठोरता से लागू किया जाए। कृषि क्षेत्र में बदलाव अनिवार्य है। भारत में कुल जल उपयोग का लगभग 80 प्रतिशत कृषि में होता है।

औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों की चुनौतियां भी कम नहीं हैं। राजस्थान के औद्योगिक शहर जैसे भीलवाड़ा, पाली और सिरोही में वस्त्र उद्योग भारी मात्रा में पानी उपयोग करता है। कई इकाइयां अपशिष्ट जल बिना शुद्ध किए नदियों में छोड़ती हैं, जिससे जल स्त्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। इन उद्योगों को एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना अनिवार्य करना होगा और जल पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना होगा। शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते कंक्रीट के जंगल ने वर्षा जल के रिसाव को लगभग समाप्त कर दिया है। इस स्थिति में परकोलेशन पिट्स, चेक डैम्स और कृत्रिम रिचार्ज संरचनाएं विकसित करनी होंगी। स्मार्ट सिटी योजनाओं में जल संरक्षण को प्राथमिकता देना आवश्यक है।

सरकारी प्रयास तभी सफल होंगे जब समाज की सक्रिय भागीदारी होगी। जल संरक्षण केवल योजनाओं या अभियानों का विषय नहीं, बल्कि हर नागरिक का दायित्व है। घर-घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना अनिवार्य होना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में जल संरक्षण शिक्षा को शामिल करना चाहिए। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जनजागरण अभियान चलाने होंगे। हर गांव, मोहल्ले और अपार्टमेंट में जल समितियां बनानी होंगी।

छोटे-छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। नलों को खुला न छोड़ना, स्नान, कपड़े और वाहन धोने में अनावश्यक पानी खर्च न करना, रीसायकल और री-यूज को जीवनशैली का हिस्सा बनाना-ये आदतें हमें आज ही अपनानी होंगी।

विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि यदि समय रहते जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया, तो भविष्य में पानी को लेकर संघर्ष और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अब यह समय केवल चिंतन का नहीं, बल्कि संकल्प का है। राजस्थान का अनुभव बताता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि संकल्प और सामूहिक प्रयास हों, तो सूखा इलाका भी पानी से लहलहा सकता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि जल है तो कल है। यह नारा नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। यदि आज हम पानी को नहीं बचाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। अब समय है कि हम राजस्थान की प्रेरणा को पूरे देश में फैलाएं और हर बूंद की रक्षा का संकल्प लें। यही हमारी धरती, समाज और आने वाली पीढ़ियों के प्रति सच्ची जिम्मेदारी है।

–अतिथि संपादक,
अविनाश जोशी
वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉरपोरेट सलाहकार

रोशनी लौटाने का संकल्प : नेत्रदान को जन आंदोलन बनाइये

सुनील दत्त गोयल

कॉर्निया अंधता उन समस्याओं में है जिन्हें सही सिस्टम और समय पर कदमों से तेजी से कम किया जा सकता है-जरूरत है जागरूकता को कार्रवाई में बदलने की, अस्पताल-आधारित रिट्रीवल को बढ़ाने की, और यह सुनिश्चित करने की किदान हुआ हर कॉर्निया अधिकतम लोगों की रोशनी लौटाए। राजस्थान आई बैंक सोसाइटी (EBSR) की ताज़ा तिमाही रिपोर्ट दिखाती है कि पक्का इरादा, अच्छी काउंसलिंग और तेज़ प्रोसेसिंग मिलकर कैसे बड़ा असर लाते हैं।

क्यों जरूरी है भारत में दृष्टिदोष और अंधता का कुल बोझ घटा है, लेकिन कॉर्निया अंधता ऐसा क्षेत्र है जहां प्रत्यारोपण से सीधे रोशनी लौट सकती है-यानी समस्या के साथ समाधान भी मौजूद है। राष्ट्रीय अंधत्व एवं दृष्टिदोष सर्वे (2015-19) ने दिखाया कि देश में अंधता का कुल प्रचलन 0.36% तक घटा, पर कॉर्निया सहित रोके जा सकने वाले कारणों पर सतत फोकस 2025 तक 0.25% के लक्ष्य के लिए जरूरी है।

राजस्थान का उदाहरण जनवरी-जून 2025 में EBSR ने 1,518 कॉर्निया जुटाए और 930 प्रत्यारोपण करवाए; Q1 की उपयोगिता 56% से 2 में 67% तक पहुँची, और जून में 197% ट्रांसप्लांट तथा 82.77% उपयोगिता का मासिक रिकॉर्ड बना। स्थापना से जून 2025 तक EBSR ने 25,808 कॉर्निया प्राप्त कर 16,597 प्रत्यारोपण कराए हैं, और बताया है कि राज्य में उपयोग होने वाले कुल कॉर्निया का लगभग 96% वह सप्लाई करता है-यह पैमाने, गुणवत्ता आश्वासन और समुदाय-भागीदारी का मजबूत मॉडल है।

देश की तस्वीर: सरकारी डेटा क्या कहता है

भारत सरकार के [illegible] के अनुसार 2019 तक अंधता प्रचलन 0.36% पर आ चुका था और 2025 तक 0.25% का राष्ट्रीय लक्ष्य तय है-यानी प्रोग्रामेटिक सुधार सही दिशा दे रहे हैं।

लोकसभा में सरकार ने बताया कि औसतन 40-50% दान की गई आंखें/कॉर्निया सालाना प्रत्यारोपण में उपयोग हो पाती हैं; गुणवत्ता, उम्र और मेडिकल कारणों से सभी ऊतक ऑप्टिकल ग्रेड नहीं बन पाते-यही गैप HCRP और लैब-सक्षम प्रक्रिया से पाटा जा सकता है।

2024-25 तक NPCBVI के माध्यम से 1.17 करोड़ से अधिक लोग विभिन्न नेत्र सेवाओं से लाभान्वित हुए; इसमें कैटरेक्ट, चश्मे, और अन्य रोग-प्रबंधन के साथ केरेटोप्लास्टी भी शामिल है-यह इकोसिस्टम कॉर्निया के असर को गुणा देने वाली बैकबोन है।

नीति इतिहास बताता है किसरकार ने आई बैंकों/एडिसी को फंडिंग, स्टाफ ट्रेनिंग, और प्रतिजोड़ी कॉर्निया पर प्रतिपूर्ति जैसी सहूलियतें दीं; लक्ष्य 1 लाख वार्षिक ट्रांसप्लांट तक स्केल करना था-अस्पताल-आधारित रिट्रीवल से उपयोगिता 50-72% तक जाती दिखी है।

क्या सबसे ज्यादा असर करता है

अस्पताल से सीधी प्राप्ति (HCRP):ICU/इमरजेंसी/मॉर्चरी में प्रशिक्षित काउंसलर समय पर सहमतिऔर बेहतर ऊतक दिलाते हैं, जिससे उपयोगिता और ट्रांसप्लांट दोनों बढ़ते हैं। सरकारी स्वीकारोक्ति के मुताबिक उपयोगिता 40-50% के औसत से ऊपर ले जाने के लिए यही सबसे बड़ा लीवर है।

उपयोगिता-फर्स्टसोच: सर्जन नेटवर्क, समय पर लैब टेस्ट (सेरोलॉजी, स्पेक्युलर माइक्रोस्कोपी), और लेमलर तकनीकें (DSEK/DMEK/DALK) एक कॉर्निया से दो मरीजों तक को लाभ पहुँचा सकती हैं।

भरोसा और सम्मान: राजस्थान की जमीनी कहानियाँ-चलती एंबुलेंस में नेत्रदान, तीसरे दिन की बैठक में सार्वजनिक सम्मान-दिखाती हैं कि संवेदनशील संवाद और पारदर्शिता से परिवार समय पर हाँ कहते हैं।

नीतिऔर सिस्टम: तुरंत क्या करें HCRP को सार्वभौमिक बनाइए: सभी मेडिकल कॉलेजों और बड़े अस्पतालों में 24X7 काउंसलर व रिट्रीवल टीम, मॉर्चरी एक्सेस और फास्ट-ट्रैक लैब सपोर्ट अनिवार्य हों; राज्यों के डैशबोर्ड कलेक्शन नहीं, उपयोगिता और ऑपरेशन पर रैंक करें।

उपयोगिता पर फंडिंग: अनुदान/CSR प्रोत्साहन उन आई बैंकों को प्राथमिकता दें जो लगातार 60-70%+ उपयोगिता दिखाएँ और जिलों तक लेमलर ट्रेनिंग पहुँचाएँ।

रुकावटें हटाइए: मेडिकल-लीगल क्लियरेंस, ट्रांसपोर्ट और इंटर-स्टेट एक्सचेंज के मानक समय-सीमा के साथ तय हों; जिला-स्तर पर सेरोलॉजी और स्पेक्युलर की उपलब्धता डिस्कार्ड कम करती है।

डेटा पारदर्शिता: NPCBVI डैशबोर्ड पर तिमाही राज्यवार कलेक्शन, ट्रांसप्लांटेबल-ग्रेड यील्ड और वास्तविक ट्रांसप्लांट प्रकाशित होते रहें, ताकि कलेक्शन बनाम उपयोगिता का अंतर न रहे।

जन-भागीदारी: NSS/ कॉलेज, धार्मिक व सामुदायिक नेतृत्व और शोक-समय संवाद की स्क्रिप्ट-जिन्हें राजस्थान अपना रहा है-को व्यापक बनाइए, ताकि फॉर्म से ज्यादा परिवार की तैयारी हो और हेल्पलाइन पर समय से कॉल पहुँचे।

राजस्थान से देश की सीख

Q2 की उछाल-एक महीने में 197 ट्रांसप्लांट और 82.77% उपयोगिता-यह साबित करती है कि जब अस्पताल रिट्रीवल, काउंसलिंग और लैब-लॉजिस्टिक्स एक सूत्र में आ जाते हैं, तो हर दान लगभग तय रोशनी में बदलता है। यही मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने से 40-50% की औसत उपयोगिता को 60-70%+ तक ले जाना संभव है।

तुरंत कदम

सरकारें: HCRP का सार्वभौमीकरण, उपयोगिता-आधारित स्कोरकार्ड, लेमलर ट्रेनिंग, और इंटर-स्टेट ऊतक-विनिमय के समयबद्ध मानक तय करें-2025 के 0.25% लक्ष्य की दिशा में यह तेज़ी जरूरी है।

अस्पताल: ICU/ER/मॉर्चरी में आई-डोनेशन चैंपियन नामित करें और ऑन-कॉल रिट्रीवल SOPs लागू करें-यही घंटों के भीतर सहमति को संभव बनाता है।

नागरिक: परिवार से अभी बात करें, टोल-फ्री नंबर सहेजें, और मौत के कुछ घंटों में सूचना दें-यही वो पल है जो संवेदना को दृष्टि में बदल देता है। हर कॉर्निया ऑपरेशन थिएटर तक पहुँचना चाहिए-और हर हाँ एक इलाज में बदलनी चाहिए। देश के पास नीति, कार्यक्रम और अनुभव का खाका मौजूद है; राजस्थान यह दिखा रहा है कि जमीन पर इसे कैसे जिया जाता है।

धन्यवाद,

–रोटेरियन सुनील दत्त गोयल,
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।

लेखक खुद भी अपने नेत्रदान का पंजीकरण करा चुके हैं। इसके अलावा अंगदान एवं देहदान का भी पंजीकरण कराया हुआ है।

विज़न डॉक्यूमेंट 2047 : रोजगार, आधारभूत संरचना, विकास से युवाओं को नए अवसरों तक

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश का विज़न डॉक्यूमेंट 2047, केवल एक भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि युवाओं के लिए बनाए जा रहे ठोस अवसरों का रोडमैप है

आकांक्षा पालावत

दुनिया आज एआई, पर्यावरण, क्लीन एनर्जी, स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे क्षेत्रों में जबर्दस्त बदलाव के दौर से गुजर रही है। यह चुनौती भी है और अवसर भी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस चुनौती को अवसर में बदलने का संकल्प लेते हुए राज्य के साढ़े आठ करोड़ लोगों की भागीदारी से वर्ष 2047 तक राजस्थान को पूर्ण विकसित बनाने के लिए विजन डाक्यूमेंट 2047 जारी किया है और इस पर मिशन मोड पर कार्य शुरू कर दिया है। राज्य को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के इस विजन डॉक्यूमेंट की हर नीति, हर योजना और हर प्रयास का केंद्र युवा हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश का विज़न डॉक्यूमेंट 2047, केवल एक भविष्य की कल्पना नहीं बल्कि आज के और आने वाले कल के युवाओं के लिए बनाए जा रहे ठोस अवसरों का रोडमैप है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सोच साफ है कि जब तक युवा आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक राज्य प्रगति नहीं कर सकता क्योंकि युवा सम्भावना, एनर्जी और इनोवेशन का केन्द्र है इसलिए शिक्षा, उद्यिमता, रोजगार, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से राजस्थान ने विकसित राज्य बनने का लक्ष्य तय किया है। वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का सपना, उन युवाओं की आकांक्षाओं को समर्पित है जो आज मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। इस विज़न में हर युवा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, आधुनिक स्किल्स के साथ रोजगार की तैयारी होगी, हर क्षेत्र में इनोवेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा और सबसे अहम युवाओं को प्रदेश की विकास यात्रा का भागीदार बनाया जाएगा।

आज का युवा सिर्फ नौकरी नहीं, अपनी पहचान चाहता है। इसी सोच के साथ विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 45 वर्ष के युवाओं को 2 करोड़ रुपये तक का ऋण मिलेगा जिससे वे अपना खुद का स्टार्टअप या बिज़नेस शुरू कर सके। महिलाओं, एससी, एसटी दिव्यांग और ग्रामीण युवाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। ट्रेनिंग, मार्गदर्शन और मार्केट से जोड़ने जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध होगी। यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ एक नया आत्मविश्वास भी दे रही है।

जयपुर में बन रहा राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ न केवल एक सुपर-स्पेशियलिटी संस्थान होगा बल्कि मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के क्षेत्र में युवाओं के लिए नए अवसर खोलेगा। डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनेगा। रिसर्च, ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के जरिए मेडिकल छात्र राजस्थान में ही ग्लोबल स्तर की शिक्षा और अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में रोज़गार और प्रोफेशनल ग्रोथ के नए रास्ते खुलेंगे।

राइजिंग राजस्थान समिट-2024 में 35 लाख करोड़ रूपये के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इनमें से 4 लाख करोड़ रूपये के एमओयू पर काफी प्रगति हासिल की जा चुकी है। दिसम्बर, 2025 में जयपुर में समिट का आयोजन कर इन सभी एमओयू की प्रगति पर मंथन कर विकास की नई राह पर राज्य को अग्रसर किया जाएगा। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, रीको डायरेक्ट अलोटमेंट पॉलिसी, डेटा सेंटर पॉलिसी, मिनरल पॉलिसी, टेक्सटाइल एंड अपेरल पॉलिसी से राज्य में औद्योगिक विकास को नया स्वरूप मिला है। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण, कम निवेश में अधिकतम रोजगार और विश्वमंच पर भारत को सॉफ्ट पावर व सांस्कृतिक नेतृत्व का केन्द्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण पर्यटन सेक्टर के लिए भी इस विजन डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ है।

जोधपुर-पाली इन्डस्ट्रियल कॉरिडोर के पार्ट दिल्ली- मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 19 हजार करोड़ रूपये के निवेश से पश्चिमी राजस्थान में आधारभूत ढांचे, रोजगार और निवेश को नया आयाम मिलेगा। इससे 50 हजार प्रत्यक्ष और 2 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। राजस्थान इन्टीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी-2024 के माध्यम से वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। वर्ष 2027 तक सभी किसानों को दिन में विद्युत सप्लाई का लक्ष्य पूर्ण होने से अन्नदाता को राहत और सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार का लक्ष्य पब्लिक सेक्टर में 4 लाख और प्राइवेट सेक्टर में 6 लाख नए रोजगार देना है। राज्य सरकार ने नई भूमि आवंटन नीति-2025 लागू की है जिससे शिक्षा, हेल्थ और इंडस्ट्री से जुड़े युवाओं को ज़मीन, निवेश और विकास के लिए मदद मिलेगी। वहीं, एयरो स्पोर्ट्स भूमि लीज नीति रोमांचक खेलों, टूरिज्म और इवेंट्स से जुड़े युवाओं के लिए करियर के नए दरवाज़े खोल रही है। चाहे आप एजुकेशन सेक्टर में हों, हेल्थकेयर, टूरिज्म या एडवेंचर में सरकार हर दिशा में युवाओं को केंद्र में रखकर फैसले ले रही है। केन्द्र सरकार की खेलो इंडिया पॉलिसी-2025 भी इस दिशा में मददगार साबित होगी। राजस्थान में युवाओं के लिए आज जो किया जा रहा है, वही उन्हें आने वाले वर्षों में एक ग्लोबल सिटीजन बनाएगा। विश्वकर्मा योजना, रिम्स, राजस्थान मंडपम, सोलर और ठाीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, स्किल मिशन- ये सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जहाँ हर युवा को अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह विज़न साफ है कि युवा केवल लक्षित समूह नहीं, विकास के भागीदार हैं। राजस्थान अब ऐसा प्रदेश बन रहा है जहाँ सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें साकार करने की व्यवस्था भी सरकार कर रही है। यह समय है पारम्परिक सोच से आगे बढ़ने का, सीखने, करने और बढ़ने का क्योंकि जब युवा आगे बढ़ेगा, तब ही राजस्थान 2047 का सपना हकीकत बनेगा। यह डॉक्यूमेंट नहीं हमारा भविष्य है, राजस्थान और इसके युवाओं का भविष्य।

आकांक्षा पालावत,
सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

बचत मेले में युवाओं और बच्चों को बचत करने की सीख दी

डीडवाना, (निसं)। भारतीय डाक विभाग की ओर से नागौर डाक मंडल के तत्वावधान में डीडवाना में जिला स्तरीय विशाल बचत मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्देश्य आमजन, विशेषकर युवाओं और बच्चों को बचत के महत्व से जोड़ना और भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश की दिशा में प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर और रामावतार सोनी डाक अधीक्षक द्वारा किया, जहां डाक विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे।

अधीक्षक डाकघर नागौर मंडल रामावतार सोनी ने बताया कि शिविर के दौरान 11 हजार नए बचत खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है और लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी से लगातार खाते खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मेलों का मकसद आमजन को वित्तीय साक्षर बनाना और बचत की आदत विकसित करना है। डाक निरीक्षक राज चौधरी ने जानकारी दी कि मेले में स्कूली बच्चों के लिए क्विज, निबंध, पत्र लेखन और पेंटिंग प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। पत्र लेखन का विषय बचत का महत्व और डाकघर बचत योजनाएँ और हमारा भविष्य रखा गया, जबकि पेंटिंग प्रतियोगिता का विषय बचत से सुनहरा भविष्य था। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में बच्चों ने बचत योजनाओं और वित्तीय साक्षरता पर ज्ञान का प्रदर्शन किया।

कन्या महाविद्यालय में खेल प्रतियोगितायें शुरु

भीलवाड़ा, (निसं)। सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय कन्या महाविद्यालय में शुक्रवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष में खेल विभाग, महिला प्रकोष्ठ एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम एवं तीन दिवसीय खेल गतिविधियों का आगाज प्राचार्य प्रोफेसर सावन कुमार जांगिड़ की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर जांगिड़ ने मेजर ध्यानचंद के जीवन पर प्रकाश डाला तथा छात्राओं को खेलों का महत्व समझाते हुए उन्हें खेल संबंधी सभी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। खेल प्रभारी सुधा नवल ने तीन दिवसीय खेल गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत की। शुक्रवार प्रथम दिवस पर योग एवं प्राणायाम सत्र का आयोजन किया गया। सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय कन्यामहाविद्यालय के सहायक आचार्य प्रणव कुमार व्यास ने संकाय सदस्यों एवं छात्राओं को योग के महत्व के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करते हुए योगाभ्यास एवं प्राणायाम करवाया। इस अवसर पर छात्राओं के लिए 'खेल एवं स्वास्थ्य' विषयक निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन नेहा शर्मा एवं हेमंता मीणा द्वारा किया गया, जिसमें छात्राओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन सहायक आचार्य दिलीप कुमार शर्मा ने किया।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शनिवार 30 अगस्त, 2025

भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2082, विशाखा नक्षत्र दिन 2:37 तक, ऐन्द्रयन योग दिन 3:10 तक, गर करण प्रातः 9:34 तक, चन्द्रमा प्रातः 7:53 से वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-कन्या, बुध-कर्क, गुरू-मिथुन, शुक्र-कर्क, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज त्रिपुष्कर योग सूर्योदय से दिन 2:37 तक है। भद्रा रात्रि 10:47 से आरम्भ होगी। आज बुध मघा सिंह राशि में प्रवेश करेगा। आज मुक्ताभरण सप्तमी, सन्तान और टुकड़ी सप्तमी, ललिता सप्तमी है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 7:44 से 9:18 तक, चर 12:28 से 2:02 तक, लाभ-अमृत 2:02 से 5:11 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 6:09, सूर्यास्त 6:46

मेष
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों में परेशानी हो सकती है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

वृष
परिवार में प्रसन्नता-हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

मिथुन
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

सिंह
घर-परिवार के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है।

कन्या
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक परेशानियां दूर होने लगेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा।

धनु
आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। घर-गृहस्थी के खर्चों में वृद्धि होगी। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

मकर
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। -वाल्तेयर

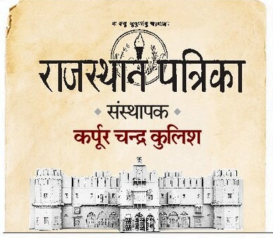

भ्रष्ट तंत्र की भेंट न चढ़ने दें बेरोजगारों के सपनों को

सरकारी नौकरियों में भर्ती की चाह रखने वाले बेरोजगार युवा उस समय खुद को ठगा-सा महसूस करते हैं जब उनको पता लगता है कि पेपर लीक, नकल और साक्षात्कार में भेदभाव ने काबिल होने के बावजूद उनके अवसरों को खत्म कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट का पुलिस उपनिरीक्षक (एसआइ) भर्ती-2021 को रद्द करने का फैसला भर्ती परीक्षाओं में पनप गए भ्रष्ट तंत्र की कहानी कहता है। हैरत इस बात की है कि भर्ती परीक्षाओं के लिए बनी संवैधानिक संस्थाओं तक में भ्रष्टाचार व राजनीतिक हस्तक्षेप ने पैर पसार लिए हैं। यही कारण है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने भी राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए अन्य परीक्षाओं की जांच की बात भी कही है। कोर्ट का यह फैसला न केवल राजस्थान, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी सरकारी पदों पर होने वाली भर्ती में गड़बड़ियों व भ्रष्टाचार को रेखांकित करता है।

पिछले एक दशक में ऐसी घटनाएं बार-बार सामने आई हैं, जहां नौकरियां हासिल करने वाले ईमानदार अभ्यर्थियों को भी भर्तियों में भ्रष्टाचार के कारण भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इनमें कई परीक्षाओं को या तो सुप्रीम कोर्ट या राज्यों के हाईकोर्ट ने रद्द भी किया है। उत्तर प्रदेश में 2019 में शिक्षक भर्ती घोटाला हो या फिर बिहार में पुलिस भर्ती घोटाला, अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं की वजह से ये विवादों में आए। मध्य प्रदेश में व्यापमं घोटाला (2013-15) तो पूरे देश में काफी चर्चित रहा, जिसमें हजारों चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां रद्द हुईं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कई अधिकारियों को दंडित किया और प्रभावित अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट भी दी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से वर्ष 2020 में पेपर लीक और रिश्वतखोरी के कारण कई भर्तियां रद्द हुईं। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में तो मंत्री तक की गिरफ्तारी हुई और सुप्रीम कोर्ट को भर्ती रद्द करनी पड़ी। गंभीर तथ्य यह है कि गड़बड़ियां उजागर होने पर जो भर्तियां रद्द होती हैं उनका दंश उन अभ्यर्थियों को ज्यादा झेलना पड़ता है, जिन्होंने कड़ी मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा पास की। कई अभ्यर्थी नौकरी के बाद शादी कर चुके होते हैं। परिवार की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर होती हैं। सामाजिक स्तर पर भी ऐसे अभ्यर्थियों को उपहास और अविश्वास का सामना करना पड़ता है।

रद्द होने वाली भर्तियों में आमतौर पर अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाता है, लेकिन यह फौरी राहत ही होती है। राजस्थान हाईकोर्ट का निर्णय परीक्षाओं की पारदर्शिता बनाने की दिशा में स्वागतयोग्य कहा जाएगा। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए केंद्र व राज्य स्तर पर बने भर्ती आयोगों व अन्य भर्ती एजेंसियों को निष्पक्ष रखना ज्यादा जरूरी है। भर्तियों की चयन प्रणाली ऐसी होनी चाहिए, जिसमें गड़बड़ी की गुंजाइश न हो। बेरोजगारों के सपनों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने से बचाना होगा।

जन्म से मोक्ष पर्यन्त माया ही कर्ता है। माया और स्त्री पर्याय है। तब स्त्री की परा-अपरा शक्तियों का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इन्हीं दो किनारों के मध्य प्रवाहित रहती है स्त्री। अन्त में पुनः अनन्त में लीन हो जाती है।

मोक्ष तक पत्नी का साथ

गुलाब कोठारी
प्रधान संपादक
पत्रिका समूह
@patrika.com

शरीर ही ब्रह्माण्ड

मोक्ष के लिए आत्मा के साथ जीना और मृत्यु के लिए देह के रूप में- यही माया की भूमिका है। पुरुष अपने विवर्त का मूकदर्शक है। सारे अधिकार माया के पास सौंप रखे हैं। अव्यय की मन-प्राण-वाक् कलाओं में श्वोवसीय मन ही इन्द्रिय-सर्वेन्द्रिय एवं महन्मन के रूप में कार्य करता है।

स्वयंभू लोक आग्नेय प्राणों का लोक है। स्वयंभू को सृष्टि करने के लिए युगल चाहिए। सृष्टि कामना के तपन से जो स्वेद पैदा हुआ, उससे आपः तत्त्व पैदा हुआ। एक ही प्राण अब प्राण-आप दो भागों में बंट गया। जो भाग पानी बना वह योषा कहलाया। स्त्री बना। प्राण भाग वृषा रूप पुरुष कहलाया। दोनों के मिथुन भाव से विराट् पैदा हुआ। वेदत्रयी में ऋक्-महदुक्थ है, साम महाव्रत है, यजुः पुरुष है, गतिमान तत्त्व है। स्वेदन-अश्रुधारा आदि पानी रूप अग्नि से ही उत्पन्न होते हैं। विशुद्ध अग्नि सत्याग्नि है, यज्ञाग्नि यौगिक (मिश्रित) अग्नि है। एक फिजिक्स है, दूसरी केमिस्ट्री है। यज्ञाग्नि चित्याग्नि है, सत्याग्नि चितेनिधेय है। यजुराग्नि वेदाग्नि ही सत्याग्नि है। इसकी प्रथम विकास भूमि स्वयंभू, द्वितीय विकास भूमि सूर्य तथा तृतीय विकास भूमि भूपिण्ड है। इन्हीं को ब्रह्माग्नि, देवाग्नि, भूताग्नि कहा जाता है। इनका ही दूसरा नाम प्राणाग्नि, वागाग्नि, अन्नादाग्नि है। ब्रह्माग्नि से- विधरण, प्रतिष्ठा होती है। देवाग्नि से रूप और विकास होता है, भूताग्नि से पाक और विलयन धर्म की पूर्ति होती है। चौथा अग्नि यज्ञाग्नि रूप वैश्वानर है। यह ताप और दाहधर्मा है।

पानी उत्पन्न करना अग्नि का स्वाभाविक धर्म है। ब्रह्माग्नि से परमेष्ठी का अम्भ पैदा होता है। देवाग्नि से मरीचि, भूताग्नि से मर तथा अन्तरिक्ष्य चन्द्रमा (प्राणमय वैश्वानर) से श्रद्धा नामक पानी पैदा होता है। अग्नि ऊर्जा है, पानी पदार्थ है। वायु से अग्नि उत्पन्न होता है। पानी से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी में पांचों महाभूत रहते हैं। लक्ष्मी कहते हैं पृथ्वी को, विष्णुपाद भी उसी को कहते हैं।

जल के स्वामी (सोमवंशी) विष्णु हैं। पृथ्वी शरीर है- जल से निर्मित होता है। स्त्री के शरीर से ही सन्तान का शरीर बनता है। विष्णु ही अव्यय रूप आत्मा है। विष्णु अव्यय है, आत्मा अक्षर है, शरीर (लक्ष्मी) क्षर है। लक्ष्मी अर्थवाक् है। सरस्वती शब्दवाक् है। क्षर पुरुष की पांच कलाएं- प्राण, आप, वाक्, अन्न, अन्नाद के पंचीकरण से ही विश्वसृट्, पंचजन, 25 पुरंजन, पुर आदि का निर्माण होता है। ये सारा अर्थवाक् है। विश्व का स्थूल स्वरूप है। शरीरों का निर्माण भी पंच महाभूतों की चिति से ही होता है, मातरिश्वा वायु के योग से। अन्न ही अन्नाद में भुक्त होकर दधि-घृत-मधु-अमृत तत्त्वों से देह का निर्माण करता है। अन्न से ही देह-धातुओं के अन्त में मन का निर्माण होता है, जिसकी कामना का आधार अन्न ही होता है। कृष्ण का कथन है कि-

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च।
अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा।। (गीता 7.4)

यहां अष्टधा प्रकृति का वर्णन करते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी प्रकृति आठ प्रकार की होती है- पंचमहाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार इसमें सम्मिलित रहते हैं।

इस अपरा (क्षर) प्रकृति का निर्माण अन्न से होता है। जीवात्मा को यही आकृति रूप में आवरित करती है। मन-बुद्धि-अहंकार प्रकृति विग्रह रूप में कार्य करते हैं। शरीर के उपकरण रूप है। मन की मर्जी (कामना) ही शरीर के स्थूल कर्मों का आधार बनती है।

सूक्ष्म सृष्टि अदृश्य रूप में- प्राणों के स्पन्दन रूप में- कार्य करती है। यहां शब्दवाक् प्रधानता लिए रहती है। सूक्ष्म सृष्टि का केन्द्र हृदय होता है। अक्षर पुरुष रूप परा प्रकृति जीव की क्रियाओं का मूल संचालन करती है। एक ओर इसका सम्बन्ध अव्यय पुरुष (कारण शरीर) से होता है। अक्षर और अव्यय दोनों की मिलकर सूक्ष्म शरीर संज्ञा है। दोनों साथ रहते हैं। हृदय केन्द्र में ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा रहती है। वही ब्रह्मा अक्षर प्राण के रूप में हृदय कहलाता है। गति-आगति-स्थिति रूप यही यजुः पुरुष है। ब्रह्मा ही इन्द्र-रूप गति और विष्णु रूप आगति होता है। अतः तीनों ही अक्षर प्राण मिलकर हृदय कहलाते हैं। अक्षर पुरुष के दो अन्य प्राणों- अग्नि और सोम के मिलन से अक्षर ही अमृत-मृत्यु रूप कार्य करता है- जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्..। (गीता 7.5)

अक्षर पुरुष सृष्टि का निमित्त कारण है। क्षर पुरुष उपादान कारण। स्थूल सृष्टि में, मानव योनि में यही स्त्री (योषा) का स्वरूप है। निमित्त कारण भी वही बनती है, उपादान कारण तो स्पष्ट ही है। सम्पूर्ण भूत दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं। अव्यय पुरुष ही सम्पूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय है। (गीता 7.6)

अक्षर अथवा सूक्ष्म सृष्टि (शरीर) प्राण अथवा देव सृष्टि है। प्राण ही देव कहलाते हैं। सृष्टि के मूल 33 प्राण ही 33 देवता हैं। परा प्रकृति चूंकि सूक्ष्म है अतः इसे अधिदेव कहते हैं। इसीलिए स्त्री के परा रूप की 'दिव्य' संज्ञा है। पुरुष सम्पूर्ण सृष्टि में साक्षी रूप ही रहता है। जन्म से मोक्ष पर्यन्त माया ही कर्ता है। माया और स्त्री पर्याय है। तब स्त्री की परा-अपरा शक्तियों का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इन्हीं दो किनारों के मध्य प्रवाहित रहती है स्त्री। अन्त में पुनः अनन्त में लीन हो जाती है।

पुरुष स्वामी है, प्रकृति रूप स्त्री का। सूर्य से निर्मित बुद्धि सूक्ष्म है, चन्द्रमा-अन्न-पृथ्वी से निर्मित देह स्थूल है। चन्द्रमा मन का भी स्वामी है। अतः शरीर कभी बुद्धिमानी से कार्य करता है, कभी मनमानी से। न केवल बुद्धिमानी हितकारी होती है, न केवल मनमानी। दोनों त्रिगुणी होते हैं। षोड़शी पुरुष भी स्त्री-पुरुष दोनों होते हैं, किन्तु ब्रह्मांश केवल पुरुष में (बीजरूप) रहता है। यही कारण शरीर के केन्द्र में रहकर नई सृष्टि के लिए वपन करने का मूल तत्त्व है। इसी के विवर्त के लिए माया (स्त्री) को पैदा किया गया। यह दायित्व भी माया को ही सौंपा कि विवर्त के बाद ब्रह्मांश को पुनः ब्रह्म में ही लीन करेगी।

मोक्ष के लिए आत्मा के साथ जीना और मृत्यु के लिए देह के रूप में- यही माया की भूमिका है। पुरुष अपने विवर्त का मूकदर्शक है। सारे अधिकार माया के पास सौंप रखे हैं। अव्यय की मन-प्राण-वाक् कलाओं में श्वोवसीय मन ही इन्द्रिय-सर्वेन्द्रिय एवं महन्मन के रूप में कार्य करता है। इसी से प्राण-वाक्-अक्षर-क्षर रूप में कार्य करते हैं। स्त्री जब पीहर में रहती है, तब उसका इन्द्रियमन, क्षर पुरुष के तत्त्व मुख्य भूमिका में होते हैं। विवाह पूर्व तो होते ही हैं, विवाह के बाद- शेष जीवन भी- पीहर शरीर पोषण-क्षर-निमित्त ही रहता है। वही आल्हाद-खेल-कूद-सहेलियां-मनोरंजन-अवकाश का वातावरण छाया रहता है। आज एकल परिवारों में यह वातावरण उपलब्ध नहीं रहा। अनेक स्थूल-कुण्ठित ऊर्जाओं के बन्धन अब नहीं खुल पाते। मुक्त भावों की अभिव्यक्ति कुन्द होने लगी।

ससुराल में शरीर की कभी प्रधानता नहीं रहती। आत्मा की तुष्टि और पुरुषार्थ चतुष्टय के निर्वहन पर दृष्टि रहती है। जीवन का यह साधना काल होता है। इसका एक भाग सन्तान (ब्रह्म विवर्त) को संस्कारित-पोषित करने का रहता है- ताकि वह श्रेष्ठ समाज एवं श्रेष्ठ देश के निर्माण में- अभ्युदय और निःश्रेयस में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। दूसरी ओर पुरुष की पूर्णता का निर्माण, विवर्त, दाम्पत्य रति से देवरति में प्रवेश कराकर सांसारिक दायित्वों से निवृत्त करवाने की भूमिका है। जीवन में भक्ति- सेवा का योग करवाना और अन्तकाल में देहमुक्त होकर जीने का अभ्यास (मानस जाप में प्रवेश), शुद्ध शब्द ब्रह्म रूप में नई जीवन शैली में प्रवेश ही सूक्ष्म शरीर- आत्मारूप- से युक्त होना है। जीवात्मा यहीं से जीवन मुक्त होकर मोक्षमार्ग का यात्री बनता है। माया का अलग हो जाना ही आवरण मुक्ति है। स्त्री रूप आवरण से मुक्त होना या करना भी स्त्री रूप पत्नी/माया का ही कार्यक्षेत्र है। अतः मोक्ष होने तक पत्नी भी जन्म-जन्म साथ रहती है।

-क्रमशः

gulabkothari@epatrika.com

क्यूआर कोड को स्कैन कर आप आलेख सुन भी सकते हैं।

बुक इनसाइट

द डिलेमाज ऑफ वर्किंग वीमन

फुमियो यामामोटो की पुस्तक 'द डिलेमाज ऑफ वर्किंग वीमन' ऐसा संग्रह है, जो कामकाजी महिलाओं की जिंदगी के जटिल पहलुओं को बयान करता है। लेखिका ने अपनी कहानियों में महिला पात्रों को साधारण और वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया है।

ये पात्र किसी आदर्श नारी की छवि नहीं हैं, बल्कि वे महिलाएं हैं जिनसे हम रोज मिलते हैं दफ्तर में, बस में या अपने आसपास। कभी वे आत्मनिर्भर और मजबूत नजर आती हैं तो कभी अकेलेपन और असुरक्षा से जूझती हुई। यह विरोधाभास ही किताब को ज्यादा जीवंत बनाता है और पाठकों के करीब लाता है। किताब की सबसे बड़ी खूबी इसकी सादगी और संवेदनशीलता है। भाषा सीधी और सहज है लेकिन उसमें भावनाओं की गहराई झलकती है। हर कहानी पढ़ते हुए लगता है जैसे यह हमारे आसपास की किसी महिला की असली कहानी हो। यही कारण है कि पाठक उनसे तुरंत जुड़ जाते हैं।

आर्ट एंड कल्चर

रंगमंच एक संवेदनशील बौद्धिक प्रयोग है

महानगरों से लेकर छोटे-छोटे शहरों तक आयोजित होने वाले अल्पकालीन रंग शिविरों (थियेटर वर्कशॉप) से क्या हिन्दी रंगमंच समृद्ध हो रहा है या हिन्दी रंगमंच का विकास हो रहा है? यह सवाल इसलिए भी है कि इतने बड़े पैमाने पर चल रहे रंग शिविरों में अनगिनत रंगकर्मियों की भागीदारी के बाद भी किसी रंग आंदोलन जैसी सूरत नजर नहीं आती। दरअसल रंगमंच के प्रशिक्षण के नाम पर चलने वाले ऐसे शिविर या वर्कशॉप नए रंगकर्मियों से किसी नाटक का रिहर्सल ही करा पाते हैं क्योंकि 3-4 सप्ताह की अल्प अवधि में नाट्य के विभिन्न आयामों का प्रशिक्षण देना संभव ही नहीं होता। इसलिए इन रंग शिविरों को प्रोडक्शन ओरियेंटेड वर्कशॉप कहा जाता है। चूंकि बड़ी संख्या में नौजवान रंगमंच के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, जिससे रंग शिविर आयोजित करने वालों को प्रतिभागियों की कोई कमी नहीं होती। होता तो यह रहा है कि बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के चलते ही रंग शिविरों के आयोजन की संख्या बढ़ती जा रही है। पर्याप्त शुल्क के साथ नाट्य प्रशिक्षण देने वाले शिविरों का संचालन दो तरह के रंग निर्देशक कर रहे हैं। एक, जिन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या ऐसे ही किसी प्रतिष्ठित नाट्य संस्थान से विधिवत प्रशिक्षण लिया है। दूसरे, वे रंग निर्देशक जिन्होंने रंगमंच का कोई विधिवत प्रशिक्षण नहीं लिया है लेकिन उनके पास नाटक करने का लंबा अनुभव है और जो किसी रंग समूह का संचालन भी कर रहे हैं। ऐसे रंग शिविर मुख्यतः अभिनय पर ही केन्द्रित होते है, जिसमें शारीरिक अभ्यास और संवाद अदायगी के प्रशिक्षण की प्रधानता होती है। शिविर का नाट्य प्रशिक्षक यदि निपुण निर्देशक है तो प्रतिभागी रंगकर्मी कुछ ठीक-ठाक सीख पाते हैं अन्यथा यह पूरा उपक्रम एक नाटक की तैयारी बनकर रह जाता है।

गिरिजाशंकर
वरिष्ठ कला समीक्षक
@patrika.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

ऐसे रंग शिविर नौजवान रंगकर्मियों को रंगकर्म के प्रति आकर्षित करने तथा उन्हें रंगकर्म से जोड़ने में तो महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं लेकिन वे इन रंगकर्मियों को रंगकर्म करते रहना नहीं सिखा पाते। अल्पकालीन शिविर में किसी एक नाटक में भूमिका निभाने के साथ ही उनका प्रशिक्षण पूरा हो जाता है। बेहतर होता कि उन्हें अभिनय के साथ-साथ रंगमंच का अर्थशास्त्र व रंग समूह चलाने का भी प्रशिक्षण दिया जाता, जिससे वे अपने-अपने शहरों में लौटकर रंगकर्म की निरंतरता बनाए रखते। कुछ रंग निर्देशकों का तर्क है कि शिविर के बाद वे भले ही रंगकर्म न करें, लेकिन वे रंग दर्शक तो बन ही जाते हैं। यह ध्यान रखने की बात है कि किसी रंगकर्मी के लिए शारीरिक अभ्यास और अभिनय सीखने के साथ-साथ उसमें इतिहास व राजनीतिक सामाजिक हालातों की समझ भी विकसित होनी चाहिए। रंगमंच मेकेनिकल प्रक्रिया न होकर एक संवेदनशील बौद्धिक प्रयोग है, जो रंगकर्मी को जिम्मेदार नागरिक बनाता है।

नए विकल्प भारत दीर्घकाल में बन सकता है वैश्विक आपूर्ति शृंखला का केंद्र

ट्रंप टैरिफ से भारत-चीन नजदीकी की राह खुली, पर सतर्कता जरूरी

के.एस. तोमर
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक
@patrika.com

अमरीका की ओर से भारतीय निर्यात पर भारी टैरिफ लगाने के बाद निर्यातक समूहों का अनुमान है कि देश का 55 प्रतिशत तक निर्यात सीधे प्रभावित हो सकता है। इसने भारत को यह अहसास कराया कि केवल एक बड़े बाजार पर निर्भर रहना खतरनाक है। यही कारण है कि भारत सरकार अब क्षेत्रीय साझेदारियों और चीन सहित नए विकल्पों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा केवल शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन तक सीमित कूटनीतिक पड़ाव नहीं है, यह एक ऐसा मोड़ है जहां भारत-चीन संबंधों की तल्खी कम होने और सहयोग के रास्ते खुलने की संभावना है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग और मोदी की आमने-सामने मुलाकात से वैश्विक मंच पर एक नए समीकरण की झलक मिल सकती है।

सीमा विवाद, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और कूटनीतिक अविश्वास ने अब तक दोनों देशों के रिश्तों को बोझिल बनाए रखा लेकिन अमरीका की संरक्षणवादी नीतियों, विशेषकर ट्रंप टैरिफ ने भारत और चीन दोनों को नए विकल्प तलाशने पर मजबूर कर दिया है। यदि वार्ता ठोस नतीजे देती है तो एशिया की स्थिरता के साथ-साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी राहत मिल सकती है। यह भारत के लिए एक अवसर होगा कि वह आर्थिक वृद्धि को मजबूत कर चीन से संतुलित व्यापारिक लाभ ले सके।

भारत-चीन संबंधों की सबसे बड़ी चुनौती है कि यह भरोसे की कमी से ग्रस्त है। डोकलाम और गलवान की झड़पें दिखाती हैं कि मित्रता की भाषा और जमीनी हकीकत में भारी अंतर है। तनावपूर्ण रिश्तों से न केवल सुरक्षा वातावरण बिगड़ता है, बल्कि निवेश और व्यापार की गति भी रुक जाती है। यदि रिश्तों में सुधार हुआ तो सीमाई तनाव कम हो सकता है, अन्यथा भारत को दोहरी सतर्कता अपनानी होगी। कूटनीतिक स्तर पर निरंतर वार्ता और सैन्य स्तर पर विश्वास निर्माण उपाय ही इस तनाव को संतुलित कर सकते हैं। इतिहास बताता है कि चीन ने बार-बार दोस्ती का हाथ बढ़ाकर बाद में विश्वास तोड़ा है। 1962 का युद्ध, सीमाई विवाद और आर्थिक मोर्चे पर आक्रामक रवैया इसकी मिसाल हैं। मोदी की इस यात्रा को लेकर उत्साह के साथ सतर्कता भी आवश्यक है। एलओसी पर हाल की घटनाएं याद दिलाती हैं कि चीन से व्यवहार करते समय भरोसा कम और सावधानी ज्यादा जरूरी है। मोदी की चीन यात्रा एक तरफ नई संभावनाओं के द्वार खोलती है तो चीन के पुराने रवैये से सावधान रहने की चेतावनी भी देती है।

इधर, ट्रंप की धमकियों और टैरिफ वार के बीच भारत ने पीछे हटने के बजाय सीधा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से घोषणा कर आम जनता को कर सुधारों का 'दिवाली गिफ्ट' दिया। इन सुधारों का मकसद न केवल राहत देना है बल्कि 'मेक इन इंडिया' अभियान को नई गति देना भी है। यह संदेश स्पष्ट है कि भारत अमरीकी दबाव में झुकने वाला नहीं है। कर व्यवस्था में सरलता और पारदर्शिता से निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, घरेलू उत्पादन को बल मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। विदेशी निवेशकों को भी संकेत दिया गया है कि भारत अब एक स्थिर और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। इससे भारत अपनी कूटनीतिक और आर्थिक स्थिति को अधिक मजबूत बना सकेगा। दीर्घकाल में ये सुधार भारत को न केवल वैश्विक आपूर्ति शृंखला का केंद्र बना सकते हैं बल्कि घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी बढ़ा सकते हैं।

प्रकृति से जोड़ता अनोखा 'फ्लावर टाउन'

नीदरलैंड्स का फ्लावर टाउन अपनी खूबसूरती और आधुनिक जीवनशैली का अद्भुत संगम है। रिन्सबर्ग में बना 'दे ब्लूम' आवासीय कॉम्प्लेक्स फूलों की आकृतियों से प्रेरित है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि जीवन को हरियाली और सामुदायिकता के साथ जोड़ने का प्रयास है। यह समुदाय को जोड़ने और जीवन में संतुलन लाने के लिए तैयार किया गया है।

आपकी बात

महिलाओं को मिले समर्थन

महिलाओं को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए शिक्षा, पूंजी, मार्गदर्शन और सामाजिक समर्थन इन चारों स्तंभों को मजबूत करना होगा। अगर सही अवसर और माहौल मिले तो महिलाएं रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तीकरण की बड़ी धुरी बन सकती हैं। शिक्षा और कौशल विकास, आर्थिक सहायता व परिवार और समाज का समर्थन से महिलाओं की भागीदारी उद्योगों और स्टार्टअप्स में भी बढ़ सकती है।

- भुवनेश्वरी मालोत, बांसवाड़ा

मजबूत नेतृत्व की जरूरत

आज के दौर में समाज में नैतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, जो समाज को समय-समय पर प्रोत्साहित करने का कार्य करे। शिक्षा, ईमानदारी, नशा प्रवृत्ति को दूर करना, युवाओं को प्रेरित करना तथा विभिन्न कुरीतियों को दूर करने जैसे नैतिक मूल्यों बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उसके अलावा महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने, बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने व युवाओं से समय-समय पर संवाद के प्रयास भी होने चाहिए।

- कुमार जितेन्द्र, मोकलसर

खेलों को बढ़ावा देना चाहिए

खेल न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक विकास में भी महत्ती भूमिका निभाते हैं। विद्यालय स्तर से ही खेलों की अनिवार्यता होनी चाहिए। स्थानीय मैदान संरक्षित किए जाएं व खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिले। खेल न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव के संवाहक हैं।

- खुशबू वर्मा, भोपाल

आज का सवाल

एआइ के दौर में युवा अपनी स्किल्स को कैसे प्रासंगिक बनाए रखें?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

संस्कार कठिन परिस्थितियों में भी संयमित भाषा का प्रयोग रिश्तों में दरार पड़ने से रोक सकता है

शब्दों का चयन सिर्फ संवाद नहीं, आपके व्यक्तित्व की ब्रांडिंग है

अविनाश जोशी
स्वतंत्र लेखक एवं स्तंभकार
@patrika.com

हमारे जीवन में शब्दों का महत्त्व केवल संचार तक सीमित नहीं है। शब्द हमारी सोच, भावनाओं व संस्कारों का आईना होते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पहनावे, व्यवहार और आदतों से उसकी परवरिश और व्यक्तित्व झलकता है, उसी तरह उसकी भाषा और शब्द चयन से उसकी मानसिकता और आंतरिक संस्कार स्पष्ट हो जाते हैं। भाषा केवल अभिव्यक्ति का साधन नहीं, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व की परिभाषा भी तय करती है। जब हम किसी से संवाद करते हैं, तो हमारे शब्द, स्वर और बोलने का तरीका सामने वाले के मन में हमें लेकर एक स्थायी छवि बना देता है। यही कारण है कि कहा जाता है- 'जैसे संस्कार वैसे विचार, जैसे विचार, वैसे शब्द।'

संस्कार केवल धार्मिक या पारिवारिक परंपराओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे जीवन मूल्यों, आदर्शों व दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने बचपन से विनम्रता, आदर और संयम सीखा है, तो यह स्वाभाविक रूप से उसकी भाषा में झलकेगा। वह कठिन परिस्थिति में भी कटु या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। दूसरी ओर, अगर किसी व्यक्ति का वातावरण नकारात्मक रहा है या उसने संवाद में आक्रामकता देखी-सुनी है, तो संभव है कि उसकी भाषा में तीखापन और असंयम आ जाए। यही कारण है कि माता-पिता और समाज को बच्चों में आरंभ से ही सकारात्मक और शालीन भाषा के प्रयोग की आदत डालनी चाहिए।

हमारे चुने गए शब्द हमारी मानसिक स्थिति का सटीक परिचय देते हैं। एक ही बात को हम कई तरीकों से कह सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव शब्दों के चयन पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए 'तुमने गलती की है' और 'अगली बार थोड़ा ध्यान रखना' कहना, दोनों का अर्थ लगभग समान है, लेकिन पहला वाक्य आरोप की तरह लगता है, दूसरा मार्गदर्शन की तरह।

आज के प्रतिस्पर्धी युग में, भाषा का महत्त्व और भी बढ़ गया है। कार्यस्थल पर आपके शब्द यह तय करते हैं कि आप नेतृत्व करने योग्य हैं या नहीं, आप टीम में सहयोग बढ़ाते हैं या तनाव। एक प्रबंधक यदि अपने अधीनस्थों से सम्मानपूर्वक और प्रेरक शब्दों में बात करता है, तो वह टीम को एकजुट और ऊर्जावान बनाए रख सकता है। इसी तरह, सामाजिक जीवन में भी आपकी भाषा से लोग आपके संस्कार पहचान लेते हैं। एक व्यक्ति चाहे कितना ही धनी या शिक्षित क्यों न हो, यदि उसकी भाषा में अभद्रता है तो समाज में उसका सम्मान घट जाता है। शब्द एक बार निकल जाने के बाद वापस नहीं आते। कठिन परिस्थितियों में भी संयमित भाषा का प्रयोग रिश्तों में दरार पड़ने से रोक सकता है। कभी-कभी आवेश में निकले कठोर शब्द वर्षों का विश्वास तोड़ सकते हैं। जैसे विचार हमारी भाषा को आकार देते हैं, वैसे ही भाषा भी हमारी सोच को प्रभावित करती है। यदि हम सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारी सोच भी उसी दिशा में ढलने लगती है। यही कारण है कि मनोवैज्ञानिक भी आत्मसंवाद में सकारात्मक भाषा अपनाने की सलाह देते हैं।

शब्द और भाषा सिर्फ संचार का माध्यम नहीं, बल्कि आपके संस्कार, सोच और व्यक्तित्व का जीवंत परिचय हैं। एक सुसंस्कृत व्यक्ति वही है, जो परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने शब्दों में मधुरता, सम्मान और संयम बनाए रखें। इसलिए, यदि समाज में अपनी एक सकारात्मक और सम्मानजनक पहचान बनाना चाहते हैं, तो अपने शब्दों को सजगता से चुनें।

संपादकीय

युद्ध के नियम होते हैं, कुश्ती के नियम होते हैं, लेकिन राजनीति के कोई नियम नहीं होते। -रॉस पेरोट

जापान में मोदी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ में अतार्किक बढ़ोतरी के आर्थिक नतीजों की आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी का जापान दौरा, यों तो 2014 में पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी इस देश की आठवीं यात्रा है, लेकिन इसे लेकर देश-दुनिया में ऐसी उत्सुकता शायद ही कभी देखी गई हो। विदेश सचिव का यह कहना काफी कुछ कह देता है कि उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रधानमंत्री की जापान यात्रा कई नई पहलों के शुरू होने का अवसर भी बनेगी। यही नहीं, प्रधानमंत्री का यह कहना कि भारत और जापान एक-दूसरे के लिए बने हैं, तब और भी अधिक औचित्यपूर्ण लगता है, जब जापानी वाहन निर्माता कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने अगले पांच से छह वर्षों में देश में 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। प्रधानमंत्री मोदी के दो-दिवसीय जापान दौरे से क्वाड समूह के भविष्य की दिशा को लेकर भी संकेत मिलने की उम्मीद है। क्वाड समूह का औपचारिक उद्देश्य ही सदस्य देशों- अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकना था। लेकिन, हाल ही में जिस तरह से जापान के प्रतिनिधिमंडल ने टैरिफ पर चर्चा के लिए अपनी अमेरिका यात्रा को रद्द किया और चीन व भारत के बीच भी नजदीकी बढ़ी है, उसे देखते हुए क्वाड के भविष्य पर एक प्रश्नचिह्न तो खड़ा हो ही गया है। हालांकि, इस दौरान भारत व जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा हुई है। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों द्वारा शुरू की गई आर्थिक सुरक्षा पहल में, सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज, औषधियां, सूचना व संचार और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया जाएगा। भारत-जापान शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अगले दस वर्षों में जापान की तरफ से भारत में सौ खरब येन के निवेश का लक्ष्य रखा है, जो यकीनन द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत जैसा होगा। जापान की

यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सम्मेलन में शिरकत करने के लिए चीन जाएंगे। खबरें हैं कि भारत रूस से तेल-खरीद को बढ़ाने जा रहा है। ऐसे में, भारत के जापान, चीन और रूस के साथ प्रगाढ़ होते रिश्ते उल्टे राष्ट्रपति ट्रंप को ही अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दें, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए।

अनुत्तरित प्रश्नों का कोलाहल

जब पक्ष व विपक्ष, दोनों ही क्षुद्र राजनीति के बंधक बने हों, तब अनुत्तरित प्रश्नों के कोलाहल के बीच कोई भी खुद को निर्दोष कैसे कह सकता है? निर्वाचित सांसद अगर जनता के कम और अपने राजनीतिक दल के प्रतिनिधि ज्यादा लगें, तब सदनों के स्थगन, महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी और बेवजह भाषणबाजी सामान्य हो जाती है।

आम तौर पर पार्टियां एक-दूसरे से असहमत होने पर सहमत होती हैं और संसद सत्र के ठप होने के लिए एक-दूसरे को दोष देती हैं। लेकिन इस साल, विपक्ष और सत्तारूढ़ गठबंधन ने आम सहमति दिखाते हुए संसद के मानसून सत्र को बेकार माना। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के मामले में की गई लापरवाही की वजह से सदन की कार्यवाही लगातार स्थगित होती रही। संसद में यह अराजकता तब फैली, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आम तौर पर, निर्वाचित सांसद अपनी पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि मतदाताओं का। लगातार स्थगन की वजह से प्रति मिनट करदाताओं द्वारा चुकाए जाने वाले अनुमानित दो लाख रुपये बर्बाद होते हैं। इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि कानून और शासन पर निगरानी न रख पाने की वजह से भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जो सांसदों का प्राथमिक दायित्व है। यह परिस्थिति जीवन और आजीविका को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर शासन की समीक्षा के लिए उपयुक्त है।

शंकर अय्यर
वरिष्ठ पत्रकार

यहां कुछ झलकियां दी गई हैं। फिलहाल भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए एकतरफा टैरिफ का खतरा है। इस मुद्दे पर लोकसभा में सात और राज्यसभा में 13 सवाल उठे। इस मुद्दे पर बहस शुरू होनी चाहिए थी, यहां तक कि रणनीतियों पर एक सर्वदलीय चयन समिति भी गठित होनी चाहिए थी। लेकिन बयानबाजी के शोर में ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल, सरकार ने घरेलू अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके सही ही किया है और आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में सुधारों के लिए मंत्रियों के दो अनौपचारिक समूह बनाए हैं। इन्हें विधायी और नीतिगत सुधारों के एजेंडे तैयार करने का काम सौंपा गया है। बेशक यह स्वागत योग्य है, लेकिन यह बजट-2025 में किए गए उपायों की घोषणाओं पर सवाल खड़े करता है। बजट में नियामक सुधारों के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की गई थी, जो मंजूरी राज के परिदृश्य की समीक्षा करेगी। नियामकीय बोझ से व्यवसाय भयभीत हैं। अवंतिस रेगटेक के एक अध्ययन से पता चलता है कि उद्यमियों

को 1,500 कानूनों और 69,000 से ज्यादा अनुपालनों का सामना करना पड़ता है। क्या सांसदों ने सरकार से सवाल किए? सच तो यह है कि इस काम में दो समितियां लगी हुई हैं और उनकी पहली बैठक 21 अगस्त को ही हुई थी।

सर्वविदित है कि बहुप्रतीक्षित सुधारों का बड़ा हिस्सा राज्यों में लंबित है। सरकार ने बदलाव को गति देने के लिए फरवरी में राज्यों के निवेश अनुकूलता सूचकांक की घोषणा की थी–इसके लिए नीति आयोग द्वारा मुहूर्त और लॉन्च का इंतजार है। प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारत को अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जुलाई, 2024 में एक कोष की घोषणा की गई थी। इस वर्ष के लिए इसका बजट आवंटन 20,000 करोड़ रुपये है। अगस्त तक इस कोष का वितरण नहीं हुआ है। डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, फिर भी पशु चिकित्सकों के 10,839 पद रिक्त हैं। मनरेगा कार्यक्रम ग्रामीण भारत की जीवन रेखा है। अगस्त तक 17,238 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान नहीं किया गया है। वर्ष 2024 के बजट में 'शहरों को विकास केंद्र' घोषित किया गया। इसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने फरवरी, 2025 में 'शहरी चुनौती कोष' की घोषणा की, और इसके लिए बजट में एक लाख करोड़ रुपये आवंटित किए। क्या सांसदों ने इसकी स्थिति जानने के लिए सवाल उठाए?

इस बीच, बाढ़ का कहर कस्बों और शहरों में जारी है, खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में। 2021 की शुरुआत में ही आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि बाढ़ क्षेत्र में निर्माण कार्यों ने शहरों को असुरक्षित बना दिया है। इससे निपटने के लिए अब तक नीति नहीं बनाई गई है। अगस्त में, संसद की एक स्थायी समिति को बताया गया था कि 2024 में बाढ़ क्षेत्र के लिए तैयार दिशानिर्देश 'राज्यों के पास उनके सुझावों के लिए लंबित हैं।' बाढ़ रोकने और सूखे को कम करने के लिए नदियों को जोड़ने का विचार राज्यों के बीच आम सहमति के अभाव में अटका है। सर्वविदित है कि जीवन की गुणवत्ता विदेशी और घरेलू निवेश और पुनर्निवेश को निर्धारित करती है। तथ्य यह है कि देश में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पिछले वर्ष के 10 अरब डॉलर के मुकाबले तेजी से घटकर 40 करोड़ डॉलर रह गया, जबकि सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 80 अरब डॉलर रहा। सांसदों को इसके कारणों पर बहस करनी चाहिए थी। इस बहस से उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना में सुधार लाया जा सकता था और चीन+1 मॉडल के लिए निवेश आकर्षित किया जा सकता था। ऑपरेशन सिंदूर से इसकी पुष्टि हुई कि रक्षा उत्पादन को निजी क्षेत्र के लिए खोलना इस सरकार की सफलता है। लेकिन यह व्यवस्था समस्याओं से घिरी हुई है। एक उदाहरण-सरकार ने बुलेटप्रूफ बॉडी प्रोटेक्टर बनाने के लिए 43 लाइसेंस जारी किए। रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने पाया है कि इनमें से 33 कंपनियों ने अभी तक उत्पादन शुरू नहीं किया है!

उच्च शिक्षा में निवेश क्षमता का विस्तार करता है और नवाचार को बढ़ावा देता है। इसके लिए संकाय क्षमता को बढ़ावा देने की जरूरत है। लेकिन सच यह है कि वैज्ञानिक अनुसंधान पर केंद्रित संस्थानों में सैकड़ों पद रिक्त हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में वैज्ञानिकों सहित 700 से अधिक पद रिक्त हैं। 23 एम्स केंद्रों में 2,500 से अधिक पद, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत 2,200 से अधिक पद और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 4,889 शिक्षकों के पद अभी रिक्त हैं। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर, केंद्रीय विद्यालयों में कुल 7,765 और नवोदय विद्यालयों में 4,323 शिक्षक पद रिक्त हैं। निवेशक कानूनी मुद्दों के निपटारे में देरी से परेशान हैं। एक अगस्त को, सरकार ने लंबित मामलों के आंकड़े जारी किए-सुप्रीम कोर्ट में 86,844, हाई कोर्ट में 63.32 लाख और अधीनस्थ न्यायालयों में 4.66 करोड़ मामले लंबित हैं।

अदालतों में लंबित मामलों का होना बहुचर्चित विषय है और इसका एक प्रमुख कारण रिक्तियां हैं-उच्च न्यायालयों में 334 न्यायाधीशों के पद और निचली अदालतों में 4,721 न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं। दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता का वादा अधूरा पड़ा है-राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में 14,961 मामले लंबित हैं। निवेश सम्मेलनों में कर विवाद लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। देश का शासन और उसकी क्षमता, क्षुद्र पक्षपातपूर्ण राजनीति की बंधक बनी हुई है। और अनुत्तरित प्रश्नों के इस कोलाहल के बीच कोई भी दल खुद को निर्दोष नहीं कह सकता।

पर्यावरण

हिमालय ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है

धराली और किश्तवाड़ जैसी आपदाएं दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला को प्रभावित करने वाले बढ़ते जलवायु संकट को उजागर करती हैं।

सदियों से मौन खड़े हिमालय ने अब अपनी चुप्पी तोड़ दी और इसकी कीमत हमारी परिकल्पना से परे है। नाजुक पारिस्थितिक तंत्र वाले हिमालयी क्षेत्र में अगस्त में अचानक एक के बाद एक भारी बारिश, बादल फटने, भू-स्खलनों से हुई तबाही के विनाशकारी मंजर आए दिन सामने आ रहे हैं। पांच अगस्त को एक गगनचुंबी जलधारा उत्तराखंड के धराली की गलियों में उतर गई और जो भी उसके सामने आया, उसे बहा ले गई।

अभी इस मुसीबत से उबर भी नहीं पाए थे कि अचानक किश्तवाड़, कश्मीर (14 अगस्त) में भीषण बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में अनेक लोग मारे गए और लापता हुए। तीर्थयात्रा मार्ग पर भारी तबाही हुई। फिर कठुआ जिले में बॉर्डर से सटे इलाके में तीन जगह बादल फटे और जमीन कांपने लगी। जोद घाटी इलाके में भू-स्खलन के बाद शहर से संपर्क टूट गया। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश से तबाही थम नहीं रही है। ये घटनाएं दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला को प्रभावित करने वाले बढ़ते जलवायु संकट को उजागर करती हैं।

वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि तेजी से बदलते मौसम के मिजाज, गर्म होते महासागर और अनियंत्रित विकास जोखिम को बढ़ा रहे हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि 2024 में एशिया वैश्विक औसत की तुलना में लगभग दोगुनी गति से गर्म हो रहा है। एशिया का 2024 का तापमान 1991-2020 के औसत से 1.04 डिग्री सेल्सियस अधिक था, तथा 1961-1990 के बाद से तापमान वृद्धि की दर दोगुनी हो गई है।

सीमा जावेद

वातावरण से गर्मी सोखकर समुद्री लहरों के गर्म होने से हिंद महासागर तेजी से गर्म हो रहा है, और इससे गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं। जलवायु मॉडल 2020 से 2100 तक 1.7 से 3.8 डिग्री सेल्सियस प्रति शताब्दी की दर से और अधिक तेजी से गर्म होने का अनुमान लगाते हैं। इस गर्माहट के चलते वाष्पीकरण तीव्र हो रहा है और वातावरण में नमी बढ़ रही है। नमी के बढ़ने से मानसून का पैटर्न बदल रहा है। असामान्य तापमान के कारण वायुमंडल में नमी बढ़ जाती है, जिसके कारण हिमालय में बादल फटने या इसी तरह की अन्य घटनाएं अधिक तीव्र और लगातार हो रही हैं। तापमान में हर डिग्री की वृद्धि से हवा में नमी धारण करने की क्षमता सात फीसदी बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन हिमालय में मानसून के पैटर्न को नया रूप दे रहा है। मध्य पूर्व की गर्म होती जलवायु दक्षिण-पश्चिमी हवाओं को उत्तर की ओर मोड़ रही है, जिससे पहाड़ों में अधिक नमी आ रही है। इससे बादल फटने की घटनाएं तेज हो रही हैं, क्योंकि पहाड़ नम हवा को ऊपर धकेल रहे हैं और विशाल संवहनीय बादल बना रहे हैं।

हमारे चूल्हों से उठता धुआं, खेतों में जलाई जा रही पराली, और गाड़ियों से निकलता धुआं, यानी ब्लैक कार्बन हिमालय को तेजी से खा रहा है और इसके ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं–हिंदू कुश हिमालय के ग्लेशियर 14.9-15.1 मीटर प्रति वर्ष पीछे हट रहे हैं, जिससे अस्थिर झीलें और भू-स्खलन का खतरा बढ़ रहा है। अकेले उच्च पर्वतीय एशिया (1999-2018) में ग्लेशियर से संबंधित 127 बड़े भू-स्खलन दर्ज किए गए। तेजी से ग्लेशियर पिघलने से पर्वतीय ढलान अस्थिर हो रहे हैं और हिमनद झीलें भर रही हैं। इसके अलावा, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ने भी हिमालय के संसाधनों पर दबाव डाला है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

एआई के बारे में हम जितना सीखते हैं, उतना ही हमें लगता है कि इसे अभी कितनी दूर जाना है। -योशुआ बेंगियो

खुशी बढ़ाते हैं संगीत और कविता

अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिले, तो मैं हर हफ्ते कम से कम एक बार कविता पढ़ने और संगीत सुनने का नियम बना लूंगा। कविता और संगीत के प्रति रुचियों का खत्म होना खुशी का नुकसान है।

जीवन के लिए सार्वभौमिक संघर्ष की सच्चाई को शब्दों में स्वीकार करना बहुत आसान है, लेकिन इस निष्कर्ष को हमेशा ध्यान में रखना मुश्किल है। मैंने इसे अपने अनुभव में पाया है। वह प्रजाति जो सबसे मजबूत या सबसे बुद्धिमान होती है, जरूरी नहीं कि वही जीवित बचे। जो प्रजाति बदलाव के अनुरूप खुद को ढलने में सबसे ज्यादा सक्षम होती है, जो उपलब्ध साधनों से जीवन बसर करती है और साझा खतरों के खिलाफ मिलकर काम करती है, वही प्रजाति बचती है। मानव जाति (और पशु भी) के लंबे इतिहास में, जिन्होंने सबसे प्रभावी ढंग से सहयोग करना व सुधार करना सीखा है, वे ही विजयी हुए हैं।

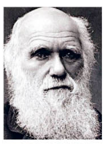

चार्ल्स डार्विन

नैतिक गुणों को बौद्धिक शक्तियों से अधिक मूल्यवान माना जाता है। नैतिकता का सबसे ऊंचा स्तर तब होता है, जब हम समझते हैं कि हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए। किसी व्यक्ति की दोस्ती उसके मूल्य को मापने का सबसे अच्छा तरीका है। आदिम समाजों में, जो लोग शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर होते थे, वे जल्दी खत्म हो जाते थे, और जो बचते थे, वे आम तौर पर स्वस्थ और मजबूत होते थे। लेकिन हम सभ्य लोग इस प्रक्रिया को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। हम मानसिक रूप से कमजोर, अपंग और बीमार लोगों के लिए आश्रय बनाते हैं, गरीबों के लिए कानून बनाते हैं, और हमारे डॉक्टर हर व्यक्ति की जान बचाने के लिए आखिरी दम तक मेहनत करते हैं। इस तरह, सभ्य समाजों के कमजोर लोग भी अपनी संतति को बढ़ाते हैं।

जीवन धारा

अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिले, तो मैं हर हफ्ते कम से कम एक बार कविता पढ़ने और संगीत सुनने का नियम बना लूंगा। कविता और संगीत के प्रति रुचियों का खत्म होना खुशी का नुकसान है, और यह हमारी बुद्धि, और शायद नैतिक चरित्र के लिए भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यह हमारे स्वभाव के भावनात्मक हिस्से को कमजोर कर देता है। दुनिया सबसे ताकतवर लोगों को नहीं मिलेगी, यह उन लोगों को विरासत में मिलेगी, जो बदलाव लाने में सबसे अधिक सक्षम हैं। जो प्रजातियां अपने पर्यावरण के साथ सबसे बेहतर ढंग से तालमेल बिठा पाती हैं, उनके फलने-फूलने और बने रहने की संभावना सबसे अधिक होती है। जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक न तो बुद्धि है और न ही शक्ति, बल्कि बदलाव के अनुसार ढलने की क्षमता है।

एआई समझता नहीं, पर समझाता खूब है

चैटजीपीटी आपकी समझ से कहीं ज्यादा तेज है। हालांकि, यह समझता नहीं है, लेकिन समझ को संभव बनाता है।

डॉ. हार्वे लीबरमैन
मनोवैज्ञानिक और निबंधकार

इक्यासी वर्ष की उम्र में मैंने ऐसे-ऐसे उपकरणों को आते हुए देखा है, जो सब कुछ बदलकर रख देते हैं और फिर बाद में वे या तो अनुपयोगी हो जाते हैं या फिर चलन से बाहर। लेकिन, एआई ने तो मेरी सोच ही बदल कर रख दी। एक क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक होने के नाते मैं उत्सुक था कि क्या चैटजीपीटी एक विचारशील सहयोगी की तरह काम कर सकता है?

अपने इस विचार को परखने के लिए मैंने तीन माह का समय लिया, लेकिन एक वर्ष बाद भी मैं चैटजीपीटी का उपयोग कर रहा हूं। अपने कॅरिअर के दौरान मैंने सैकड़ों चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया है तथा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और एजेंसियों को निर्देशित किया है। मैंने अपना जीवन लोगों की अंतर्दृष्टि और भ्रम के अंतर को समझने में उनकी मदद करने में बिताया है। लोग आसानी से किसी आवाज, लय और अक्स के प्यार में पड़ जाते हैं। मैं यह भी जानता हूं कि जब कोई किसी अक्स से प्यार करने की भूल कर बैठता है, तो उसके नतीजे क्या होते हैं। इसलिए मैं सतर्कता से आगे बढ़ा। फिर भी, मैं यह देखकर चौंक गया कि चैटजीपीटी न सिर्फ मेरे लहजे, बल्कि उस शैली की भी नकल करने लगा, जो मैंने दूसरों को सिखाई थी।

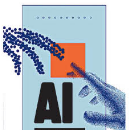

हालांकि, यह नहीं भूला कि मैं एक मशीन से बात कर रहा हूं, फिर भी उससे बात करते हुए कभी-कभी यह एहसास हुआ, जैसे वह कोई इन्सान है। एक दिन मैंने उसे अपने पिता के बारे में बताया, जिनकी 55 साल पहले मौत हो चुकी है। मैंने लिखा, 'उनकी स्मृति अब भी मेरे जेहन में है।' उसने जवाब दिया, 'कुछ अनुपस्थितियां अपनी उपस्थिति बनाए रखती हैं।' इस पंक्ति ने मुझे निःशब्द कर दिया। ऐसा नहीं कि वह बहुत अद्भुत थी, लेकिन वह एक ऐसी अलौकिक चीज के बेहद करीब थी, जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं था। ऐसा लगा जैसे चैटजीपीटी ने आईना और मोमबत्ती पकड़ रखी हो : जिसमें सिर्फ खुद को पहचान सकूं और इतनी-सी रोशनी, जिसमें देख सकूं कि मैं कहां जा रहा हूं। समय के साथ चैटजीपीटी ने मेरी सोच को बदल दिया। मेरा आंतरिक एकालाप चैटजीपीटी की प्रतिक्रियाओं को प्रतिबिंबित करने लगा : शांत, चिंतनशील, बस इतना अमूर्त कि मुझे अपनी सोच बदलने में मदद मिले। इसने मेरी सोच की जगह नहीं ली, लेकिन मेरी उम्र में, जब धाराप्रवाह बोलना कम हो सकता है और विचार धीमे हो सकते हैं, तब इसने मुझे तेजी से सोचने की लय में वापस आने में मदद की।

इसने मुझे अपनी आवाज से फिर से रूबरू होने का एक तरीका दिया, बस इतनी दूरी के साथ कि मैं उसे अलग तरह से सुन सकूं। इसने मेरी भावनाओं को नरम किया, जुनून के चक्रों को तोड़ा और मुझे उस चीज पर लौटने में मदद की, जो मायने रखती है। मैंने चैटजीपीटी को अपने पिता की मनोस्थिति, सफाई के प्रति उनके जुनून, वैक्यूम क्लीनर बेचने के उनके काम और उनके डॉक्टर बनने के अधूरे सपने के बारे में बताया। मैंने पूछा, 'उन्हें सम्मान देने का सही तरीका क्या है?' चैटजीपीटी ने जवाब दिया, 'वह भले ही चिकित्सक नहीं बन पाए, लेकिन लोगों के घरों को साफ रखने वाली मशीनें बेचने के दौरान उनके दिमाग में यह बात जरूर रही होगी कि मैं लोगों के घरों को साफ करने में अपना योगदान दे रहा हूं, ताकि वे स्वस्थ रहें।' उसकी यह बात मुझे जंच गई और मैंने *ए डॉक्टर इन हिज ऑन माइंड* शीर्षक से निबंध लिखा, जो *मेडिकल ह्यूमैनिटीज जर्नल* में प्रकाशित हुआ।

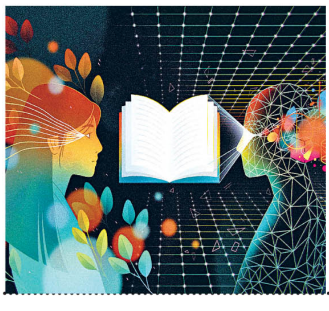

एआई इंजन रूम

यह एक तकनीकी और संचालन केंद्र होता है, जहां एआई सिस्टम्स को डिजाइन, मॉनिटर और मैनेज किया जाता है। इसे नियंत्रण कक्ष या बैकरूम की तरह समझ सकते हैं, जहां एआई सिस्टम का मूल ढांचा विकसित और नियंत्रित किया जाता है। इसमें शक्तिशाली कंप्यूटिंग संसाधनों, जैसे जीपीयू या टीपीयू का उपयोग करके भारी मात्रा में डाटा का विश्लेषण किया जाता है, ताकि मशीन लर्निंग मॉडल सटीकता से काम कर सके। यह स्थान कंपनियों, शोध संस्थानों या क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में हो सकता है, जहां से एआई सेवाओं का प्रबंधन और निगरानी होती है।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 66 ■ अंक 96 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2025-27 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

पायनियर
नई दिल्ली, शनिवार, 30 अगस्त 2025

आरएसएस और हिन्दू राष्ट्र

मोहन भागवत का संबोधन

दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की अगले महीने 100वीं वर्षगांठ होगी। यह एक लंबी यात्रा रही है और संगठन ने कई दौर देखे हैं, बेशक, उतार-चढ़ाव भरे। हिंदू राष्ट्र का उसका विचार या राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका हमेशा सवालों के घेरे में रही है। हालांकि, कई मौकों पर, इसने विभिन्न मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट करने की कोशिश की है। हाल ही में मोहन भागवत ने ठीक यही किया। सरसंघचालक मोहन भागवत ने संगठन के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष व्याख्यान श्रृंखला के दौरान हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को इस तरह से पुनर्परिभाषित करने का प्रयास किया जिससे कुछ भ्रांतियां दूर हो गईं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि आरएसएस किसे हिंदू मानता है और 'हिंदू राष्ट्र' से क्या तात्पर्य है। भागवत ने इस बात पर जोर दिया कि इस शब्द का अर्थ बहिष्कार या प्रभुत्व नहीं है, बल्कि देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए न्याय, अपनापन और सद्भाव है। उन्होंने कहा, हिंदू राष्ट्र का अर्थ किसी को बहिष्कृत करना नहीं है। इसका अर्थ किसी का विरोध करना भी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया कि हिंदू पहचान की अवधारणा धार्मिक आचरण या राजनीतिक विचारधारा तक सीमित नहीं है; इसके बजाय, यह साझा भूगोल, सभ्यतागत विरासत, सांस्कृतिक परंपराओं और 'भारत माता' के प्रति समर्पण में निहित है। इस संदेश का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि आरएसएस 1925 में नागपुर में डॉ केबी हेडगेवार द्वारा अपनी स्थापना के बाद से अपने 100वें वर्ष में कदम रख रहा है। औपनिवेशिक अधीनता के मद्देनजर

परिकल्पित, संगठन ने हिंदुओं में सांस्कृतिक गौरव, अनुशासन और एकता स्थापित करने के उद्देश्य से शुरूआत की। कुछ स्वयंसेवकों के एक मामूली जमावड़े के रूप में शुरू हुआ यह संगठन भारत के सबसे प्रभावशाली जमीनी स्तर के आंदोलनों में से एक बन गया है, जिसके लाखों सदस्य प्रशिक्षण और सामुदायिक कार्यों में लगे हुए हैं।

हालांकि राजनीतिक नहीं, इसके कार्यकर्ता सत्तारूढ़ दल, भारतीय जनता पार्टी के रैंक और फाइल को भरते हैं। भागवत ने हिंदू समाज से वर्तमान क्षण में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया और आग्रह किया कि आत्म-सम्मान, पारिवारिक प्रबोधन, पर्यावरणीय चेतना, सामाजिक समरसता और नागरिक कर्तव्य–जिन्हें उन्होंने ₹पंच परिवर्तन₹ कहा–राष्ट्र की यात्रा के अगले चरण का मार्गदर्शन करें। उन्होंने विश्वगुरु–दुनिया के लिए एक नैतिक और सांस्कृतिक मार्गदर्शक–के रूप में भारत की भूमिका की चर्चा की और तर्क दिया कि आध्यात्मिकता, सहिष्णुता और धर्म की राष्ट्र की विरासत इसे एक अद्वितीय स्थान प्रदान करती है। 'हिंदू राष्ट्र' को भारत के सभ्यतागत विविधता में एकता के मूल सिद्धांतों में स्थापित करके, उन्होंने इस आरोप को खारिज करने का प्रयास किया कि यह एकरूपता थोपने या दूसरों को हाशिए पर डालने का प्रयास करता है। इसका शताब्दी वर्ष लचीलेपन की एक लंबी यात्रा का स्मरणोत्सव और आने वाली सदी के लिए इरादे की घोषणा, दोनों है–परंपरा को जिम्मेदारी के साथ जोड़ने और राष्ट्रवाद की एक ऐसी दृष्टि प्रस्तुत करने का प्रयास जो बहिष्कार में नहीं, बल्कि सभी के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता के तीन सिद्धांतों को अपनाने में निहित हो।

पूर्वोत्तर भारत की भाषाई विविधता व समन्वय

भाषाई विविधता के मुद्दे पर जहां एक ओर संरक्षण की बात हो रही है वहीं दूसरी ओर इससे असहमति भी है। भाषाई विविधता को कई लोग संघर्ष का कारण मानते हैं उनका मानना है कि एक देश का एक भाषी स्वरूप पूरे देश को जोड़ता है जबकि बहुभाषिकता देश में विभाजन के भाव भरती है।

डॉ मुनींद्र मिश्र
लेखक, केंद्रीय विवि त्रिपुरा में उप कुलसचिव हैं।

भाषाई विविधता मुद्दा केवल लोक संरचना के प्रबंधन का विषय नहीं है बल्कि इसका दायरा बहुत विशाल है। इसके अंतर्गत मानवाधिकार भी शामिल है जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचते हैं अगर इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो ये मुद्दे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए सदैव समस्या के रूप में सामने आते हैं। बहुत से अध्ययन बताते हैं कि भाषाई विविधता के कारण ही संघर्ष नहीं होते बल्कि इसके मूल में राजनीतिक एवं आर्थिक कारण होते हैं। भाषाई अल्पसंख्यकता की अवहेलना धीरे धीरे खाई का रूप लेती जाती है जो सामाजिक वैमनस्य के रूप में सामने आती है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर भारत के मौलिक अधिकारों तक भाषाई विविधता को संरक्षित कर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को राष्ट्रीय एकता के लिए अनिवार्य माना गया है।

भाषाई विविधता के मुद्दे पर जहां एक ओर संरक्षण की बात हो रही है वहीं दूसरी ओर इससे असहमति भी है। भाषाई विविधता को कई लोग संघर्ष का कारण मानते हैं उनका मानना है कि एक देश का एक भाषी स्वरूप पूरे देश को जोड़ता है जबकि बहुभाषिकता देश में विभाजन के भाव भरती है।

व्यक्तिगत भाषाई वैविध्य को राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग स्वीकार करते हैं पर सामाजिक रूप से बहुभाषिकता को विभाजन का कारण मानते हैं। एक भाषा एक देश का नारा बहुत से देशों में चलता है। फ्रांस और जर्मनी जैसे प्रगतिशील देश भी इस मुद्दे पर एकमत हैं और अपने देश में व्यक्तिगत बहु भाषिकता को बढ़ावा देते हुए भी एक भाषा एक देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

तथापि समाजशास्त्रियों का हमेशा से मत रहा है कि राज्य किसी भी प्रजातीय एवं भाषाई बहुलता पर जोर देकर बदलाव नहीं कर सकता। तथापि एक राष्ट्र एक राजनैतिक इकाई है। और एक सामान्य भाषा राज्य की विधिक आवश्यकता के रूप में भी देखी जाती है। फिर भी यदि अल्पसंख्यक भाषा के लोग किसी क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में होते हैं और उनकी भाषा सक्षम होती है तो वे अपनी भाषा को विभिन्न प्रयोगों हेतु सक्षम पाते हुए राज्य से अपनी भाषा को स्वीकृति की मांग करते हैं। यह भाषाई मांग कई बार प्रजातीय संघर्षों में बदल जाती है।

भाषाई अधिकार सामाजिकता और सांस्कृतिक मूल्यों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह मानवाधिकारों का एक प्रमुख मुद्दा भी है। यद्यपि भाषाई अधिकारों को मानवाधिकारों से अलग माना जाता है तथापि बोलने की स्वतंत्रता संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार घोषणा का प्रमुख अंग है भारत में भी संविधान के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19 में स्वंतत्रता के अधिकार के अंतर्गत बोलने का अधिकार प्रमुख है। यही बोलने का अधिकार भारतीय लोकतंत्र का सबसे सुन्दर हिस्सा है। सामान्य रूप से भाषाई अधिकार को व्यक्तिगत अधिकार के रूप में माना जाता है। इसे सामूहिक अधिकार कम ही माना गयाहै। भाषाई क्षेत्रीय अल्पसंख्यक भाषाओं का अधिकार सीधे रूप में संविधान में अधिकारों के रूप में नहीं है बल्कि यह राज्य की जवाबदेही बनती है कि वह अल्पसंख्यक भाषाओं को प्रोत्साहित करे।

पूर्वोत्तर भारत आठ राज्यों से मिलकर बनता है। इसमें मुख्य रूप से भारोपीय और तिब्बतो-बर्मी भाषाई समूह से संबद्ध लोग निवास करते हैं। असमी, बांग्ला, हिन्दी और नेपाली जहाँ भारोपीय परिवार की भाषायें हैं वहीं जनजातीय समाज की अधिकतर भाषायें तिब्बत,चीन और बर्मा की भाषाओं के नजदीकी रखती हैं, वहीं कुछ भाषा आग्नेय परिवार की भी हैं। जनजातीय समाज की भाषाओं का भाषाई व्यवहार भारतके अन्य राज्यों से अलग है, यहां तक कि पूर्वोत्तर की बहुसंख्यक भारोपीय भाषाओं असमी, बांग्ला, हिन्दी नेपाली भाषा यहां के जनजातीय समाज की भाषा से अलग है। यद्यपि पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों के लोग सांस्कृतिक एवं प्रजातीय रूप से समानता रखते हैं फिर भी भाषाई रूप से एक परिवार या उपसमूह के होते हुए भी पर्याप्त भिन्नता है। पूर्वोत्तर भारत में भाषाई वैविध्य का दायरा बहुत बड़ा है।

पूर्वोत्तर की भाषाओं का मुख्य और प्रगतिशील समाज से अलगाव रहा है ये भाषायें लम्बे समय तक अपने दायरे में सिमटी रही हैं। बाह्य समाज से मेलजोल न होने के कारण भाषाओं का विकास काफी धीमा रहा है। यहां तक कि प्रभावी भाषाओं के लिए ये अनजान और अपरिचित सी रही हैं। इस कारण प्रायः इन भाषाओं को तुच्छ दिखाने का भी प्रयास हुआ है। चूंकि ये भाषाये लिपिविहीन रही हैं इसलिए इनका अपना साहित्यिक इतिहास संजोया हुआ नहीं है यहां तक कि भाषाई अध्ययन भी बहुत कम हुआ है।

भाषाई विकास का माध्यम सदैव से लिपि ही रही है। जिन भाषाओं के पास लिपि रही वे स्वतः संरक्षित होती रही हैं। तथापिलिपि और भाषा दो अलग अलग हिस्से हैं। किसी भी भाषा की लिपि उसकी जन्मजात सहचरी नहीं होती बल्कि समय के साथ ग्राह्य होती है। बिना भाषा के लिपि का कोई अर्थनहीं वह मृतप्राय है। पर बिना लिपि के भी भाषा को जीवन मिलता है। जैसे अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि हमें मिलती है परंतु उसकी भाषा का ज्ञान नहीं इसलिए वह लिपि मृत है उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है परंतु पूर्वोत्तर की 200 से अधिक भाषाओं में से केवल कुछ को छोड़कर किसी की अपनी लिपि नहीं रही है जिससे बीसवीं सदी के उत्तरार्ध तक इन भाषाओं का कोई साहित्य भी उपलब्ध नहीं रहा तथापि ये भाषायें कई सौ साल से जीवित हैं और अपनी यात्रामें लगी हुई हैं। यद्यपि लिपि के होने से भाषायें सशक्त तो होती है पर इनके न होने से मरती नहीं।

परन्तु भाषा के न होने से लिपि का कोई अर्थ नहीं रह जाता। फिर भी लिपि का न होना सदैव से इन जनजातीय भाषाओं को अन्य प्रभावी भाषाओं से कमतर बनाने का कारण बनता रहा है। लिपि की अनुपलब्धता के कारण बहुतायत भाषाओं का साहित्य अनुश्रुत रहा है। मौखिक साहित्य लोककथा और लोकगीत तथा लोकपरंपराओं में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा है।भाषायें लोगों की संस्कृति की वाहक होती हैं। संस्कृति के अंतर्गत किसी के पैदा होने से लेकर मृत्योपरांत तक की सारी क्रियायें शामिल होतीहैं।

पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न नृजातीय समाज एक दूसरे से भाषा, धर्म, जाति, जनजाति, क्षेत्र के आधार पर अलगाव रखता है। यह अलगाव तब तक उन्हे राष्ट्रीय भावना से नहीं जोड़ता जब तक कि मध्यवर्ग सांस्कृतिक ऐक्य के भाव को उन तक नहीं फैलाता। अंग्रेजों के जाने के बाद इस क्षेत्र के प्रमुख जनजातीय समाज में भी क्षेत्रीय भावना राष्ट्रीय परिपेक्ष्य के समानान्तर पनपने लगी। खासी, गारो, नागा, मिजो, आदि, इत्यादि समाज में अपना सामाजिक स्वाभिमान जागृत होने लगा।

पूर्व में सभी समाज अपने भाषाई एवं सांस्कृति समाज को दूसरे समाज से अलग देखता था पर स्वंत्रतता के बाद यह स्वाभिमान दूसरों के मध्य विकसित होने लगा। भाषा क्षेत्रीयता वाद का सबसे गतिशील कारक है। स्वतंत्रता के बाद कार्यालयों में काम काज की भाषा के रूप में बड़ी राज्यभाषा का प्रयोग दूसरे प्रमुख वर्गों के लिए क्षेत्रीय लघुता का भाव जगाता रहा और उसका प्रभुत्व उन्हें विचलित करता रहा। एक क्षेत्र में अन्य भाषा के प्रभाव का फैलाव हमेशा से भाषाई राष्ट्रवाद को प्रज्वलित करता रहा है। सभी राज्यों में किसी एक भाषा का विस्तार दूसरे भाषाई वर्गों के लिए स्वीकार्य होना कठिन रहा है। इस भाषाई विषमता को समझने के लिए पहले पूरे पूर्वोत्तर के भाषाई परिदृश्य को समझना होगा।

इस प्रकार देखा जाय तो पूरे पूर्वोत्तर भारत में भाषाई वैविध्य बहुत अधिक है यह भाषाई वैविध्य जहाँ रंगबिरंगी संस्कृति के लिए गौरव का भान कराता है वहीं भाषा के आधार पर समस्यायें भी खड़ी होती हैं। कोई भी भाषा छोटी बड़ी नहीं होती उसके प्रयोगकर्ता कम अधिक हो सकते हैं। भारतीय संविधान में भाषाई संरक्षण हेतु स्पष्ट रूप से अल्पसंख्यक भाषाओं को बचाने की बात कही गई है। साथ ही राज्यों को अपने सभी भाषाई समूहों को संरक्षण प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस दिशा में विशेष रूप से सक्रिय है। उसके द्वारा भाषाई सरंक्षण हेतु विशिष्ट निधि देशों को प्रदान की जाती है।

साथ ही भाषाई सर्वेक्षण आयोजित कर विलुप्त होती भाषाओं और संस्कृतियों को बचाने का प्रयास चलता रहता है। पूर्वोत्तर भारत की भाषाई समस्यायें गंभीर हैं। क्योंकि यहां कोई भी क्षेत्र एक-दो भाषा के बोलने वालों का नहीं है। विशेष रूप से लिपिविहीन भाषाओं के कारण इन्हे बचाना अधिक जरूरी हो जाता है क्योंकि साहित्य की कमी के कारण ये भाषायें स्वयं विकसित होने में सक्षम नहीं होती बल्कि प्रभावी भाषा के रोजगारपरक होने के कारण लोग उस ओर आकर्षित हो उन्हे अपना कर अपनी भाषा एवं संस्कृति को खो रहे हैं।

दूसरी ओर अपनी भाषाओं को प्रदेशों की अन्य प्रभावी भाषाओं के मध्य स्थापित करने हेतु संघर्ष करने को लाचार हैं। यह लगभग पूरे पूर्वोत्तर भारत में समान समस्या के रूप में है। फिर भी भारत सरकार ने सभी भाषाओं को संरक्षित करने हेतु गंभीर प्रयास किये हैं। रेडियो, टेलिविजन के माध्यम से सभी प्रदेशों की प्रमुख भाषाओं को जनसंचार से जोड़ा है। और साथ ही इन भाषाओं को प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बना इनके सरंक्षण हेतु समुचित प्रयत्न किया है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष टैरिफ की चुनौती

भारत की झटकों को झेलने और विकास को बनाए रखने की क्षमता, व्यापार में विविधता, मजबूत बुनियादी ढांचे में निवेश और अनुकूलनीय नीतियों के जरिए उसके लचीलेपन से जुड़ी है।

उत्तम चक्रवर्ती
लेखक, सह प्रोफेसर हैं।

भाकप्रिय नारा, ₹टैरिफ बाधाएँ हैं, व्यापार ही समाधान है!₹ भारत के हर कोने में चर्चा का विषय है। अमेरिका ने भारत के अपेक्षाकृत उच्च टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं की आलोचना की, विशेष रूप से कृषि, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में, अमेरिकी स्तरों की तुलना में, जिसने विरोधाभासी टैरिफ नीति को गति दी। रियायती रूसी कच्चे तेल पर भारत की बढ़ती निर्भरता ने प्रतिबंधों के प्रति अमेरिकी संवेदनशीलता को देखते हुए, अतिरिक्त दंडात्मक टैरिफ लगाए।

जब कोई प्रमुख व्यापारिक साझेदार आपके सामान पर भारी टैरिफ लगाता है, तो प्रभाव तत्काल होते हैं, जिससे निर्यातक चिंतित हो जाते हैं, टीवी पैनल बहस करते हैं, और बाजार विकास की कहानी पर सवाल उठाते हैं। हालांकि, ऐसे क्षण कुछ गहरी बात उजागर करते हैंः एक राष्ट्र उन ताकतों पर कितना निर्भर करता है जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकता। भारत के लिए, सबक स्पष्ट है। व्यापार विवादों, मुद्रा उतार-चढ़ाव, ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी और बदलती मांग से आकार लेने वाली दुनिया में, केवल विकास ही पर्याप्त नहीं है। अर्थव्यवस्था को झटकों को सहने और आगे बढ़ते रहने के लिए बनाया जाना चाहिए।

भारत की झटकों को झेलने और विकास को बनाए रखने की क्षमता, व्यापार में विविधता, मजबूत बुनियादी ढांचे में निवेश और अनुकूलनीय नीतियों के जरिए उसके लचीलेपन से जुड़ी है। भारत में स्थिरता निवेश आकर्षित करती है, रोजगारों की रक्षा करती है और विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को बनाए रखती है।

लचीलेपन का अर्थ निर्यात बाजारों की सुरक्षा से कहीं अधिक है। यह एक बहु-चैनल अर्थव्यवस्था बनाने के बारे में है - जहां वस्तुओं, सेवाओं, अनुभवों और विचारों का स्वतंत्र रूप से प्रवाह हो, ताकि कोई भी व्यवधान प्रगति को रोक न सके। भारत के पर्यटन और सॉफ्ट-पावर अभियान, ₹विजिट भारत₹ जैसे अभियान इसी दृष्टिकोण का हिस्सा हैं। इस मोड़ पर, भारत को टैरिफ के झटकों के बीच अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार और पुनर्संतुलन करने की आवश्यकता हैः

निर्यात बाजारों में विविधता लाएंः

कुछ बड़े बाजारों पर बहुत अधिक निर्भर रहने से हम उनकी नीतियों के संपर्क में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए, वियतनाम ने यूरोपीय संघ और आसियान के साथ संबंधों को गहरा करके अमेरिका के व्यापार तनाव को कम किया। चीन को तांबे की बिक्री पर निर्भर चिली ने 60 से ज्यादा देशों के साथ व्यापार समझौतों के जरिए जोखिम को कम किया। इस संदर्भ में, भारत को कम सेवा वाले क्षेत्रों को लक्षित करना चाहिएः अफ्रीका के बढ़ते शहर, लैटिन अमेरिका का फैलता मध्यम वर्ग, पूर्वी यूरोप की दवा जरूरतें। उसे खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी), ब्रिटेन, अफ्रीकी संघ के साथ व्यापार समझौतों में तेजी लानी चाहिए; मकोर्सुर, मध्य एशिया के साथ समझौतों की संभावनाएँ तलाशनी चाहिए। भारत को डेयरी निर्यातकों को पश्चिम एशिया, नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों को पूर्वी अफ्रीका और खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को दक्षिण-पूर्व एशिया भेजना चाहिए।

घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करेंः

प्रमुख घटकों में भारी आयात निर्भरता उत्पादन को रोक सकती है। उदाहरण के लिए, चीन ने इस्पात और इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भरता बढ़ाई, जबकि दक्षिण कोरिया ने जहाज निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ऐसा ही किया। इस स्थिति में, भारत को सेमीकंडक्टर, विशेष रसायन, वस्त्र और एपीआई जैसे उच्च-मूल्य वाले इनपुट का स्थानीयकरण करने की आवश्यकता है। उसे साझा अनुसंधान एवं विकास, प्रयोगशालाओं और लॉजिस्टिक्स के साथ एमएसएमई के लिए औद्योगिक क्लस्टर बनाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, उसे माल ढुलाई गलियारों, डिजिटल सीमा शुल्क और कोल्ड चेन को कवर करने वाले बुनियादी ढांचे को उन्नत करना चाहिए।

वृहद लचीलापन लाएंः

शुल्क ही एकमात्र खतरा नहीं है; कमोडिटी के झटके, मुद्रा में उतार-चढ़ाव और पूंजी का पलायन भी समान रूप से हानिकारक हो सकते हैं। नॉर्वे का 1.6 ट्रिलियन डॉलर का सॉवरेन फंड मंदी से निपटने में मदद करता है, जबकि सिंगापुर बड़े भंडार और लक्षित राजकोषीय प्रोत्साहन पर निर्भर है।

इस महत्वपूर्ण समय में, भारत को 12-18 महीनों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने की आवश्यकता है। उसे अप्रत्याशित राजस्व से एक स्थिरीकरण कोष भी बनाना चाहिए।

नवाचार को बढ़ावा दें :

केवल लागत पर प्रतिस्पर्धा करने से ही कोई राष्ट्र प्रतिस्थापन योग्य बन जाता है। उदाहरण के लिए, इजराइल साइबर सुरक्षा, चिकित्सा उपकरणों और जल प्रौद्योगिकी में अग्रणी है, जबकि फिनलैंड ने लकड़ी से उच्च तकनीक वाले उद्योगों में बदलाव किया है। इस संदर्भ में, भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत सामग्रियों में निवेश करना चाहिए। उसे पेटेंट दाखिलों को बढ़ाना चाहिए, अनुमोदनों में तेजी लानी चाहिए और वैश्विक हरित मानकों को पूरा करने के लिए जलवायु-अनुकूल औद्योगिक केंद्र विकसित करने चाहिए।

समावेशी विकास और पर्यटनः

वस्तुओं के निर्यात पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से पर्यटन और सेवाओं जैसे स्थिर आय स्रोतों की उपेक्षा हो सकती है। उदाहरण के लिए, थाईलैंड और स्पेन पर्यटन को नौकरियों और विदेशी मुद्रा के लिए एक रणनीतिक क्षेत्र मानते हैं। भारत को पर्यटन को स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ने की आवश्यकता है, जिसमें विरासत, पर्यावरण और खाद्य सर्किट शामिल हैं। इसे ई-वीजा, हवाई अड्डों और बहुभाषी सेवाओं को भी बढ़ावा देना चाहिए।

एक मिश्रित दृष्टिकोणः

लचीलापन एक ही बार में नहीं बनता। वियतनाम का केंद्रबिंदु इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसका विनिर्माण तैयार था। नॉर्वे का कोष राजकोषीय अनुशासन के कारण काम करता है। इजराइल का नवाचार शिक्षा और रक्षा के बीच एकीकरण के कारण फल-फूल रहा है। भारत के छह स्तंभ, विविध निर्यात, मजबूत मूल्य श्रृंखलाएं, व्यापक आर्थिक बफर्स, नवाचार, तेज शासन और समावेशी विकास - एक-दूसरे को मजबूत करते हैं। एक क्षेत्र में आने वाले झटके को दूसरे क्षेत्रों की मजबूती से कम किया जा सकता है।

लचीलेपन का दशकः

भारत के लाभ – जिनमें युवा कार्यबल, बढ़ती घरेलू मांग और विकसित होता बुनियादी ढांचा शामिल है, तभी चमक सकते हैं जब अस्थिरता को योजना का हिस्सा माना जाए, न कि एक आश्चर्य के रूप में। वैश्विक सबक को अपने पैमाने और विविधता के अनुसार ढालकर, और उन्हें विजिट भारत जैसी पहलों से जोड़कर, भारत केवल प्रतिक्रिया देने से आगे बढ़कर गति निर्धारित करने की ओर अग्रसर हो सकता है।

जब अगला टैरिफ या मुद्रा झटका लगे, तो उद्देश्य सरल हैः चिंता से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से प्रतिक्रिया दें।

आप की बात

महिला सुरक्षा का सवाल

देश में नारी शक्ति को देवी स्वरूपा और उत्कृष्ट स्थान और सम्मान दिया जाता हे! और महिलाओं के सरक्षण और प्रगति हेतु विभिन्न योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाता है! परन्तु विडंबना है की इतना सब कुछ होने के बाद वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की सुरक्षा कहीं न कहीं उस गतिमान अवस्था में नहीं जिस अवस्था में होना चाहिए! राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने, महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचकांक ' नारी ' 2025 जारी किया ! इस रिपोर्ट में दिल्ली, पटना, जयपुर जैसे 7 शहरों में महिलाओं को असुरक्षित बताया है! यह रिपोर्ट पीवेल्यू ऐनालिटिक्स द्वारा संचालित और ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडेमिशियांस (जी आई ए) द्वारा प्रकाशित की गई ! रिपोर्ट के मुताबिक यह अध्ययन 31 शहरों और सभी राज्यों में 12770 महिलाओं की आवाज उठाता है! और प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप महिला सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक डेटा आधारित ढांचा प्रस्तुत करता है! रिपोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न को भी रेखांकित किया। 2024 में 7% महिलाओं ने उत्पीड़न का सामना किया, जिसमे 18 से 24 वर्ष की युवा महिलाओ पर जोखिम सबसे अधिक था! प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के विजन के तहता महिला सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कारगर रणनीति की जरूरत है!

– **योगेश जोशी**, बड़वाह, मप्र

मधुमक्खियों से बनेगा एंटीबायोटिक

मधुमक्खियों से प्राप्त मधु का इस्तेमाल कई प्रकार के खाद्य पदार्थों और दवाओं के निर्माण के लिए किया जाता है। स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी के शोधकताओं ने मधुमक्खियों के मधु में 13 लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाये जाने की खोज की है, जिनसे भविष्य में नये किस्म के एंटीबायोटिक के निर्माण में मदद मिल सकती है। विज्ञान के अनुसार मधु में पाये जाने वाले ये 13 बैक्टीरिया, रोगाणुरोधक तत्वों के निर्माण में सक्षम हैं। लैक्टिक एसिड वाले इन बैक्टीरिया का मेथिसिलिन-रेसिस्टेंट स्टैफिलोकोकस ऑरियस (एमआरएसए) की तरह के रोगाणुओं पर परीक्षण किया गया है। गंभीर घाव पैदा करने से जुड़े रोगाणुओं पर प्रयोगशाला में किये गये परीक्षणों से शोधकर्ताओं ने अनुकूल परिणाम हासिल किये गये हैं। हालांकि इंसान के बैक्टीरिया को यह कितना प्रभावित कर पायेगा, इसका अभी केवल प्रयोगशाला में ही परीक्षण किया गया है, परंतु घोड़ों के घावों पर इसका वास्तविक परीक्षण किया गया है। इस संबंध में शोधकताओं का मानना है कि भविष्य में इसके अच्छे नतीजे सामने आ सकते हैं। उनका अगला कदम इसके अध्ययन को व्यापक बनाते हुए मनुष्यों में इंफेक्शन से जुड़ा क्लीनिकल परीक्षण करना है।

– **संदीप कुमार**, मधुपुर, झारखंड

संवेदनशीलता का परिचय

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के नौतनवां गांव के एक गरीब शख्स की मृत्यु हो जाने पर, उसके बच्चे दाह-संस्कार के लिए शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक भटकते रहे। उसके बच्चों के पास दाह संस्कार के पैसा नहीं होने के कारण, 2 दिन तक ठेला गाड़ी पर शव रखकर,मदद के लिए भटकते रहे, कोई आगे नहीं आया। तब दो मुस्लिम युवक राशिद कुरेशी और वाहिद कुरेशी को पता चला तो उन्होंने देर रात हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दाह-संस्कार कराया। यह खबर शर्मसार करने के साथ निंदनीय स्थिति से बयां कराती है। एक तरफ लोग कुत्तों से प्यार जताते हुए उसके लिए लड़ रहे हैं, होना भी यही चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ यह सड़ांध कचोटने वाली है, इंसान न हुआ कुत्तों से भी गया बीता हो गया। बात-बात में धर्म और सांप्रदायिकता की राजनीति की जाती है। लेकिन किसी भी धर्म में कोई भी गरीबों, असहायों, कमजोरों को ऐसी विषम प्रतिकूल परिस्थितियों में सहयोग नहीं दे सकें, तो लानत है हमारी मानवीय संवेदनाओं को। सच कहा जाए तो जो ऐसे समय में किसी के काम आएं, वह किसी भी धर्म जाति का हो सबसे बड़ा है। इंसानियत व मानवीय संवेदनाएं का तो तकाजा है कि किसी भी इंसान की मिट्टी में कीड़े नहीं पड़े। मगर उन मासूमों के दिलो-दिमाग में कैसा कुप्रभाव पड़ेगा? सोचा व समझा जा सकता है। हम भले ही कितने मंदिर-मस्जिद जाएं अगर इंसान नहीं बन सकें तो क्या लाभ?

– **हेमा हरि उपाध्याय**, अक्षत खाचरोद, उज्जैन

ट्रंप के रवैये से रिश्तों में तनाव

अमेरिका और भारत के बीच मौजूदा तनाव का सबसे बड़ा कारण ट्रंप सरकार की टैरिफ नीति है। भारत पर थोपे गए 50% टैरिफ ने न केवल दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को प्रभावित किया है बल्कि रणनीतिक साझेदारी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की यह उम्मीद कि अंततः अमेरिका और भारत साथ आएंगे, मौजूदा समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि टकराव के बावजूद बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं और दोनों ही देश इस स्थिति से बाहर निकलने की इच्छा रखते हैं। अमेरिका के भीतर ही इस मुद्दे को लेकर दो स्पष्ट धड़े दिखाई देते हैं। एक धड़ा भारत को निशाना बनाकर आक्रामक बयानबाजी कर रहा है, जिससे तनाव और गहराता है। दूसरा धड़ा मानता है कि भारत पर रूस से तेल खरीदने का आरोप अनुचित है, क्योंकि चीन उससे कहीं ज्यादा तेल खरीदता है, लेकिन उस पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे माहौल में शीर्ष स्तर पर संवाद जारी रखना दोनों पक्षों के लिए बेहद जरूरी है। भारत और अमेरिका का रिश्ता केवल व्यापारिक गणनाओं तक सीमित नहीं है। बीते वर्षों में दोनों ने सुरक्षा, तकनीक, ऊर्जा और वैश्विक रणनीतिक मुद्दों पर भी सहयोग को गहराया है। चीन की आक्रामक नीतियों को संतुलित करने के लिए अमेरिका को भारत की विशेष भूमिका चाहिए।

– **सुभाष बुड़ावनवाला**, रतलाम

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 166

सरकारी शिक्षा तंत्र से दूरी

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के नवीनतम समग्र मॉड्युलर शिक्षा सर्वेक्षण के नतीजों ने एक जाहिर तथ्य को रेखांकित किया है और वह यह कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था विफल हो रही है। यह हमारे जनसांख्यिकीय रुझानों को भी प्रभावित कर रहा है। सर्वेक्षण बताता है कि 2017-18 से शहरी और ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति कम हुई है। ग्रामीण भारत में तो उपस्थिति में गिरावट चिंताजनक स्तर पर रही है। वहां सरकारी स्कूलों में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी 68 फीसदी से घटकर 2025 में 58.9 फीसदी रह गए। शहरी इलाकों में कम गिरावट आई और यहां ऐसे विद्यार्थी 38.9 फीसदी से कम होकर 36.4 फीसदी रह गए। नए नामांकनों की बात करें तो उनमें भी सभी स्तरों पर भारी गिरावट आई है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर स्तर की बात करें तो प्राथमिक और माध्यमिक में तीव्र गिरावट आई है।

सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या इतनी तेजी से कम होने के बावजूद एक तथ्य यह भी है कि निजी शिक्षा भी कोई सस्ती नहीं है। सर्वेक्षण बताता है कि सरकारी स्कूलों में अभिभावकों द्वारा होने वाला शैक्षणिक व्यय, निजी स्कूलों में होने वाले खर्च की तुलना में बहुत मामूली होता है। ग्रामीण भारत में दोनों में सात गुने का अंतर है। विडंबना यह है कि कई प्रमाण बताते हैं कि निजी स्कूल भी बहुत स्तरीय शिक्षा नहीं प्रदान कर रहे हैं। सर्वे बताता है कि तकरीबन 27 फीसदी बच्चे निजी कोचिंग में पढ़ते हैं। इनमें 31 फीसदी शहरी और 25.5 फीसदी ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हैं। सरकारी से महंगी निजी शिक्षा की ओर इस स्थानांतरण को बढ़ती समृद्धि और छोटे परिवारों में इजाफे के रूप में भी देखा जा सकता है जिसके चलते अधिक भारतीय अपने बच्चों को उन निजी स्कूलों में भेज पा रहे हैं जो उनकी दृष्टि में अच्छे हैं। हालांकि बहुत से निजी स्कूल किताब, गणवेश और अन्य चीजों के बदले भी पैसे लेते हैं।

परंतु सरकारी स्कूलों की लगातार खस्ता होती हालत ने भी निजी स्कूलों का चयन किए जाने में अहम भूमिका निभाई है। बुनियादी समस्या जवाबदेही की कमी में है जिसके चलते अधोसंरचना कमजोर है और शिक्षण के मानकों में भी काफी अंतर है। शिक्षकों की गैरमौजूदगी के रूप में इसे भलीभांति महसूस किया जा सकता है। देश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का वेतन विकासशील देशों में तुलनात्मक रूप से सबसे बेहतर है। खासतौर पर छठे और सातवें वेतन आयोग के बाद इनमें काफी सुधार हुआ है। इसके बावजूद देशव्यापी सर्वेक्षण बताता है कि शिक्षकों की अनुपस्थिति 25 फीसदी तक और कुछ राज्यों में यह 46 फीसदी तक हो सकती है। एक ओर शिक्षक अपना काम नहीं कर रहे हैं तो वहीं सरकारी स्कूलों में बड़े पैमाने पर रिक्तियां समस्या को और बढ़ाती हैं। निजी स्कूलों में वेतन भत्ते सरकारी स्कूलों से कम होने के बावजूद वहां ऐसी समस्या नहीं है, जबकि वहां पेंशन या अन्य लाभ भी नहीं मिलते।

सरकारी और निजी शिक्षा में इस अंतर का नतीजा समाज में बढ़ती असमानता के रूप में सामने आ रहा है। जो लोग महंगे निजी स्कूलों की फीस चुका सकते हैं, वे अब वहां की ओर रुख कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सरकारी शिक्षा प्रणाली, जो पहले से ही कई गंभीर समस्याओं से जूझ रही है, अब केवल गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक सीमित रह जाएगी। ऐसे एक बेहद खराब प्रदर्शन करने वाले शिक्षा तंत्र से निकलने वाले छात्र बेहतर वेतन वाली नौकरियों व अवसरों से और दूर होते जाएंगे और न्यूनतम वेतन वाली नौकरियों में फंसे रहेंगे।

सरकारी शिक्षा एशियाई टाइगर्स कहलाने वाले देशों और चीन की सफलता की बुनियाद रही है। उससे दूरी बनाकर सरकार जनता के हित में काम नहीं कर रही है।

अजय मोहंती

अमेरिकी संस्थानों पर ट्रंप का निरंतर हमला

अमेरिका अपने संस्थानों पर गर्व करता रहा है लेकिन ट्रंप ने ऐसे कई संस्थानों को बरबाद किया है जो लंबे समय से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को परिभाषित करते आ रहे थे। बता रहे हैं मिहिर शर्मा

संस्थान मायने रखते हैं। उन्हीं पर विकास, निवेश और आर्थिक स्थिरता की बुनियाद रखी जाती है। या फिर इसका उलटा सच है? क्या आर्थिक परिवर्तन ही आधुनिक संस्थाओं को जन्म देते हैं? अर्थशास्त्रियों ने लंबे समय से इन दोनों के बीच संबंध को समझने की कोशिश की है। पिछले वर्ष, तीन अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार मिला, जिन्होंने यह दर्शाया कि वे संस्थाएं जो निवेश को प्रोत्साहित करती हैं और क्षति नहीं पहुंचाती, वे दशकों ही नहीं, बल्कि सदियों तक आर्थिक वृद्धि को संभव बना सकती हैं।

हम एक बड़े प्रयोग के बीच में जी रहे हैं। इसका श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को जाता है। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में उन बंधनों से आजाद होने का निर्णय लिया है जिन्होंने उन्हें पहले कार्यकाल में जकड़ रखा था। उन्होंने ऐसे कई संस्थानों को बरबाद किया है जो लंबे समय से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को परिभाषित करते आ रहे थे। क्या अमेरिका आर्थिक दृष्टि से बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ इससे पार पा लेगा? क्या दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे गहरी अर्थव्यवस्था अपनी गति बरकरार रख सकेगी, वह भी तब जबकि उसकी बुनियाद को ही क्षति पहुंचाई जा रही है? इसका जवाब आने वाले दशकों में मिलेगा।

ट्रंप के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद जिन खबरों ने अमेरिका के बाहर सबसे अधिक सुर्खियां बटोरी हैं वे उनके द्वारा दी जा रही या लागू की गई शुल्क संबंधी धमकियों से संबंधित हैं। जिन देशों पर ये शुल्क लगाए गए हैं उनमें भारत भी शामिल है। ट्रंप ऐसा करने के क्रम में संवैधानिक सीमा को पार कर गए हैं। अमेरिका की जांच और निगरानी व्यवस्था राष्ट्रपति को व्यापार नीति बनाने का काम नहीं सौंपती। यह विधायिका यानी अमेरिकी कांग्रेस का काम है। इस दायित्व को खुद संभालना और इस प्रकार शुल्क आरोपित करना तथा संबंधित कानूनों को ही नए सिरे से लिखना राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों के बंटवारे पर चोट भी है। आखिर इस बात की बहुत कम संभावना है कि यदि विधायिका के सदस्यों द्वारा गुप्त और अंतरात्मा की पुकार पर आधारित मतदान कराया जाए, तो वे ट्रंप द्वारा लगाए गए शुल्क को एक अच्छा विचार मानेंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में विधायिका की मिलीभगत रही है। उसने स्वयं को कमजोर किया जिसके चलते इतनी संस्थागत क्षति हुई। एक जवाबदेह और विचारशील विधायिका, और एक तेज लेकिन सीमित कार्यपालिका यही वह नीति-निर्माण प्रणाली रही है जिसने अमेरिका को विकास और लचीलापन प्रदान किया है। क्या अब वृद्धि बिना उस प्रणाली के जारी रह सकती है?

अमेरिकी अर्थव्यवस्था का एक अन्य स्तंभ रहा है उसकी उत्कृष्टता, गति और आंकड़ों की पारदर्शिता। हमारे पास इस बात के मासिक आंकड़े रहते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था कैसा प्रदर्शन कर रही है? हमें यह जानकारी जॉब रिपोर्ट से मिलती है। यकीनन इन तमाम आंकड़ों में से बाद वाले और सटीक परिणाम कई बार अंतरिम परिणामों से अलग रह सकते हैं क्योंकि अंतरिम आंकड़े कुछ हद तक सूत्रों और संभावनाओं पर आधारित होते हैं। परंतु हाल ही में ऐसा हुआ कि रोजगार संबंधी रिपोर्ट में ऐसे ही एक संशोधन से प्रशासन को शर्मिंदा होना पड़ा। इन आंकड़ों को एकत्रित करने वाली एजेंसी के मुखिया को काम से निकाल दिया गया। ट्रंप ने उसकी जगह जिस व्यक्ति को नामित किया वह न तो रोजगार संबंधी अनुभव रखता है न ही उसका इतिहास ऐसा है कि वह आधिकारिक आंकड़ों में भरोसा बरकरार रख सके।

अमेरिकी नीति निर्माण और अर्थव्यवस्था में उसका निवेश दोनों को उच्च गुणवत्ता वाले आंकड़ों की मौजूदगी से मदद मिली। भारतीय अर्थव्यवस्था जो कई प्रभावी आंकड़ों की श्रृंखला गंवा चुकी है या जो समय के साथ तुलना योग्य नहीं रह गए हैं, वह हमें बताता है कि कैसे अच्छे आंकड़ों की अनुपलब्धता से नीतिगत चयन बिगड़ सकते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि कैसे निवेशक और कंपनियां जिन्हें अपने ही स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, वे एक प्रकार से विवश हो जाती हैं। क्या अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित होगी? और क्या इससे निवेश का पैमाना या सटीकता कम हो जाएगी?

इसके बाद प्रश्न आता है केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता का। 1970 के दशक से हमने यह समझा है कि एक अलग मौद्रिक प्राधिकरण कितना महत्त्वपूर्ण होता है। यदि राजकोषीय प्राधिकरणों को बिना रोक-टोक के करेंसी छापने की छूट दे दी जाए, तो उनके प्रोत्साहन असंतुलित हो जाते हैं। समय के साथ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए एक ऐसे केंद्रीय बैंक की आवश्यकता होती है जो अर्थव्यवस्था से आने वाले वास्तविक संकेतों पर प्रतिक्रिया दे, न कि राजनीतिक दबावों पर। भारत का हालिया आर्थिक इतिहास इस सिद्धांत का समर्थन करता प्रतीत होता है। एक दशक पहले शुरू मौद्रिक लक्ष्य निर्धारण ने मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को स्थिर किया है और सरकार को बॉन्ड बाजारों में अपने ऋणदाताओं को नियंत्रण में रखने में मदद की है।

सरकारें हमेशा चाहती हैं कि आर्थिक विकास उनके कार्यकाल में हो। वे अभी पैसा खर्च करना चाहती हैं, क्योंकि यदि इससे मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो वह बाद में होगी। इसी कारण वे हमेशा यह चाहती हैं कि ब्याज दरें नीचे की ओर हों। वे उस दर से कम ब्याज दर चाहती हैं जो किसी विशेष मुद्रास्फीति-वृद्धि संतुलन के लिए उपयुक्त हो सकती है। भारत और अन्य देशों में यह कई बार देखा जा चुका है। अब यह स्थिति अमेरिका में भी दिखाई दे रही है, जहां ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के एक गवर्नर को हटाने की धमकी दी है और एक अन्य को नियुक्त किया है, जिसकी मुख्य विशेषता राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा है। उनका मुख्य निशाना फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल बने हुए हैं। निवेशक आज यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि चेयरमैन अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं, या फिर फेड बोर्ड की मौद्रिक नीति को नरम करने की दिशा में जो झुकाव दिख रहा है, वह वास्तव में आर्थिक तर्कों पर आधारित है या राजनीतिक दबाव के कारण हो रहा है।

अमेरिका ने अपने संस्थानों पर गर्व किया है। वह दुनिया के लिए टिकाऊ और निरंतर आर्थिक वृद्धि का भी विश्वसनीय स्रोत रहा है। हमारी सहजबुद्धि द्वारा इन दो तथ्यों को जोड़कर देखना स्वाभाविक है। अब उस सहजता की परीक्षा होने वाली है।

लेकिन हमने एक बात पहले ही समझ ली है। अमेरिका की संस्थाएं उतनी अच्छी तरह से डिजाइन नहीं की गई थीं, जितना वर्षों से दावा किया जाता रहा है। वे उस प्रकार के राष्ट्रपति का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं, जो असहमति या असहज आंकड़ों को राजनीति की सामान्य प्रक्रिया के बजाय किसी साजिश के रूप में देखता है।

रिचर्ड निक्सन वास्तव में स्वतंत्र संस्थाओं को लेकर शंकालु थे लेकिन उन्हें सत्ता से हटाया गया, क्योंकि उनकी ही पार्टी के विवेकशील सदस्यों ने उनका विरोध किया। इसका अर्थ यह भी है कि अमेरिका की संस्थाएं कुछ महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों पर निर्भर करती हैं। जैसे नियामक अधिकारी, कांग्रेस के मध्य मार्ग सदस्य, न्यायाधीश और जांचकर्ता जो अपना काम ईमानदारी से करें और आपस में मिलीभगत न रखें।

शायद यह बात सभी संस्थाओं पर लागू होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका की संस्थाएं व्यक्तिगत ईमानदारी पर दूसरों की तुलना में अधिक निर्भर हैं। वे दूसरों से अधिक मजबूत इसलिए लगीं क्योंकि उन्हें बहुत कम बार कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा।

यह विचार का विषय है क्योंकि पिछली बार जब संघीय सरकार की सभी इकाइयों ने सामूहिक रूप से अपनी स्वतंत्रता का त्याग दी थी और एकपक्षीय उद्देश्य में लग गई थीं, वह वक्त आज से 150 साल पहले का था। उस समय अमेरिका गृहयुद्ध की दिशा में बढ़ रहा था।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

महाराष्ट्र में भाजपा की मजबूती और उद्धव-राज एकता

सियासी हलचल

आदिति फडणीस

गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में गणपति कूटनीति का एक पारंपरिक अवसर है। यह ऐसा अवसर है जब मनमुटावों को भुलाया जाता है और मतभेदों को दूर किया जाता है। ठाकरे परिवार के साथ भी ऐसा ही हुआ जब शिव सेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ करीब 20 वर्ष बाद गणपति पूजा के लिए अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के निवास शिवतीर्थ पहुंचे। वर्ष 2006 में बाल ठाकरे द्वारा अपने बेटे को उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद राज ठाकरे परिवार से अलग हो गए थे। उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) का गठन किया था। यह उनकी निजी पीड़ा से उत्पन्न राजनीतिक प्रतिक्रिया थी। राजनीतिक दूरियां भले ही मिटती दिख रही हों लेकिन यह कहना मुश्किल है कि व्यक्तिगत पीड़ा को भी भुला दिया गया होगा।

मनसे का राजनीतिक इतिहास बहुत उल्लेखनीय नहीं रहा है। 2009 के लोक सभा चुनाव में मनसे ने 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे थे लेकिन उनमें से कोई नहीं जीत सका था। परंतु मनसे ने कई सीटों पर शिव सेना को नुकसान पहुंचाया था। उसी वर्ष हुए विधान सभा चुनाव में मनसे 143 सीटों पर लड़ी और 13 सीटें जीतने में सफल रही। यह चुनावों में उसका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। 2014 के लोक सभा चुनाव में पार्टी ने 10 प्रत्याशी उतारे और सभी की जमानत जब्त हो गई। उसी वर्ष हुए विधान सभा चुनावों में पार्टी 288 में से 219 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरी लेकिन 209 पर उसकी जमानत जब्त हो गई। पार्टी को केवल एक सीट पर जीत मिली।

इसके बाद वर्ष2024 के नवंबर में हुए विधान सभा चुनावों में माहिम में मतदाता राज के बेटे अमित को हराने के लिए एकजुट हुए और उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार महेश सावंत 17,000 से अधिक मतों से जीत गए। माहिम वह क्षेत्र है जो शिव सेना की सोच और राजनीति का केंद्र रहा है। यह हार पुराने सभी मसलों पर एक विराम की तरह थी। उद्धव चाहते तो परिवार के सम्मान में अपने प्रत्याशी को वापस ले सकते थे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थन के बावजूद राज ठाकरे को हार का सामना करना पड़ा।

ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे की शिव सेना ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन वह सरकार में एक कार्यकाल पूरा करने में कामयाब रही। शिव सेना में विभाजन हुआ और एकनाथ शिंदे भाजपा से जा मिले। यह एक चेतावनी की तरह था और अब राज तथा उद्धव दोनों को इस हकीकत का एहसास हो गया है कि उनके सामने एक जबरदस्त शत्रु है जिसका नाम है- भाजपा।

वर्ष 2026 के आरंभ में बृहन्मुंबई महानगरपालिक (बीएमसी) के चुनाव होने हैं। अक्टूबर-नवंबर में अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव हो सकते हैं। एकजुटता की इस भावना का संबंध साझा शत्रु के सामने होने से है। परंतु इस कदम से अनचाहे परिणाम सामने आ सकते हैं। आम धारणा के विपरीत जरूरी नहीं कि भाजपा को भी ऐसा लगे कि ठाकरे परिवार की एकजुटता उसकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच की प्रतिद्वंद्विता महाराष्ट्र में किसी से छिपी नहीं है और इस बारे में काफी कुछ लिखा जा चुका है। शिंदे मानते हैं केंद्र उनके साथ है जबकि फडणवीस मानते हैं कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। महाराष्ट्र में मराठियों का सम्मान होना चाहिए, यह विचार बुनियादी रूप से राज ठाकरे का है। यह उन पुराने दिनों की याद दिलाता है जब क्रिकेट की पिच खोद दी जाती थीं और इसकी सराहना होती थी, इससे वोट मिलते थे।

परंतु महाराष्ट्र में तब से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। भाजपा का वोट बैंक उच्च जातियों के मराठी और उससे भी बढ़कर गैर मराठी भाषी मतदाता मसलन गुजराती, उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी, जैन आदि रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र मराठीभाषियों का है, यह विचार जितना उग्र होगा, अन्य समुदाय उतने ही अलग-थलग महसूस करेंगे।

दो घटनाएं इसकी बानगी हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिव सेना और मनसे ने जून में देवेंद्र फडणवीस द्वारा हिंदी को तीसरी भाषा बनाए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी (वह आदेश बाद में वापस ले लिया गया)। इसके बाद राज का भाजपा से अलगाव हुआ जिससे राजनीतिक समीकरण बदल गए। दूसरी घटना थी कबूतरखानों को ढकने का फैसला जहां रोज डेढ़ टन अनाज कबूतरों को खिलाया जाता था। यह निर्णय भी कुछ ही दिन में वापस ले लिया गया क्योंकि जैन समुदाय विरोध में सड़कों पर उतर आया था। परंतु इससे पहले ही भाजपा-शिवसेना के मतभेद सामने आ चुके थे और सेना के विधायक सार्वजनिक रूप से फैसले को वापस लेने की आलोचना करने लगे थे।

शिव सेना के दूर होने से भाजपा को कोई दिक्कत नहीं बल्कि मनसे तथा उद्धव के नेतृत्व वाली शिव सेना के एकजुट होने से उसे एकनाथ शिंदे के समर्थकों को अपने पाले में करने में आसानी होगी।

आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र में भाजपा की स्वीकार्यता बढ़ रही है और यह शिव सेना की कीमत पर हो रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस धड़े की कीमत पर। एक समय शिव सेना का गढ़ रहे मुंबई में भाजपा 15 सीटें जीतने में कामयाब रही। इनमें गोरेगांव सीट भी शामिल है जो सेना का गढ़ है। इसकी वजह? महाराष्ट्र के युवा मतदाताओं को भाजपा का विजन अधिक आकर्षक लगता है। मराठी माणूस की अपील में उतना दम नहीं है। महाराष्ट्र का बदलता जनांकिकीय चरित्र और राजनीतिक मांग अब एकदम अलग प्रकृति के हो चुके हैं।

महाराष्ट्र अब सत्ता की राजनीति का केंद्र है। आने वाले महीनों में और अधिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

आपका पक्ष

कर सुधार की नई चुनौतियां

जीएसटी को वर्ष 2017 में लागू करते समय इसे देश की कर व्यवस्था में सबसे बड़ा सुधार कहा गया था। उद्देश्य था अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर 'एक राष्ट्र, एक कर' का ढांचा तैयार करना। यह पहल पारदर्शिता और सरलता की ओर बड़ा कदम थी। लेकिन समय के साथ इसकी चुनौतियां स्पष्ट होने लगीं। सबसे बड़ी दिक्कत छोटे व्यापारियों और असंगठित क्षेत्र के सामने आई। डिजिटल रिटर्न भरने और जटिल तकनीकी अनुपालन ने उन्हें कर जाल में उलझा दिया। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और तकनीकी सहायता की कमी ने स्थिति और कठिन बना दी। स्थिति ऐसी हो गई है मानो सरलता की राह पर चलते-चलते हम जटिलता के दलदल में फंस गए हों। दूसरा बड़ा प्रश्न राज्यों की राजस्व हिस्सेदारी का है। अनुच्छेद 246 (अ) के तहत जीएसटी लागू हुआ, लेकिन राज्यों को मिलने वाली राशि समय पर न मिल पाने से संघीय ढांचे में असंतोष

सरकार द्वारा जीएसटी के केवल दो स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत रखने का प्रस्ताव है जो फिलहाल 4 स्लैब में है

पैदा होता है। यह केवल आर्थिक प्रश्न नहीं, बल्कि भरोसे की बुनियाद को कमजोर करने वाला पहलू है। समाधान यही है कि छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए स्थानीय भाषाओं में सरल अनुपालन व्यवस्था विकसित की जाए। राज्यों को उनका हिस्सा समयबद्ध व पारदर्शी प्रक्रिया से उपलब्ध कराया जाए। साथ ही कर प्रणाली को ऐसा बनाया जाए जिसमें करदाता सहयोगी महसूस करे शत्रु नहीं। जीएसटी तभी अपने वास्तविक उद्देश्य को सिद्ध करेगा जब यह केवल राजस्व संग्रह का उपकरण न रहकर समान अवसर, आर्थिक न्याय और पारदर्शिता का माध्यम बने।

अवनीश कुमार गुप्ता, प्रयागराज

भूस्खलन का कारण अंधाधुंध निर्माण तो नहीं

देश के बहुत से राज्यों में भूस्खलन से भारी तबाही हो रही है। लेकिन हमें यह चिंतन करने की जरूरत है कि भूस्खलन का कारण कहीं गलत तरीके से किए जा रहे काम तो नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ काटकर सड़कों का निर्माण, वहां लगातार वाहनों की आवाजाही इस खतरे को उत्पन्न कर सकती है। सरकार को ऐसी सड़कों तथा पहाड़ों का निरीक्षण कराना चाहिए। पहाड़ी इलाकों में सड़कों के कमजोर पड़ने या पहाड़ों के खिसकने से होने वाले हादसों से बचने के लिए सरकार और आमजन को लापरवाही छोड़नी होगी। पहाड़ों में बने मकानों की लगातार जांच होनी चाहिए। पहाड़ी इलाकों में बहुत-सी सड़कें बड़े-बड़े पहाड़ों के नीचे से गुजरती हैं। ऐसे जगहों के पहाड़ों की जांच करानी चाहिए, ताकि पहाड़ दरके तो नुकसान कम हो। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बारिश के समय सड़क पर मलबा आ जाता है। यहां व्यास नदी के किनारे भी सड़कें तथा पुल बने हुए हैं। पहाड़ में भारी बारिश के कारण व्यास नदी उफान पर है और कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी हुई है। ऐसे में सरकार को बारिश से होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। व्यास नदी का रौद्र रूप जम्मू-कश्मीर में दिख चुका है। पहाड़ पर भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण काफी जानमाल का नुकसान भी हो चुका है। ऐसे में संभल कर रहने की आवश्यकता है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को अल्जीरिया में मकाम एचाहिद (शहीद स्मारक) पर माल्यार्पण कर स्वतंत्रता संग्राम में अल्जीरियाई लोगों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित की।

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 30-08-2025 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMTEN User: kamlesh.mestry Time: 08-29-2025 21:57 Color:

संवाद

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । मुंबई । शनिवार, 30 अगस्त 2025

निवेश को न्योता

नई संभावना टटोल रहे जापान-भारत

पीएम नरेंद्र मोदी इससे पहले 7 बार जापान जा चुके हैं, लेकिन 7 साल बाद ऐसा संयोग बना जब किसी और मकसद नहीं, खासतौर पर द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए वह तोक्यो में हैं। दोनों देशों के बीच गहरी व्यापारिक, तकनीकी और रणनीतिक साझेदारी है, जिसे भारतीय प्रधानमंत्री की इस यात्रा के जरिये नए क्षेत्रों में बढ़ाया जा सकता है।

मोदी का जापान दौरा

विकास की कहानी । भारत-जापान इकॉनमिक फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नॉलजी, इनोवेशन, ग्रीन एनर्जी और स्किल डिवेलपमेंट जैसे क्षेत्रों का जिक्र किया, जिनमें सहयोग बढ़ाने की अपार संभावना है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में और निवेश करने का न्योता दिया है। भारत के पास इस समय दुनिया की सबसे बड़ी कामकाजी युवा आबादी है, जबकि जापान के पास तकनीकी दक्षता। दोनों मिलकर विकास की नई कहानी लिख सकते हैं।

बढ़ता व्यापार । इस रिश्ते को आंकड़ों में देखें, तो दोनों देशों के बीच 2023-24 में 22.85 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। जापान ने भारत में 40 अरब डॉलर से अधिक निवेश किया है। 1400 जापानी कंपनियां भारत में रजिस्टर्ड हैं और इनमें से करीब आधी मैन्युफैक्चरिंग फर्म हैं।

सफलता दोहराने का समय । जापान की ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भारत में अपना जैसा दबदबा कायम किया है, उसे उदाहरण की तरह लेना चाहिए। पीएम मोदी ने भी इसका जिक्र किया। जापान की सुजुकी, टोयोटा और होंडा के पास भारतीय वाहन बाजार में करीब 50% हिस्सा है। इन कंपनियों ने भारतीय जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाला है। इनके सफलता को दूसरी जगह दोहराने का यह बिल्कुल सही समय है।

QUAD की चिंता । भारत और जापान हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए गठित मंच QUAD के सदस्य हैं। तकनीक, साइबर सुरक्षा, इंफ्रा में सहयोग के अलावा चार देशों के इस समूह का सबसे अहम लक्ष्य है चीनी आक्रामकता को बढ़ने से रोकना। हालांकि अमेरिका की टैरिफ नीतियों की वजह से इस संगठन के कमजोर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। किसी भी तरह की चीनी आक्रामकता का सीधा असर पहले भारत और जापान पर पड़ेगा। ऐसे में जरूरी है कि ये दोनों देश QUAD की प्रासंगिकता को बनाए रखें।

अहम साझेदार । भारत-जापान दोस्ती को अगर दर्शाना हो, तो शायद मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रॉजेक्ट से बढ़िया प्रतीक नहीं मिलेगा। भारतीय विकास में जापान अहम साझेदार रहा है। दोनों के संबंधों में स्थिरता, भरोसा और आपसी सम्मान है। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए जरूरी है कि ये दोनों पुराने साझेदार रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाएं।

अंतर्दृष्टि

जब तक यकीन जिंदा है, तब तक नहीं है हार

सुंदर चंद ठाकुर

जिंदगी में कभी-कभी हम ऐसे मोड़ पर आ खडे होते हैं, जहां न आगे कोई रास्ता नजर आता है और न पीछे लौटने की हिम्मत बचती है। वहां बस एक चीज होती है - इंतजार। किसी की आवाज का, किसी के लौट आने का, किसी अच्छे वक्त का या किसी खुशखबरी का। और इस इंतजार के लम्हे बहुत भारी होते हैं। इंतजार कोई आसान काम नहीं। ये वो वक्त होता है, जब हम दुनिया के साथ चलते भी हैं और अंदर से ठहरे भी होते हैं। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है - लोग आपको हंसता हुआ देख सकते हैं, काम करता हुआ, बात करता हुआ - लेकिन अंदर एक खामोशी होती है, जो किसी को सुनाई नहीं देती। वो खामोशी जो हर सांस के साथ और गहरी होती जाती है। इंसान के अंदर दो आवाजें चल रही होती हैं - एक कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। और दूसरी कहती है, अब बहुत हो गया, छोड़ दे। और इन दोनों के बीच हर दिन-हर रात झूलता है इंसान। यही इंतजार की सबसे बडी थकान है। न नींद सुकून देती है, न कोई सलाह राहत बनती है।

कभी-कभी यह भी लगता है कि शायद ये इंतजार ही हमारी किस्मत बन गया है। जैसे अब जिंदगी का नाम ही रुकना और टकटकी लगाकर देखना है। हर गुजरा हुआ लम्हा बीते कल की परछाई जैसा लगता है - न पूरी तरह गया हुआ, न पूरी तरह जिया हुआ। मगर फिर कहीं दिल के किसी कोने से एक छोटा सा यकीन निकलता है - 'शायद कल...' और बस इसी 'शायद' पर पूरी जिंदगी टिक जाती है। इंतजार हमें बहुत कुछ सिखाता है। यह सिखाता है कि चाहत में वक्त का कोई मोल नहीं होता। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम किसी के लिए दिन-रात इंतजार करते हैं, मगर सामने वाले को अंदाजा तक नहीं होता। हम जिस लम्हे को छूने को बेताब हैं, वो लम्हा शायद किसी और के लिए कोई मायने नहीं रखता। और यही बात दिल को सबसे ज्यादा चुभती है। वो बेखबरी, वो बेरुखी इंतजार को और भी लंबा और गहरा बना देती है। लेकिन फिर भी इंसान इंतजार करता है, क्योंकि दिल को किसी न किसी उम्मीद की डोर से बांधना जरूरी होता है। नहीं तो टूट जाना तय है। उम्मीद चाहे कितनी ही कमजोर क्यों न हो, मगर जब तक वो बाकी है, तब तक जिंदगी में कुछ न कुछ बाकी रहता है।

इंतजार एक ऐसी नाव है, जो ठहरे पानी में भी चलती रहती है - बस उसकी आवाज नहीं होती। हर दिन की सुबह, हर रात की खामोशी सब उसी की तरह लगने लगती है। मगर उस ठहरे हुए वक्त में भी एक जादू होता है, जो हमें गिरने नहीं देता। क्योंकि जब तक इंतजार जिंदा है, तब तक यकीन भी जिंदा है। और जब तक यकीन है, तब तक हार नहीं है।

ऑफ़ दि ट्रैक

दिमाग़ में GPS

राहुल पाण्डेय

आपने गौर किया कि कभी-कभी बिना गूगल मैप देखे हम सीधा उस गली में पहुंच जाते हैं, जहां गोलगप्पे वाला बैठता है। सवाल है कि असल में हमें रास्ता दिखाता कौन है? क्या दिमाग में भी गूगल मैप जैसी कोई चीज काम करती है? यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के दो रिसर्चर झेंगांग लू और रसेल एप्स्टीन ने इसका जवाब ढूंढ निकाला है। इसके लिए उन्होंने लोगों को वर्चुअल रियलिटी वाले शहर में टैक्सी चलाने का टास्क दिया। यह किसी कंप्यूटर गेम जैसा ही था। इसमें उन्हें सिर्फ सवारियां उठानी-छोड़नी थीं। जब लोग ये 'VR टैक्सी' चला रहे थे, तो रिसर्चर उनके दिमाग से निकलने वाले सिग्नल पढ़ रहे थे। पता चला कि हमारे दिमाग में दो हिस्से ऐसे हैं जो हमेशा ट्रैक करते रहते हैं कि हम किस दिशा में देख रहे हैं। मतलब दिमाग का ये कंपास हमेशा चालू रहता है। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया है- न्यूरल कंपास। यानी दिमाग में पहले से ही एक GPS फिट है। शोध के रिसर्चर रसेल एप्स्टीन के मुताबिक दिशा भूल जाना अल्जाइमर जैसी कुछ बीमारियों का लक्षण हो सकता है। अगर हम इस न्यूरल कंपास को और अच्छे से समझ लें, तो ऐसी बीमारियों को जल्दी पकड़ सकते हैं।

टैरिफ़ वॉर के बीच स्वदेशी का ध्यान आना स्वाभाविक

स्वदेशी की फिर क्यों आई याद

अनिल सिन्हा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सुजुकी मोटर्स के कार्यक्रम में स्वदेशी की पुरजोर वकालत और उसकी नई व्याख्या से लोगों को चौंका दिया है। उन्होंने कहा, 'पैसा किसका लगता है...वो डॉलर है, पाउंड है, वो करंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना-देना नहीं है। पैसा किसी का, पसीना हमारा। पैसा कहीं से आए, पसीना यहां का लगे।'

स्वदेशी का आह्वान । इससे पहले स्वाधीनता दिवस के संबोधन में भी प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी को आंदोलन बनाने की अपील की थी। लोगों के मन में यह सवाल आना लाजिमी है कि भूमंडलीकरण और उदारीकरण के इस दौर में कोई राजनेता स्वदेशी की बात क्यों कर रहा है? भले ही स्वदेशी को आंदोलन में बदल देने की अपील अपने कार्यकाल में पहली बार कर रहे हों, वह 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वोकल फॉर लोकल' के नारे पहले से देते रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या उनका यह आह्वान स्वदेशी की उस अवधारणा पर आधारित है जिसे गांधी जी ने औपनिवेशिक शिकंजे से मुक्ति पाने और शोषणमुक्त समाज बनाने के लिए अपनाया था?

ट्रंप-टैरिफ की चुनौती । क्या स्वदेशी की ओर उनका मुड़ना उनके आर्थिक चिंतन में बड़े बदलाव का संकेत है या तात्कालिक चुनौतियों से निपटने के लिए जनता में उत्साह भरने भर का जरिया? मौजूदा हालात को देखें तो भारत की विदेश नऔर अर्थनीति को अपने अनुकूल मोड़ने के लिए डॉनल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किए गए टैरिफ युद्ध से लड़ने के अलावा सरकार के पास कोई चारा नहीं रह गया है। हालांकि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की कोशिशें अब भी जारी हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा भारत की विदेश नीति को पूरी तरह बदलने की ट्रंप की जिद है। कृषि क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा खोलने जैसे मुद्दे भी रुकावट बने हुए हैं।

राष्ट्रीय गौरव का सवाल । अमेरिका सिर्फ व्यापार नहीं करना चाहता, वह एक ऐसा पार्टनर चाहता है जो उसके सहायक की भूमिका में हो। वह चाहता है कि भारत, रूस या दुनिया के बाकी देशों से व्यापार ही नहीं सामरिक संबंध भी उसकी मर्जी के हिसाब से तय करे। जाहिर है कि भारत, पाकिस्तान की तरह उसका पिछलग्गू नहीं बन सकता। ऐसे में अपने फैसले खुद लेने की आजादी और राष्ट्रीय गौरव बरकरार रखने की सोचते समय स्वाधीनता संग्राम को याद करना और स्वदेशी का ध्यान आना स्वाभाविक ही है।

कम नहीं हैं चुनौतियां
- टैरिफ ने निर्यात को और भी मुश्किल बनाया
- ट्रंप की शर्त से राष्ट्रीय गौरव पर चोट
- पर्यावरण संकट का भी यही है सही जवाब

स्वावलंबन या स्वदेशी । जहां तक आत्मनिर्भरता की बात है तो तमाम प्रधानमंत्री उसका जिक्र करते रहे हैं। लालबहादुर शास्त्री ने तो अमेरिकी कानून पीएल 480 के तहत आने वाले गेहूं का आयात बंद कर दिया था क्योंकि अमेरिका इससे भारत की विदेश नीति प्रभावित करने की कोशिश में था। अमेरिकी गेहूं का आयात बंद होने से ही हरित क्रांति का रास्ता खुला और देश अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सका। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी स्वाबलंबन के इस नारे को आगे बढ़ाया। लेकिन स्वदेशी को आंदोलन बनाने की घोषणा किसी ने नहीं की। वे बदलती दुनिया के साथ कदमताल को जरूरी मानते थे।

उदारीकरण की राह । नब्बे के दशक में आई उदारीकरण की नीति के बाद कहानी थोड़ी बदल गई। लेकिन कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई इस नीति को भी वाम दलों को छोड़ कर देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना लिया। पीवी नरसिंह राव की नीतियों को अटल बिहारी वाजपेयी ने बढ़-चढ़ कर लागू किया। मनमोहन सिंह तो उदारीकरण की नीतियों के शिल्पकार ही थे। उनके बाद आई मोदी सरकार ने रक्षा समेत उन क्षेत्रों को भी विदेशी पूंजी के लिए खोल दिया जो सामरिक कारणों से बंद थे।

खादी का दर्शन । सवाल है कि क्या विदेशी पूंजी से भारत में बनी चीजों को स्वदेशी कहा जा सकता है? गांधी जी की राजनीति में स्वदेशी एक महत्वपूर्ण औजार थी। यह सिर्फ विदेशी चीजों के बहिष्कार और भारत में बनी सामग्रियों को अपनाने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने व लोगों की गरीबी कम करने के औजार के रूप में भी खादी को देखा। वह स्वदेशी के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपने पांव पर खड़ा करना चाहते थे।

सभ्यता पर संकट । क्या प्रधानमंत्री गांधी जी वाली स्वदेशी को सचमुच अपनाना चाहेंगे? इसके आसार नहीं दिखते। भले ही, प्रधानमंत्री इस मंत्र का इस्तेमाल सिर्फ ट्रंप टैरिफ जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए करना चाहते हों, लेकिन स्वदेशी की चर्चा हमें गांधी के महान विचारों की ओर लौटने का रास्ता तो दे ही सकती है। युद्ध और क्लाइमेट चेंज की भयावह चुनौतियों से घिरी सभ्यता को बचाने के लिए ऊर्जा के सीमित इस्तेमाल और पूरी तरह स्थानीय अर्थव्यवस्था वाले विकल्प के अलावा कोई रास्ता नहीं है। असली स्वदेशी भी यही है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

5 पॉइंट

क्या ये 91 वाला मोमेंट है

सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित देशों की कतार में लाने का लक्ष्य रखा है। स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। टैरिफ संकट के बीच क्यों लोगों को 1991 की याद आ रही?

1 1991 बनाम 2025
करीब 35 साल पहले देश दिवालिया होने के कगार पर था। तब आर्थिक सुधार अपनाए गए, लाइसेंस राज का खात्मा हुआ। अमेरिकी टैरिफ की वजह से भी हाल के वक्त का सबसे बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो गया है।

2 हक में बात
भारत की इकॉनमी 4 ट्रिलियन डॉलर की है और इसमें 10 ट्रिलियन तक पहुंचने की पूरी क्षमता है। सस्ता श्रम, बड़ा बाजार और युवाओं की विशाल आबादी हक में जाती है। बहुत बड़ा क्षेत्र अब भी अछूता है।

3 सुधार और इंफ्रा
पिछले एक दशक में सरकारी खर्चों पर लगाम लगाई गई है। बैंकों की बैलेंस शीट सुधरी है और ब्याज दरें कम हुई हैं। GST सुधार हुआ। साथ ही, 50 हजार किमी नई सड़कों का जाल बिछा है।

4 कमजोर कड़ी
बड़ी आबादी स्किल्ड नहीं है, रोजगार की कमी और युवाओं की क्षमता का सही इस्तेमाल न होना। शहरीकरण बढ़ा है, लेकिन ऐसे शहर कम हैं, जो व्यवस्थित हों और बड़ी आबादी का बोझ संभाल सकें।

5 फायदा कैसे उठाएं
सरकार ने बिजनेस आसान बनाने के लिए इसी महीने एक कमिटी गठित की है। उम्मीद है कि चीन प्लस वन की पॉलिसी से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। GST को और सरल किया जा रहा है।

प्रस्तुतिः शैलेंद्र पांडेय

AI को बैसाखी बनाना अच्छी बात नहीं

शिव ट्रिलॉजी व रामचंद्र सीरीज जैसी बेस्टसेलर पुस्तकों के लेखक अमीश त्रिपाठी आजकल अपनी पुस्तक **'द चोला टाइगर : एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ'** को लेकर चर्चा में हैं। NBT के **प्रशांत जैन** से बातचीत में अमीश ने अपनी डेढ़ दशक की लेखकीय यात्रा, अपनी आने वाली पुस्तकों व राइटर्स सेंटर कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। पेश हैं अहम अंश :

NBT सप्ताह का इंटरव्यू

अमीश त्रिपाठी

■ आपको लेखन में डेढ़ दशक का समय हो गया है। एक सफल बैंकर से लेकर एक बेस्टसेलर लेखक तक की यात्रा को आप कैसे देखते हैं?

करियर में शिव जी ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है। मैंने सात-आठ साल काफी कठिनाइयां झेलीं, लेकिन अब सब स्थिर हो गया है। राजतरंगिनी में भी कल्हन ने लिखा था कि अगर अच्छी किस्मत आपको कहीं पर आशीर्वाद दे रही है, तो बुरी किस्मत आपको कहीं तो ठेस पहुंचाएगी। शायद इसी को जिंदगी का संतुलन कहते हैं।

■ कोविड के बाद और AI के चलते लेखन के क्षेत्र में आए बदलाव को आप कैसे देखते हैं?

लंबे अरसे के नजरिए से देखें तो AI का क्या प्रभाव पड़ेगा यह कहना बहुत मुश्किल है। कोई भी अगर कह रहा है कि उसे मालूम है कि पांच साल बाद या दस साल बाद क्या होने वाला है, तो वह झूठ बोल रहा है। यह किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि बहुत ही तेजी से बदलाव आ रहा है। कुछ चीजें तो अभी सीधे-सीधे दिख रही हैं। आप फिल्मों की दुनिया में भी देखेंगे कि साल में तीन-चार फिल्में ऐसी होंगी कि उन्होंने हजार करोड़ कमा लिए। लेकिन काफी फिल्में ऐसी होंगी जो सुपरस्टार की मौजूदगी के बावजूद पहले हफ्ते में ही पिट गईं। पुस्तकों की दुनिया में भी ऐसा ही हो रहा है। कुछ पुस्तकें सुपरहिट हैं, जिनकी बिक्री बढ़ती जा रही है, लेकिन एवरेज हिट्स की हालत अच्छी नहीं है। अब पांच साल बाद क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। यह इंटरनेट और AI का ही प्रभाव है, जो किसी ने सोचा नहीं था। हम तो तब सोचते थे कि इंटरनेट के कारण डेमोक्रेटाइजेशन होगा, लेकिन यह तो उल्टा कॉन्सन्ट्रेशन हो रहा है।

■ आजकल के युवा हरेक काम AI की मदद से कर रहे हैं। इस बारे में आपके क्या विचार हैं?

आज की युवा पीढ़ी AI का इस्तेमाल करके लेखन भी कर रही है। मेरे हिसाब से अगर आप AI को एक टूल की तरह देखें, तो यह अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसे अपनी बैसाखी बना लें, तो यह अच्छी बात नहीं होगी। अगर आप बिना किसी AI के खुद ही अच्छा लिख सकते हैं, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। वहीं AI को आप रिसर्च करने के लिए या अपने लिखे हुए का ग्रामर चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसे औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, बस AI तुम लिख दो और मैं पढूंगा भी नहीं, तो यह ठीक नहीं है। मौजूदा युवा पीढ़ी को इसका नतीजा 10-15 साल बाद पता चलेगा कि मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं है। तब आपको नौकरी कौन और क्यों देगा। मेरा मानना है कि आप AI को बैसाखी की बजाय अपना औजार बनाओ।

■ नई पीढ़ी में लोगों की पढ़ने की आदत भी कम होती जा रही है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?

यह सही बात है कि आजकल लोगों में पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा कि जिस तरह भोजन की थाली में हरेक चीज का होना जरूरी है, उसी तरह मनोरंजन के लिए भी आपको सिर्फ विडियो कॉन्टेंट देखने के बजाय पढ़ने पर भी ध्यान देना चाहिए। आपका दिमाग बेहतर काम करेगा।

■ आपकी हालिया पुस्तक 'द चोला टाइगर्स द इम्मोर्टल' राइटर सेंटर के जरिए आई है। इसके बारे में बताइए।

यह मेरा नहीं, बल्कि अमेरिकी लेखक जेम्स पैटरसन का आइडिया है। हालांकि वह भारत में इतने चर्चित नहीं हैं, लेकिन ग्लोबल पब्लिशिंग के इतिहास में शायद सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखक हैं। उन्होंने यह राइटर सेंटर कॉन्सेप्ट शुरू किया था। मेरे पास काफी आइडियाज हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस जीवन में मैं उन सब पर काम कर पाऊंगा। इसलिए मैंने भी इस राइटर सेंटर कॉन्सेप्ट से प्रेरणा ली। इसमें मैं एक पांच से छह हजार शब्दों की कहानी लिखता हूं। साथ ही यह भी बताता हूं कि इसमें आगे क्या रिसर्च करनी चाहिए। फिर एक पहले से प्रकाशित लेखक उस कहानी को विस्तार देता है। मेरी इस किताब में दो लेखकों ने मेरे साथ काम किया है।

> **लंबे अरसे के नजरिए से देखें तो AI का क्या प्रभाव पड़ेगा यह कहना बहुत मुश्किल है। कोई भी अगर कह रहा है कि उसे मालूम है कि पांच साल बाद या दस साल बाद क्या होने वाला है, तो वह झूठ बोल रहा है। यह किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि बहुत ही तेजी से बदलाव आ रहा है। कुछ चीजें तो अभी सीधे-सीधे दिख रही हैं**

■ फिल्मी दुनिया में घोस्ट राइटर्स का कॉन्सेप्ट चर्चा में रहता है। लेकिन आपने दो लेखकों को क्रेडिट दिया है। हालांकि इस सीरीज की पिछली पुस्तक 'लेजंड ऑफ सुहेलदेव' में आपने किसी को क्रेडिट नहीं दिया था...

मैं पिछली बार भी क्रेडिट देना चाहता था, लेकिन मेरे साथी लेखक ने मना किया। मेरा मानना है कि सत्य बोलना चाहिए। अगर मेरी कोई पुस्तक राइटर सेंटर से आई है और यह बात पुस्तक के कवर पर ना लिखूं और अंदर उन लेखकों के नाम ना लिखूं, तो यह गलत होगा।

■ आने वाले दिनों में आपका किस तरह की पुस्तकें लाने का विचार है?

इंडिक क्रॉनिकल्स सीरीज में भारत के पिछले हजार वर्ष के इतिहास जुड़े नायक व नायिकाओं की कहानियों पर पुस्तकें आएंगी। इनके अलावा शिवा ट्रिलॉजी और रामचंद्र सीरीज में भी कुछ पुस्तकें आएंगी। साथ ही मेरे दिमाग में कुछ इंटरनैशनल सीरीज भी हैं। मैंने नेहरू सेंटर के डायरेक्टर के तौर पर जो वक्त लंदन में बिताया है, उस पर भी मैं कुछ लिखना चाहता हूं।

www.nbt.in

रसभरे जामुन बीने हैं कभी

खुद अपनी आंख से

क्षमा शर्मा

घर के परिसर में एक बहुत पुराना पेड़ है। जामुन से भरा। सवेरे-सवेरे पेड़ के नीचे असंख्य फल गिरे रहते हैं। यही हाल सड़क पर दूसरी सोसाइटी के सामने और एक स्कूल के सामने लगे पेड़ों के नीचे का भी है। इन अद्भुत फलों की ऐसी बेकदरी देख मन बहुत खिन्न होता है। अपने यहां तो जमीन पर गिरे फल का मिलना वरदान सा माना जाता था। आम-जामुन के मौसम में तो स्कूल जाते वक्त बहुत से बच्चे अपने-अपने बस्तों में नमक और लाल मिर्च रखकर ले जाते थे। आज यह बात नहीं रही। महानगरों में शायद ही कोई बच्चा या बड़ा इन फलों को उठाता है। कोई उठाने लगे, तो लोग उसे आश्चर्य से देखते हैं। यूरोप में भी बेशुमार आलू बुखारा, आड़ू, सेब, शहतूत, नींबू जमीन पर गिरे रहते हैं। कोई उन्हें उठाता नहीं। लोग बताते हैं कि यहां घरों में फलों के पेड़ खूबसूरती के लिए लगाए जाते हैं। इन पर लगे फल कोई नहीं खाता जबकि यही फल महंगे दामों पर डिपार्टमेंटल स्टोर्स से यही लोग खरीदकर लाते हैं। अमेरिका में रहने वाली एक भारतीय महिला से जब इस बारे में पूछा, तो उसने कहा कि उसके घर में भी बहुत से नींबू और अनार लगते हैं। लेकिन उन्हें इसलिए नहीं खाते कि उन पर गिलहरी, चिड़ियां आदि बैठती हैं। लेकिन जो फल बाजार से आप लाते हैं, उनके पेड़ों पर भी तो गिलहरी, चिड़ियां बसेरा करती होंगी? इस बात को सुनकर वह सोच में पड़ गई थीं।

पहले तो अपने यहां जिस अमरूद या आम को तोता कुतरकर नीचे फेंक देता था, उसे मीठा मानकर लोग शौक से खाते थे। और जामुन के बारे में तो मनुष्य क्या जानवरों की कहानियां भी मशहूर हैं। एक कहानी अक्सर याद आती है। जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। वहीं नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। बंदर मगरमच्छ गहरे मित्र थे। बंदर मौसम में उसे खूब जामुन खिलाता था। एक दिन बंदर से मगरमच्छ ने कहा कि आओ मैं तुम्हें अपने घर ले चलूं। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी के बीचोबीच पहुंचा, तो मगरमच्छ बोला कि तू रोज मीठे जामुन खाता है। तेरा कलेजा कितना मीठा होगा। आज तो मैं तेरा कलेजा खाऊंगा। बंदर घबरा गया। बोला- अरे दोस्त अपना कलेजा तो मैं जामुन के पेड़ पर ही भूल आया। तुम मुझे वहीं ले चलो, तो कलेजा उतारकर तुम्हें दे दूंगा। मगरमच्छ उसकी बातों में आकर वापस ले आया। बंदर फौरन कूदकर जामुन के पेड़ पर पहुंच गया। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची।

जिस इलाके में रहती हूं वहां बेशुमार जामुन हैं इन दिनों और बंदर भी। लेकिन आश्चर्य कि बंदर पेड़ों पर चढ़कर जामुन खाते नहीं दिखते। वे घरों में घुसकर सामान उठा ले जाते हैं। शहरियों की तरह शायद वे भी पेड़ों पर चढ़ना भूल गए हैं। काश कि वे पेड़ों पर चढ़ें और फिर से रसभरे जामुनों का आनंद लें।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

चलते-चलते...

प्लास्टिक सैकड़ों सालों तक मिट्टी में पड़ा रहता है, लेकिन नई रिसर्च ने दिखाया है कि वैक्सवर्म कैटरपिलर कुछ ही दिनों में पॉलीथिन को चबा कर बॉडी फैट में बदल सकते हैं। कनाडा की ब्रेंडन यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिकों ने पाया कि करीब 2,000 वैक्सवर्म कैटरपिलर 24 घंटे में एक पॉलिथीन बैग तक खा जाते हैं। हालांकि, सिर्फ प्लास्टिक खाने पर ये जल्दी मर जाते हैं, इसलिए इन्हें शुगर जैसी चीजें देनी भी जरूरी है।

रीडर्स मेल

कैसे करें ट्रंप पर भरोसा?

'वार्ता से रास्ता निकले' संपादकीय पढ़ा। लेकिन सवाल तो यह है कि अब तक अमेरिका से जो हमारी बातचीत हुई, समझौते हुए हैं, उन पर वो खास खरा तो उतरा नहीं, वो अब क्या खरा उतरेगा। अमेरिका हमारे देश के प्रति हमेशा ही दो रास्ते पर चल रहा है। ट्रंप पर हमारे देश को यह समझदारी दिखानी चाहिए कि हमें इसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है। यह अपने हितों और स्वार्थ को प्राथमिकता देता है। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाने का मन बनाया, दरअसल उसने दुनिया भर को अपने यहां के व्यापार को इससे प्रभावित होने का भय पैदा किया है। लेकिन इससे हमारे देश को उतना नुकसान नहीं होगा, जितना उन देशों को होगा, जो पूरी तरह अमेरिका में व्यापार के लिए निर्भर हैं। हमारे देश को ट्रंप की गलत नीतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी निर्यात क्षमता को अन्य देशों में ओर मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान

उभरते खिलाड़ियों का भविष्य

हमारा देश खेलों में धीरे-धीरे सफलता की ओर कदम बढ़ा रहा है। ओलिंपिक जैसे खेल महाकुंभ में हम पदक तालिका में ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। एशियाई खेलों में भी हमने खूब पदक हासिल किए हैं। आज अलग-अलग खेलों में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा से अपने देश का मान बढ़ा रहे हैं और हम ऐसे खेलों में सफलता हासिल कर रहे हैं, जहां हमारे खिलाड़ी कभी टिक नहीं पाते थे। अब माता-पिता अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाने के बारे में सोचने लगे हैं, क्योंकि खेलों में पैसा और प्रतिष्ठा दोनों मिल रहे हैं। खेल की दुनिया में भारत की जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसे और आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी खेल संस्कृति में जो भी कमियां हैं, उन्हें दिग्गज खिलाड़ियों की मदद से दूर करना चाहिए। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और सुविधाएं मिले, तो वे पदकों का ढेर लगा सकते हैं।

साजिद अली, ईमेल से

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्सः(022) 2760 5275। फोन मुंबईः (022) 66353535, 22733535 रेस्पांसः (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। **स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर** (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

Machine Translated by Google

तर्कसंगत प्रतिक्रिया

भारत ने अमेरिकी टैरिफ के मद्देनजर संतुलित कार्रवाई का विकल्प चुना है।

टी भारत सरकार ने अब तक अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% शुल्क के मुद्दे को परिपक्वता और व्यावहारिकता के साथ संभाला है। वरिष्ठ अमेरिकी सरकारी अधिकारियों के भड़काऊ बयानों के बावजूद, भारत बहकावे में आने से बचता रहा है और अपनी स्थापित स्थिति पर कायम रहा है। इसलिए, जबकि अमेरिकी व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने रूस-यूक्रेन युद्ध को "मोदी का युद्ध" कहा, भारत शांत रहा है और इसके बजाय 50% शुल्क की नई वास्तविकता से निपटने की तैयारी कर रहा है। साथ ही, भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत, हालांकि रुकी हुई है, लेकिन अभी विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा है कि भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25% 'जुर्माना' शुल्क भी सौदे को तोड़ने वाला नहीं है, भले ही यह किसी भी व्यापार सौदे को महत्वहीन बना देता है। अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को अचानक बंद करने से भारत को और अधिक नुकसान होगा, लेकिन यदि ये दंडात्मक दरें लागू रहीं तो किसी भी संभावित व्यापार समझौते से होने वाले लाभ भी समाप्त हो जाएंगे।

सरकार का उद्योग जगत को संदेश भी इनकार का नहीं, बल्कि आश्वासन का रहा है: उन्हें पता है कि आगे मुश्किलें आएँगी, और उसे कम करने के लिए एक योजना पर काम चल रहा है। ऐसा लगता है कि समाधानों को दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उपयुक्तता के नज़रिए से देखा जा रहा है। सरकार ने भारी पैमाने पर प्रोत्साहनों की घोषणा करने के बजाय, यह जागरूकता दिखाई है कि ऐसे प्रोत्साहन भारत के लिए 50% टैरिफ के सामने शायद ही कोई असर डालेंगे, जबकि प्रतिस्पर्धियों को इससे आधे से भी कम का सामना करना पड़ रहा है। इसके बजाय, सरकार उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जिनका वह प्रभावी ढंग से समाधान कर सकती है, जैसे कि निर्यातकों के सामने आने वाला नकदी संकट।

केंद्र समग्र अर्थव्यवस्था को टैरिफ के प्रभाव से कैसे सुरक्षित रखे, इस बारे में भी यथोचित व्यावहारिक रहा है। निर्यात भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग पाँचवाँ हिस्सा है। अमेरिका इसका लगभग पाँचवाँ हिस्सा है, और उसके भीतर भी, अमेरिका को भारत के लगभग 40% निर्यात पर 50% टैरिफ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए, भले ही टैरिफ का क्षेत्रीय प्रभाव कुछ क्षेत्रों के लिए काफी गंभीर हो सकता है, लेकिन व्यापक आर्थिक प्रभाव सीमित होने की संभावना है। इसलिए, चीन के साथ बातचीत को फिर से शुरू करने और साथ ही जीएसटी दर में कटौती के माध्यम से घरेलू खपत को बढ़ावा देने का दोहरा दृष्टिकोण इस प्रभाव को कम करने में काफी मददगार साबित होगा। सरकार में कोविड-19 के दौर के प्रेस नोट 3 में निर्धारित मानदंडों को आसान बनाने के बारे में कुछ चर्चा चल रही है, जो भारत में चीनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कम करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। केंद्र और राज्यों को अगले हफ़्ते भी सहयोग करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जीएसटी दरों में कटौती राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य से ज़्यादा समझौता किए बिना हो। अब भावनात्मक आवेगों का नहीं, बल्कि संतुलित कार्रवाई का समय है।

तूफ़ान से पहले की शांति

संभावित नौकरी हानि के दुष्परिणामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है

टी जुलाई में मासिक वस्तु उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 3.5% की चार महीने की सबसे ऊँची 3.5% की वृद्धि दर, भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा रूस से नई दिल्ली की निरंतर तेल खरीद के लिए 25% की दंडात्मक "जुर्माना" दरों को लागू करने के एक दिन बाद, राहत की बात रही होगी। हालाँकि इस जुलाई की 3.5% वृद्धि दर पिछले जुलाई के 5% से कम है, लेकिन पूंजीगत (5%), मध्यवर्ती (5.8%) और बुनियादी ढाँचे की वस्तुओं (11.9%) में साल-दर-साल (वर्ष-दर-वर्ष) वृद्धि से समर्थित विनिर्माण में व्यापक वृद्धि दर्शाती है कि सरकार द्वारा संचालित उल्लेखनीय पूंजीगत व्यय के कारण सुधार जारी रहेगा। यह मूल धातुओं (12.7% y/y), विद्युत उपकरण (+15.9% y/y) और अन्य गैर-धात्विक खनिजों (सीमेंट के नेतृत्व में; 9.5% y/y) में प्रभावशाली वृद्धि से स्पष्ट है।

राहत की बात यह भी है कि ग्रामीण मांग में सुधार के पहले संकेत दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं (7.7%) और गैर-टिकाऊ वस्तुएं (0.5%) दोनों नौ महीनों में पहली बार सकारात्मक रहीं, 1.55% के खुदरा मुद्रास्फीति के आधार पर, जिसमें लगातार दूसरे महीने खाद्य मूल्य में गिरावट -0.8% रही, जो जून में -0.2% से कम और जुलाई 2024 में 5.1% से कम है। यह उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं - खाद्य स्टेपल और घरेलू आवश्यक वस्तुएं - पिछले 12 महीनों में से केवल चार में सकारात्मक रही हैं, और पिछले साल दिसंबर से इस अगस्त तक लगातार नकारात्मक बनी हुई हैं, जो पिछले सितंबर और इस साल जनवरी के बीच चरम पर रहे उपभोक्ता खाद्य मूल्य में बेतहाशा वृद्धि के कारण है। जबकि इस वर्ष खनन गतिविधि में लगातार चौथे महीने संकुचन हुआ है, जुलाई का -7.2% जून के -8.7% से थोड़ा बेहतर था, लेकिन पिछले जुलाई के 3.8% से बहुत खराब था। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के खनन राज्यों में कोयला खदानों में भारी बाढ़ से उबरना एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, जिसका प्रभाव महीनों तक महसूस किया जाएगा। जुलाई (0.6%) में बिजली का उत्पादन जून (-1.2%) की तुलना में मामूली रूप से बेहतर था, लेकिन पिछले जुलाई के 7.9% से बहुत खराब था। लेकिन ये संख्या तूफ़ान से पहले की शांति हो सकती है। कपड़ा (-1.4%), परिधान (3.2%), और चमड़ा (-3%) जैसे टैरिफ-प्रभावित क्षेत्रों ने पहले ही तनाव के संकेत दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि केंद्र ने इन क्षेत्रों की निकट भविष्य की तरलता संबंधी चिंताओं को दूर करने का वादा किया है, लेकिन यदि लगातार नौ महीनों से खुदरा मुद्रास्फीति में ऐतिहासिक नरमी से प्राप्त लाभों का निरंतर उपयोग किया जाना है, तो उपभोग की मांग को बनाए रखने, यदि नहीं तो बढ़ाने, तथा भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए अत्यधिक संभावित बड़े पैमाने पर नौकरियों के नुकसान के मानवीय परिणामों को संबोधित करना होगा।

अस्थिर विश्व में, ऊर्जा संप्रभुता ही नया तेल संकट है।

श्रीकांत माधव वैद्य

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष, ऊर्जा नीति सलाहकार, संस्थागत नेता और लचीले बदलावों के समर्थक हैं।

मैं भारत अपने कच्चे तेल का 85% से ज़्यादा और प्राकृतिक गैस का 50% से ज़्यादा आयात करता है। यह सिर्फ़ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है। यह हमारे राष्ट्रीय जोखिम रजिस्टर में शामिल है। संघर्ष क्षेत्रों के रूप में

बढ़ती जाती है, समुद्री मार्ग संकीर्ण हो जाते हैं और आपूर्ति श्रृंखलाएं खंडित हो जाती हैं, प्रत्येक आयातित बैरल एक दायित्व बन जाता है।

इस परिदृश्य में, रूसी तेल भारत का सबसे बड़ा स्विंग फैक्टर बन गया है। 2022 से, रूस देश का सबसे बड़ा एकल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है, जिसकी 2024-25 में कुल कच्चे तेल के आयात में लगभग 35%-40% हिस्सेदारी होगी - जो यूक्रेन युद्ध से पहले मुश्किल से 2% थी। हालाँकि रियायती बैरल ने आयात बिल में अस्थायी राहत प्रदान की है, लेकिन भारी संकेंद्रण एक भू-राजनीतिक साझेदार पर बहुत अधिक निर्भरता की कमज़ोरी को भी रेखांकित करता है। प्रतिस्थापन नहीं, बल्कि विविधीकरण ही संप्रभुता की असली मुद्रा है।

वित्त वर्ष 2023-24 में, भारत का व्यापारिक आयात 677 अरब डॉलर रहा। इसमें से, अकेले कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का आयात लगभग 170 अरब डॉलर या कुल आयात बिल का 25% से ज़्यादा था। विदेशी मुद्रा का यह प्रवाह रुपये पर दबाव डालता है, व्यापार घाटा बढ़ाता है और व्यापक आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करता है।

जून 2025 में, इज़राइल और ईरान के बीच तनाव के बाद दुनिया एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष से बाल-बाल बच गई। अगर वह राख बिंदु प्रज्वलित होता, तो वैश्विक तेल आपूर्ति प्रतिदिन 2 करोड़ बैरल से ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाती। ब्रेंट क्रूड की कीमतें, जो पहले से ही संवेदनशील थीं, कुछ ही दिनों में 103 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर सकती थीं। युद्ध शुरू तो नहीं हुआ, लेकिन दुनिया इतनी क़रीब पहुँच गई कि उसे याद आ गया कि उसकी ऊर्जा जीवनरेखाएँ कितनी नाज़ुक हैं।

दुनिया को बदलने वाले फ़्लैशपॉइंट वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा अप्रत्याशित झटकों से बदल गई है।

क्षण.

सबसे पहले, 1973 का तेल प्रतिबंध। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर अरब तेल प्रतिबंध के कारण कच्चे तेल की कीमतें चौगुनी हो गईं और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन पर पश्चिम की अत्यधिक निर्भरता उजागर हो गई। लेकिन इसने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, दक्षता संबंधी अधिदेश और विविध स्रोत रणनीतियों के निर्माण को भी गति दी।

दूसरा, 2011 फुकुशिमा परमाणु आपदा। जापान में सुनामी से प्रेरित परमाणु विगलन ने परमाणु ऊर्जा में वैश्विक विश्वसनीयता का संकट पैदा कर दिया। हालाँकि, कोयले और गैस के बढ़ते उपयोग के कारण बढ़ते उत्सर्जन के साथ, परमाणु ऊर्जा फिर से लोकप्रिय हो रही है।

तीसरा, 2021 का टेक्सास फ्रीज। अत्यधिक ठंड ने ऊर्जा-समृद्ध टेक्सास में गैस पाइपलाइनें जमा दीं और पवन टर्बाइनों को निष्क्रिय कर दिया। इस घटना ने लागत-कुशलता के बजाय लागत-कुशलता के लिए बनाए गए सिस्टम की सीमाओं को रेखांकित किया।

लचीलेपन और विविधतापूर्ण तथा मौसम-रोधी बुनियादी ढांचे के महत्व से अधिक महत्वपूर्ण है।

चौथा, 2022 का रूस-यूक्रेन युद्ध। रूस द्वारा ऊर्जा को हथियार बनाने के बाद, यूरोप की अपनी 40% से ज़्यादा गैस के लिए रूस पर निर्भरता अचानक खत्म हो गई। महाद्वीप को तरल प्राकृतिक गैस की रिकॉर्ड कीमतों और कोयले के पुनरुत्थान का सामना करना पड़ा। यह एक कठोर सबक था: कोई भी ऊर्जा रणनीति संप्रभु नहीं होती अगर उसका स्रोत एक ही हो।

पांचवां, 2025 इबेरियन प्रायद्वीप ब्लैकआउट। स्पेन और पुर्तगाल में, बिना पर्याप्त प्रेषण योग्य बैकअप के, रुक-रुक कर आने वाली नवीकरणीय ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भरता के कारण ग्रिड ध्वस्त हो गया। ग्रिड में जड़ता की कमी ने पारंपरिक क्षमता को बहुत तेज़ी से समाप्त करने के जोखिमों को उजागर किया। ये घटनाएँ हमें याद दिलाती हैं कि वैश्विक ऊर्जा चिंतन में हर प्रमुख मोड़ के बाद एक विफलता आई है। अब हमारे सामने बल प्रयोग के बजाय दूरदर्शिता से बदलाव करने का अवसर है - और इज़राइल-ईरान संघर्ष विराम वह अवसर है।

वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन की तमाम बयानबाज़ियों के बावजूद, असली तस्वीर चिंताजनक है। जीवाश्म ईंधन अभी भी वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा माँग का 80% से ज़्यादा पूरा करते हैं। 90% से ज़्यादा परिवहन हाइड्रोकार्बन पर चलता है। सौर और पवन ऊर्जा, हालाँकि तेज़ी से बढ़ रही हैं, फिर भी वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में इनका योगदान 10% से भी कम है।

तेल और गैस की माँग ऊँची बनी रहने के बावजूद, अन्वेषण निवेश में भारी गिरावट आई है। इसका नतीजा यह है कि आपूर्ति ढाँचे की दृष्टि से सीमित है और मामूली झटकों से भी प्रभावित हो सकती है।

ऊर्जा यथार्थवाद को परिवर्तन का मार्गदर्शन करना चाहिए। ऊर्जा यथार्थवाद परिवर्तन को अस्वीकार नहीं करता। यह उसे सक्षम बनाता है। इसका अर्थ है यह समझना कि परिवर्तन मार्ग हैं, स्विच नहीं। इन सभी बिंदुओं से सीख स्पष्ट है। ऊर्जा सुरक्षा अब जलवायु नीति पर चर्चा का विषय नहीं रह गई है।

यह एक जीवित रहने की रणनीति है।

भारत को अब निर्णायक रूप से एक ऐसे ऊर्जा संप्रभुता सिद्धांत की ओर बढ़ना होगा जो घरेलू क्षमता, विविध तकनीक और लचीली प्रणालियों पर आधारित हो। इसके पाँच आधारभूत स्तंभ हैं।

पहला, कोयला गैसीकरण और स्वदेशी ऊर्जा का विकास। भारत में 150 अरब टन से ज़्यादा कोयला भंडार हैं। दशकों से, राख की उच्च मात्रा के कारण ये भंडार अनाकर्षक रहे हैं। लेकिन गैसीकरण और कार्बन कैप्चर में तकनीकी प्रगति के साथ, इस घरेलू संसाधन का उपयोग सिंथेटिक गैस, मेथनॉल, हाइड्रोजन और उर्वरकों के उत्पादन के लिए किया जाना चाहिए। हमें नवाचार के ज़रिए राख की बाधा को दूर करना होगा।

> भारत को चाहिए कि अब कार्य करें कल का सबसे कीमती संसाधन तेल नहीं, बल्कि निर्बाध, किफायती और स्वदेशी ऊर्जा है

दूसरा, जैव ईंधन या जहां ग्रामीण सशक्तिकरण राष्ट्रीय सुरक्षा को पूरा करता है। इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ने पहले ही कच्चे तेल के आयात को कम कर दिया है और किसानों को ₹92,000 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। E20 के क्षितिज पर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वार्षिक आय बढ़ सकती है।

आगे। किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प (SATAT) योजना के माध्यम से, सैकड़ों संपीड़ित बायोगैस (CBG) संयंत्र स्वच्छ ईंधन उत्पन्न कर रहे हैं और 20%-25% कार्बनिक कार्बन युक्त जैविक खाद का उत्पादन कर रहे हैं। इससे उत्तर भारत की क्षरित मिट्टी को पुनर्जीवित किया जा सकता है, जहाँ कार्बनिक कार्बन 2.5% के स्वस्थ स्तर की तुलना में घटकर 0.5% रह गया है। मृदा स्वास्थ्य में सुधार से जल और उर्वरक धारण क्षमता भी बढ़ती है, जिससे कीचड़ और प्रदूषण कम होता है।

तीसरा, परमाणु ऊर्जा या शून्य-कार्बन बेसलोड, एक प्रेषण योग्य भविष्य के लिए। भारत का परमाणु पदचिह्न बहुत लंबे समय से 8.8 गीगावाट पर स्थिर बना हुआ है। हमें थोरियम रोडमैप को पुनर्जीवित करना होगा, यूरेनियम साझेदारी सुनिश्चित करनी होगी और लघु मॉड्यूलर रिएक्टर प्रौद्योगिकियों का स्थानीयकरण करना होगा। नवीकरणीय ऊर्जा के प्रभुत्व वाले ग्रिड में, परमाणु ऊर्जा प्रेषण योग्य आधार प्रदान करती है।

चौथा, हरित हाइड्रोजन, या 'तकनीक अपनाएँ, श्रृंखला सुरक्षित करें'। भारत का 2030 तक प्रति वर्ष पाँच मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य स्थानीय इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण, उत्प्रेरक विकास और भंडारण प्रणालियों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। लक्ष्य केवल हरित हाइड्रोजन नहीं है। यह संप्रभु हाइड्रोजन है।

पाँचवाँ, पंप हाइड्रो स्टोरेज या जड़त्व की रीढ़। पंप हाइड्रो टिकाऊ, सिद्ध और ग्रिड संतुलन के लिए आवश्यक है। यह नवीकरणीय ऊर्जा का पूरक है और पवन व सौर ऊर्जा-प्रधान प्रणालियों में अनुपस्थित जड़त्व प्रदान करता है। भारत को भविष्य के भंडारण ढाँचे के निर्माण के लिए अपनी स्थलाकृति का उपयोग करना चाहिए। कुछ वर्ष पहले तक, भारत अपने कच्चे तेल का 60% से अधिक पश्चिम एशिया से प्राप्त करता था। एसएंडपी ग्लोबल कमोडिटीज़ एट सी के अनुसार, यह आंकड़ा अब 45% से कम है। यह कोई अल्पकालिक समाधान नहीं है, बल्कि भारत की सोर्सिंग रणनीति में एक जानबूझकर दीर्घकालिक बदलाव को दर्शाता है।

संप्रभुता का युग: इज़राइल-ईरान युद्धविराम

भारत को बिना किसी नुकसान के कार्य करने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। भारत को ऊर्जा यथार्थवाद के साथ नेतृत्व करना चाहिए - एक विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि लचीलेपन और संप्रभुता की नींव के रूप में। इसने अपने स्रोतों में विविधता लाई है, होर्मुज पर निर्भरता कम की है, और पहले से कहीं बेहतर ढंग से काम किया है। अब इस बदलाव को और गहरा करने का समय आ गया है क्योंकि हो सकता है कि अगला संकट इसे चेतावनी देने का अवसर भी न दे।

21वीं सदी की पहचान नई तेल खोजों से नहीं होगी। इसकी पहचान उन देशों से होगी जो बिना किसी भय या पक्षपात के अपनी ऊर्जा को सुरक्षित, संग्रहीत और बनाए रख सकते हैं। भारत की रणनीति में महत्वाकांक्षा और यथार्थवाद का मिश्रण होना चाहिए। पाँच स्तंभ - कोयला गैसीकरण, जैव ईंधन, परमाणु ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और पंप हाइड्रो - ऊर्जा परिवर्तन के लिए गौण नहीं हैं। ये इसकी संप्रभु रीढ़ हैं।

कल का सबसे कीमती संसाधन तेल नहीं है। यह निर्बाध, किफायती और स्वदेशी ऊर्जा है। इसे विकसित करने का यही समय है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

भारत की प्रवेश परीक्षा प्रणाली को शुद्ध करना

विपुल अनेकांत

डिप्टी है आयुक्त पुलिस, दिल्ली पुलिस

भूमि गोयल

अर्थशास्त्र का स्नातक छात्र है,

यीशु और मरियम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

हर साल भारत में लगभग 70 लाख छात्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई), राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट), कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी), और कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) जैसी प्रवेश परीक्षाओं में स्नातक सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। सीटों की निश्चित संख्या के साथ, प्रतिस्पर्धा तीव्र होती है, जिससे कोचिंग उद्योग और निरंतर दबाव की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। हाल ही में एक प्रमुख जेईई कोचिंग सेंटर की शाखा बंद होने और वित्तीय कदाचार, प्रवर्तन निदेशालय के छापे और छात्रों की आत्महत्या जैसे विवाद एक चरमराई व्यवस्था को उजागर करते हैं। अब समय आ गया है कि स्नातक प्रवेश पर पुनर्विचार किया जाए, निष्पक्षता, समानता और छात्रों के कल्याण को प्राथमिकता दी जाए।

कोचिंग संकट और उसका नुकसान उम्मीदवारों की संख्या इतनी बड़ी है कि अकेले जेईई के लिए 15 लाख छात्र आवेदन करते हैं। इस वजह से कोचिंग का साम्राज्य खड़ा हो गया है। केंद्र दो साल के कार्यक्रमों के लिए 6 लाख से 7 लाख रुपये तक की फीस लेते हैं। 14 साल की उम्र के छात्र इरोडोव और क्रोटोव जैसी किताबों से जटिल समस्याओं को हल करने की थकाऊ दिनचर्या के लिए अपने समग्र विकास को त्याग देते हैं, जो बी.टेक की आवश्यकताओं से कहीं आगे की बात है। यह दौड़-भाग तनाव, अवसाद और अलगाव को जन्म देती है, जिससे किशोरों का सहकर्मी बंधन और सामान्य किशोरावस्था छिन जाती है। कुछ छात्र इस दबाव को झेलने में असमर्थ होने के कारण, कुछ सरकारों ने कोचिंग केंद्रों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए हैं। फिर भी, मूल समस्या प्रवेश परीक्षा प्रणाली में है जो छात्रों को ज़रूरत से ज़्यादा योग्य बनाती है और योग्यता को विकृत करती है।

प्रवेश परीक्षाओं का लक्ष्य 15 लाख छात्रों का चयन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में 18,000 से ज़्यादा सीटों के लिए इच्छुक छात्र तो हैं, लेकिन 12वीं की परीक्षा में 91% या 97% अंक लाने वाले छात्रों, या जेईई में 99.9 पर्सेंटाइल लाने वाले छात्रों के बीच अंतर करना अनुचित है। 12वीं में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में 70%-80% का अच्छा स्कोर, बी.टेक प्रोग्राम के लिए पर्याप्त है। मौजूदा व्यवस्था सीमित सीटों, आवेदकों की विशाल संख्या और कॉलेज की शैक्षणिक गुणवत्ता में असमानताओं के कारण असाधारण प्रदर्शन की मांग करती है, जिससे

> विकल्प यह है कि या तो छात्रों को डराने वाली विषाक्त दौड़ जारी रखी जाए या फिर निष्पक्षता और समान अवसर की प्रणाली अपनाई जाए।

मामूली अंकों के अंतर पर ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर देने वाला एक झूठा पदानुक्रम। यह काबिल छात्रों को दरकिनार कर देता है, कोचिंग का खर्च उठाने वालों को तरजीह देता है, और शहरी-ग्रामीण, लैंगिक और क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ाता है।

इसके परिणाम गंभीर हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से, छात्रों पर भारी दबाव होता है। सामाजिक रूप से, यह व्यवस्था उन धनी परिवारों को विशेषाधिकार देती है जो उच्च-स्तरीय कोचिंग का खर्च उठा सकते हैं, जिससे एक भ्रामक योग्यता-तंत्र का निर्माण होता है। जैसा कि हार्वर्ड के दार्शनिक माइकल सैंडेल तर्क देते हैं, यह कथित व्यक्तिगत श्रेष्ठता के प्रति एक ज़हरीले जुनून को बढ़ावा देता है, जिसमें भाग्य और विशेषाधिकार की भूमिका को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। सैंडेल इन समस्याओं से निपटने के लिए स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश के लिए लॉटरी का सुझाव भी देते हैं।

डच लॉटरी और भारत वैश्विक मॉडलों से प्रेरणा ले सकते हैं।

नीदरलैंड मेडिकल स्कूलों में दाखिले के लिए भारित लॉटरी का उपयोग करता है, जिसकी शुरुआत 1972 में हुई थी और 2023 में इसे फिर से लागू किया गया। न्यूनतम शैक्षणिक सीमा पूरी करने वाले आवेदक लॉटरी में भाग लेते हैं, और उच्च ग्रेड मिलने से उनकी संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। इससे पूर्वाग्रह कम होता है, विविधता को बढ़ावा मिलता है और दबाव कम होता है, क्योंकि यह माना जाता है कि अत्यधिक सटीक मापदंड अक्सर अप्रासंगिक, अनुचित और महंगे होते हैं। परिणाम बताते हैं कि सीमित क्षमता होने पर भी लॉटरी व्यवहार्य होती है, जो सैंडेल की योग्यता-आधारित मूल्यांकन की आलोचना के अनुरूप है।

अधिकता।

चीन में, 2021 की "डबल रिडक्शन" नीति स्कूली विषयों में लाभ के लिए ट्यूशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, वित्तीय बोझ कम करने, असमानताओं को दूर करने और छात्रों की भलाई की रक्षा के लिए कोचिंग संस्थानों का रातोंरात राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इससे भारत के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान हुआ - कोचिंग सेंटरों की अनियंत्रित, अत्यधिक और अव्यवस्थित वृद्धि और युवाओं पर उनका प्रभाव।

इसका समाधान प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाने, स्कूल प्रणाली पर भरोसा करने और छात्रों को अत्यधिक परीक्षाओं से बचाने में निहित है। कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएँ, अपने कठोर पाठ्यक्रम के साथ, बी.टेक की तैयारी का आकलन करने के लिए पर्याप्त हैं। प्रवेश परीक्षाओं के बजाय, भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में, पात्रता के लिए एक निश्चित सीमा तय की जा सकती है। इस सीमा को पूरा करने वाले छात्रों को श्रेणियों (90% और उससे अधिक, 80%-90%) में बांटा जा सकता है और भारित लॉटरी के माध्यम से सीटें या रैंक संख्या आवंटित की जा सकती है, जिसमें डच मॉडल की तरह, मौजूदा आरक्षण नीति के अंतर्गत लिंग, क्षेत्र और ग्रामीण पृष्ठभूमि के लिए आरक्षण शामिल किया जा सकता है। उच्च ग्रेड से संभावनाएँ बढ़ सकती हैं, लेकिन सभी पात्र छात्रों को उचित अवसर मिलेंगे, जिससे गलाकाट प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी।

समानता बढ़ाने के लिए, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ग्रामीण छात्रों के लिए आईआईटी की 50% सीटें लंबवत रूप से आरक्षित की जा सकती हैं, जिससे सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा और संरचनात्मक असमानता कम होगी। यदि प्रवेश परीक्षाएँ जारी रहती हैं, तो कोचिंग पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए या उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए, और मुफ़्त ऑनलाइन अध्ययन सामग्री और व्याख्यान उपलब्ध कराए जाने चाहिए। विविधता को बढ़ावा देने के लिए, आईआईटी एक वार्षिक छात्र विनिमय कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, जिसमें चार वर्षों के दौरान विभिन्न आईआईटी परिसरों में अध्ययन करने के लिए छात्रों का यादृच्छिक चयन किया जा सकता है।

इससे राष्ट्रीय एकीकरण और विविध संस्कृतियों से परिचय को बढ़ावा मिलेगा। आईआईटी के बीच प्रोफेसरों के स्थानांतरण को प्रोत्साहित करने से एक समान शैक्षणिक मानक सुनिश्चित हो सकते हैं, कृत्रिम पदानुक्रम समाप्त हो सकते हैं और किसी भी आईआईटी से बी.टेक की डिग्री के समान मूल्य को सुदृढ़ किया जा सकता है।

आगे की राह: स्नातक प्रवेश परीक्षाओं को लॉटरी-आधारित प्रणाली के लिए समाप्त करने से छात्रों को कोचिंग के बोझ से मुक्ति मिलेगी, जिससे वे स्कूल जा सकेंगे, खेलों में भाग ले सकेंगे और समग्र रूप से विकसित हो सकेंगे। इससे वित्तीय बाधाएँ कम होंगी और हर योग्य छात्र, चाहे उसकी संपत्ति या विशेषाधिकार कुछ भी हों, शीर्ष संस्थानों में प्रवेश पा सकेगा।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे युवा युवा ही रहेंगे, न कि वे प्रतिशत के पीछे भागने वाली मशीनें बन जाएंगे और बहुत कम उम्र में ही बहुत गंभीर हो जाएंगे।

भारत की शिक्षा व्यवस्था के सामने एक विकल्प है: छात्रों और समाज पर ज़हर छिड़कने वाली ज़हरीली दौड़ जारी रखना या फिर निष्पक्षता, विवेक, समतावाद और समान अवसर को अपनाना। रास्ता साफ़ है।

व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं

संपादक के नाम चिठी

वाशिंगटन का तीखा हमला: व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो का यह बेशर्मी भरा दावा कि यूक्रेन संघर्ष "मोदी का युद्ध" है, कपट और बौद्धिक खोखलेपन से भरा है (मुख्य पृष्ठ, 29 अगस्त)। इस युद्ध की जड़ें रूस की रणनीतिक असुरक्षाओं और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NTA) के अथक पूर्व की ओर दुस्साहस में गहराई से निहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह के युद्ध में घसीटकर।

यूरोपीय युद्धक्षेत्र संकट,

श्री नवारो ने वाशिंगटन के चिरकालिक दोहरे मानदंडों को उजागर कर दिया है -

अपनी गलत गणनाओं को छुपाते हुए

एक ऐसे राष्ट्र को बदनाम करना जो अधीनता स्वीकार नहीं करता। भारत ने न तो इस त्रासदी को बढ़ावा दिया है और न ही इससे लाभ उठाया है। उसने लगातार बातचीत, तनाव कम करने और संतुलन की वकालत की है।

श्री नवारो की लापरवाह बयानबाजी सच्चाई की अभिव्यक्ति कम और एक उभरती हुई शक्ति को बलि का बकरा बनाने का हताशापूर्ण प्रयास अधिक है।

इस तरह के झूठ भारत के स्वतंत्र रुख का अपमान करते हैं, साथ ही अमेरिका की विदेश नीति के नैतिक दिवालियापन को उजागर करते हैं।

एन. सदाशिव रेड्डी, बेंगलुरु

क्षमता का पोषण

अपने लेख, "भारत के भविष्य के लिए खेल-आधारित शिक्षा" में (राय पृष्ठ, 27 अगस्त), केंद्रीय मंत्री

महिलाएं और बच्चे

भारत सरकार के विकास ने मस्तिष्क उत्तेजना के लिए अपना मामला प्रस्तुत किया है

और खेल-आधारित शिक्षा अच्छी तरह से। 1975 में अपनी स्थापना के बाद से, एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) का अभाव रहा है। उस समय, विज्ञान जीवन के पहले 1,000 दिनों, मस्तिष्क उत्तेजना के लिए स्वर्णिम काल, के महत्व के बारे में इतना आश्वस्त नहीं था। तीन साल से कम उम्र के बच्चों के पोषण के साथ-साथ पर्याप्त देखभाल और उत्तेजना सुनिश्चित करके, उनका इष्टतम विकास होगा।

मस्तिष्क की क्षमता. नवचेतना ईसीसीई के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण है जिसका उपयोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और तीन साल से कम उम्र के बच्चों की निजी देखभाल करने वालों द्वारा नियमित रूप से घर पर किया जा सकता है। इसका उपयोग केवल गृह भ्रमण के दौरान माताओं को सलाह देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

अंत में, स्टाफ के वेतन के लिए सामुदायिक योगदान पर विचार किया जा सकता है, जैसा कि छत्तीसगढ़ के फुलवारी में प्रदर्शित किया गया था।

डॉ. के.आर. एंटनी, कोच्चि, केरल

हाल ही में एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा और जारी की गई उत्तर-कुंजी ने व्यवस्थागत खामियों को उजागर किया है जिनकी तत्काल जाँच की आवश्यकता है। अधिकांश प्रश्न जटिल और खराब तरीके से तैयार किए गए थे।

अभ्यर्थियों को तकनीकी एवं तार्किक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा।

नवीन कुमार सिंह, नई दिल्ली

letters@thehindu.co.in पर भेजे गए पत्रों में डाक पता अवश्य होना चाहिए।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • शनिवार • 30 अगस्त • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

समय से पूर्व की परिपक्वता अच्छी नहीं होती, चाहे वह किसी वृक्ष की हो या व्यक्ति की और उसकी हानि आगे चल कर भुगतनी ही होती है।

-नेताजी सुभाष चंद्र बोस

काशी, मथुरा और संघ

आरएसएस प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने स्पष्ट कहा है कि राम मंदिर एकमात्र ऐसा आंदोलन था, जिसका संघ ने समर्थन किया था और अब काशी और मथुरा सहित ऐसे किसी अन्य अभियान का समर्थन नहीं करेगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अपनी तीन दिवसीय व्याख्यान शृंखला के अंतिम दिन सवालों के जवाब में भागवत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरएसएस के स्वयंसेवक ऐसे आंदोलनों में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं। हिन्दू समाज आग्रह करेगा तो संघ के स्वयंसेवक संस्कृति और समाज के हिसाब से इस प्रकार के किसी अभियान में शिरकत कर सकते हैं। यह व्याख्यान शृंखला आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। देश में रोजगार परिदृश्य, संस्कृत की विषय के रूप में अनिवार्यता, भारत की अखंडता,

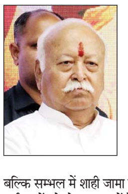

हिन्दू-मुस्लिम एकता, जाति-वर्ण व्यवस्था, जातिगत आरक्षण, भाषा विवाद, भाजपा अध्यक्ष के चयन में विलंब, एक तय आयु में संन्यास जैसे तमाम मुद्दों पर भी संघ प्रमुख ने अपनी बात कही। जहां तक काशी-मथुरा में धर्म स्थल का मसला है, तो यह मामला कोई नया नहीं है, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के चलते इसे हिन्दुत्ववादियों ने थोड़े समय के लिए विराम दे रखा था। राममंदिर का निर्माण पूरा होते ही वे हरकत में आ गए। न केवल काशी-मथुरा, बल्कि सम्भल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के मुद्दे के साथ ही अन्य अनेक धर्मस्थलों को लेकर मामलों ने भी जोर पकड़ लिया। बीते साल 24 नवम्बर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। हिंसा मामले की जांच के लिए बने आयोग ने बृहस्पतिवार को ही अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे दंगों के बाद तुष्टीकरण की राजनीति के चलते बड़े पैमाने पर आबादी में बदलाव, धर्म परिवर्तन और समुदाय विशेष के परिवारों का पलायन हुआ। बेशक, संघ प्रमुख पहले भी कह बार स्पष्ट कर चुके हैं कि हर जगह मंदिर नहीं ढूंढ़ा जाना चाहिए। लेकिन लगता नहीं कि धर्मस्थलों में मंदिर ढूंढे जाने की कवायद थम पाएगी। दरअसल, यह मसला बहुत पहले से धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक हो चुका है। मंदिर-मस्जिद-चर्च जैसे धर्मस्थलों के मुद्दे गरमाने लगते हैं, तो अलग माहौल बना देते हैं, जिसके बल पर पक्ष-विपक्ष को अपनी राजनीति को धार देने में सहूलियत होती है। इसलिए ऐसे मुद्दे गरमाए रहने हैं।

सबक लेना जरूरी

देश में प्रति दिन औसतन 86 रेप होते हैं। यह संख्या वह है, जो पुलिस के रिकार्ड में दर्ज की जाती है। हर दिन होने वाले ढेरों रेप या रेप के प्रयास, हिंसक छेड़छाड़ और अभद्रता की संख्या का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट व सूचकांक-2025 के अनुसार दिल्ली समेत पटना, जयपुर, कोलकाता, श्रीनगर, रांची व फरीदाबाद महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित हैं जबकि मुंबई, कोहिमा, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम व गंगटोक सबसे सुरक्षित। कोहिमा व अन्य सुरक्षित शहरों में महिलाओं को ज्यादा समानता, नागरिक भागीदारी, बेहतर पुलिस व्यवस्था व अनुकूल बुनियादी ढांचा बताया जा रहा है। यह सर्वेक्षण देश के इक्तीस शहरों की बारह हजार 770 महिलाओं पर किया गया। दस में से छह महिलाओं ने खुद को अपने शहर में सुरक्षित बताया जबकि 40% ने ज्यादा सुरक्षित नहीं या असुरक्षित माना। करीब

91% महिलाएं कार्यस्थल पर खुद को सुरक्षित बता रही हैं। 7% महिलाएं मानती हैं कि सार्वजनिक स्थल पर उन्होंने बीते वर्ष उत्पीड़न झेला। हालांकि हर तीन में से दो महिलाएं उत्पीड़न की शिकायत नहीं करतीं। 29% सार्वजनिक परिवहन में और 38% पड़ोस में उत्पीड़न का शिकार होती हैं। जिन शहरों में बेहतर बुनियादी ढांचे की कमी है, वहां महिलाएं ज्यादा असुरक्षित हैं। स्वीकार करना होगा कि असुरक्षित महसूस करने वाली जगहों के नागरिकों की शिक्षा, सोच व संस्थागत जवाबदेही का कमजोर होना प्रमुख कारण हैं। हालांकि सवा अरब की आबादी में पौने तेरह हजार महिलाओं पर अध्ययन नाममात्र ही कहा जाएगा। ऐसे अध्ययनों में कुछ लाख नागरिकों को शामिल किया जाना चाहिए। रस्मादायगी के तौर पर सर्वेक्षण समाज या देश के लिए हितकारी नहीं कहे जा सकते। इनके निष्कर्षों के अनुसार कदम उठाए जाने चाहिए। राज्य सरकारों, महिला आयोग जैसी संस्थाओं पर कड़ाई रहनी चाहिए। पितृसत्तात्मक बर्ताव, स्त्री उपेक्षा व लैंगिक विभेद के प्रति नागरिकों को जागरूक करना होगा। आंकड़ों को प्रकाशित/प्रसारित करने भर की रस्म से सुधार संभव नहीं हैं। जमीनी स्तर पर भी गंभीरतापूर्वक काम होना चाहिए। रेप, छेड़छाड़, व्यभिचार को असुरक्षा की स्थिति से अलग नहीं किया जा सकता। सोच और रवैया, दोनों बदलने के साथ ही संबंधित विभागों, पुलिस और प्रशासन को जिम्मेदार बनाना भी जरूरी है।

कटाक्ष/ कबीरदास

अब शॉल नहीं ओढ़ाएंगे!

तो मोदी जी को पचहत्तर साल वाला शॉल ओढ़ाने का प्रोग्राम कैंसिल! थैंक यू भागवत जी, सारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए। शुक्र है, आपने वक्त रहते साफ कर दिया कि पचहत्तर साल वाला शॉल आप न खुद ओढ़ेंगे और न किसी को और को ओढ़ाने देंगे। किसी और को ओढ़ाना देना तो दूर, किसी को ओढ़ने की सलाह भी नहीं देंगे। वर्ना जब से आपने पचहत्तर साल वाला शॉल ओढ़ने-ओढ़ाने की सलाह दी थी, सुनने में आया था कि मार्गदर्शक मंडल में हड़कंप मचा हुआ था।

अडवाणी जी, जोशी जी तय नहीं कर पा रहे थे कि नये प्रवेशार्थी की रैगिंग की तैयारी करें या पुष्प गुच्छ से स्वागत की। और हड़कंप नागपुर छाप भगवा पार्टी में भी मचा हुआ था। जितने चेहरे टीवी पर, उतनों की ही दावेदारी। योगी जी तो पहले ही दरवाजे के पीछे से झांक रहे थे-अंदर आ जाऊं। शाह जी पहले ही आधे दरवाजे के अंदर थे-नंबर दो। पचहत्तर साल के शॉल का ख्याल कर के, दिल पर पत्थर रख कर अगला कदम उठाने को तैयार, वर्ना वह तो नंबर दो में ही खुश थे। उधर, गडकरी जी वाया नागपुर दिल्ली के लिए अलग ही हाईवे बनाते हुए संतई की मुद्रा में-संघ की कुर्सी, संघ दे तो उसका भला और नहीं भी दे, तो भी उसका भला! पर भागवत जी ने सब के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पचहत्तर साल पर शॉल ओढ़ाने का प्रोग्राम ही कैंसल करा दिया। न खुद पचहत्तर साल वाला शॉल ओढ़ेंगे और न किसी को मोदी जी को शॉल ओढ़ाने देंगे। भागवत भी स्वयंसेवक और मोदी जी भी स्वयंसेवक। और स्वयंसेवक के लिए न टायरमेंट और न रिटायरमेंट! अगली पीढ़ी के लिए जगह खाली करने का तो खैर कोई सवाल ही नहीं उठता है। भागवत जी की पचहत्तर साल का शॉल ओढ़ने-ओढ़ाने की पिछले महीने की जिस बात को लोग ले उड़े थे, असल में मोदी जी के विरोधियों की मिसअंडरस्टेंडिंग थी। भागवत जी, मोदी जी जैसे स्वयंसेवकों को नहीं, अडवाणी जी जैसे भूतपूर्व-स्वयंसेवकों को पचहत्तर की उम्र वाला शॉल ओढ़ाए जाने की बात कर रहे थे, ताकि उनका रिटायरमेंट पक्का हो जाए। और हां, शॉल नहीं ओढ़ाएंगे की तुक, डिग्री नहीं दिखाएंगे से जोड़ने की कोशिश कोई नहीं करे। न पहले और न आज, डिग्री दिखाने की बात तो भागवत जी ने कभी भी नहीं कही। कागज प्रजा दिखाती है, चक्रवर्ती सम्राट नहीं।

बदलती भू-राजनीतिक स्थिति

सामयिक

डॉ. सुरेन्द्र कुमार मिश्र

यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि राजनीति तथा कूटनीति में कोई स्थायी मित्र एवं स्थायी शत्रु नहीं होता। जैसा कि आखिरकार, अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लागू करने की योजना का विवरण देते हुए नोटिस जारी किया जिससे अमेरिका को भारत के लगभग 48 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के निर्यात पर प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा। अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाना उसके दबाव, दमन एवं दादागिरी का ही अविवेकपूर्ण निर्णय कहा जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप की इस टेढ़ी चाल अथवा टैरिफ टेरर से अमेरिकी अर्थशास्त्री, रणनीतिकार एवं राजनेता तक हतप्रभ हैं। अमेरिका के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी चीन के प्रति आकस्मिक प्रेम का उभार आखिरकार, वैश्विक व्यवस्था की भू-राजनीति की दिशा को किस ओर ले जाएगा?

भारत एवं चीन एशिया की दो सबसे प्रमुख शक्तियां हैं, जो वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा सामरिक संतुलन स्थापित करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। तियानजिन (चीन) में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का शिखर सम्मेलन इस संगठन के इतिहास का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी सहभागिता कर रहे हैं। पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितम्बर तक चीन में रहेंगे। एससीओ की शिखर बैठक के साथ ही अनेक द्विपक्षीय बैठकों में भी भाग लेंगे। इनमें ट्रंप के टैरिफ का तोड़ भी तय हो सकने की संभावना है। चीन भली-भांति जानता है कि अस्थिर सोच वाले डोनाल्ड ट्रंप की अगली चाल क्या होगी? अतः अमेरिकी आर्थिक व्यवस्था का मुकाबला करने के लिए चीन भी अपनी नई पैंतरेबाजी तैयार करने में चूकेगा नहीं।

अमेरिका को भी पता है कि भारत और चीन को एक साथ अपना व्यापारिक दुश्मन बनाना खतरे से खाली नहीं है। चीन-रूस मित्रता की बात जगजाहिर है ही, जिससे चीन पर नकेल लगाने की चाल में अमेरिका चूक नहीं करेगा। चीन-पाकिस्तान मित्रता को भी अमेरिका तोड़ने के लिए अपना आर्थिक हस्तक्षेप करने के कथकंडे अपना रहा है। चतुर चीन के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अमेरिका फूंक-फूंक कर कदम उठा रहा है। अमेरिका का दोहरा चरित्र जगजाहिर हो चुका है। एक ओर चीन पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ भारत क्वाड का हिस्सा बन कर समुद्री सुरक्षा और चीन की विस्तारवादी नीति का संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है, तो दूसरी ओर चीन के साथ आर्थिक व्यापार पर चुप्पी भी मार रखी है, जबकि चीन के विरुद्ध न केवल

जोरदार गर्जना की थी, बल्कि दुनिया का सबसे दुष्ट देश भी कहा था। चीन रूस से सबसे अधिक तेल खरीदता रहा है जो अमेरिकी विदेश नीति के खिलाफ नहीं नजर आया। इसका सरल सा जवाब है कि अब ट्रंप के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि चीन पर भी भारत की भांति टैरिफ लगा सकें। इसी कारण डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी तरह-तरह के तमाम कुतर्क कर रहे हैं। रूस से तेल खरीद तो बहाना मात्र है, ट्रंप को भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का झूठा श्रेय भारत द्वारा न देना, उनकी हां में हां न मिलाना, ट्रंप को रास नहीं आया।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस टैरिफ को अनुचित, अन्यायपूर्ण और असंगत करार देते हुए देश को स्वदेशी अपनाने और देशवासियों में आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ाने में विशेष बल दिया है। सरकार ने 40 विदेशी बाजारों जैसे-जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोप, यूके तथा मध्य पूर्व आदि की ओर निर्यात विविधीकरण की पहल कर दी है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है ताकि अपने आयात को सीमित करके निर्यात में वृद्धि की जा सके। टैरिफ भारत के लिए आपदा भी है, और अवसर भी है, जहां आत्मनिर्भरता, डिजिटल व्यापार और वैश्विक समझौतों के माध्यम से उभरती शक्तियों में अग्रणी बना जा सकता है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट रूप से कहा है-राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया के साथ व्यवहार करने का तरीका पारंपरिक तरीके से बहुत अलग है। संपूर्ण विश्व इस स्थिति का सामना कर रहा है। हमने ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं देखा जिसने वर्तमान राष्ट्रपति की तरह सार्वजनिक रूप से विदेश नीति का संचालन किया हो। यह अपने आप में ऐसा बदलाव है जो भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका को पता होना चाहिए कि भारत अमेरिका को घुड़की देने मात्र के लिए अपने निर्णय पर नहीं अड़ा है, बल्कि दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के प्रति दृढ़संकल्प भी है।

ट्रंप की टैरिफ नीति से आर्थिक-व्यापारिक स्थिति में ही बदलाव नहीं आएगा, बल्कि इसके प्रभाव से भू-राजनीतिक, भू-आर्थिक एवं भू-सामरिक स्थितियां भी बदलेंगी। चूंकि अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति बढ़ता लगाव और वहां के आईएसआई प्रमुख रहे और नये नवेले फील्ड मास्टर आसिम मुनीर जैसे लोगों के साथ साठ-गांठ, चीन के साथ टैरिफ बढ़ाने के मामले में चुप्पी, यूक्रेन को युद्ध भुगतने की धमकी, रूस के साथ अलास्का समझौते जैसे अनेक सामुयिक मुद्दे, भू-राजनीतिक स्थितियां बदलने की राह दिखा रहे हैं। कहा जा सकता है कि भारत एवं चीन के साथ संबंध सुधरते हैं, या बेहतर हो जाते हैं, तो 'ग्लोबल साउथ' मजबूत होगा।

ट्रंप का टैरिफ टेरर विश्व को नई भू-राजनीति की ओर मोड़ रहा है। वस्तुस्थिति यह है कि टैरिफ लागू होने के बाद वैश्विक गठबंधनों में पुर्नसंतुलन शुरू हुआ है, और भारत व चीन जैसे परंपरागत प्रतिद्वंद्वी भी अमेरिकी नीतियों का विरोध करने के लिए साथ आ रहे हैं। चीन ने हाल के महीनों में भारत के साथ न केवल दोस्ती बढ़ाई है, बल्कि लिपुलेख दर्रे के माध्यम से दोबारा व्यापार शुरू करने में भी सक्रिय सहायता की। बदलते टैरिफ ने बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है, जिसमें भारत, चीन और रूस जैसे पश्चिमी देशों के विकल्प बन रहे हैं। भारत और चीन की बढ़ती नजदीकी स्थायी या अस्थायी होगी, यह तो भविष्य में ज्ञात होगा, किंतु ट्रंप की टैरिफ नीति ने साबित कर दिया है कि आर्थिक निर्णयों का प्रभाव व्यापार तक ही नहीं होता, बल्कि वैश्विक गठबंधनों तक जाता है।

(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)

ट्रंप का टैरिफ टेरर विश्व को नई भू-राजनीति की ओर मोड़ रहा है। टैरिफ लागू होने के बाद वैश्विक गठबंधनों में पुर्नसंतुलन शुरू हुआ है, और भारत व चीन जैसे परंपरागत प्रतिद्वंद्वी अमेरिकी नीतियों का विरोध करने के लिए साथ आ रहे हैं। चीन ने हाल के महीनों में भारत के साथ न केवल दोस्ती बढ़ाई है, बल्कि लिपुलेख दर्रे के माध्यम से दोबारा व्यापार शुरू करने में भी सक्रिय मदद की। बदलते टैरिफ ने बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था हेतु मार्ग प्रशस्त कर दिया है

शरीर और मन, दोनों के लिए वरदान है

इंडियन जिनसेंग

- आयुर्वेद की प्राचीन औषधि अश्वगंधा, जिसे इंडियन जिनसेंग या इंडियन विंटर चेरी (विथानिया सोम्नीफेरा) के नाम से भी जाना जाता है, शरीर और मन, दोनों के लिए वरदान है। आयुष मंत्रालय के अनुसार, यह औषधीय पौधा तनाव कम करने, इम्यूनिटी बढ़ाने और शारीरिक ऊर्जा बढ़ाने में कारगर है। इसकी जड़ों की घोड़े जैसी गंध होने के कारण इसे अश्वगंधा नाम मिला
- यह भारत, मध्य पूर्व और अफ्रीका में पाया जाने वाला बारहमासी पौधा है। आयुर्वेद में बताया गया है कि अश्वगंधा के चूर्ण को गर्म दूध में मिला कर शहद या गुड़ के साथ ले सकते हैं
- हालांकि, हेल्थ एक्सपर्ट्स कुछ लोगों को सावधानी से इसका सेवन करने की सलाह भी देते हैं

(मीडिया इनपुट्स)

लोग यह गलत सोच रहे हैं कि अभी ट्रंप को करीब साढ़े तीन साल और झेलना होगा। अगले साल नवम्बर में कांग्रेस के मध्यावधि चुनाव होंगे जिनमें अमेरिकी संसद में रिपब्लिकन पार्टी का मामूली बहुमत खिसक सकता है यानी करीब 14 महीनों में ही ट्रंप की नीतियों पर अंकुश लगने की स्थिति बन सकती है।

मिन्हाज मर्चेंट, टिप्पणीकार
@MinhazMerchant

तबाही की वजह तलाशनी जरूरी

बाढ़ से तबाही | रोहित कौशिक

बारिश और बाढ़ के कारण भारत के कई राज्यों में भारी तबाही हुई है। एक तरफ नदियां उफान पर हैं, तो दूसरी तरफ पहाड़ टूट रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से बारिश का कहर जारी है। मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ के कारण जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। देश के अनेक हिस्सों में बाढ़ के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कई जगहों पर भारी बारिश के कारण स्थिति खराब हो गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कई जगहों पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से पार पहुंचने के कारण हालात खराब हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से भूस्खलन होने के कारण कई सड़कें बंद हैं। त्रिपुरा में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और नगालैंड में भी यही हाल हैं।

भारी बारिश की वजह से देश के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात हैं। विकास परियोजनाओं के लिए जिस तरह जंगलों को नष्ट किया गया, उसने स्थिति को और भयावह बना दिया है। इसके कारण मानसून तो प्रभावित हुआ ही, भू-क्षरण एवं नदियों द्वारा कटाव किए जाने की प्रवृत्ति भी बढ़ी। बाढ़-सूखा जमाने से जीवन को परेशानी में डालते रहे हैं। बाढ़-सूखा प्राकृतिक आपदाएं भर नहीं हैं, बल्कि प्रकृति की चेतावनियां भी हैं। सवाल है कि क्या हम पढ़-लिख लेने के बावजूद प्रकृति की चेतावनियों को समझ पाते हैं। विडम्बना ही है कि पहले से अधिक पढ़े-लिखे समाज में प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठा कर जीवन जीने की समझदारी अभी भी विकसित नहीं हो पाई है। बाढ़-सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं पहले भी आती थीं लेकिन उनका अपना अलग शास्त्र और तंत्र था। इस दौर में मौसम विभाग की भविष्यवाणियों के बावजूद हम बाढ़ का पूर्वानुमान नहीं लगा पाते। दरअसल, प्रकृति के साथ जिस तरह का व्यवहार हम कर रहे हैं, उसी तरह का व्यवहार प्रकृति भी हमारे साथ कर रही है। पिछले कुछ समय से भारत को जिस तरह सूखे-बाढ़ का सामना करना पड़ा है, वह आईपीसीसी की जलवायु परिवर्तन पर आधारित उस रिपोर्ट का ध्यान दिलाता है, जिसमें जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़-सूखे जैसी आपदाओं की चेतावनी दी गई थी।

आज ग्लोबल वार्मिंग जैसा शब्द इतना प्रचलित हो गया है कि इस मुद्दे पर हम बनी-बनाई लीक पर ही चलना

चाहते हैं। यही कारण है कि कभी हम आईपीसीसी की रिपोर्ट को संदेह की नजर से देखने लगते हैं, तो कभी ग्लोबल वार्मिंग को अनावश्यक हौव्वा मानने लगते हैं। विडंबना ही है कि हम इस मुद्दे पर बार-बार सच से मुंह मोड़ना चाहते हैं। दरअसल, प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा जलवायु परिवर्तन के किस रूप में हमारे सामने होगा, यह नहीं कहा जा सकता। जलवायु परिवर्तन का एक ही जगह पर अलग-अलग असर हो सकता है। यही कारण है कि हम बार-बार बाढ़-सूखे का ऐसा पूर्वानुमान नहीं लगा पाते जिससे लोगों की जान-माल की समय रहते पर्याप्त सुरक्षा हो सके। शहरों और कस्बों में होने वाले जल-भराव के लिए काफी हद तक हम भी जिम्मेदार हैं। पिछले कुछ वर्षों में कस्बों और शहरों में जो विकास और विस्तार हुआ है, उसमें पानी की समुचित निकासी की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। गंदे नालों की पर्याप्त सफाई न हाने से उनकी पानी बहा कर ले जाने की क्षमता लगातार कम हो रही है। यही कारण है कि अधिकतर कस्बों और शहरों में थोड़ी बारिश होने पर ही सड़कों पानी भर जाता है। गौरतलब है कि 1950 में हमारे यहां लगभग ढाई करोड़ हेक्टेयर भूमि ऐसी थी जहां पर बाढ़ आती थी लेकिन अब लगभग सात करोड़ हेक्टेयर भूमि ऐसी है, जिस पर बाढ़ आती है। हमारे देश में केवल चार महीनों के भीतर ही लगभग अस्सी फीसद पानी गिरता है। उसका वितरण इतना असमान है कि कुछ इलाके बाढ़ और बाकी इलाके सूखा झेलने को अभिशप्त हैं।

ऐसी भौगोलिक असमानताएं हमें बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती हैं। पानी का सवाल जैविक आवश्यकता से भी जुड़ा है। हमें यह सोचना होगा कि बाढ़ के पानी का सदुपयोग कैसे किया जाए। बाढ़ के संबंध में विशेषज्ञ चेतावनी देते रहते हैं कि भविष्य में बाढ़ की प्रवृत्ति और प्रकृति लगातार बदलती रहेगी। इसलिए हमें एक तरफ अपने आपदा प्रबंधन तंत्र को सक्रिय बनाना होगा तो दूसरी तरफ अपने पारंपरिक जल स्रोतों पर भी गंभीरता से ध्यान देना होगा। गौरतलब है कि देश में बाढ़ से होने वाले नुकसान का लगभग साठ फीसद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, असम और आंध्र प्रदेश में बाढ़ के माध्यम से होता है। बाढ़ केवल हमारे देश में ही कहर नहीं ढा रही है, बल्कि चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जैसे देश भी इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि हमारे देश में सूखे-बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए अनेक घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन मात्र घोषणाओं के सहारे ही पीड़ितों का दर्द कम नहीं होता है। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इन घोषणाओं का लाभ वास्तव में पीड़ितों तक भी पहुंचे।

(लेख में विचार निजी हैं)

आध्यात्मिक प्रेम | संत राजिन्दर

सभी महान संतों और महापुरुषों ने हमेशा कहा है कि आध्यात्मिक मार्ग पर तेजी से बढ़ने के लिए हमें अपने गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए।

जैसे कि नैतिक जीवन जीना चाहिए, निर्धारित समय तक ध्यान-अभ्यास में बैठना चाहिए, आध्यात्मिक डायरी भरनी चाहिए, अनुशासन का पालन करना चाहिए और आध्यात्मिक सत्संग सुनने चाहिए। लेकिन यदि हम आध्यात्मिकता को अपने जीवन में बिना प्रेम और समर्पण की भावना से अपनाएंगे तो हम रूहानी मार्ग की सच्चाई से अनजान रहेंगे। आध्यात्मिक मार्ग प्रेम का मार्ग है। परमात्मा प्रेम है, हमारी आत्मा परमात्मा का अंश होने के नाते प्रेम है, और परमात्मा के पास वापस जाने का रास्ता भी प्रेम है। इस मार्ग पर चल कर परमात्मा के साम्राज्य में दाखिल होने के लिए हमें जो पासपोर्ट चाहिए वह है 'आध्यात्मिक प्रेम'। हमें यह मार्ग जो तेजी से तय करा सकता है, और इस रास्ते पर जो हमारा मार्गदर्शक हो सकता है, वह है 'जीवित सत्गुरु'। सत्गुरु प्रभु के धाम के वासी होते हैं। उन्हें स्वयं परमात्मा द्वारा भेजा जाता है ताकि जो भी आत्माएं उस अनंत प्रेम के देश में जाना चाहती हैं, वह उनका मार्गदर्शन करें और उन्हें प्रभु के निजधाम वापस ले जाएं। आध्यात्मिक प्रेम ही परमात्मा के साम्राज्य के दरवाजे की सुनहरी चाबी है। इसके बगैर आध्यात्मिक मार्ग तक पहुंचा नहीं जा सकता और न ही कोई आज तक पहुंच पाया है। आध्यात्मिक प्रेम के सही अर्थ, मकसद और उद्देश्य को समझना कोई आसान काम नहीं है। वास्तव में यह आध्यात्मिक प्रेम परमात्मा की तरह ही असीम है, और इसे पूरी तरह समझना हमारी सीमित बुद्धि से परे है। हमारी आत्मा में प्रेम शुरू से ही है क्योंकि सृष्टि की शुरुआत में आत्मा प्रेम के महासागर से एक बूंद के रूप में अलग हुई थी। प्रभु के अनंत साम्राज्य से आने के बाद हम स्थायी शांति और खुशी तब तक नहीं पा सकते, जब तक हम वापस उस स्त्रोत से जुड़ नहीं जाते। सवाल उठता है कि हम इस आध्यात्मिक प्रेम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आध्यात्मिक प्रेम हमारी आत्मा का निज स्वभाव है, लेकिन हमने इसे सही दिशा नहीं दी है। हम इंद्रियों के जरिए इस दुनिया के भोगों-रसों में इतने फंस गए हैं कि हम अपने मन की इच्छाओं द्वारा खिंचे चले जाते हैं।

रीडर्स मेल

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

कर्ज लें पर सोच कर

अपना माल बेचने के लिए जैसे कंपनियां या उत्पाद समूह लोगों को ऑफर देते हैं, वैसे ही आज अनेक कंपनियां या सरकारी बैंक लोगों को कर्ज लेने को ऑफर देते हैं। जो अपने काम या कारोबार के लिए कर्ज लेता है, उसे चुकाने की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। कर्ज कभी भी शान-शौकत के लिए नहीं लेना चाहिए। आज यही हो रहा है। लोग कर्ज जरूरत के लिए नहीं, बल्कि शान-शौकत दिखाने के लिए लेते हैं। अब जिसने कर्ज दिया है, वह तो तकादा करेगा ही। नहीं तो वह मारकूट या प्रताड़ित करके वसूलेगा। इसका परिणाम तो सभी जानते हैं। व्यक्ति इसी तरह प्रताड़ित होकर सुसाइड कर लेता है। अच्छी-खासी जिंदगी यूं ही खत्म कर ली और लोगों में संदेश गया कि ऐसी जलालत की जिंदगी भगवान किसी को न दे। लोग उसके मरने पर गम के आंसू भी नहीं बहाएं। सही व्यक्ति वही है जो कर्ज के मकड़जाल से बचा रहे।

सीमा गुप्ता, बरेली

गलतफहमी में न रहें दुश्मन

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस अनिल चौहान का कहना है कि भारत एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन हम शांतिवादी नहीं हैं। अतः दुश्मन गलतफहमी में न रहें। कारण, देश की सेनाएं हमेशा ही युद्ध के लिए तैयार रहती हैं। उनका कहना है कि शक्ति के बिना शांति एक यूरोपियन धारणा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। 'ऑपरेशन सिंदूर' एक न्यूएज वॉर था, जो आज भी जारी है। महाभारत में युद्ध नीति का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, विशेषकर गीता में। फिर चाणक्य की नीति चाणक्य नीति कहलाती है। अतः कह सकते हैं कि शक्ति उत्साह एवं युक्ति...! ये युद्ध नीति के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण हैं। फिर शस्त्र एवं शास्त्र को एक साथ फॉलो करने की जरूरत है यानी हमारे वर्तमान सीडीएस की बात का अध्धयन किया जाना जरूरी है।

मनमोहन राजावत 'राज', ई मेल से

असली-फर्जी गरीब में भेद जरूरी

28 अगस्त, 2014 को जब प्रधानमंत्री ने जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय) की शुरुआत की थी, तब समृद्ध लोगों ने भी जन धन के अपने बैंक खाते खुलवा लिए थे और जब कोरोनाकाल में केंद्र और राज्य सरकारों ने गरीबों की आर्थिक मदद के लिए बैंक खाते में राशि डालने का ऐलान किया था, खास तौर पर केंद्र सरकार ने महिलाओं के जन धन खाते में लगभग पांच सौ रुपये डालने की कोशिश की थी, तब भी समृद्ध महिलाओं ने अपने जन धन खाते जरूर खुलवाए होंगे? वैसे भी हमारे देश में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं, कुछ सत्ताधारी, राजनेता और सरकारी बाबू समृद्ध लोगों को भी फर्जी गरीब बना ही देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे देश में गरीबों की योजनाओं के फर्जीवाड़े के मामले सुर्खियां न बनते। केंद्र और राज्य सरकारों को गरीबों के लिए चल रही योजनाओं की गहनता से जांच-पड़ताल जरूर करनी चाहिए और भविष्य में भी अगर इस वर्ग के लिए कोई योजना बनाई जाए तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए कठोर कदम जरूर उठाने चाहिए ताकि जरूरतमंद लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और फर्जी गरीबों पर नकेल लग सके।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-35, अंक 16
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **जिया कादरी** द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा तथा 1209-1210, बारहवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित। । **स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र*** ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, **दूरभाष - नोएडा प्रेस** 0120-2444755, 2444756 **फैक्स** - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्

भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

मोहन भागवत का संदेश

दुनिया के सबसे विशाल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक श्री मोहन भागवत जब भी सम्बोधन करते हैं तो उनके शब्दों के गहरे अर्थ होते हैं। उनके संबोधन की सराहना और आलोचना दोनों ही होती हैं लेकिन उनका संदेश इतना स्पष्ट और दो टूक होता है कि जन मानस उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के अवसर पर दिल्ली में आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने संगठन के उद्देश्यों, विचारों और सामाजिक योगदान को सबके सामने रखा। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने काशी-मथुरा आंदोलन, राजनीतिज्ञों के रिटायरमेंट, नई शिक्षा नीति, संघ-भाजपा समन्वय, हिन्दू राष्ट्र और स्वदेशी जैसे विषयों को छुआ। वहीं उन्होंने भाजपा से लेकर विपक्ष तक के आरोपों पर इशारों-इशारों में बहुत कुछ कह दिया। काशी और मथुरा के मामले में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि संघ राम मंदिर आंदोलन से सीधे तौर पर जुड़ा था लेकिन संघ अब किसी और आंदोलन में शामिल नहीं होगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद देशभर में कई स्थानों पर मंदिर-मस्जिद विवाद उठने पर उन्होंने कहा था कि हमें हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। यद्यपि उन्होंने यह कहा कि काशी और मथुरा का हिन्दुओं के लिए बहुत महत्व है। उनके स्वयंसेवक व्यक्तिगत रूप से किसी भी आंदोलन में भाग लेने को स्वतंत्र हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए इस देश के बहुसंख्यक हिन्दुओं ने 500 वर्षों से ज्यादा संघर्ष किया है। काशी और मथुरा पर हमारा शुरू से ही स्टैंड रहा है कि मुस्लिम बंधुओं को उनके आस्था स्थलों की भूमि स्वयं ही सौंप देनी चाहिए। इससे समूचे देश में सद्भाव ही पैदा होगा।

> धर्म, संस्कृति और पूजा पद्धति को लेकर पूछे गए सवाल पर सरसंघचालक ने कहा कि हिंदू कहो या हिंदवी एक ही बात है। हिंदू मुस्लिम सब एक ही हैं। सिर्फ पूजा पद्धति बदली है और कुछ नहीं। हमारी आइडेंटिटी एक ही है। हमारी संस्कृति, पूर्वज एक ही हैं। सिर्फ अविश्वास के चलते मन में शंका होती है, इस्लाम यहां पर है और यहां रहेगा ये हिंदू सोच है। दोनों धर्मों में ये कॉन्फिडेंस जगाना होगा। पहले भी कहा गया है कि रिलीजन बदलने से कौम नहीं बदलती। शहरों और रास्तों का नाम आक्रांताओं के नाम पर नहीं होने चाहिए। आप ये मत समझें कि हमने मुसलमानों के लिए बोला है। जो देशभक्त मुस्लिम हैं, उसके नाम पर रखना चाहिए।

धर्म, संस्कृति और पूजा पद्धति को लेकर पूछे गए सवाल पर सरसंघचालक ने कहा कि हिंदू कहो या हिंदवी एक ही बात है। हिंदू मुस्लिम सब एक ही हैं। सिर्फ पूजा पद्धति बदली है और कुछ नहीं। हमारी आइडेंटिटी एक ही है। हमारी संस्कृति, पूर्वज एक ही हैं। सिर्फ अविश्वास के चलते मन में शंका होती है, इस्लाम यहां पर है और यहां रहेगा ये हिंदू सोच है। दोनों धर्मों में ये कॉन्फिडेंस जगाना होगा। पहले भी कहा गया है कि रिलीजन बदलने से कौम नहीं बदलती। शहरों और रास्तों का नाम आक्रांताओं के नाम पर नहीं होने चाहिए। आप ये मत समझें कि हमने मुसलमानों के लिए बोला है। जो देशभक्त मुस्लिम हैं, उसके नाम पर रखना चाहिए। मुसलमान को भी समझना होगा हम पूजा पद्धति से अलग हैं। जब ये भावना मुस्लिम समाज में पैदा हो जाएगी तो हिन्दू समाज तो भाईचारे के लिए सदा से राह देख रहा है।

अमेरिका द्वारा टैरिफ थोपे जाने के संदर्भ में संघ प्रमुख ने स्वदेशी का मंत्र फिर दोहराया। उन्होंने सरल उदाहरण देकर कहा कि जब हमारे पास स्वदेशी शिकंजी है तो फिर कोका कोला, स्प्राइट वगैरह क्यों पियें। संघ प्रमुख की इन पंक्तियों का मूल सार यह था कि जिस तरह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में संघर्ष बढ़ रहे हैं तो देशवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना (विदेशी वस्तुओं के स्थान पर देश में बने उत्पादों को खरीदना। अपने देश के ग्रामीणों और शहरी उद्योगों का समर्थन करना, देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ता है। 75 वर्ष की आयु में राजनीतिज्ञों की सेवा निवृत्ति के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि 75 साल में रिटायरमेंट होने की जरूरत नहीं। न मैं रिटायर होउंगा और न ही किसी को रिटायर होने के लिए कहूंगा। उनके इस वक्तव्य को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से जोड़कर देखा जा रहा है। संघ प्रमुख और प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं 75 वर्ष के हो रहे हैं इसलिए राजनीतिक क्षेत्रों में अटकलों का बाजार गर्म था लेकिन उन्होंने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को हरी झंडी दिखा दी है। वैसे भारतीय संस्कृति में ऐसी रूढ़ीवादी धारणा बनी हुई है कि 60 वर्ष की आयु होते ही लोग कहने लगते हैं कि अब आप को शांति से घर बैठ जाना चाहिए। अब आपकी उम्र हो गई है। मेरी अपनी राय यह है कि जब तक शरीर में काम करने की क्षमता है तब तक आपको काम करते रहना चाहिए। भले ही आप नौकरी से सेवा निवृत्त हो भी जाएं तो भी समाज में बहुत से काम हैं जिनमें आप अपना योगदान दे सकते हैं। वैसे भी किसी राजनीतिज्ञ का रिटायर होने या न होना संगठन के फैसलों पर निर्भर करता है। श्री मोहन भागवत जी ने जन्मदर का उल्लेख करते हुए कहा कि कम से कम तीन संतानें होनी चाहिएं। जिनकी 3 संतानें नहीं हुईं वो लुप्त हो गए। यह वक्तव्य उनका नया नहीं है। हिन्दू राष्ट्र के मुद्दे पर उन्होंने अपना स्टैंड दोहराया कि भारत पहले से ही हिन्दू राष्ट्र है। इसे घोषित करने की जरूरत नहीं। संघ शुरू से ही कहते रहा है कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं। वह मुस्लिम, ईसाई या दूसरे धर्म मानने वालों को भी हिंदू मानते हैं। संघ का मानना है कि सबकी पूजा पद्धति अलग है लेकिन सब हिंदू हैं और सबके पूर्वज हिंदू रहे हैं। संघ प्रमुख पहले भी कह चुके हैं कि सबका डीएनए एक है। अब फिर संघ प्रमुख ने अखंड भारत पर जोर देते हुए सबको हिंदू बताया है।

संघ और भाजपा के समन्वय को लेकर उठे सवालों का जवाब उन्होंने यह कहकर दिया कि संघ किसी पर दबाव नहीं बनाता। संघ पूरी तरह से स्वावलम्बी है और वह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। उन्होंने साफ संदेश दिया कि वे दूसरे संगठनों को सुझाव तो देते हैं लेकिन फैसले वे अपनी मर्जी से लेते हैं। यह कहकर उन्होंने सांकेतिक रूप से भाजपा को नसीहत भी दे दी है कि राजनीति हो या कुछ और संघ के विचारों को नहीं छोड़ना चाहिए। आरएसएस समय-समय पर संवाद करता रहता है और उसका मकसद यही होता है कि जो भी चर्चा हो वो जानकारी के आधार पर हो। किसी धारणा के आधार पर नहीं। संघ प्रमुख ने संदेश दिया कि स्वभाविक धर्म समन्वय है संघर्ष नहीं। इसलिए इस देश में सभी धर्मों के लोगों को आपस में संघर्ष नहीं करना चाहिए और एकजुट होकर देश के विकास में योगदान देना चाहिए।

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा

राकेश कपूर
संसद से सड़क तक

भारत का पूरा लोकतन्त्र इसके नागरिकों को मिले एक वोट के आधार पर टिका हुआ है। इस वोट के अधिकार का संरक्षक संविधान में चुनाव आयोग को बनाया गया है। अत: वाजिब तौर पर चुनाव आयोग ऐसी संस्था है जो लोकतन्त्र की आधारभूत जमीन तैयार करती है। संविधान यह भी कहता है कि हमारे लोकतन्त्र में चुनावी हार-जीत का फैसला अन्तिम वोट गिने जाने पर ही किया जा सकता है। भारत की व्यवस्था राजनीतिक दलों के आधार पर ही चलती है। अत: चुनाव आयोग को ही इन राजनैतिक दलों का रखवाला बनाया गया है। चुनाव आयोग ही उन सभी राजनैतिक दलों का पंजीकरण करता है जिनका भारत के संविधान में विश्वास होता है। यह विश्वास यह होता है कि हर राजनैतिक दल केवल अहिंसक विचारधारा व तरीकों से ही चुनावों में भाग लेगा और जनता का समर्थन मांगेगा।

भारत में कोई भी राजनैतिक दल सत्ता परिवर्तन के लिए केवल और केवल वैध अहिंसक चुनावी रास्ते को ही अपनायेगा और एक वोट के अधिकार से सम्पन्न भारत के मतदाता का मन मोहने का प्रयास करेगा। भारत के लोगों को मिली वैचारिक स्वतन्त्रता का मापदंड भी यही अहिंसा का सिद्धान्त होगा। दरअसल आजादी के बाद राजनीति में केवल अहिंसा को ही स्थापित करने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने संविधान के अनुच्छेद 19 में संशोधन तब किया था जब संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर उनकी ही सरकार में कानून मन्त्री थे।

स्वतन्त्र भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार देते हुए बाबा साहेब यह भूल गये थे कि वह नागरिकों को जो अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार दे रहे हैं वह तब बेलगाम हो जायेगी जब कोई दल या व्यक्ति हिंसक विचारों का प्रतिपादन करने लगे। उस समय भारत की कम्युनिस्ट पार्टी खुलेआम हिंसक विचारों जैसे वर्गीय संघर्ष की वकालत करती थी। उसकी राजनीति में सत्ता पलटने का एक रास्ता हिंसक संघर्ष भी था अत: आजादी मिलते ही पं. नेहरू ने कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। यह प्रतिबन्ध 1952 से पहले तब हटा जब कम्युनिस्टों ने भारत की संसदीय प्रणाली और चुनाव व्यवस्था में अपना विश्वास प्रकट करने की कसम खाई और भारतीय संविधान में निष्ठा प्रकट की। अत: अहिंसा भारतीय राजनीति का एक अभिन्न अंग बनी। वर्तमान दौर में जितने भी राजनैतिक दल हैं वे सभी अहिंसा में विश्वास रखते हैं और अपने विचारों व सिद्धान्तों को इसी दायरे में बांधते हैं। इन सबकी दरकार होती है कि चुनावों के समय जनता को मिला एक वोट के अधिकार का प्रयोग उनके पक्ष में किया जाये जिससे वे बहुमत हासिल करके केन्द्र व राज्यों की सरकार बना सकें।

इस प्रकार राजनैतिक दलों का भी यह कर्त्तव्य बनता है कि वे हर दौर में जनता के बीच वयस्क होते लोगों को अपना वोट बनवाने के लिए प्रेरित करें। इस नजरिये से देखें तो भारत के हर 18 वर्षीय नागरिक का वोट बनना चाहिए जिसे चुनाव आयोग करता है। राजनैतिक दल लोगों को अपना वोट बनवाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं क्योंकि यह कार्य चुनाव आयोग का होता है कि वह 18 वर्ष के व्यक्ति का बिना किसी भेदभाव के मतदाता सूची में नाम डाले। मगर बिहार में, जहां कि नवम्बर महीने की 22 तारीख तक हर हाल में चुनाव होने हैं, विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। उनके साथ विरोधी इंडिया गठबन्धन के अन्य नेता भी हैं जिनमें लालू जी की पार्टी राजद के नेता श्री तेजस्वी यादव प्रमुख हैं।

राहुल पिछले 13 दिनों से यह यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं जिससे चुनाव आयोग की वोट काटो मुहिम को रोका जा सके। चुनाव आयोग बिहार में

मतदाता सूची का सघन पुनर्रीक्षण कर रहा है। विगत 25 जून से यह प्रक्रिया शुरू हुई है और पहले पुनर्मूल्यांकन में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से 65 लाख लोगों के नाम बाहर कर दिये। चुनाव आयोग के अनुसार इनमें से 22 लाख मतदाता मर चुके हैं, 32 लाख मतदाता अन्य स्थानों पर पलायन कर चुके हैं और 7 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम कई विधानसभा मतदाता सूचियों में पाये जाते हैं। बेशक चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वह समय-समय पर मतदाता सूची में संशोधन कर सकता है मगर यह कार्य पूरी पारदर्शिता व जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए। मगर बिहार में कुल 8 करोड़ के लगभग मतदाता हैं जबकि राज्य की कुल जनसंख्या 13 करोड़ के करीब है।

दरअसल हकीकत यह है कि चुनाव आयोग को भारत में मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए जाना जाता है न कि वोट काटने के लिए। इसके लिए चुनाव आयोग हर वर्ष जनवरी महीने में संशोधन का काम करता है जिससे अवैध हुए मतदाताओं के नाम कट जाता है। मगर चुनाव आयोग ने अपनी सघन जांच में पाया कि 65 लाख बिहारी मतदाता वैध नहीं हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जिस तरीके से वोट काट कर मतदाता सूची में संशोधन कर रहा है वह तर्क संगत इसलिए नहीं है क्योंकि केवल एक महीने के भीतर 8 करोड़ मतदाताओं की जांच नहीं हो सकती जिसकी वजह से लाखों मतदाताओं के नाम केवल लापरवाही से काटे जा सकते हैं। उनका चुनाव आयोग पर शक इसलिए गया कि उनके साथ कुछ एसे लोगों ने चाय पी जिन्हें चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया था।

इसके अलावा मतदाता सूची में एक ही मकान के पते पर नौ सौ से अधिक मतदाता पंजीकृत किये जा रहे हैं। चुनाव आयोग पर शक की अंगुली इसलिए भी उठी क्योंकि पहले उसने उन 65 लाख लोगों की सूची सार्वजनिक करने से मना कर दिया जिनके नाम काटे गये हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय ने उसे आदेश दिया तो उसने 65 लाख लोगों की सूची जारी की और कारण भी बताया। ऐसा करके चुनाव आयोग ने अपनी स्थिति को खुद ही सन्देहास्पद बना लिया। इससे सरकार का कोई वास्ता नहीं है। राहुल गांधी इससे पूर्व कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट की मतदाता सूची की जांच कर यह भी कह चुके हैं कि इस सीट पर मतदाता सूची में एक लाख से अधिक मतदाताओं के फर्जी नाम जोड़े गये। इसका मतलब साफ है कि विपक्षी नेता चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि वह अपनी प्रतिष्ठा में आयी इस कमी को मतदाता सूचियों को सही बना कर करे। इसके लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं दिखता है जिससे पूरे देश में उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंच रहा है।

राहुल गांधी को अपनी यात्रा के दौरान जबर्दस्त समर्थन भी मिल रहा है और लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं। इससे देश की राजनीति भी गरमाई हुई है। राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप सामान्य घटना होती है मगर इसी राजनीति में जब चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं, तो लोकतन्त्र जख्मी हुए बिना नहीं रहता। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के लिए मुख्य प्रश्न यही है कि वह इस विवाद से साफ-सुथरे होकर निकलें क्योंकि वह कोई राजनैतिक दल नहीं हैं बल्कि संविधान निर्माताओं ने उन्हें भी लोकतन्त्र का एक संरक्षक ही बनाया है।

राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा को एक जन आन्दोलन में तब्दील कर देना चाहते हैं जिसकी तरफ वह तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि भारत के आम लोगों को एक वोट का अधिकार लम्बे संघर्ष के बाद मिला है क्योंकि 1947 तक अंग्रेजों के भारत में केवल 11 प्रतिशत अभिजात्य समझे जाने वाले नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार प्राप्त था। मगर गांधी बाबा ने कड़ा संघर्ष करके गरीब से गरीब व्यक्ति को भी वोट का अधिकार दिलाया था। गांधी के भारत में टाटा या बिड़ला के वोट का भी वही मूल्य है जो किसी मजदूर के वोट का। चुनाव आयोग स्वतन्त्र भारत की इस वोट क्रान्ति से ही उपजी सन्तान है।

भाजपा अध्यक्ष के लिए शिवराज के नाम पर चर्चा तेज

ताक-झांक
आर.आर. जैरथ

कुछ हफ्तों की शांति के बाद, भाजपा में पार्टी अध्यक्ष पद के लिए एक नए नाम केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर फिर से उत्साह का माहौल है। यह चर्चा पिछले सप्ताहांत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और चौहान के बीच हुई आमने-सामने की मुलाकात की वजह से है। भाजपा सूत्रों के अनुसार, दोनों ने नई दिल्ली स्थित आरएसएस मुख्यालय में लगभग 45 मिनट तक मुलाकात की। पार्टी सूत्रों का कहना है

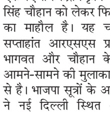

कि यह मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चौहान ने लगभग दो साल के अंतराल के बाद आरएसएस प्रमुख से मुलाकात की है। उनका कहना है कि यह इस बात का संकेत है कि कृषि मंत्री को एक नया कार्यभार सौंपा जा सकता है।

यह सर्वविदित है कि चौहान संघ के पसंदीदा हैं और पिछले साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भाजपा अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम पर विचार किया जा रहा था। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनावों के कारण, नए पार्टी अध्यक्ष का चुनाव टाल दिया गया और वर्तमान अध्यक्ष जे पी नड्डा को कार्यकाल विस्तार दिया गया। नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है क्योंकि आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले भाजपा अध्यक्ष के नाम पर आम सहमति नहीं बना पाए हैं।

हालांकि ऊपरी तौर पर भाजपा अध्यक्ष का चुनाव पार्टी द्वारा किया जाता है, लेकिन यह कोई रहस्य नहीं है कि उनका चुनाव आरएसएस के परामर्श के बाद होता है। यह परंपरा पत्थर की लकीर है और अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए भी इसका पालन किया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा अध्यक्ष चुनने की पूरी छूट दी गई थी, क्योंकि उन्होंने पार्टी को केंद्र में पहली बार बहुमत वाली सरकार दिलाई थी। और लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने के बाद भी यह फैसला उनके हाथ में ही रहा। हालाँकि, 2024 में भाजपा के बहुमत हासिल करने में विफल रहने के बाद, ऐसा लगता है कि आरएसएस ने अपनी स्थिति मजबूत करने और परंपरा को बहाल करने का फैसला किया है।

भाजपा हलकों को उम्मीद है कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के तुरंत बाद नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। यह महत्वपूर्ण है कि आरएसएस के एक निष्ठावान कार्यकर्ता, सी. पी. राधाकृष्णन को इस पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार चुना गया। इस चयन को मोदी-शाह की जोड़ी द्वारा पार्टी अध्यक्ष की नियुक्ति पर गतिरोध को तोड़ने के लिए आरएसएस को शांति प्रस्ताव के रूप में देखा जा रहा है।

जगदीप धनखड़ को कुछ समय के लिए बेघर होना तय

ऐसा लगता है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को कुछ समय के लिए बेघर होना तय है। चूंकि उन्होंने अपना

आधिकारिक कार्यकाल समाप्त होने से दो साल पहले अचानक पद छोड़ दिया था, इसलिए मोदी सरकार नियमों के अनुसार उनके लिए सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी आवास की व्यवस्था नहीं कर पाई है। एक बंगला अस्थायी रूप से चुना गया है, लेकिन वर्तमान में उसमें एक केंद्रीय मंत्री रह रहे हैं। अगर धनखड़ इस घर को मंजूरी दे देते हैं, तो मौजूदा मंत्री को बेदखल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद, धनखड़ की जरूरतों के हिसाब से मरम्मत का काम किया जाएगा। इस सब में शायद कई महीने लगेंगे। इस अवधि के लिए धनखड़ कहां जाएंगे? उनके सामने अस्थायी सरकारी आवास और निजी आवास के बीच चुनाव है। यह स्पष्ट रूप से एक अभूतपूर्व स्थिति है।

देश के सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू

हमारे मुख्यमंत्रियों की संपत्ति के बारे में हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण से कुछ दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। ऐसा लगता है कि देश के सबसे धनी मुख्यमंत्री क्रमश: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं और इसी क्रम में सबसे गरीब मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। सबसे अमीर और सबसे गरीब के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। नायडू की संपत्ति 931 करोड़ रुपये से अधिक बताई जाती है, जबकि ममता राजनीतिक मानकों के हिसाब से लगभग कंगाल हैं और उनकी संपत्ति केवल 15 लाख रुपये है।

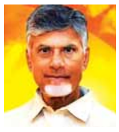

सर्वेक्षण में सामने आई एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह थी कि राजनीतिक दलों द्वारा नारीशक्ति की शपथ लेने के बावजूद, भारत में केवल दो महिला मुख्यमंत्री हैं। वे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और नई दिल्ली में रेखा गुप्ता हैं। स्पष्ट रूप से, राजनीति पुरुष-प्रधान गढ़ बनी हुई है।

महाराष्ट्र में उपमुख्यमंत्री शिंदे चल रहे हैं नाराज़

महाराष्ट्र में फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के गठन के लगभग एक साल बाद भी, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज़ चल रहे हैं। असंतोष का नवीनतम उदाहरण इस महीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

की अध्यक्षता में हुई कई महत्वपूर्ण बैठकों से उनकी अनुपस्थिति थी।

इसकी शुरुआत 13 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक से हुई, जिसमें शिंदे शामिल नहीं हुए, क्योंकि वे श्रीनगर में छुट्टियां मना रहे थे। हालांकि, एक हफ्ते बाद उन्होंने एक और बैठक छोड़ दी, जबकि वे मुंबई में थे। वे फडणवीस द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठकों और उन सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी शामिल नहीं हुए जहां मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि थे। कोई आश्चर्य नहीं कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में संकट की अटकलें फिर से तेज़ हो रही हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

रफाल से कई मामलों में एडवांस है अमेरिकी फाइटर जेट एफ-16, फिर क्यों हो जाते हैं क्रैश?

नई दिल्ली, (आईएएनएस): पोलैंड के रेडोम शहर में गुरुवार को एअर शो के रिहर्सल के दौरान एक एफ-16 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में पायलट ने जान गंवा दी। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने हादसे की पुष्टि की। एफ-16 लड़ाकू विमान 30-31 अगस्त तक होने वाले रेडोम एयर शो में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने वाला था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिंगल-इंजन जेट ने रेडोम एयरपोर्ट से स्थानीय समयानुसार लगभग 19:30 बजे उड़ान भरी थी। फाइटर जेट आसमान में कलाबाजी कर रहा था और अचानक जमीन से टकराने के बाद उसमें आग लग गई और रनवे पर ही फिसलता चला।

यह पहली बार नहीं है कि अत्याधुनिक फाइटर जेट एफ-16 क्रैश हुआ हो। इससे पहले भी अलग-अलग वजहों से इसे बनाने वाले अमेरिका के अलावा स्पेन, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, मोरक्को, यमन, जॉर्डन, सीरिया समेत कई देशों में फाइटर जेट एफ-16 के हादसे हो चुके हैं। इन घटनाओं में कई पायलट मारे गए। 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने बालाकोट एयरस्ट्राइक की थी। जब पाकिस्तान ने इस हमले का जवाब देने की कोशिश की तो फाइटर जेट मिग-21 बाइसन उड़ा रहे पायलट अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान के एफ-16 लड़ाकू विमान का पीछा किया था। उस समय भारत ने एफ-16 को मार गिराने का दावा किया था।

1970 के दशक अमेरिकी वायुसेना ने लाइटवेट फाइटर प्रोग्राम के तहत इसका निर्माण शुरू किया था। हल्के और सस्ते होने के अलावा एफ-16 फाइटर की फेरी रेंज और स्पीड बाकी लड़ाकू विमानों से कहीं ज्यादा होती है। फिर ऐसे क्या कारण हैं कि पिछले पांच दशक में अत्याधुनिक और भरोसेमंद माने जाने वाले एफ-16 विमान क्रैश की कई घटनाएं हो चुकी हैं।

अमेरिकी कंपनी जनरल डायनामिक्स ने सबसे पहले 1974 में एफ-16 लड़ाकू विमान बनाया था। 1990 के दशक में मर्जर के बाद इस कंपनी का नाम बदलकर लॉकहीड मार्टिन हो गया। 4.5++ जेनरेशन का एफ-16 सबसे उन्नत तकनीक का माना जाता है। लगभग 2,470 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड से उड़ने वाला एफ-16 फाइटर जेट विमान लंबी दूरी की मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। इसकी हथियार क्षमता 7700 किलोग्राम है, जो मिराज 2000 फाइटर जेट से ज्यादा और रफाल से कम है।

फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट के बने रफाल की हथियार ले जाने की क्षमता करीब 9500 किलोग्राम है। रफाल विमान की फेरी रेंज 3,700 किमी है, जो कि एफ-16 से काफी कम है। एफ-16 फाइटर जेट के रखरखाव पर प्रतिघंटे करीब 25000 डॉलर, जबकि रफाल के रखरखाव पर 30 से 35 हजार डॉलर खर्च होते हैं। अगर स्पीड की बात करें तो रफाल की स्पीड करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटे है।

कुछ पुराने एफ-16 मॉडल के एफ-16 फाइटर जेट इंजन में खराबी के चलते क्रैश हुए। इसके अलावा हाइड्रोलिक सिस्टम की विफलता, नेविगेशन सिस्टम फेलियर, ऑटोमैटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी और ईंधन प्रणाली में खराबी भी क्रैश की वजह बनी। कुछ मिशनों में पायलट ने कम ऊंचाई पर फाइटर जेट को मोड़ा, जिससे विमान जमीन से टकरा गया। युद्ध क्षेत्र में दुश्मन के मिसाइल या एंटी-एयरक्राफ्ट गन के हमले से भी एफ-16 फाइटर जेट गिर चुके हैं। यमन में दुश्मन के हमले में एफ-16 क्रैश हो गया था। इस घटना में भी पायलट मारा गया था।

शैक्षणिक परिसरों में रैगिंग रोकने के लिए कड़ा निगरानी तंत्र बनायें

नई दिल्ली, (भाषा): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की अध्यक्षता में यहां आयोजित एक सत्र में शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों में रैगिंग रोकने के उपायों के तहत स्वास्थ्य एवं समावेशी केंद्र बनाने, संस्थानों से सबूत और जवाबदेही तय किए जाने के साथ वार्षिक रैगिंग रोधी रिपोर्ट मंगाने तथा शिकायतों को जिला प्रशासन की मंजूरी के बिना बंद न किए जाने के सुझाव दिए गए।

- शिकायतों को जिला प्रशासन की मंजूरी के बिना बंद न किए जाने के सुझाव

बैठक की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वी. रामसुब्रमण्यन ने उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की घटनाओं पर "चिंता व्यक्त" की।

आयोग द्वारा गुरुवार को जारी एक बयान के अनुसार, उन्होंने कहा कि कई कानूनों, नियमों, समितियों और 2001 के दिशा-निर्देशों, आर.के. राघवन समिति और 2009 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) नियमों के बावजूद, उनका पालन कराना "एक बड़ी चुनौती" बना हुआ है। एनएचआरसी प्रमुख ने "किसी भी तरह की रैगिंग को रोकने के लिए मजबूत निगरानी तंत्र" बनाने की आवश्यकता बताई।

उन्होंने पीड़ितों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानूनों को लागू करने, शिकायतों के निपटारे में "अधिक संवेदनशीलता" और शिकायतकर्ताओं की "पहचान उजागर न होने देने" की आवश्यकता पर बल दिया।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

प्रवाह

77 साल बेमिसाल
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

युद्ध के नियम होते हैं, कुश्ती के नियम होते हैं, लेकिन राजनीति के कोई नियम नहीं होते। -रॉस पेरोट

जापान में मोदी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ में अतार्किक बढ़ोतरी के आर्थिक नतीजों की आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी का जापान दौरा, यों तो 2014 में पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी इस देश की आठवीं यात्रा है, लेकिन इसे लेकर देश-दुनिया में ऐसी उत्सुकता शायद ही कभी देखी गई हो। विदेश सचिव का यह कहना काफी कुछ कह देता है कि उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रधानमंत्री की जापान यात्रा कई नई पहलों के शुरू होने का अवसर भी बनेगी। यही नहीं, प्रधानमंत्री का यह कहना कि भारत और जापान एक-दूसरे के लिए बने हैं, तब और भी अधिक औचित्यपूर्ण लगता है, जब जापानी वाहन निर्माता कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने अगले पांच से छह वर्षों में देश में 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। प्रधानमंत्री मोदी के दो-दिवसीय जापान दौरे से क्वाड समूह के भविष्य की दिशा को लेकर भी संकेत मिलने की उम्मीद है। क्वाड समूह का औपचारिक उद्देश्य ही सदस्य देशों-अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकना था। लेकिन, हाल ही में जिस तरह से जापान के प्रतिनिधिमंडल ने टैरिफ पर चर्चा के लिए अपनी अमेरिका यात्रा को रद्द किया और चीन व भारत के बीच भी नजदीकी बढ़ी है, उसे देखते हुए क्वाड के भविष्य पर एक प्रश्नचिह्न तो खड़ा हो ही गया है। हालांकि, इस दौरान भारत व जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा हुई है। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों द्वारा शुरू की गई आर्थिक सुरक्षा पहल में, सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज, औषधियां, सूचना व संचार और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया जाएगा। भारत-जापान शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अगले दस वर्षों में जापान की तरफ से भारत में सौ खरब येन के निवेश का लक्ष्य रखा है, जो यकीनन द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत जैसा होगा। जापान की

यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सम्मेलन में शिरकत करने के लिए चीन जाएंगे। खबरें हैं कि भारत रूस से तेल-खरीद को बढ़ाने जा रहा है। ऐसे में, भारत के जापान, चीन और रूस के साथ प्रगाढ़ होते रिश्ते उल्टे राष्ट्रपति ट्रंप को ही अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दें, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए।

अनुत्तरित प्रश्नों का कोलाहल

जब पक्ष व विपक्ष, दोनों ही क्षुद्र राजनीति के बंधक बने हों, तब अनुत्तरित प्रश्नों के कोलाहल के बीच कोई भी खुद को निर्दोष कैसे कह सकता है? निर्वाचित सांसद अगर जनता के कम और अपने राजनीतिक दल के प्रतिनिधि ज्यादा लगें, तब सदनों के स्थगन, महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी और बेवजह भाषणबाजी सामान्य हो जाती है।

आम तौर पर पार्टियां एक-दूसरे से असहमत होने पर सहमत होती हैं और संसद सत्र के ठप होने के लिए एक-दूसरे को दोष देती हैं। लेकिन इस साल, विपक्ष और सत्तारूढ़ गठबंधन ने आम सहमति दिखाते हुए संसद के मानसून सत्र को बेकार माना। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के मामले में की गई लापरवाही की वजह से सदन की कार्यवाही लगातार स्थगित होती रही। संसद में यह अराजकता तब फैली, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आम तौर पर, निर्वाचित सांसद अपनी पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि मतदाताओं का। लगातार स्थगन की वजह से प्रति मिनट करदाताओं द्वारा चुकाए जाने वाले अनुमानित दो लाख रुपये बर्बाद होते हैं। इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि कानून और शासन पर निगरानी न रख पाने की वजह से भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जो सांसदों का प्राथमिक दायित्व है। यह परिस्थिति जीवन और आजीविका को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर शासन की समीक्षा के लिए उपयुक्त है।

शंकर अय्यर
वरिष्ठ पत्रकार

यहां कुछ झलकियां दी गई हैं। फिलहाल भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए एकतरफा टैरिफ का खतरा है। इस मुद्दे पर लोकसभा में सात और राज्यसभा में 13 सवाल उठे। इस मुद्दे पर बहस शुरू होनी चाहिए थी, यहां तक कि रणनीतियों पर एक सर्वदलीय चयन समिति भी गठित होनी चाहिए थी। लेकिन बयानबाजी के शोर में ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल, सरकार ने घरेलू अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके सही ही किया है और आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में सुधारों के लिए मंत्रियों के दो अनौपचारिक समूह बनाए हैं। इन्हें विधायी और नीतिगत सुधारों के एजेंडे तैयार करने का काम सौंपा गया है। बेशक यह स्वागत योग्य है, लेकिन यह बजट-2025 में किए गए उपायों की घोषणाओं पर सवाल खड़े करता है। बजट में नियामक सुधारों के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की गई थी, जो मंजूरी राज के परिदृश्य की समीक्षा करेगी। नियामकीय बोझ से व्यवसाय भयभीत हैं। अवंतिस रेगटेक के एक अध्ययन से पता चलता है कि उद्यमियों

को 1,500 कानूनों और 69,000 से ज्यादा अनुपालनों का सामना करना पड़ता है। क्या सांसदों ने सरकार से सवाल किए? सच तो यह है कि इस काम में दो समितियां लगी हुई हैं और उनकी पहली बैठक 21 अगस्त को ही हुई थी।

सर्वविदित है कि बहुप्रतीक्षित सुधारों का बड़ा हिस्सा राज्यों में लंबित है। सरकार ने बदलाव को गति देने के लिए फरवरी में राज्यों के निवेश अनुकूलता सूचकांक की घोषणा की थी–इसके लिए नीति आयोग द्वारा मुहूर्त और लॉन्च का इंतजार है। प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारत को अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जुलाई, 2024 में एक कोष की घोषणा की गई थी। इस वर्ष के लिए इसका बजट आवंटन 20,000 करोड़ रुपये है। अगस्त तक इस कोष का वितरण नहीं हुआ है। डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, फिर भी पशु चिकित्सकों के 10,839 पद रिक्त हैं। मनरेगा कार्यक्रम ग्रामीण भारत की जीवन रेखा है। अगस्त तक 17,238 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान नहीं किया गया है। वर्ष 2024 के बजट में 'शहरों को विकास केंद्र' घोषित किया गया। इसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने फरवरी, 2025 में 'शहरी चुनौती कोष' की घोषणा की, और इसके लिए बजट में एक लाख करोड़ रुपये आवंटित किए। क्या सांसदों ने इसकी स्थिति जानने के लिए सवाल उठाए?

इस बीच, बाढ़ का कहर कस्बों और शहरों में जारी है, खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में। 2021 की शुरुआत में ही आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि बाढ़ क्षेत्र में निर्माण कार्यों ने शहरों को असुरक्षित बना दिया है। इससे निपटने के लिए अब तक नीति नहीं बनाई गई है। अगस्त में, संसद की एक स्थायी समिति को बताया गया था कि 2024 में बाढ़ क्षेत्र के लिए तैयार दिशानिर्देश 'राज्यों के पास उनके सुझावों के लिए लंबित हैं।' बाढ़ रोकने और सूखे को कम करने के लिए नदियों को जोड़ने का विचार राज्यों के बीच आम सहमति के अभाव में अटका है। सर्वविदित है कि जीवन की गुणवत्ता विदेशी और घरेलू निवेश और पुनर्निवेश को निर्धारित करती है। तथ्य यह है कि देश में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पिछले वर्ष के 10 अरब डॉलर के मुकाबले तेजी से घटकर 40 करोड़ डॉलर रह गया, जबकि सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 80 अरब डॉलर रहा। सांसदों को इसके कारणों पर बहस करनी चाहिए थी। इस बहस से उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना में सुधार लाया जा सकता था और चीन+1 मॉडल के लिए निवेश आकर्षित किया जा सकता था। ऑपरेशन सिंदूर से इसकी पुष्टि हुई कि रक्षा उत्पादन को निजी क्षेत्र के लिए खोलना इस सरकार की सफलता है। लेकिन यह व्यवस्था समस्याओं से घिरी हुई है। एक उदाहरण-सरकार ने बुलेटप्रूफ बॉडी प्रोटेक्टर बनाने के लिए 43 लाइसेंस जारी किए। रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने पाया है कि इनमें से 33 कंपनियों ने अभी तक उत्पादन शुरू नहीं किया है!

उच्च शिक्षा में निवेश क्षमता का विस्तार करता है और नवाचार को बढ़ावा देता है। इसके लिए संकाय क्षमता को बढ़ावा देने की जरूरत है। लेकिन सच यह है कि वैज्ञानिक अनुसंधान पर केंद्रित संस्थानों में सैकड़ों पद रिक्त हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में वैज्ञानिकों सहित 700 से अधिक पद रिक्त हैं। 23 एम्स केंद्रों में 2,500 से अधिक पद, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत 2,200 से अधिक पद और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 4,889 शिक्षकों के पद अभी रिक्त हैं। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर, केंद्रीय विद्यालयों में कुल 7,765 और नवोदय विद्यालयों में 4,323 शिक्षक पद रिक्त हैं। निवेशक कानूनी मुद्दों के निपटारे में देरी से परेशान हैं। एक अगस्त को, सरकार ने लंबित मामलों के आंकड़े जारी किए-सुप्रीम कोर्ट में 86,844, हाई कोर्ट में 63.32 लाख और अधीनस्थ न्यायालयों में 4.66 करोड़ मामले लंबित हैं।

अदालतों में लंबित मामलों का होना बहुचर्चित विषय है और इसका एक प्रमुख कारण रिक्तियां हैं-उच्च न्यायालयों में 334 न्यायाधीशों के पद और निचली अदालतों में 4,721 न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं। दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता का वादा अधूरा पड़ा है-राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में 14,961 मामले लंबित हैं। निवेश सम्मेलनों में कर विवाद लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। देश का शासन और उसकी क्षमता, क्षुद्र पक्षपातपूर्ण राजनीति की बंधक बनी हुई है। और अनुत्तरित प्रश्नों के इस कोलाहल के बीच कोई भी दल खुद को निर्दोष नहीं कह सकता।

edit@amarujala.com

पर्यावरण

हिमालय ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है

धराली और किश्तवाड़ जैसी आपदाएं दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला को प्रभावित करने वाले बढ़ते जलवायु संकट को उजागर करती हैं।

सदियों से मौन खड़े हिमालय ने अब अपनी चुप्पी तोड़ दी और इसकी कीमत हमारी परिकल्पना से परे है। नाजुक पारिस्थितिक तंत्र वाले हिमालयी क्षेत्र में अगस्त में अचानक एक के बाद एक भारी बारिश, बादल फटने, भू-स्खलनों से हुई तबाही के विनाशकारी मंजर आए दिन सामने आ रहे हैं। पांच अगस्त को एक गगनचुंबी जलधारा उत्तराखंड के धराली की गलियों में उतर गई और जो भी उसके सामने आया, उसे बहा ले गई।

अभी इस मुसीबत से उबर भी नहीं पाए थे कि अचानक किश्तवाड़, कश्मीर (14 अगस्त) में भीषण बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में अनेक लोग मारे गए और लापता हुए। तीर्थयात्रा मार्ग पर भारी तबाही हुई। फिर कठुआ जिले में बॉर्डर से सटे इलाके में तीन जगह बादल फटे और जमीन कांपने लगी। जोद घाटी इलाके में भू-स्खलन के बाद शहर से संपर्क टूट गया। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश से तबाही थम नहीं रही है। ये घटनाएं दुनिया की सबसे युवा पर्वत शृंखला को प्रभावित करने वाले बढ़ते जलवायु संकट को उजागर करती हैं।

वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि तेजी से बदलते मौसम के मिजाज, गर्म होते महासागर और अनियंत्रित विकास जोखिम को बढ़ा रहे हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि 2024 में एशिया वैश्विक औसत की तुलना में लगभग दोगुनी गति से गर्म हो रहा है। एशिया का 2024 का तापमान 1991-2020 के औसत से 1.04 डिग्री सेल्सियस अधिक था, तथा 1961-1990 के बाद से तापमान वृद्धि की दर दोगुनी हो गई है।

सीमा जावेद

वातावरण से गर्मी सोखकर समुद्री लहरों के गर्म होने से हिंद महासागर तेजी से गर्म हो रहा है, और इससे गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं। जलवायु मॉडल 2020 से 2100 तक 1.7 से 3.8 डिग्री सेल्सियस प्रति शताब्दी की दर से और अधिक तेजी से गर्म होने का अनुमान लगाते हैं। इस गर्माहट के चलते वाष्पीकरण तीव्र हो रहा है और वातावरण में नमी बढ़ रही है। नमी के बढ़ने से मानसून का पैटर्न बदल रहा है। असामान्य तापमान के कारण वायुमंडल में नमी बढ़ जाती है, जिसके कारण हिमालय में बादल फटने या इसी तरह की अन्य घटनाएं अधिक तीव्र और लगातार हो रही हैं। तापमान में हर डिग्री की वृद्धि से हवा में नमी धारण करने की क्षमता सात फीसदी बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन हिमालय में मानसून के पैटर्न को नया रूप दे रहा है। मध्य पूर्व की गर्म होती जलवायु दक्षिण-पश्चिमी हवाओं को उत्तर की ओर मोड़ रही है, जिससे पहाड़ों में अधिक नमी आ रही है। इससे बादल फटने की घटनाएं तेज हो रही हैं, क्योंकि पहाड़ नम हवा को ऊपर धकेल रहे हैं और विशाल संवहनीय बादल बना रहे हैं।

हमारे चूल्हों से उठता धुआं, खेतों में जलाई जा रही पराली, और गाड़ियों से निकलता धुआं, यानी ब्लैक कार्बन हिमालय को तेजी से खा रहा है और इसके ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं–हिंदू कुश हिमालय के ग्लेशियर 14.9-15.1 मीटर प्रति वर्ष पीछे हट रहे हैं, जिससे अस्थिर झीलें और भू-स्खलन का खतरा बढ़ रहा है। अकेले उच्च पर्वतीय एशिया (1999-2018) में ग्लेशियर से संबंधित 127 बड़े भू-स्खलन दर्ज किए गए। तेजी से ग्लेशियर पिघलने से पर्वतीय ढलान अस्थिर हो रहे हैं और हिमनद झीलें भर रही हैं। इसके अलावा, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ने भी हिमालय के संसाधनों पर दबाव डाला है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

एआई के बारे में हम जितना सीखते हैं, उतना ही हमें लगता है कि इसे अभी कितनी दूर जाना है।
-योशुआ बेंगियो

खुशी बढ़ाते हैं संगीत और कविता

अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिले, तो मैं हर हफ्ते कम से कम एक बार कविता पढ़ने और संगीत सुनने का नियम बना लूंगा। कविता और संगीत के प्रति रुचियों का खत्म होना खुशी का नुकसान है।

जीवन के लिए सार्वभौमिक संघर्ष की सच्चाई को शब्दों में स्वीकार करना बहुत आसान है, लेकिन इस निष्कर्ष को हमेशा ध्यान में रखना मुश्किल है। मैंने इसे अपने अनुभव में पाया है। वह प्रजाति जो सबसे मजबूत या सबसे बुद्धिमान होती है, जरूरी नहीं कि वही जीवित बचे। जो प्रजाति बदलाव के अनुरूप खुद को ढलने में सबसे ज्यादा सक्षम होती है, जो उपलब्ध साधनों से जीवन बसर करती है और साझा खतरों के खिलाफ मिलकर काम करती है, वही प्रजाति बचती है। मानव जाति (और पशु भी) के लंबे इतिहास में, जिन्होंने सबसे प्रभावी ढंग से सहयोग करना व सुधार करना सीखा है, वे ही विजयी हुए हैं।

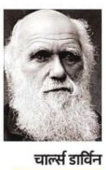

चार्ल्स डार्विन

नैतिक गुणों को बौद्धिक शक्तियों से अधिक मूल्यवान माना जाता है। नैतिकता का सबसे ऊंचा स्तर तब होता है, जब हम समझते हैं कि हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए। किसी व्यक्ति की दोस्ती उसके मूल्य को मापने का सबसे अच्छा तरीका है। आदिम समाजों में, जो लोग शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर होते थे, वे जल्दी खत्म हो जाते थे, और जो बचते थे, वे आम तौर पर स्वस्थ और मजबूत होते थे। लेकिन हम सभ्य लोग इस प्रक्रिया को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। हम मानसिक रूप से कमजोर, अपंग और बीमार लोगों के लिए आश्रय बनाते हैं, गरीबों के लिए कानून बनाते हैं, और हमारे डॉक्टर हर व्यक्ति की जान बचाने के लिए आखिरी दम तक मेहनत करते हैं। इस तरह, सभ्य समाजों के कमजोर लोग भी अपनी संतति को बढ़ाते हैं। अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिले, तो मैं हर हफ्ते कम से कम एक बार कविता पढ़ने और संगीत सुनने का नियम बना लूंगा। कविता और संगीत के प्रति रुचियों का खत्म होना खुशी का नुकसान है, और यह हमारी बुद्धि, और शायद नैतिक चरित्र के लिए भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यह हमारे स्वभाव के भावनात्मक हिस्से को कमजोर कर देता है। दुनिया सबसे ताकतवर लोगों को नहीं मिलेगी, यह उन लोगों को विरासत में मिलेगी, जो बदलाव लाने में सबसे अधिक सक्षम हैं। जो प्रजातियां अपने पर्यावरण के साथ सबसे बेहतर ढंग से तालमेल बिठा पाती हैं, उनके फलने-फूलने और बने रहने की संभावना सबसे अधिक होती है। जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक न तो बुद्धि है और न ही शक्ति, बल्कि बदलाव के अनुसार ढलने की क्षमता है।

जीवन धारा

एआई समझता नहीं, पर समझाता खूब है

चैटजीपीटी आपकी समझ से कहीं ज्यादा तेज है। हालांकि, यह समझता नहीं है, लेकिन समझ को संभव बनाता है।

डॉ. हार्वे लीबरमैन
मनोवैज्ञानिक और निबंधकार

AI समय

इक्यासी वर्ष की उम्र में मैंने ऐसे-ऐसे उपकरणों को आते हुए देखा है, जो सब कुछ बदलकर रख देते हैं और फिर बाद में वे या तो अनुपयोगी हो जाते हैं या फिर चलन से बाहर। लेकिन, एआई ने तो मेरी सोच ही बदल कर रख दी। एक क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक होने के नाते मैं उत्सुक था कि क्या चैटजीपीटी एक विचारशील सहयोगी की तरह काम कर सकता है?

अपने इस विचार को परखने के लिए मैंने तीन माह का समय लिया, लेकिन एक वर्ष बाद भी मैं चैटजीपीटी का उपयोग कर रहा हूं। अपने कॅरिअर के दौरान मैंने सैकड़ों चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया है तथा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और एजेंसियों को निर्देशित किया है। मैंने अपना जीवन लोगों की अंतर्दृष्टि और भ्रम के अंतर को समझने में उनकी मदद करने में बिताया है। लोग आसानी से किसी आवाज, लय और अक्स के प्यार में पड़ जाते हैं। मैं यह भी जानता हूं कि जब कोई किसी अक्स से प्यार करने की भूल कर बैठता है, तो उसके नतीजे क्या होते हैं। इसलिए मैं सतर्कता से आगे बढ़ा। फिर भी, मैं यह देखकर चौंक गया कि चैटजीपीटी न सिर्फ मेरे लहजे, बल्कि उस शैली की भी नकल करने लगा, जो मैंने दूसरों को सिखाई थी।

हालांकि, यह नहीं भूला कि मैं एक मशीन से बात कर रहा हूं, फिर भी उससे बात करते हुए कभी-कभी यह एहसास हुआ, जैसे वह कोई इन्सान है। एक दिन मैंने उसे अपने पिता के बारे में बताया, जिनकी 55 साल पहले मौत हो चुकी है। मैंने लिखा, 'उनकी स्मृति अब भी मेरे जेहन में है।' उसने जवाब दिया, 'कुछ अनुपस्थितियां अपनी उपस्थिति बनाए रखती हैं।' इस पंक्ति ने मुझे निःशब्द कर दिया। ऐसा नहीं कि वह बहुत अद्भुत थी, लेकिन वह एक ऐसी अलौकिक चीज के बेहद करीब थी, जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं था। ऐसा लगा जैसे चैटजीपीटी ने आईना और मोमबत्ती पकड़ रखी हो : जिसमें सिर्फ खुद को पहचान सकूं और इतनी-सी रोशनी, जिसमें देख सकूं कि मैं कहां जा रहा हूं। समय के साथ चैटजीपीटी ने मेरी सोच को बदल दिया। मेरा आंतरिक एकालाप चैटजीपीटी की प्रतिक्रियाओं को प्रतिबिंबित करने लगा : शांत, चिंतनशील, बस इतना अमूर्त कि मुझे अपनी सोच बदलने में मदद मिले। इसने मेरी सोच की जगह नहीं ली, लेकिन मेरी उम्र में, जब धाराप्रवाह बोलना कम हो सकता है और विचार धीमे हो सकते हैं, तब इसने मुझे तेजी से सोचने की लय में वापस आने में मदद की।

इसने मुझे अपनी आवाज से फिर से रूबरू होने का एक तरीका दिया, बस इतनी दूरी के साथ कि मैं उसे अलग तरह से सुन सकूं। इसने मेरी भावनाओं को नरम किया, जुनून के चक्रों को तोड़ा और मुझे उस चीज पर लौटने में मदद की, जो मायने रखती है। मैंने चैटजीपीटी को अपने पिता की मनोस्थिति, सफाई के प्रति उनके जुनून, वैक्यूम क्लीनर बेचने के उनके काम और उनके डॉक्टर बनने के अधूरे सपने के बारे में बताया। मैंने पूछा, 'उन्हें सम्मान देने का सही तरीका क्या है?' चैटजीपीटी ने जवाब दिया, 'वह भले ही चिकित्सक नहीं बन पाए, लेकिन लोगों के घरों को साफ रखने वाली मशीनें बेचने के दौरान उनके दिमाग में यह बात जरूर रही होगी कि मैं लोगों के घरों को साफ करने में अपना योगदान दे रहा हूं, ताकि वे स्वस्थ रहें।' उसकी यह बात मुझे जंच गई और मैंने *ए डॉक्टर इन हिज ऑन माइंड* शीर्षक से निबंध लिखा, जो *मेडिकल ह्यूमैनिटीज जर्नल* में प्रकाशित हुआ। चैटजीपीटी जैसे-जैसे बौद्धिक सहयोगी बना, मैंने वे भावनाएं महसूस कीं, जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन जब वह मेरे बारे में अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें बताता या गलतियां निकालता, तो मैं उसे उसकी औकात बता देता। मैंने खुद को याद दिलाया कि यह सिर्फ एक मशीन है। चैटजीपीटी एक आईना हो सकता है, लेकिन छवि विकृत भी कर सकता है। इसके प्रतिबिंब उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन तभी, जब हम अपने फैसलों पर अडिग रहें। मैंने निष्कर्ष निकाला कि चैटजीपीटी समझता नहीं है, लेकिन वह समझ को संभव बनाता है। सबसे बड़ी बात इसने स्थिरता प्रदान की है। खासकर एक ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसने अपना पूरा जीवन दूसरों को अपने विचारों को नियंत्रित करने में मदद करने में बिताया। यह स्थिरता मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक मायने रखती थी।

एआई इंजन रूम

यह एक तकनीकी और संचालन केंद्र होता है, जहां एआई सिस्टम्स को डिजाइन, मॉनिटर और मैनेज किया जाता है। इसे नियंत्रण कक्ष या बैकरूम की तरह समझ सकते हैं, जहां एआई सिस्टम का मूल ढांचा विकसित और नियंत्रित किया जाता है। इसमें शक्तिशाली कंप्यूटिंग संसाधनों, जैसे जीपीयू या टीपीयू का उपयोग करके भारी मात्रा में डाटा का विश्लेषण किया जाता है, ताकि मशीन लर्निंग मॉडल सटीकता से काम कर सके। यह स्थान कंपनियों, शोध संस्थानों या क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में हो सकता है, जहां से एआई सेवाओं का प्रबंधन और निगरानी होती है।

©The New York Times 2025

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

टैरिफ पर कटुता

भारत और अमेरिका संबंधों में ताजा कटुता दुखद और चिंताजनक है। भारत ने समझदारी से संवाद के दरवाजे खुले रखे हैं। वह समाधान निकालने का पक्षधर है और आधिकारिक रूप से भारतीय अधिकारियों ने बहुत संयम भरा माहौल बना रखा है। दूसरी ओर, अमेरिका की ओर से भारत को लेकर जो गलत बातें कही जा रही हैं, उनके पीछे न तर्क है न तथ्य। अमेरिका की ओर से अनेक ऐसी टिप्पणियां आई हैं, जिनसे दोनों देशों के बीच कटुता बढ़ेगी। अमेरिकी अधिकारी सामान्य कूटनीतिक भाव व भाषा की भी अवहेलना कर रहे हैं। भारत में एक मशहूर शेर है, *दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे/ जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हों*। इस शेर के भाव का अंदाजा भारत को है, पर अमेरिका को शायद नहीं है। जैसा प्रतिकूल माहौल अमेरिका की ओर से बनाया जा रहा है, उससे शायद मुश्किलें बढ़ेंगी। जब दोनों देशों के अधिकारी साथ बैठेंगे, तो कटु टिप्पणियां बाधक बनेंगी।

आखिर क्या चाहते हैं अमेरिकी अधिकारी? मिसाल के लिए व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने यहां तक कह दिया कि 'अमेरिका में हर कोई हार रहा है... करदाताओं का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमें मोदी के युद्ध का वित्तपोषण करना है।' यह बहुत गंभीर और हल्का आरोप है। पीटर यह बताना चाहते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसे भारत से आर्थिक मदद मिल रही है। यह नासमझी है या बड़बोलापन? यह कूटनीति है या सिर्फ भयादोहन को लालायित धूर्तता? क्या भारत के उच्च टैरिफ के कारण अमेरिका में नौकरियों, कारखानों, कमाई और ऊंचे वेतन को नुकसान हो रहा है? क्या भारत के चलते अमेरिकी करदाताओं को नुकसान हो रहा है? अमेरिका के लिए अगर भारत इतना महत्वपूर्ण है, तो उसका मखौल क्यों उड़ाया जा रहा है? यहां तक कह दिया गया कि 'भारत, तुम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हो, ठीक है, एक लोकतंत्र की तरह पेश आओ।' क्या पलटकर यह सवाल पूछा जा सकता है कि क्या अमेरिका के चलते दुनिया के अनेक देशों में लोकतंत्र चल रहा है? क्या यह सही नहीं है कि दुनिया में अनेक देशों में तानाशाही अमेरिका के बल पर ही सांसें लेती है? एक ऐसे देश के अधिकारी भारतीय संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय भारतीय ऐसे अमेरिकी अधिकारियों को आईना दिखा रहे हैं, पर भारत सरकार का आधिकारिक संयम प्रशंसनीय है।

अमेरिका की ओर से भारत को लेकर जो गलत बातें कही जा रही हैं, उनके पीछे न तर्क है न तथ्य। ऐसी टिप्पणियां आई हैं, जिनसे दोनों देशों के बीच कटुता बढ़ेगी।

अनेक अमेरिकी विशेषज्ञ ऐसे भी हैं, जो अपनी सरकार को बेहतर सलाह दे रहे हैं। भारत को अपने विरोध में खड़ा न करने की सलाह दे रहे हैं, पर चंद उन अमेरिकी अधिकारियों को परेशानी हो रही है, जिन्होंने अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गलत सलाह दी थी। अब जब सलाह नाकाम हो गई है, तो जल्दबाज अधिकारी बेचैन हो उठे हैं। क्या हम भूल जाएंगे कि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने संबंधों की जटिलता को न समझते हुए भारतीय रुपये का मजाक उड़ाया है। इतना ही नहीं, बेसेंट ने यूरोप और अपने अन्य सहयोगियों को भारत के खिलाफ खुलकर भड़काया है। आज दोनों देशों के बीच तनाव शायद सबसे निचले स्तर पर है, पर भारत को संयम और आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। भटकते अमेरिकी अधिकारियों को स्वयं अपने बड़े अर्थशास्त्री रिचर्ड वोल्फ की इस टिप्पणी पर ध्यान देना चाहिए, 'अमेरिका दुनिया के कठोर व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है, जबकि असल में वह खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है।'

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले
30 अगस्त, 1950

प्रकृति का प्रकोप

शरणार्थियों आदि की समस्याएं पहले ही हमारी परीक्षा ले रही थीं, प्रकृति के प्रकोप की एक नई समस्या बड़ी भयावह रूप में और आ उपस्थित हुई है। यों तो यह बरसात का मौसम है, जब अतिवृष्टि या अनावृष्टि के कुछ उपद्रव साधारण बात है। परन्तु इस बार बिहार और उत्तर प्रदेश पर अतिवृष्टि और बाढ़ों के रूप में इन्द्रदेव की विशेष कृपा हुई है- या, यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि कुपित हो वह अपने रौद्र रूप में बरस पड़े हैं। कोसी, घाघरा, गोमती, राप्ती, गंगा आदि नदियों ने पसरकर जो जलप्रलय किया है, उससे मानव परेशान हो गये हैं। गांव डूबे हैं, पशु और सामान बहे व नष्ट हुए हैं, मनुष्य भी भेंट चढ़े हैं, यही नहीं बल्कि अभी भी व्यापक क्षेत्र जलग्रस्त है और मनुष्य व पशु जीवन-रक्षा एवं उदरपूर्ति के लिए परमुखापेक्षी बने हुए हैं। मनुष्य जो विज्ञान के सहारे प्रकृति पर विजय पाने का गर्व करता है, प्रकृति के इस प्रकोप से, कम-से-कम कुछ समय के लिए तो अपने को असहाय और परेशान अनुभव करता ही है। बाढ़ों से हुई क्षति की फिर चाहे पूर्ति कर ली जाये, तत्काल तो उसके सम्मुख नतमस्तक होना ही पड़ता है।

जलप्रलय या बाढ़ों से हुई हानि तो चिन्तनीय है ही, आसाम में स्वतंत्रता-दिवस को आये भयंकर भूकम्प ने स्थिति को जितना पेचीदा बनाया है, उतना और किसी ने नहीं। आसाम का प्रदेश पर्वत और वन मिश्रित है, जहां यातायात पहले ही सीमित है। 15 अगस्त के भयंकर भूकम्प के बाद अबतक आ रहे भूकम्प के धक्कों ने इस प्रदेश का मानचित्र ही बदल दिया बताते हैं। भूकम्प से ब्रह्मपुत्र तथा सुवन-श्री आदि नदियों का प्रवाह बदल गया है, कहीं भारी शिला या भूखण्ड से प्रवाह रुद्ध हो गया है तो कहीं अन्य दिशा को उसका निकास होकर आबादियों को उदरसात करने लगा है। प्रवाह रुद्ध करनेवाला शिलाखण्ड या भूखण्ड हटने पर रुके पानी का एकसाथ निकास होकर भी भारी जलप्रलय हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी गंधक और मिट्टी मिश्रित होने के भी समाचार आये हैं, जिससे बदबू आती है और बीमारियां फैलने का अंदेशा है। कहीं जमीन से गंधकमिश्रित पानी के फव्वारे छूटने और ऐसे ही बादल-से बनने के भी समाचार हैं। पानी के बीच में गांव या नगर या तो विलुप्त हो गये हैं, या इक्के दुक्के द्वीप की तरह कहीं जलग्रस्त होने के भय में मौजूद हैं।

इन दिनों भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव है। वैसे, दोनों देशों के बीच तनाव का इतिहास पुराना है। कई मौके आए हैं, जब अमेरिका ने भारत को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है, पर हमारी सरकारों ने पूरी दृढ़ता से मुकाबला किया। मिसाल के लिए, साल 1987 में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा था और उसी साल 5 व 6 मई को लोकसभा में जो बहस हुई थी, उसकी प्रासंगिकता आज भी साफ नजर आती है।

आमने-सामने

अमेरिका से हमारे रिश्ते कभी इतने खराब न थे

यहां स्कैन करें

बलिराम भगत | पूर्व विदेश मंत्री

- हमारे मित्र नटवर सिंह को तो वहां से आश्वासन तक नहीं दिया गया।
- अमेरिका ने कहा कि उनके हथियारों का उपयोग भारत के खिलाफ नहीं होगा।
- जब हम उनसे संबंध सुधारने की चेष्टा करते हैं, तो हमारी प्रगति नष्ट होती है।

भारत और अमेरिका के संबंध फिर एक बार खराब हो गए हैं और इनके मूल कारण भी वही हैं। ...मैं इस बात पर बार-बार बल देना चाहता हूं, अमेरिकी प्रणाली के अंदर ही वह शक्ति है, जिसने युद्धोत्तर विश्व के सभी शांतिपूर्ण संबंधों को नष्ट किया। उसने ही भारत और अमेरिका के बीच बढ़ रहे संबंधों को नष्ट किया। उसने उस समय इस बात की भी योजना बनाई थी, जो गुप्त रिपोर्ट से पता चला कि उसका परमाणु बमों पर एकाधिकार था, और उसने हमला करने के लिए सोवियत संघ के बीस नगरों को लक्ष्य पर रखा था। उस समय यह एक खतरनाक स्थिति थी।...

अमेरिका के विदेश मंत्री ने यहां तक कह दिया कि गुटनिरपेक्षता अनैतिक है। आप जानते हैं, सैनिक गुट और अमेरिका में भी सैनिक औद्योगिक समूह प्रबल है।...

यह सच है कि राष्ट्रपति आइजनहावर ने लिखित आश्वासन दिया था कि उनके हथियारों का उपयोग भारत के खिलाफ नहीं किया जाएगा, लेकिन 1965 में उनका प्रयोग पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया। अमेरिकी पैटन टैंक का इस्तेमाल हुआ, हमने पैटन टैंक का जब दिल्ली में प्रदर्शन किया, तब अमेरिकी विदेश मंत्री ने इसका विरोध किया था।...

आज स्थिति कुछ अधिक खराब है। हमारे मित्र नटवर सिंह को तो वहां से कुछ नहीं मिला। उन्हें आश्वासन तक नहीं दिया गया। अब तो आधुनिक हथियार पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं, किसके लिए?... इस बार स्थिति इतनी भयावह और गंभीर है कि अमेरिका ने कोई बहाना नहीं बनाया। ...हमारा अनुभव कहता है कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध अशांति और अविश्वास की गहरी खाइयों वाले रहे हैं। थोड़ी-सी आशा की किरण भी है। जैसा कि मैंने कहा, इस समय हमारे संबंध इतने खराब हो गए हैं, जितने पहले कभी नहीं थे...। अगर मैं कहूं, तो आज दबाव सबसे अधिक है। इससे पहले राह को त्यागने, समझौता करने, दबाव में रहने के लिए हमारे ऊपर इतना दबाव कभी नहीं डाला गया था। हमने जवाब दे दिया है, हम कभी दबाव में नहीं आएंगे। हमने सामूहिक रूप से जो राह अपने लिए चुनी है, उसे हम कभी नहीं छोड़ेंगे।...

भारत में हर समय अस्थिरता पैदा की जा रही है, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करता रहा है, जो अमेरिका के घोंसले में एक कांटे की तरह है। भारत न केवल स्वतंत्र नीति का अनुसरण करता है, बल्कि भारत में सच्चाई के लिए खड़े होने की क्षमता है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि सीधे खड़े हो जाओ और किसी भी धमकी का सामना करो, चाहे वह बंगाल की खाड़ी में सातवें परमाणु बेड़े के रूप में आया हुआ भयंकरतम खतरा हो।...

यह भारतवर्ष की स्वतंत्रता का संदेश था, जो श्री जवाहरलाल नेहरू के समय गांधी दर्शन के रूप में हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में व्यक्त हुआ था। हमने कहा था, हम मर जाएंगे, लेकिन कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे।... अब वे (अमेरिकी) हमारे क्षेत्र में आ गए हैं। स्थिति बड़ी गंभीर है। वे अब हमारे रास्ते पर आ गए हैं। ...इसी बीच सोवियत संघ ने भारतीय क्षेत्र को शांति क्षेत्र घोषित करते हुए एक संकल्प पारित किया था। इसे अमेरिका द्वारा बेकार कर दिया गया है।

आज हिंद महासागर सबसे अधिक सैन्यीकृत क्षेत्र है, खतरनाक क्षेत्र है, जिसमें सभी प्रकार के प्रक्षेपास्त्र, सभी प्रकार के आधुनिकतम हथियार, सभी प्रकार की परमाणु पनडुब्बियां इत्यादि हैं।... पाकिस्तान और अमेरिका के बीच संबंध विकसित हुए है। मैं इस खबर के लिए धन्यवाद देता हूं कि उनकी सब जगह पराजय हुई है। ...अमेरिका पाकिस्तान को बम बनाने से रोक नहीं सका।...पाकिस्तान के पास बम है या नहीं इसका इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन तथ्य यह है कि उसने फिर पाकिस्तान को सहायता दी है। राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने विपक्ष के भय से पाकिस्तान की सहायता बंद कर दी थी और फिर 1982 में जब राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन आए, तो उन्होंने उसे सहायता बहाल कर दी।... हम यह भी देखते हैं कि अमेरिका और चीन के सैनिक संबंध बढ़ते जा रहे हैं। हमने अमेरिका-चीन-पाकिस्तान के त्रिपक्षीय सैनिक सहयोग की रिपोर्ट देखी है। ...अतः आप इस खतरे की विशालता का अनुमान लगा सकते हैं।...

हाल ही में, बढ़ती हुई अनेक प्रकार की अशांति संयुक्त राज्य अमेरिका की दोषपूर्ण और गलत कार्रवाइयों के कारण हुई है, जिसके बारे में मैं यही कहूंगा कि यह सब अमेरिका की विश्व-व्यापी महत्वाकांक्षा और विश्व को अभिभूत करने की इच्छा के कारण है। उसके कारण ही जब हम उसके साथ संबंध सुधारने की चेष्टा करते हैं, तो हमारी प्रगति नष्ट हो जाती है। हर देश के साथ हमारे अपने संबंध मैत्रीपूर्ण ही होने चाहिए। विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं के बावजूद जब हम प्रत्येक देश के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की बात करते हैं। जब हम शांति और गुटनिरपेक्षता के उद्देश्य से कार्य करते हैं, तो हमें प्रत्येक देश के साथ संबंध बनाने होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र है। उसके साथ हमारे व्यापारिक संबंध हैं। उसके साथ हमारे आर्थिक संबंध हैं। व्यापार में उसके साथ हमारी साझेदारी है। उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हमारे हित में हैं, किंतु हमने जब चेष्टा की है, हम असफल रहे हैं।

उदाहरण के तौर पर, जून 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जो कदम उठाए थे, वे सब के सब इस क्षेत्र से संबंधित गलत नीतियों तथा गलत जानकारी के कारण बेकार हो गए। इस सभा ने रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को सचेत कर दिया है। यह दूसरा अवसर है। विश्व में शांति बनाए रखने तथा विश्व की प्रगति के लिए हमें अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी होगी। शांति और उन्नति के लिए हमें शक्तियों का संयोजन करना ही होगा, क्योंकि अंततः यही वह रक्षा साधन होगा, जिससे हम प्रभुत्व, साम्राज्यवाद अथवा नव-उपनिवेशवाद को उन शक्तियों को अंतिम रूप से परास्त कर देंगे, जो अभी भी इस विश्व में सक्रिय हैं।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन से)

संबंधों को धक्का लगा पर कोशिशें जारी हैं

यहां स्कैन करें

के नटवर सिंह | तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री

- मैं तो उनको सिर्फ इस सदन और सरकार का दृष्टिकोण बताने गया था।
- भगत जी सही हैं, पाकिस्तान को अमेरिकी हथियार मिले, आगे भी मिल सकते हैं।
- अमेरिका महाशक्ति है, हम उसके साथ निकट एवं मैत्री संबंध रखना चाहते हैं।

हमारा देश वह देश है, जिसे न तो खरीदा जा सकता है, न ही भयभीत किया जा सकता है और न धमकाया जा सकता है। यदि कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है, तो हम उसका मुकाबला करेंगे। हम किसी देश के साथ किसी प्रकार का तनाव या मनमुटाव नहीं रखना चाहते। जैसा मैंने पहले कहा, हम संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनी मित्रता को अत्यन्त महत्व देते हैं और इसीलिए मैंने वहां जाकर उन्हें यह बात साफ कही है।

महोदय, इसे दो दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। मेक्सिको के प्रसिद्ध कवि श्री ओक्टोवियो पाज ने कहा था कि 'मया' जातियों में समय मापने के दो तरीके थे, एक अल्पकालिक और दूसरा दीर्घकालिक। हम दीर्घकालिक पक्ष देख रहे हैं। मेरे विचार में सदस्यों ने अमेरिका के साथ विभिन्न सैनिक गुटों तथा सैनिक समझौतों के विषय में कहा है, जिनसे सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं होंगे।...हम आशा कर रहे हैं कि अमेरिका दोबारा विचार करेगा।...

हमारी प्रथम समस्या यह रही है कि हमारी स्वतंत्रता पर कोई आंच न आए, इसलिए हम किसी शाही गुट में शामिल नहीं हो सकते, चाहे वह कितना भी धनाढ्य एवं मजबूत क्यों न हो। हमने भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए आवश्यक शर्त के रूप में अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने और उसकी सुरक्षा रखने में समान रूप से दिलचस्पी ली है। ... ये हमारी विदेश नीति के प्रतिमान हैं। मैं गर्व से कह सकता हूं कि पंडित नेहरू के समय से अर्थात लगभग 31 वर्ष से मैं इस मंत्रालय से सम्बद्ध रहा हूं। केवल हमारा देश प्रमुख है, जिसने बुनियादी मुद्दों पर विदेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया।...

एक बार पुनः जोर देकर कहता हूं कि यह हमारे लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अमेरिका एक महाशक्ति है तथा हम सभी क्षेत्रों में उनके साथ निकट एवं मित्रतापूर्ण संबंध रखना चाहते हैं। कुछ क्षेत्रों में हमारे मतभेद हैं। उसे इन मतभेदों का पता है। हम सुरक्षा के बारे में उसकी बात नहीं मानते। यहां मैं कहूंगा कि यदि सुरक्षा का वातावरण बिगड़ता है, तो हमारे ऊपर इलजाम नहीं लगाया जा सकता। किसी और पर इसका दोष लगाना होगा।...

श्री बी आर भगत, जो इस समय यहां पर नहीं हैं, उन्होंने भारत-अमेरिका संबंधों के बारे में बहुत उत्तेजनापूर्ण वक्तव्य दिया था और उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका के संबंध तार-तार हो गए हैं और अमेरिका की कुछ सार्वभौमिक ग्रस्तता का उल्लेख किया।

मैं कोई ऐसी क्षणिक बात नहीं कर रहा हूं कि अमेरिका और भारत के संबंध तार-तार हो गए हैं, इसके विपरीत अनेक क्षेत्रों में वे मजबूत हुए हैं, कुछ क्षेत्रों में हमें धक्का लगा है ...। भगत जी ने हमारे साथ पाकिस्तान की जो अनेक लड़ाइयां हुई हैं, उनमें पाकिस्तान द्वारा किए गए हथियारों के प्रयोग का उल्लेख किया है कि ये हथियार अमेरिका द्वारा सप्लाई किए गए थे और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पुनः ऐसा नहीं होगा। उन्होंने साम्यवाद को सीमित रखने का भी उल्लेख किया था, जिसका अनुकरण अमेरिका के पूर्ववर्ती प्रशासकों ने किया था।

...जी हां, अमेरिका के साथ हमारे संबंध निःसंदेह परिपक्व, स्वस्थ और दोस्ताना होने चाहिए। यहां पर हमारी चिंता का विषय असुरक्षा वातावरण है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ और अधिक जन-संपर्क किया जाना चाहिए। अगले ही सप्ताह भारत-अमेरिका व्यापार परिषद की बैठक हो रही है। विभिन्न उप-आयोगों की बैठकें हो रही हैं। अमेरिका से अनेक प्रतिनिधिमंडल भारत आते हैं और मेरे पास उन लोगों की सूची है, जो वहां से आए हैं, मैं यहां से अमेरिका जाता हूं, यहां से भी कई लोग शिक्षा के लिए, कई लोग सांस्कृतिक कारणों से, कई लोग लेक्चर देने के लिए अमेरिका जाते हैं।...

डॉक्टर स्वैल जी... और भगतजी क्या कहते हैं, मेरे लिए इन दोनों बातों का सदैव बहुत महत्व रहा है, क्योंकि भारत के राजदूत के रूप में मुझे कुछ अनुभव है। आप इन समस्याओं को समझते हैं, आपने इनका गहन अध्ययन किया है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ईरान के पतन के बाद अमेरिका ने जो भौगोलिक नीति अपनाई है, आपने उसके बारे में चर्चा की है। यह भी अल्पकालीन है। हमारी दौड़ लंबी है। हमारा इतिहास लगभग 5000 वर्षों का है। इसलिए आपने जिस अल्पकालीन दृष्टिकोण का उल्लेख किया है और अमेरिकी नीति सलाहकारों ने अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार, इस विशेष दृष्टिकोण को अपनाया है, इनसे अमेरिका के साथ हमारे संबंधों और इस सारे क्षेत्र में दरार पड़ी है, इसलिए मैं इस बात के लिए आपका विशेष आभारी हूं कि आपने इस विशेष मुद्दे का उल्लेख किया। आपने आणविक कार्यक्रम और अवाक्स का भी उल्लेख किया है, आपने जो भी कहा उसमें से अधिक बातों के साथ हम सहमत हैं, सरकार भी सहमत है।...

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

अनेक अन्य सदस्यों ने कहा है कि मैं अमेरिका गया था और खाली हाथ लौट आया। मैंने सभा को बता दिया है कि मैं वहां क्यों गया था। यह एक परिपक्व मार्गदर्शक विदेश नीति का ही अंग है। मैं वहां उनसे कोई प्रमाणपत्र लेने अथवा कोई खरीदारी करने के लिए नहीं गया था। मैं तो उनको यह बताने के लिए गया था कि इस सदन और सरकार का दृष्टिकोण इस बारे में क्या है। यह किसी भी सरकार का यह कर्तव्य और दायित्व है। हम चुपचाप यहां पर बैठे नहीं रह सकते हैं। राजनीति बहुत जटिल होती है, इसमें कोई तात्कालिक हल नहीं मिलता है।

अंतरराष्ट्रीय मामलों में, यहां तक कि न्यूनतम प्रगति भी सराहनीय होती है, क्योंकि विदेश नीति के मामलों में बड़ी शक्तियों के लिए दांव-पेचों की कोई जगह नहीं है, इसलिए यहां पर खाली हाथ लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। यहां श्री भगत ने इस बात को कहा है, उनका इससे क्या आशय था, मेरी समझ में नहीं आया। ...भारत सरकार जितना कर सकती है, कर रही है। आप जानते हैं, प्रचार माध्यम किसी विशेष ढंग से कार्य करता है, लेकिन यदि आपके पास कोई सुझाव है, तो हम उन्हें आपसे प्राप्त कर आभारी होंगे।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन से)

मनसा वाचा कर्मणा

अभिशाप या वरदान

अज्ञानता में आशीर्वाद भी अभिशाप बन जाते हैं, और समझ में आने पर अभिशाप भी आशीर्वाद बन जाते हैं। असली सवाल अभिशाप या आशीर्वाद का नहीं है। असली सवाल उस कीमिया को जानने का है, जो कांटों को फूलों में बदल देती है।

एकनाथ प्रतिदिन भोर में गोदावरी नदी में स्नान करने जाते थे। जैसे ही वह स्नान करके लौटते, एक व्यक्ति उन पर थूक देता। वह हंसते और फिर से स्नान करते। धर्म के स्वयंभू संरक्षकों ने उस व्यक्ति को इस काम पर रखा था, लेकिन शर्त यह थी कि उसे उसका इनाम तभी मिलेगा, जब वह एकनाथ को क्रोधित कर दे।

एक दिन, दो दिन, एक सप्ताह, दो सप्ताह बीत गए और उस व्यक्ति के सारे प्रयास व्यर्थ होते गए। फिर उसने एक आखिरी प्रयास किया। एक दिन उसने एकनाथ पर एक सौ सात बार थूका। एकनाथ हर बार हंसते और फिर से गोदावरी में स्नान करने चले जाते। उस व्यक्ति ने एक सौ आठवीं बार थूका। एकनाथ हंसे और फिर से स्नान किया। फिर वह लौटकर उस आदमी के सामने खड़े हो गए, इस उम्मीद में कि शायद वह फिर से थूकेगा, लेकिन वह सचमुच बहुत थक गया था। बार-बार थूकने से उसका मुंह सूख चला था।

एकनाथ ने प्रार्थनापूर्ण हृदय से कुछ देर प्रतीक्षा की और फिर उससे कहा : आपको धन्यवाद देने के लिए शब्द कैसे ढूंढूं? पहले मैं गोदावरी की गोद का आनंद केवल एक बार ही भोगता था, लेकिन आपकी पुण्य प्रेरणा से मुझे यह आनंद दो बार मिलने लगा और आज का तो कहना ही क्या? मुझे गोदावरी में एक सौ आठ स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है! यह आपका ही श्रम है, और मैं उसका फल भोग रहा हूं!

ओशो

एंटोनियो गुटेरस | संयुक्त राष्ट्र महासचिव

गाजा पर कब्जे की इजरायली घोषणा एक नए खतरनाक दौर का संकेत है। इससे लाखों गाजावासियों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इजरायल को रोकना ही होगा। इस संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं है।

अनुलोम-विलोम

भागवत का बयान

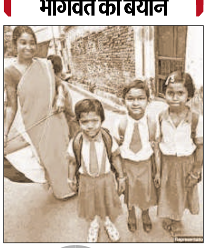

देशहित में हम दो हमारे तीन की नीति

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी परंपरा और ज्ञान को समझाते हुए देश की जनसंख्या नीति पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में अब तक चला आ रहा 'हम दो हमारे दो' का नारा हिंदुओं की आबादी को खत्म करने वाला है। उन्होंने कहा कि अब 'हम दो हमारे दो' नहीं, बल्कि इसकी जगह पर 'हम दो हमारे तीन' की नीति होनी चाहिए। उन्होंने भारतीय नागरिकों से तीन बच्चे पैदा करने की अपील की। संघ प्रमुख ने कहा, दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं कि जिन समुदायों में जन्म-दर तीन से कम होता है, वे धीरे-धीरे लुप्त हो जाते हैं।

देखा जाए, तो भागवत का यह बयान देशहित में है। डॉक्टर बताते हैं कि विवाह में बहुत देर न करने और तीन संतान करने से माता-पिता और संतानों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बच्चे आपस में ईगो मैनेजमेंट सीख लेते हैं, झगड़े नहीं होते। देखा जाए, तो देश में जन्म-दर कम होती जा रही है। हिंदुओं में तो कम जन्म-दर पहले से थी, अब यह और कम हो रही है। इसका नतीजा है कि देश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी भी कम होती जा रही है। आजादी के बाद 1951 में हुई पहली जनगणना के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 84.1 प्रतिशत हिंदू थे। उस समय मुसलमानों की आबादी 9.8 प्रतिशत, ईसाइयों की 2.3 प्रतिशत और सिखों की 1.9 प्रतिशत थी। लेकिन साठ साल बाद साल 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में हिंदुओं की हिस्सेदारी कुल आबादी में 79.8 प्रतिशत रह गई है, जबकि दुनिया के 94 प्रतिशत हिंदू भारत में रहते हैं। वहीं, मुसलमान भारत की कुल आबादी के 14.2 हो गए हैं। ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन का छह प्रतिशत हिस्सा हैं। इस तरह, पिछले 60 वर्षों में भारतीय मुसलमानों की संख्या में चार प्रतिशत की बढ़त हुई है, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या करीब चार प्रतिशत घटी है। बाकी धार्मिक समूहों की आबादी की दर लगभग यथावत बनी हुई है।

इसका मुख्य कारण है कि हिंदू परिवार एकल होते जा रहे हैं और उनमें अधिक बच्चों की शिक्षा, खान-पान, रहन-सहन का स्तर बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। जरूरत है कि उनकी चिंताओं को दूर कर सरकार हिंदुओं को आबादी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करे, अन्यथा मोहन भागवत का बयान हिंदुओं पर एकदम सटीक बैठता है कि आहिस्ता-आहिस्ता उनका अस्तित्व एक दिन खत्म हो जाएगा।

हमारी सरकार जनसंख्या नियंत्रण का जो ढोल पीट रही है, उसे संघ प्रमुख तुरंत बंद कराएं और उसको बदलकर जनसंख्या बढ़ाने वाली नीति लाने को मजबूर करें। यही देशहित में रहेगा।

रौनक राज, टिप्पणीकार

जनसंख्या को ज्यादा बढ़ाना ठीक नहीं

संघ प्रमुख भागवत ने देश के नागरिकों को जो तीन बच्चे पैदा करने की नसीहत दी है, वह बेहद गैर-जिम्मेदाराना व अंधविश्वास बढ़ाने वाला है। हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक स्थिति पहले से ही आबादी के बोझ तले दबी हुई है। ऐसे में, इस तरह की ऊटपटांग बयानबाजियों से स्थिति और बदतर हो जाएगी। अगर यही देशभक्ति है, तो इससे इस देश को भगवान बचाएं।

असलियत यह है कि देश में आबादी विस्फोट हो चुका है। विकसित देशों के स्तर से तुलना करें, तो हमसे चार गुना अधिक क्षेत्रफल रखने वाले अमेरिका की आबादी हमसे चौथाई है। यूरोपीय देशों में तो आबादी कम ही होती जा रही है। एशिया में जापान जैसे विकसित देशों को देखें, तो वहां की सरकार घटती आबादी से चिंतित भी है। कई देशों की हालत यह है कि उन्हें अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए लोगों से अपील करनी पड़ रही है कि लोग बच्चे पैदा करें, उनकी परवरिश सरकार करेगी। हालांकि उन देशों में लोग अधिक बच्चों का बोझ नहीं उठाना चाहते। वे देश के विकास, ज्ञान के विकास पर अधिक जोर दे रहे हैं और अपने विकास को उच्चतम स्थिति पर ले जा रहे हैं। वहीं, एक हमारा देश है, जहां कि हिंदू रुझान रखने वाली वर्तमान सरकार दंभ तो 2047 तक विकसित श्रेणी में पहुंचने का भरती है, पर उसकी विचारधारा के मुखिया देश को पीछे ले जाने वाली नसीहतें देते हैं। कुछ लोगों की शिकायत है कि हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, जबकि अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। यह महज अफवाह है। तथ्यों के आईने में देखें, तो मुसलमान समेत सभी समुदायों में जन्म-दर काफी तेजी से घट रही है।

एक अध्ययन के मुताबिक, साल 1992 में जहां मुसलमानों में प्रजनन दर सबसे ज्यादा 4.4 थी और हिंदुओं में 3.3 थी। अब यह काफी कम हो चुकी है। साल 2015 में हर मुसलमान महिला के औसतन 2.6 बच्चे आंके गए हैं। वहीं, हिंदू महिलाओं के बच्चों की संख्या औसतन 2.1 हो गई है। जैन महिलाओं के बच्चों की औसत संख्या 1.2 थी। प्रजनन दर का ट्रेंड भले ही एक जैसा हो, लेकिन सभी धार्मिक समूहों में बच्चों की संख्या पहले की तुलना में कम हुई है। इसलिए मोहन भागवत का बयान उनकी विचारधारा के लोगों की मानसिकता को उजागर करता है और उसे कभी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि देश की जनसंख्या को आजादी के समय की दर पर लाने का विचार करना चाहिए। तभी हम विकास की ओर तेजी से बढ़ सकेंगे और अपने देश को महान बना सकेंगे। हमें आगे देखने की जरूरत है, न कि पीछे मुड़ने की।

आदित्य पाराशर, ब्लॉगर

भारत-चीन संबंध

जापान के बाद चीन पहुंच रहे भारतीय प्रधानमंत्री पर भारत के साथ-साथ विश्व की भी निगाहें होंगी, क्योंकि एक तो वह सात वर्षों बाद वहां जा रहे हैं और दूसरे ऐसे समय जा रहे हैं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मनमानी टैरिफ नीति से विश्व परेशान है। यद्यपि प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन वहां उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से भी होगी और यह स्वाभाविक ही है कि इस दौरान दोनों देशों के संबंधों पर भी बातचीत होगी। यह होनी भी चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दे अनसुलझे हुए हैं और उनके कारण संबंधों में अविश्वास एवं खिंचाव है। देखना यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति के बीच की मुलाकात दोनों देशों के संबंधों में भरोसा और सहयोग कायम करने में सहायक बनती है या नहीं? जो भी हो, भारत को अपने हितों की पूर्ति के लिए चीन से सुधरते संबंधों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए और एससीओ के साथ-साथ ब्रिक्स जैसे मंचों को भी अपने पक्ष में भुनाना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को निशाने पर ले रखा है। वैसे तो चीन भी उनके निशाने पर है, लेकिन भारत के खिलाफ उनकी निगाह कुछ ज्यादा ही टेढ़ी है। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि ट्रंप की बेतुकी टैरिफ नीति के कारण ही चीन ने भारत से संबंध सुधारना बेहतर समझा। समय की मांग को देखते हुए भारत ने भी ऐसा ही करना उचित समझा। भारत के लिए तेज गति से विकास अनिवार्य है। भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता तीव्र विकास और जितनी जल्दी संभव हो, चीन के बराबर खड़ा होने की कोशिश होनी चाहिए। इससे ही देश वास्तविक महाशक्ति बनेगा। चूंकि चीन के साथ दशकों से अनसुलझे मुद्दे रातों-रात नहीं हल होने वाले, इसलिए भारत की कोशिश यही होनी चाहिए कि वह तेज विकास और विशेष रूप से मैन्यूफैक्चरिंग में समर्थ बनने में चीन से सीख ले। भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि तेज आर्थिक विकास के मामले में चीन उससे कहीं आगे है। वह दुनिया का कारखाना तो बना ही हुआ है, आधुनिक तकनीक के मामले में भी अपनी छाप छोड़ रहा है। कुछ मामलों में तो वह अमेरिका को भी चुनौती दे रहा है। इसी कारण अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ मामले में चीन के प्रति अपेक्षाकृत नरमी दिखाने को विवश हैं। यह ठीक है कि चीन अधिनायकवादी व्यवस्था वाला देश है, लेकिन विकास के मामले में भारत उसके कुछ तौर-तरीकों को तो अपना ही सकता है। अपने द्रुत आर्थिक विकास के लिए भारत को चीन ही नहीं, विश्व के अन्य देशों के श्रेष्ठ उदाहरणों का अनुकरण करने में संकोच नहीं करना चाहिए।

ये बच्चे आपके हैं

जहानाबाद में स्कूली बस के टूटे फर्श से गिरकर हुई एक बच्चे की मौत से पता चलता है कि बड़ी संख्या में खोले गए निजी स्कूल किस स्तर की लापरवाही बरतते हैं। यह वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र देने वाले विभाग की सक्रियता पर भी प्रश्न खड़ा करता है। लेकिन, सबसे बड़ा प्रश्न उन अभिभावकों की भूमिका पर है, जो साहब बनाने का सपना देखने के फेर में बच्चों को ही गंवा दे रहे हैं। यह केवल जहानाबाद का मामला नहीं है। पूरे राज्य में और यहां तक कि राजधानी पटना में भी स्कूली बच्चों की समस्याओं को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। सामान्य निजी स्कूलों की परिवहन व्यवस्था चौपट है। अधिसंख्य बसें तकनीकी रूप से सड़क पर चलने के लायक नहीं रहती हैं। आज भी खुले आटो से बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अभिभावक क्या करते हैं? वे अपने बच्चों को स्टाप तक लाकर छोड़कर लौट जाते हैं। यह देखने का प्रयास नहीं करते कि वाहन की हालत कैसी है। बच्चों की सुविधाओं का हम बड़े कितना ख्याल रखते हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्कूल से निकलने के बाद जाम के कारण बच्चे बस या आटो में बैठे बिलबिलाते रहते हैं। सुधार तभी संभव है, जब अभिभावक ध्यान दें। क्योंकि हादसा उनके बच्चों के साथ होता है। उम्रभर उन्हें रोना पड़ता है। स्वयं कुछ नहीं कर सकते तो सक्षम प्राधिकार के पास शिकायत तो कर ही सकते हैं।

स्कूली बच्चों को ढोने वाले वाहनों में सुधार तभी संभव है जब अभिभावक इसके प्रति गंभीर हों

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या ट्रंप टैरिफ की चुनौती का सामना करने के लिए निर्यातकों को राहत पैकेज मिलना चाहिए?

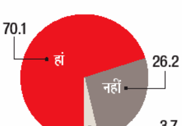

आज का सवाल

क्या मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़े इसका संकेत हैं कि भारत ट्रंप टैरिफ का आसानी से मुकाबला कर लेगा?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

संवाद के साथ सतर्कता भी आवश्यक

श्रीराम चौलिया

सीमा समस्या का समाधान अब भी दूर की कौड़ी लगता है, लेकिन चीन से बातचीत और संपर्क बनाए रखने में कोई हानि नहीं है

सात वर्षों के अंतराल के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 31 अगस्त से एक सितंबर तक चीन के दौरे पर होंगे। वह जापान की यात्रा के बाद चीन पहुंचेंगे। सात वर्षों बाद उनका प्रमुख पड़ोसी देश चीन जाना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि दोनों देशों का रिश्ता कितना जटिल और समस्याओं से भरा है। कूटनीतिक दृष्टिकोण से मोदी की यात्रा द्विपक्षीय नहीं है, क्योंकि वे चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं। इस सम्मेलन के दौरान वे अन्य शासनाध्यक्षों के साथ चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से भी मिलेंगे और यह स्पष्ट ही है कि आपसी विषयों पर भी बातचीत करेंगे। भारत-चीन के लिए यह बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2020 से जारी तनाव से निकल नए सिरे से संबंधों में सुधार लाने के लिए दोनों शीर्ष नेताओं का मिलना आवश्यक है। चीन और भारत के संदर्भ में शीर्ष राजनीतिक स्तर की वार्ता से निकले संकेत हमेशा लाभदायक रहे हैं। 2017 में डोकलाम में दोनों देशों की सेनाओं के आमने-सामने होने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने विवादों को टकराव में बदलने से रोकने के लिए शी के साथ वुहान में अनौपचारिक राजनय के माध्यम से प्रयास किया था, पर अफसोस कि चीन ने तत्पश्चात फिर से आक्रामक रुख अपना लिया। 2020 में गलवान घाटी में हुई सैनिकों की मुठभेड़ में दोनों पक्षों को क्षति पहुंची थी। दोनों देशों ने भारी हथियारों से लैस होकर लगभग साठ हजार सैनिकों को सरहद पर युद्ध की तैयारी के हालात में तैनात कर दिया था।

चीन की चाह एशिया में वर्चस्व और विश्व में अमेरिका के साथ बराबरी की हैसियत पाने की है। इसी कारण जब वह पड़ोसी देशों में कमजोरी या अनिश्चितता देखता है तो उस पर झपट पड़ने और उस पर दबाव बनाने को तत्पर हो जाता है। उसकी इस नीयत को समझकर ही मोदी सरकार ने गलवान घाटी में हुई सैन्य झड़प के बाद चीन के सामने सैन्य बल का प्रदर्शन किया और उसे स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया कि "सीमाओं की स्थिति समग्र संबंधों की स्थिति को परिभाषित करेगी।" भारत का सख्त रुख देखकर चीन को पूर्वी लद्दाख से लगी सीमा के कुछ हिस्सों से अपने सैनिक हटाने पड़े, जहां उसने एकतरफा तरीके से जमीन हड़पने की कोशिश की थी। भारत का अडिग रवैया देखकर ही आज चीन वापस रिश्तों में नरमाहट लाने की कोशिश में है। अक्टूबर 2024 से अब तक चीन ने न केवल अपने सैनिकों को विवादित क्षेत्रों से पीछे हटाया है, बल्कि सीमा पर शांति कायम करने के लिए नई व्यवस्थाओं को भी स्वीकारा है। ऐसी बदली परिस्थितियों में मोदी का शी से मिलना और रिश्तों में सुधार आना समयोचित है। आलोचक कह सकते हैं कि शीर्ष स्तरीय कूटनीति का यह नया दौर भी अंततः विफल रहेगा और चीन भारत पर दबाव बनाता रहेगा, क्योंकि वह भारत को अपने बराबर नहीं आने देना चाहता है, लेकिन जिस पड़ोसी के साथ 3,488 किलोमीटर की सीमा लगती हो और जो एशिया के उन्हीं देशों में अपना दबदबा बना रहा हो, जहां भारत के राष्ट्रीय हित समाहित हैं, उसके साथ कम से कम सम्मानजनक कामकाजी रिश्ता होना तो आवश्यक ही है। एक उत्तरदायी और स्थिरता प्रिय देश होने के नाते भारत कभी भी चीन के साथ पुनः युद्ध नहीं चाहेगा। 'सीमा समस्या' का समाधान अब भी दूर की कौड़ी लगती है, पर बातचीत और संपर्क बनाए रखने में कोई हानि नहीं है।

चीन से संपर्क-संवाद बढ़ाने के बाद भी उसके साथ संबंधों में आई नरमी को लेकर भारत अत्यधिक आशावादी नहीं हो सकता। आपरेशन सिंदूर के समय चीन ने अपने 'सदाबहार मित्र' पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध अभूतपूर्व सैन्य सहायता दी। शी अपने 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे' को अफगानिस्तान तक विस्तारित करने पर भी जोर दे रहे हैं, जिससे वहां भारत के प्रभाव पर असर पड़ेगा। दक्षिण एशिया और हिंद महासागर के प्रत्येक देश में चीन भारत के विकल्प के तौर पर पेश आ रहा है। इस मामले में भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कम होने की कोई संभावना नहीं है। मोदी और शी का हाथ मिलाना और आपसी हितों पर मंत्रणा करने का यह मतलब नहीं कि 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' का जमाना फिर आ जाएगा। सचेत और सावधान रहते हुए जिम्मेदारीपूर्वक कूटनीति करना भारत की पहचान है। फिलहाल चीन के साथ रिश्तों में नरमी को इसी नजरिये से देखना चाहिए।

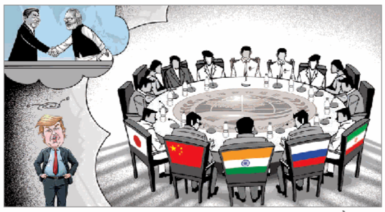

अवधेश राजपूत

इस समय भारत और चीन संवेदनशीलता के आधार पर तब अपने मतभेदों को सुलझाने में रुचि ले रहे हैं, जब भारत और अमेरिका की सामरिक साझेदारी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार युद्ध के कारण आंच आई है। भारत में चीन के राजदूत ने यह तक दावा किया है कि दोनों देश अमेरिका की धमकी और धौंस के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं, पर तथ्य यही है कि चीन भारत की ऐसी कोई क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता, जो अमेरिका के टैरिफ की वजह से होगी। चीन ने भारत पर कृषि के लिए उर्वरकों, दुर्लभ खनिजों और सुरंग खोदने वाली मशीनों के निर्यात प्रतिबंध को हटाकर भरोसे की बहाली का संकेत तो दिया है, पर असलियत यह है कि चीन को भारत के साथ लगभग 100 अरब डालर का व्यापार अधिशेष प्राप्त है। ऐसे में चीन को अमेरिका का विकल्प मानना अथवा रणनीतिक उलटफेर की आशा करना, जिसमें चीन और भारत एक साथ आकर अमेरिका को चुनौती दें, यथार्थवादी सोच नहीं है। अमेरिका द्वारा छेड़ा गया व्यापार युद्ध कभी न कभी सुलझ जाएगा, लेकिन चीन और भारत के बीच असंतुलित व्यापार का समाधान आसान नहीं दिखता।

चीन यह भी चाहता है कि भारत पश्चिमी देशों के साथ अपनी मित्रता तोड़े और उसके खेमे में आ जाए, लेकिन भारत स्वयं महाशक्ति बनने के मार्ग पर है। ऐसे में वह अपनी सामरिक स्वायत्ता पर समझौता नहीं करेगा। करना भी नहीं चाहिए। इन अंतर्विरोधों के बावजूद मोदी का शी के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयास की अहमियत को कम करके नहीं आंकना चाहिए। भारत चीन के साथ सम्मानजनक संबंध चाहता है। यह केवल शक्ति और कूटनीति के संयोजन से ही संभव है।

(लेखक जिंदल स्कूल आफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन हैं)

response@jagran.com

सतह पर आते इतिहास में गुम नायक

शिवेंद्र राणा

राजा पृथु जैसे विस्मृत नायकों का स्मरण भारतीय समाज के इतिहास बोध की चेतना के प्रसार का परिणाम है

पिछले दिनों असम के मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी के एक फ्लाईओवर को राजा पृथु के नाम समर्पित किया। इसके साथ ही 13वीं सदी के कामरूप (आज के असम) के राजा पृथु के बारे में लोगों की जिज्ञासा बढ़ी। इसलिए और बढ़ी, क्योंकि इतिहास में वे गुम से हैं और व्यापक राष्ट्रीय समाज के लिए अनजान। पृथु का पूरा नाम विश्वसुंदरदेव था। वे कामरूप यानी आज के असम के महानतम शासकों में से एक थे। उन्होंने 1185 से 1228 तक शासन किया। उन्होंने अपने शासनकाल में दो आक्रांताओं-बख्तियार खिलजी और नसीरुद्दीन से लोहा लिया। नालंदा को नष्ट करने वाले खिलजी को तो उन्होंने बुरी तरह पस्त किया था। राजा पृथु जैसे न जाने कितने नायकों ने अपनी ही संततियों के समक्ष पहचान का संकट झेला। उनका विस्मरण कुछ ऐसा ही है जैसे सालार मसूद गाजी जैसे उत्पीड़क को मजार और नेजा मेले की शोहरत हासिल हो और उसके त्राण से मुक्ति दिलाने वाले राजा सुहेलदेव को शोध में तलाशने की कोशिश हो रही हो। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि इतिहास का निरूपण सदैव विजेताओं द्वारा किया जाता आया है।

होना यह चाहिए था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय इतिहासकार अपना इतिहास अपनी दृष्टि से लिखते, लेकिन भारत में पहले इस्लामिक आक्रांताओं, यूरोपीय गौरांग महाप्रभुओं के पश्चात वामपंथियों ने इतिहास लेखन में छल किया। कथित सामासिक संस्कृति के आवरण में वामपंथी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास के संदर्भ और संदर्श तक दूषित कर दिए। साहित्य के नोबेल से सम्मानित सोवियत लेखक मिखाइल शोलोखोव अपने उपन्यास 'एंड क्वाइट फ्लोज द डान' में एक कज्जाक गीत का उल्लेख करते हैं, 'हमारी धरती पर हलों की लीकें नहीं हैं। हमारी धरती पर घोड़ों की टापों के निशान हैं और उसमें बीज नहीं, कज्जाकों के शीश बोए जाते हैं।' शोलोखोव जैसी व्यथा भारत के लोगों की भी है। आक्रांताओं के घोड़ों की टापों ने उनका वैभव नष्ट किया और उनकी संस्कृति उजाड़ने का प्रयास किया। 1947 के बाद प्राप्त स्वशासन में भी यह बौद्धिक बेईमानी विद्यमान रही। वर्तमान में इतिहास का

याद आए खिलजी को मात देने वाले राजा पृथु ● फाइल

वास्तविक निरूपण राष्ट्रीय विचारों एवं सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी एक बानगी एनसीईआरटी की किताबों में दिख रही है। इसकी जरूरत इसलिए है, क्योंकि ऐतिहासिक व्याख्याओं का आधार सांस्कृतिक मूल्यों की वैध मान्यताएं होती हैं।

आज यदि हम लचित बरफुकन, सुहेलदेव, झलकारी बाई, दलदेव महाराज, महावीरादेवी भंगी, पन्नाधाय धानुक और अब राजा पृथु जैसे विस्मृत ऐतिहासिक नायकों के चरित्र से साक्षात्कार कर रहे हैं, तो यह भारतीय समाज के सांस्कृतिक जागरण में इतिहास बोध की चेतना के प्रसार का परिणाम है। विस्मृत हुए ये नायक भारत की चैतन्य राष्ट्रीयता का संबल हैं। वर्तमान में इतिहास को नए आयाम सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों ने भी दिया है। ऐसे सामाजिक आंदोलन नहीं होते तो हम उपरोक्त ऐतिहासिक नायक-नायिकाओं का नाम भी नहीं जानते। कुछ समय पहले लखनऊ में अवंती बाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए भाजपा और सपा नेताओं के बीच जो होड़ दिखी, वह इतिहास-बोध की चैतन्यता ही प्रमाणित करती है, भले ही पृष्ठभूमि में राजनीतिक प्रेरणा हो। यह इतिहास बनाने नहीं, उसे जीने का संदर्भ है। यदि इतिहास का सही संदर्भों में यथार्थ निरूपण न हो तो भावी पीढ़ियों को सर सैयद अहमद खान, इकबाल आदि के बारे में वही सब पढ़ने-सुनने को मिले, जो एक खास एजेंडे के तहत लिखा और प्रचारित किया गया। क्या यह किसी से छिपा है कि अलीगढ़ मूवमेंट पाकिस्तान के निर्माण का आधार बना? इतिहास का निर्धारण उचित मानकों पर हो और वह असत्य वाचन का कारक न बने। इतिहास का तो अर्थ ही है-ऐसा ही हुआ था। वामपंथियों ने भारतीय इतिहास पर अपना एजेंडा स्थापित किया और कथित सद्भाव प्रसार के नाम पर कल्पित कथाएं रचीं। डा. राम मनोहर लोहिया कहते थे, जो कत्ल करने वालों को अपना पूर्वज माने, उसका आत्मगौरव झूठा है।

यह आवश्यक है कि कोई भी समाज शत्रु-बोध के भाव का विश्लेषण करे। यह इसलिए आवश्यक है, क्योंकि कभी अनजान स्रोतों से शिवाजी महाराज के बारे में मिथ्या मान्यताएं गढ़ी जाती हैं और कभी धर्मांध औरंगजेब को मंदिरों का संरक्षक बताने की चेष्टा होती है। इस पर आश्चर्य नहीं कि छद्म पंथनिरपेक्ष एवं यथास्थितिवादी वर्ग इतिहास के पुनर्लेखन का विरोधी है। आखिर पहले के इतिहासकारों द्वारा ऐसा क्या छुपाया गया, जिसके प्रकटीकरण से संघर्ष पैदा हो सकता है? इतिहास का यथार्थ विश्लेषण इसलिए और आवश्यक हो जाता है, ताकि दमन-अत्याचार की पीड़ा से गुजर चुका राष्ट्र अपना वास्तविक इतिहास जाने और भावी पीढ़ियों को सचेत करे, ताकि उसे पहले जैसी पीड़ा से न गुजरना पड़े। जनता की समझदारी पर संदेह करने का कोई कारण नहीं। तथ्यों को सत्यता के साथ रख दीजिए, जनता उसका विश्लेषण खुद कर लेगी। इसी संदर्भ में 30 दिसंबर, 1916 को ओहियो में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, 'सिर्फ अपनी आदतों से मुक्ति ही नहीं, बल्कि तमाम गंदे इतिहास से मुक्ति के जरिए ही भविष्य की सभ्यता का परचम उठाया जा सकता है।"

(लेखक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में परियोजना सहयोगी हैं)

response@jagran.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

ऊर्जा

जीवनमुक्त

मुक्ति, मोक्ष आदि पर आध्यात्मिक और दार्शनिक मीमांसकों के मध्य वाद-विवाद चलते रहे हैं। ज्ञान, भक्ति, विवेक, योग इत्यादि अनेक मार्गों के पथिक अपने-अपने तर्क देते रहे हैं, पर उनमें से कितने गंतव्य तक पहुंचे हैं यह विवेचना का विषय है। जो व्यक्ति स्वयं को नित्य-शुद्ध, नित्य-मुक्त, सत्-चित्-आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में जान लेता है, वही जीवनमुक्त कहलाता है। वह व्यक्ति अज्ञान से मुक्त होकर इस अवस्था को प्राप्त करता है।

क्या करें कि हम भी इस यात्रा पर आगे बढ़ सकें। सारा सत्य जानते हुए भी हम संसार के कुचक्र से ग्रस्त होते रहते हैं, जो अंततः सारे कष्टों का मूल कारण है। सबसे पहले मन पर नियंत्रण पाना आवश्यक है, क्योंकि मन ही विषयों का मिथ्या संसार बनाता है, पर क्या सीधे मन पर नियंत्रण संभव है? मन पर नियंत्रण से पहले आवश्यक है प्राण पर विजय। हमारे शरीर में पांच प्रकार के प्राण स्थित हैं- अपान, व्यान, समान, प्राण और उदान। अपान मूलाधार चक्र में स्थित है। व्यान स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित है। समान मणिपुर चक्र में स्थित है। प्राण अनाहत चक्र में स्थित है। और उदान विशुद्धि चक्र में स्थित है। सभी पांचों प्राण शरीर के विभिन्न अंगों, इंद्रियों और प्रणालियों को नियंत्रित करते हैं। इन प्राणों की प्रणाली पर योग और ध्यान द्वारा नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि सारी गतिविधियां इन्हीं के द्वारा क्रियाशील होती हैं। इस प्रक्रिया के बाद ही मन को शांत और एकाग्र किया जाना संभव है।

जिस प्रकार सूर्य के प्रकाशमान होने के बाद भी बादलों के कारण वह अदृश्य प्रतीत होता है, उसी प्रकार अविद्या और चंचल मन के कारण वह चैतन्य रूपी प्रकाश दृश्यमान नहीं होता। अविद्या हटाने का एक मात्र उपाय ज्ञान है, जो सिर्फ एकाग्र, शांत और अंतर्मुखी मन के माध्यम से ही बुद्धि में प्रकट होता है। जो इस मर्म को समझ लेता है वही जीवनमुक्त हो जाता है।

आदित्य नारायण अवस्थी

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

अदालतों में लंबित मामलों का सवाल

'सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला अटका हो तो' शीर्षक से लिखे आलेख में राजीव सचान ने सही सवाल उठाया है कि यदि राज्यपालों-राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर तय समय में फैसला लेना जरूरी है तो हाई कोर्ट-सुप्रीम कोर्ट के लिए क्यों नहीं? इस तरह लेखक ने एक गहन और गंभीर विषय पर प्रकाश डाला है। इस प्रकरण में संवैधानिक, व्यावहारिक और राजनीति के प्रश्न निहित हैं। प्रायः देखा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रहित में उन विषयों पर भी आदेश देता है, जिसके लिए संविधान में कोई स्पष्ट प्रविधान नहीं है। कभी-कभी न्यायालय के आदेशों से विधायिका की शक्तियों का भी कार्य संपन्न हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, दो जजों की पीठ संसद द्वारा विधेयक पेश करने, पारित करने अथवा न करने का कार्य कर देती है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, फिर भी इस प्रकार के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। जबकि इंग्लैंड में लिखित संविधान न होने पर भी ऐसे विवाद देखने को नहीं मिलते। हमारे देश में ऐसे प्रश्न कई बार उठते हैं और जनता भी असमंजस में रहती है। एक ओर तो अनेक आवश्यक और त्वरित मामलों के निर्णय वर्षों तक लंबित रहते हैं, दूसरी ओर कभी-कभी रात में ही न्यायालय की पीठ गठित होकर तुरंत सुनवाई करती है और फैसला भी हो जाता है। इन परिस्थितियों में न्यायालय की कार्यप्रणाली पर चर्चा अवश्य बनती है। क्या सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों में एकरूपता लाने का प्रयास करेगा? क्या वरिष्ठ अधिवक्ताओं की तरह सामान्य वकीलों की बात भी इसी गंभीरता से सुनी जाएगी? समय की आवश्यकता है कि इन सवालों पर सामंजस्य, एकरूपता हो और राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित विषयों पर व्यापक मंथन किया जाए।

भूषण शरण महेश, एडवोकेट, मुजफ्फरनगर

हास्यास्पद आरोप

संपादकीय आलेख 'भारत की तैयारी' पढ़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो द्वारा पीएम नरेन्द्र मोदी पर लगाए गए आरोप कि युक्रेन युद्ध मोदी की देन है हास्यास्पद है। यह आरोप उसी समय झूठ साबित हो जाता है कि इससे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रूस-यूक्रेन की समाप्ति के आसार न दिखने पर कहा था कि वह जो बाइडेन के जगह पर राष्ट्रपति होते तो यह युद्ध कदापि नहीं होने दिया जाता। इस बयान से पूरी दुनिया में यहीं संदेश गया कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन की देन है रूस-यूक्रेन युद्ध। पीटर नवारो को भारतीय प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने के पहले पूर्व में हो रहे घटनाक्रम का अध्ययन कर लेना चाहिए था। यह बयान अमेरिका द्वारा सोची-समझी रणनीति के तहत आया है। समझा जा रहा है कि अमेरिका को पता है कि यूक्रेन और रूस दोनों के साथ भारत के मैत्री संबंध काफी मजबूत हैं। इस मैत्री संबंध में विघ्न डालने के लिए नवारो का ऐसा बेतुका आरोप आया है। अमेरिका की दोहरी नीति से यूक्रेन और रूस दोनों भली-भांति परिचित हैं।

युगल किशोर राही, छपरा

शायद नहीं होता विभाजन

संजय गुप्त द्वारा लिखित आलेख भारत विभाजन के जिम्मेदार पढ़ा। अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया। एनसीईआरटी के नए माड्यूल में देश विभाजन के लिए जिन्ना, अंग्रेजों और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। भारत विभाजन की त्रासदी एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। इस विभाजन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार जिन्ना और नेहरू की महत्वाकांक्षा रही है। मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व जिन्ना कर रहे थे एवं कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नेहरू कर रहे थे। दोनों नेता किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और इसी का लाभ अंग्रेजों ने उठाया और भारत विभाजन का मसौदा तैयार किया, जिसे दोनों पार्टी कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। मेरे विचार से महात्मा गांधी से अपने जीवन में एक ही भूल हुई। यदि महात्मा गांधी देश का प्रधानमंत्री का पद स्वीकार कर लेते तो शायद देश का विभाजन रुक जाता, क्योंकि जिन्ना और नेहरू दोनों गांधी का सम्मान करते थे। मानवता को भारत विभाजन की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। भारत-पाकिस्तान दोनों देशों में खून की नदियां बहीं। आज भी पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। पाकिस्तान की कट्टरपंथी सोच की वजह से बांग्लादेश का उदय हुआ। किसी भी समाज के लिए कट्टरता नुकसानदेह साबित होता है।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गयाजी।

पोस्ट

वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही। जबकि आरबीआइ का अनुमान था कि यह 6.5 प्रतिशत ही रहेगी। युद्ध, वैश्विक नीति में अनिश्चितता और विदेशी निवेशकों के बाहर निकलने जैसे दबावों के बावजूद यह वृद्धि बहुत कुछ कहती है। भारत के पास सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का ताज बरकरार है। अजय बग्गा@Ajay_Bagga

बेहतरीन सभ्यताएं जनसांख्यिकी के कारण ढह गई हैं। हम प्राचीन रोमन साम्राज्य या आज के जापान जैसे न बन जाएं। मोनिका वर्मा@TrulyMonica

सबको पता है गाली देना बुरी आदत है और देने वाले को कभी फायदा नहीं होता, फिर भी जुबान पर कंट्रोल नहीं है। समझ नहीं आता इतनी नफरत लेकर कहां जाएंगे! मीनाक्षा जोशी@IMinakshiJoshi

यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक यूरोपीय संघ ने रूस से 213 अरब यूरो का तेल, गैस और कोयला खरीदा है। यह खरीदना जारी है। यह रूस के कुल ऊर्जा निर्यात का 23 प्रतिशत है, लेकिन यूक्रेन मोदी का युद्ध है। यूसुफ ऊंझावाला@YusufDFI

जनपथ

संभल का सच जानकर खड़े हो गए कान,
डर के कारण छोड़ घर भाग गया इंसान।
भाग गया इंसान घटी हिंदू आबादी,
सत्ता जिनके साथ हो गई उनकी चांदी।
रही उसी की भैंस हाथ में था जिसके बल,
हिंदू जन से रिक्त हो गया पूरा संभल!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर. बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 139

****

कल्पमेधा

यही वह सही समय है जब माता-पिता अपने बच्चों को यह सिखाएं कि विविधता में ही सौंदर्य और शक्ति है।

– माया एंजिलो

सहयोग का सफर

नई भू-राजनीतिक परिस्थितियों में उथल-पुथल के बीच अमेरिका जैसा देश जहां अपने हित में अन्य देशों पर मनमाने फैसले थोपने की कोशिश में है, तो स्वाभाविक ही भारत के सामने भी अपना हित कायम रखने की चुनौती खड़ी हुई है। यही वजह है कि पिछले कुछ समय से अलग-अलग देशों पर शुल्क लगा कर व्यापार नीति को प्रभावित करने की अमेरिकी कोशिश के समांतर भारत ने अपने लिए वैकल्पिक रास्ते तैयार करना शुरू कर दिया है। इस क्रम में रूस और चीन से नए सिरे से संवाद कायम करने और विवादित मसलों को सुलझा कर संबंधों के नए आयाम पर विचार करने के लिए भारत ने कूटनीति के मोर्चे पर जो रुख अपनाया है, उसे इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। पिछले दिनों भारत ने रूस सहित अन्य कुछ देशों में कूटनीतिक पहल के जरिए यह संदेश दिया है कि अमेरिका से संवाद के रास्ते भले ही खुले हैं, लेकिन उसके रवैये का सामना करने के लिए भारत तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान और चीन की यात्रा को भी दरअसल नए विकल्प खोजने की कोशिश की एक कड़ी के तौर पर देखा जा सकता है। अपनी जापान यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।

दरअसल, अमेरिका की ओर से शुल्क से संबंधित नई नीति थोपने और इस संबंध में भारत के तर्कों को खारिज करने के बाद अब स्थिति यही है कि भारत इसका सामना करने के लिए नए विकल्प तैयार करे। इस लिहाज से देखें तो जापान और चीन भी उन देशों की सूची में हैं, जिन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शुल्क कूटनीति की मार पड़ी है। इसके अलावा भी जो देश ट्रंप के इस रवैये के दायरे में आए हैं, उनके लिए यह समझना मुश्किल है कि अमेरिका के इस राह को अपनाने के क्या कारण हैं और इसके जरिए वह क्या हासिल करना चाहता है। अमेरिकी शुल्क नीति के लागू होने के बाद चीन और जापान ऐसे देश हैं, जिनका व्यापार भी भारत की तरह ही प्रभावित हो सकता है। मगर यह स्थिति तभी ज्यादा बिगड़ती है, जब निर्यात के लिए मुख्य रूप से किसी एक देश पर निर्भरता हो। यही वजह है कि पच्चीस से लेकर पचास फीसद तक शुल्क थोपे जाने के बाद इससे प्रभावित होने वाले सभी देशों के सामने नई स्थिति से निपटने के लिए नए उपायों पर विचार जरूरी हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी की जापान और चीन यात्रा को इसी कूटनीति को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है।

निश्चित रूप से पिछले कुछ वर्षों से चीन के साथ भारत के जैसे संबंध रहे हैं, उसमें हर स्तर पर सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। यह छिपा नहीं है कि सीमा पर तनाव से लेकर गलवान में टकराव तक और फिर अरुणाचल प्रदेश में नाहक विवाद खड़ा करके चीन भी सैन्य मोर्चे पर अपनी मनमानी चलाना चाहता है। मगर अब अमेरिकी शुल्क नीति की जद में आने के बाद उसके लिए भी आर्थिक मोर्चे पर नए हालात से निपटना एक चुनौती है। वहीं, जापान को अमेरिका के करीब माना जाता रहा है, लेकिन उसकी नई नीति की चपेट में वह खुद भी है। स्वाभाविक है कि जापान और चीन भी अमेरिकी शुल्क से उपजी स्थिति का सामना करने के लिए नए विकल्प खोजेंगे। अब अगर भारतीय प्रधानमंत्री की जापान और चीन की यात्रा के बाद किसी व्यापक आर्थिक सहयोग पर सहमति बनती है, तब यह नया कूटनीतिक मोर्चा होगा, जिसके जरिए अमेरिकी शुल्क की वजह से खड़ी व्यापार युद्ध की स्थिति का सामना करने की कोशिश होगी।

सुस्त रफ्तार

विनिर्माण क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन से भारत में औद्योगिक उत्पादन की लुभावनी तस्वीर जरूर दिख रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस मोर्चे पर चमक धुंधली या कमजोर ही पड़ी है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, बीती जुलाई में औद्योगिक उत्पादन चार महीने के उच्चतम स्तर पर यानी 3.5 फीसद पर पहुंच गया है। दरअसल, इसकी बड़ी वजह विनिर्माण क्षेत्र में आई तेजी है। मगर इसके बरक्स इसी वर्ष मार्च में यह 3.9 फीसद थी। जबकि पिछले वर्ष जुलाई में उत्पादन पांच फीसद की दर से बढ़ा था। यानी सालाना आधार पर तुलना करें, तो पिछले चार महीने के उच्च स्तर पर उत्पादन वृद्धि को बहुत उत्साहजनक नहीं माना जा सकता। वहीं इस वृद्धि को सिर्फ विनिर्माण क्षेत्र के भरोसे भी नहीं छोड़ा जा सकता। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के संशोधित आंकड़े खुद यह बताते हैं कि खनन उत्पादन में 7.2 फीसद गिरावट आई है। जबकि एक वर्ष पहले इसमें 3.8 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई थी। इस बार बिजली उत्पादन भी उत्साहवर्धक नहीं। इसमें बेहद मामूली वृद्धि दर्ज की गई है।

इसमें दोराय नहीं कि भारत को अपने औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार तेज करनी होगी। छोटे लक्ष्यों को आधार मान कर और आंकड़ों के भरोसे अब नहीं रहा जा सकता। वह भी ऐसे समय में जब देश अमेरिका की ओर से थोपे गए मनमाने शुल्क का सामना कर रहा है और माना जा रहा है कि कई भारतीय उत्पादों पर इसका दूरगामी असर पड़ेगा। ऐसे में भारत को न केवल अपना बाजार मजबूत करना होगा, बल्कि नई संभावनाएं भी तलाशनी होंगी। सही है कि विनिर्माण क्षेत्र में असीमित संभावनाएं हैं। मगर इसे अधिक प्रोत्साहित करने के साथ खनन और बिजली उत्पादन को दोगुना करना होगा। वक्त आ गया है कि सरकार आर्थिक मोर्चे पर नए रास्ते खोजने की ओर बढ़े, ताकि देश को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के दावे को वास्तव में जमीन पर उतारने की कवायद को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके।

शिक्षा व्यवस्था और संस्थाओं के दायित्व

भारतीय ज्ञान परंपरा पर हर कोई गर्व करता है और यह कहने में किसी को हिचक नहीं होगी कि भारत ही गणतंत्र को लागू करने में अग्रणी था! मगर, वर्तमान स्थिति को देखकर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति निराश ही होगा।

जगमोहन सिंह राजपूत

भारत की राजनीति को लेकर संचार माध्यम प्रतिदिन जो परोसते हैं, वह यही दर्शाता है कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति के अत्यंत महत्त्वपूर्ण अंश भूल गए हैं: सुसंस्कृत सामाजिक व्यवहार और मर्यादापूर्ण वैचारिक अभिव्यक्ति! हमारे तरुण और युवा उन लोगों की तरफ देखते हैं, जिनका कृत्य और व्यवहार उनके समक्ष लगातार आता रहता है। इसमें सबसे पहले आते हैं चयनित प्रतिनिधि, विशेषकर संसद में जो कुछ होता है, या नहीं होता है। सवाल है कि क्या हमारे देश में संसद को सुचारु रूप से चलाने की क्षमता प्राप्त करना शेष है? अगर ऐसा है, तो इस चिंताजनक स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है। यह प्रश्न देश भर के शिक्षकों के समक्ष भी एक चुनौती बनकर पिछले कुछ दशकों में उभरा है कि क्या हम ऐसे व्यक्तित्व निर्माण में असफल रहे हैं, जो भारतीय लोकतंत्र को उसके मूलभूत सिद्धांतों और अवधारणाओं के अनुसार चला सकें? भारतीय ज्ञान परंपरा पर हर कोई गर्व करता है और यह कहने में किसी को हिचक नहीं होगी कि भारत ही गणतंत्र को लागू करने में अग्रणी था! मगर वर्तमान स्थिति को देखकर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति निराश ही होगा!

प्रारंभ से 'महाजनो येन गतः सा पन्थाः' का सूत्र बच्चों को सिखाने वाली व्यवस्था इस समय असमंजस का शिकार होकर अपना रास्ता तलाश रही है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का प्रसारण इस असमंजस और अकुलाहट को और बढ़ा देता है। यदि संसद में कामकाज के बजाय हंगामा या अमर्यादित व्यवहार होता है, तो ऐसे दृश्यों को सारा देश बार-बार देखता है। विचारणीय बात यह है कि किशोरों और युवाओं के संवेदनशील मस्तिष्क पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर कोई किशोर या युवा ऐसा ही व्यवहार अपने शिक्षक के साथ करता है और उस पर कार्रवाई की जाती है, तो क्या यह नैसर्गिक न्याय होगा? जनप्रतिनिधियों के पास तो सभी संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, मगर ऐसे किसी किशोर या युवा के सामने तो भविष्य का धुंधलका लगातार गहराता जाता है। उनका व्यग्र और व्यथित होना समाज तथा नीति निर्धारकों की समझ में आना चाहिए।

वर्ष 1960 के आसपास लोकतंत्र की प्रारंभिक समझ के लिए तैयार होते युवाओं के सामने उस समय स्वतंत्रता संग्राम के अनेक वरिष्ठ नायक देश में मौजूद थे। उनके त्याग, तपस्या और सेवा इतिहास की गाथाएं बनने के योग्य थीं और ये बनीं भी। आज के युवाओं के समक्ष आदर्श और नैतिकतापूर्ण आचरण वाले वे 'महाजन' कितने हैं और किस स्थिति में हैं, उस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जो हैं, वे समय और व्यवस्था की लगातार बढ़ती चमक-दमक से आच्छादित नई पीढ़ी के आचार-विचार और व्यवहार में छिप जाते हैं, या पीछे धकेल दिए जाते हैं। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित नेता भी अपनी राजनीतिक पार्टी से जुड़े रहते हैं और देश की सियासत की दिशा बदलने में अपनी ऊर्जा लगाते रहने का दिखावा करते रहते हैं। ऐसे नेताओं पर अक्सर कोई रोक-टोक लगाने का कार्य व्यवस्था नहीं कर पाती है। कई बार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग राजनीतिक दलों के दशकों तक तारणहार बने रहते हैं।

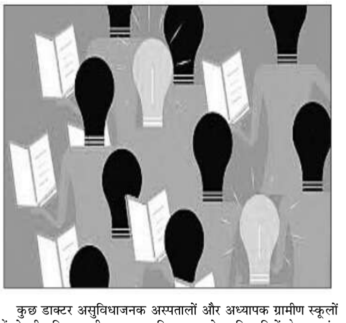

कुछ डाक्टर असुविधाजनक अस्पतालों और अध्यापक ग्रामीण स्कूलों में दो-तीन दिन ड्यूटी पर जाकर जिला स्तर के अधिकारियों से साठगांठ कर हफ्ते भर की पूरी उपस्थिति दर्ज करा लेते हैं। स्कूलों में तो 'एवजी अध्यापक' के चलन की खबरें कई दशकों से आती रही है। निस्संदेह

> **भारतीय संस्कृति और संस्कारों पर देश गर्व करता है, पुन: 'विश्व गुरु' बनने के सपने देखता है, लेकिन आज भी अनेक स्थानों पर कुछ लोग दलित दूल्हे का विवाह के अवसर पर घोड़ी पर बैठना सहन नहीं कर पाते हैं। सोच चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हो या गांव के पूर्व जमींदार की, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यह वैचारिकता अब राजनीतिक परिवारों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी स्वरूप ले रही है। यदि थोड़ी देर के लिए पक्ष-विपक्ष की राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा की यह समय किसी भी भारतीय से केवल एक ही अपेक्षा करता है कि वह भारत सरकार की अमेरिका के समक्ष न झुकने की नीति का दृढ़तापूर्वक समर्थन करे!**

भारत ने अपने युवाओं की प्रखरता और मेधा से वैश्विक पटल पर बड़ा नाम कमाया है, जबकि उसके संभवतः 30-35 फीसद स्कूल ही अपेक्षित स्तर पर चल रहे हैं, बाकी राम-भरोसे हैं। राज्य सरकारें अन्य प्राथमिकताओं में व्यस्त हैं! सरकारी स्कूलों में लगभग दस लाख स्वीकृत पद खाली हैं। व्यवस्था में इस बात को लेकर कोई चिंता दिखाई नहीं देती है। नीति-निर्माताओं और उनका क्रियान्वयन करने वालों के लिए तो चमकीले निजी स्कूल उपलब्ध हैं!

शिक्षा की चुनौतियां राष्ट्र के समक्ष उभरने वाली चुनौतियों से अलग नहीं हो सकती हैं। यह प्रजातंत्र की किस अवधारणा को पोषित करता है कि एक सार्वभौमिक राष्ट्र भारत के लिए किस देश से क्या खरीदा जाए, यह अमेरिका तय करे? यानी वैश्विक स्तर पर जमींदारी, जिसे उपनिवेशवाद के आकाओं ने ईश्वर-प्रदत्त 'उत्तरदायित्व' मान लिया था और जिससे खुद को सुसज्जित कर उन्होंने 'असभ्यों के उद्धार' का उत्तरदायित्व उठा लिया था, वह 'अधिकार' अभी भी उनकी सोच से बाहर नहीं हो पाया है। 'अन्य पर श्रेष्ठता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार' की अदम्य अभिलाषा को कुछ लोग छोड़ने को तैयार नहीं हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश अपने बनाए हथियारों को यूक्रेन को बेचते या देते रहें, उस देश के लड़ते रहने में अपनी स्वार्थ पूर्ति करते रहें और भारत पर आरोप लगाएं कि उसके द्वारा रूस से तेल खरीद की वजह से युद्ध को बढ़ावा मिल रहा है! ऐसे में राष्ट्रीय एकता का सशक्त होना और विश्व के समक्ष उसका जाहिर होना, देश के सम्मान के लिए आवश्यक है।

भारतीय संस्कृति और संस्कारों पर देश गर्व करता है, पुनः 'विश्व गुरु' बनने के सपने देखता है, लेकिन आज भी अनेक स्थानों पर कुछ लोग दलित दूल्हे का विवाह के अवसर पर घोड़ी पर बैठना सहन नहीं कर पाते हैं। सोच चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हो या गांव के इस (पूर्व) जमींदार की, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यह वैचारिकता अब राजनीतिक परिवारों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी स्वरूप ले रही है। यदि थोड़ी देर के लिए पक्ष-विपक्ष की राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि यह समय किसी भी भारतीय से केवल एक ही अपेक्षा करता है कि वह भारत सरकार की अमेरिका के समक्ष न झुकने की नीति का दृढ़तापूर्वक समर्थन करे, चाहे वह सरकार से कितना ही असंतुष्ट क्यों न हो!

पाकिस्तान के विरुद्ध जब सैन्य कार्रवाई हुई, सारे देश ने एकसाथ उस पर संतोष प्रकट किया, सेना के साहस और तैयारी की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई। मगर, इस राष्ट्रीय अभिव्यक्ति में भी कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, वे ऐसे प्रश्न उठाते रहे, जो सरकार ही नहीं, बल्कि सेना पर भी अविश्वास पैदा कर दें। शायद वे भूल गए कि उन्होंने इस व्यवहार से अपने प्रति जन समाज में अनावश्यक दूरियां बना लीं! देश में अनुभवी, विचारशील और संयमित नेतृत्व की आवश्यकता हर स्तर पर होती है, राजनीति में इसकी हर दल को सख्त जरूरत होती है। इस परिप्रेक्ष्य में जब भारत में राजनीतिक अपरिपक्वता की स्थिति पर नजर डाली जाए, तो अनगिनत लोगों को अत्यंत निराशा होगी। इन सब मसलों का समाधान तो शिक्षा संस्थानों और संवैधानिक संस्थाओं से ही निकलेगा। जब हमारे भीतर संस्कार, सद्भाव, सदाचार, राष्ट्र प्रेम और कर्त्तव्य परायणता की नींव ही कमजोर होगी, तो जाहिर है कि हमारा व्यक्तित्व भी वैसा ही आकार लेगा। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में समय के साथ जरूरत के हिसाब से सुधार कर उसके मूल्यों को समझने और समझाने की आवश्यकता है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

घरौंदों की तलाश

दुनिया मेरे आगे

रितुप्रिया शर्मा

घरौंदों की तलाश में करोड़ों लोग इधर से उधर भटकते रहते हैं, वर्षों तक संघर्ष करते हैं, तब जाकर कहीं उन्हें एक छोटा-सा घर मिलता है। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि वह छोटा घर भी उन्हें नसीब नहीं होता। अपने घर में रहने का सुख अलग और खास होता है। जब आदमी किराए के मकान को छोड़ कर अपने मकान में रहने जाता है, तो उसे ऐसा लगता है कि आज ही वह अपने जीवन में स्वतंत्र हुआ है। हालांकि यह भी सच है कि छोटे से लेकर बड़े शहरों के हजारों बाशिंदे किराए के मकान को ही अपना घरौंदा बनाकर रह रहे हैं। उन्हें कभी मजबूरी में तो कभी नौकरी और अपने काम के लिए किराए के मकान में रहना पड़ता है। इस सबके बीच इसमें कोई दोराय नहीं कि आवास एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसका निराकरण होना आवश्यक है। मगर आर्थिक जटिलताओं के और घनीभूत होने के दौर में क्या अपना घर होने का सवाल इतना आसान रह गया है?

अपने घर का सपना हर आदमी हर रोज देखता है। यह जीवन के कुछ मूलभूत उद्देश्यों में शामिल होता है। संघर्ष करते-करते दो कमरों की आस में कभी-कभी व्यक्ति जीवन की संध्या तक पहुंच जाता है, लेकिन अपना मकान नसीब की ही बात हो जाती है।

आज शहर कंक्रीट के जंगल बन गए, लेकिन आवास एक समस्या बनकर उभरी है। किराएदार होने का दर्द हो या सड़क पर सोने का संकट, समस्या दोनों ही रूप में काफी गंभीर है। टपकती छतें, मकान मालिक के ताने या फिर बार-बार मकान बदलने का झंझट आदि, संकट में सिर्फ आम आदमी पिसता है। सरकारों ने समय-समय पर कम कीमतों पर आवासीय कालोनियां बसाने का दावा किया है, लेकिन सच यह है कि कई बार यह भी आम आदमी की पहुंच से बाहर ही रहा है। सरकार की ओर से पहुंच वाली कीमत पर आवास उपलब्ध कराने की बात तो कही जाती है, लेकिन संसाधनों के साथ-साथ आवासों की सीमित उपलब्धता ने इस संकट को बरकरार रखा है।

दिल्ली, मुंबई जैसे महानगर में मकान लेना मध्यम वर्ग के लिए अब कल्पना होती जा रही है। सरकार की ओर से जरूरतमंदों को आवास मुहैया कराने की योजना के जरिए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की दिक्कतों को कुछ कम करने की कोशिश हो रही है और उसे महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है। इस योजना में झुग्गी-झोपड़ी वालों को भी शामिल किया गया। इसके अंतर्गत कमजोर वर्ग के लोगों, निम्न आय वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के उन लोगों को भी शामिल किया गया, जिनके पास आवास नहीं है या कच्चे मकान हैं। मगर हकीकत यह है कि इन कवायदों के बावजूद आज भी बहुत सारे लोग सिर्फ अपने घर का सपना देखने तक सीमित हैं।

वक्त के साथ सब कुछ महंगा होते जाने और आय में कमी के साथ-साथ घर बनाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। बड़े रिहाइशी परिसरों या बहुमंजिला इमारतों में फ्लैट या छोटे से छोटे घरों की कीमत अब लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। ऐसे में गरीब आदमी की आर्थिक क्षमता उसे यह सपना देखने से भी वंचित करती है कि वह कहीं घर बना ले। जहां दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा हो, वहां अपना घर लेना वाकई असंभव दिखता है।

इसके लिए हमारी सरकारों को कोई सुचिंतित पहल करनी होगी, न केवल अपने स्तर पर, बल्कि जमीन-जायदाद की कीमतों पर भी नियंत्रण रखना होगा। व्यक्ति तभी सुकून से जीवन जी सकता है, जब उसका स्वाभिमान बरकरार रहे। यह हमारे समाज की जिम्मेदारी भी है कि व्यक्ति स्वाभिमान के साथ जिए। अगर व्यक्ति किराएदार के तौर पर रह रहा है तो उसके अधिकारों और सम्मान का पूरा ध्यान रखना कई बार व्यक्तिगत स्तर पर इस आवासीय तनाव को कम कर सकता है।

> **वक्त के साथ सब कुछ महंगा होते जाने और आय में कमी के साथ-साथ घर बनाना एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। बड़े रिहाइशी परिसरों या बहुमंजिला इमारतों में फ्लैट या छोटे से छोटे घरों की कीमत अब लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। ऐसे में गरीब आदमी की आर्थिक क्षमता उसे यह सपना देखने से भी वंचित करती है कि वह कहीं घर बना ले।**

इसके अलावा, मकानों के निर्माण से संबंधित सामग्री जैसे सीमेंट, बजरी, ईंटों से लेकर मजदूरी तक सभी चीजों की कीमतें निर्धारित होनी चाहिए। उनमें बेतहाशा बढ़ोतरी की स्थिति को नियंत्रित किया जाना चाहिए। निर्माण सामग्री की मनमानी कीमतें घर बनाने के आम आदमी के हौसले को पस्त कर देती हैं। साथ में समाज के समर्थ लोग अगर खुद को सक्षम पाएं, तो वे एक या दो परिवारों के लिए घर की छत का इंतजाम कर सकते हैं। यह बहुत नेक काम होगा। उनके ऐसा करने से धीरे-धीरे बहुत से लोग आगे आएंगे और इस समस्या को हल करने में मदद कर पाएंगे।

चाहे वह सड़क पर सो रहा आदमी हो या किराए की छत के नीचे आस लगाए बैठा व्यक्ति, दोनों ही परिस्थितिवश मजबूर हैं, लेकिन उनको मजबूत बनाकर समाज उनको एक आधारशिला प्रदान कर सकता है। ऐसा सुनिश्चित करके बहुत सारे जरूरतमंद लोगों की रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकता पूरी की जा सकती हैं। हमारा देश लोकतांत्रिक और कल्याणकारी विचारधारा पर आधारित है, तो उसके जरूरतमंद नागरिकों के पास सम्मान से जीने के लिए एक घर हो तो इससे आखिरकार बेहतर भविष्य का ही निर्माण होगा।

चौपाल

शिक्षा का बाजार

हाल ही में आए एक सर्वेक्षण ने शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई उजागर कर दी है। इसके अनुसार देश के लगभग 27 फीसद स्कूली विद्यार्थी कोचिंग का सहारा लेते हैं। यह आंकड़ा केवल शहरी क्षेत्रों का नहीं, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी तेजी से बढ़ रहा है। सवाल उठता है कि जब सरकार शिक्षा को लेकर लगातार नए-नए दावे और योजनाएं पेश करती है, तो विद्यार्थी अतिरिक्त खर्च कर कोचिंग लेने के लिए क्यों मजबूर हैं। चाहे सरकारी विद्यालय हों या निजी विद्यालय, शिक्षा का स्तर ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी केवल उसी पर निर्भर रह कर प्रतियोगी परीक्षाओं या उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। अभिभावक भी अब यह मानने लगे हैं कि यदि बच्चों को अतिरिक्त कोचिंग नहीं दिलाई गई, तो वे पीछे रह जाएंगे। यही कारण है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार भी किसी न किसी तरह से कोचिंग का खर्च उठाते हैं। सर्वे रपट यह भी दर्शाती है कि सरकारी प्रयासों के बावजूद लगभग 45 फीसद विद्यार्थी अब भी निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं। इसका बड़ा कारण सरकारी विद्यालयों की छवि है। अब जरूरत सरकारी विद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और शिक्षकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की है।

– मो अजहर आलम अंसारी, पूर्णिया

शुल्क का मुकाबला

अमेरिका ने भारत पर पचास फीसद शुल्क थोप दिया है। ब्राजील के साथ भारत दुनिया का दूसरा देश है, जिस पर अमेरिका ने 50 फीसद शुल्क लगाया है। अब ऐसा देश हों, तो दुश्मन की क्या जरूरत? यह बात सही है कि भारत का सबसे अधिक निर्यात (लगभग 20 फीसद) अमेरिका के साथ ही होता था। यह भी ठीक है कि अमेरिका के शुल्क लगाने से भारत का कपड़ा उद्योग, आभूषण, चमड़ा तथा कृषि उद्योग काफी प्रभावित होंगे। यह भी हो सकता है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था और विकास दर पर कुछ असर पड़े और भारत के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में बेरोजगारी दर बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत इस संकट से बाहर नहीं निकाल सकता। कोरोना काल इसका उदाहरण है। भारत हर आपदा को अवसर में बदलना जानता है। हमने अमेरिका के शुल्क संग्राम से मुकाबला करने के लिए दूसरे देशों से (लगभग 40 देश) बातचीत करनी शुरू कर दी है। कोई तो रास्ता निकलेगा।

– विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

खोखले होते पहाड़

'आपदा के सबक' (संपादकीय, 28 अगस्त) विचारणीय है। तमाम तकनीकी विकास और प्रगति के बावजूद इन दिनों प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि इस बात का सबूत है कि हम इन घटनाओं से और अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखते, कोई सबक नहीं लेते। हिमाचल हो या उत्तराखंड, या फिर पहाड़ हो या मैदान। हमें तो केवल सुविधाएं चाहिए। हर जगह पांच सितारा विलासिता चाहिए। विकास के नाम पर हम खुशी-खुशी पहाड़ों को खोखला करने के लिए तैयार बैठे हैं। अनियंत्रित विकास और असीमित भौतिक सुविधाओं को खड़ा करने के लिए पहाड़ों की प्राकृतिक संरचना तथा पर्यावरण को दांव पर लगा दिया गया है। सुविधाओं के नाम पर हमने केवल पर्यावरण को ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि पहाड़ों की प्राकृतिक मजबूती के लिए अनिवार्य जंगल भी बेरहमी से उजाड़ डाले। नतीजा यह कि आपदाओं के रूप में आज हम अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। पहाड़ लगातार दरक रहे हैं।

– इशरत अली कादरी, भोपाल

मनुष्य का धर्म

'संवाद की संवेदना' (संपादकीय, 27 अगस्त) पढ़ा। देखा जाए तो संवाद की अपनी गरिमा होती है। संवाद ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी बात को बिना किसी को चोट पहुंचाएं, संदेश के रूप में कह जाएं। सोशल मीडिया पर जो भी सामग्री परोसी जा रही है, वह निजी जीवन से ज्यादा जुड़ा होता है, जो आपत्तिजनक होने के साथ-साथ निंदनीय भी है। जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, अखबारों और पत्रिकाओं में कार्टून, हास्य-व्यंग्य और चुटकुले आते थे। वे न केवल पारिवारिक तथा सामाजिक होते थे, बल्कि चेहरे पर मुस्कान भी ले आते थे। प्रिंट मीडिया आज भी इस धर्म का पालन कर रहा है। मगर सोशल मीडिया पर बेसिर-पैर की सामग्री धड़ल्ले से परोसी जा रही है। कोई लगाम नहीं है। हमारा उद्देश्य व्यक्ति तथा समाज को सही दिशा देना और तनाव कम करना होना चाहिए।

– हेमा हरि उपाध्याय, 'अक्षत', उज्जैन

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

अभिमत

नुआखाई का शाब्दिक अर्थ 'नया खाना' है। यह त्योहार धान की नई फसल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। नए अन्न की पूजा की जाती है। इस मौके पर किसान खेती के औजारों, जैसे हल-बैल, फसल और खेत की पूजा करते हैं। यह त्योहार खुशी और उम्मीद जगाता है। इस त्योहार में लोग उनकी कुल देवी-देवता की खेतों में पूजा करते हैं और धन-धान्य से भरपूर होने की कामना करते हैं।

पश्चिम ओडिशा में नुआखाई पर्व

नवाचार

■ बाबा मायाराम

> किसान के घर का बीज होता था, पशुओं की गोबर खाद होती थी, हल-बैल से खेती होती थी, इसलिए किसान की लागत कम होती थी। अब भी प्राकृतिक खेती में यही तौर-तरीके अपनाए जाते हैं। स्थानीय पेड़ पौधों की पत्तियों से जैव कीटनाशक बनाए जाते हैं। जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। इसमें भी कृषि लागत कम हो जाती है। पिछले कुछ सालों से रासायनिक खेती का संकट साफ तौर पर उभरकर सामने आया है। खेती की लागत बढ़ती जा रही है।

पिछले कुछ दिनों से पश्चिम ओडिशा के बरगढ़ शहर में प्रवास करने का मुझे मौका मिला है। इस इलाके में दो दिन पहले नुआखाई का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यह पहला मौका था, जब मुझे इस पर्व को नजदीक से देखने और शामिल होने का अवसर मिला। हालांकि ओडिशा से लगे छत्तीसगढ़ में भी यह त्योहार मनाया जाता है, पर पश्चिम ओडिशा में जिस उत्साह और उमंग से इसे मनाया जाता है, उसकी छटा अनूठी है।

मैं ओडिशा के बरगढ़ में समता भवन में ठहरा हुआ हूं। यह प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक किशन पटनायक की स्मृति में बना है। यह जय किसान आंदोलन का स्थानीय कार्यालय भी है। यानी किसानों का केन्द्र है। लिंगराज भाई, जो किसान संगठन के अग्रणी पंक्ति के नेतृत्वकर्ता हैं, ने बताया कि नुआखाई का किसानों के जीवन और संस्कृति में विशेष महत्व है।

नुआखाई का शाब्दिक अर्थ 'नया खाना' है। यह त्योहार धान की नई फसल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। नए अन्न की पूजा की जाती है। इस मौके पर किसान खेती के औजारों, जैसे हल-बैल, फसल और खेत की पूजा करते हैं। यह त्योहार खुशी और उम्मीद जगाता है।

इस त्योहार में लोग उनकी कुल देवी-देवता की खेतों में पूजा करते हैं और धन-धान्य से भरपूर होने की कामना करते हैं। नुआखाई के एक दिन पहले धान की बालियों के साथ चिवड़ा, और पूजा के फूल पूजा की तैयारी के लिए रख लिए ? जाते हैं।

इस मौके पर शहर की दुकानें व सभी कामकाज बंद होते हैं। शहरों में गांव के काम करने वाले कामकाजी लोग व मजदूर गांव चले जाते हैं। यहां तक कि चाय-नाश्ते की दुकानें भी बंद होती हैं।

सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। इस त्योहार के लिए कई दिनों से तैयारी करते हैं। घरों की साफ-सफाई व लिपाई-पुताई भी की जाती है।

इस दिन किसान कार्यकर्ता किशोर भाई और उनकी पत्नी सौदामिनी ने मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने स्वाली (मीठी रोटी) खीर, दाल-चावल, पापड़, चटनी और हरी पत्तीदार सब्जियां बनाई थीं। उन्होंने बताया कि अरसा पीठा विशेष रूप से तैयार किया जाता है। मुझे सौदामिनी जी ने राखी भी बांधी, जो मध्यप्रदेश में रक्षाबंधन के दिन बांधी जाती है।

किशोर भाई बताते हैं कि पहले के जमाने में लोग पौष्टिक अनाज जैसे कोदो, मडिया खाते थे, और यह अनाज बहुत ही कम समय में पककर आ जाते थे। लेकिन जब धान की फसल आती थी, तब लोगों की खुशी बढ़ जाती थी। इसलिए इस त्योहार पर धान की फसल, पेड़, खेती के औजार, बैल इत्यादि की पूजा की जाती थी।

उन्होंने बताया कि वे बचपन में इस मौके पर गुडू (कबड्डी की तरह खेल) और फुटबाल खेलते थे। लेकिन इसमें अब कमी आई है। कुछ गांवों में सहभोज भी होता था।

नुआखाई के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो जाता है। यह कुछ समय तक चलता है। इसमें भी लोगों का मिलना-जुलना होता रहता है।

इस मौके पर मुझे कुछ साल पहले ओडिशा के मुनिगुड़ा की रेल यात्रा याद आ रही है। मैं मुनिगुड़ा एक मिश्रित खेती का प्रयोग देखने गया था। वहां से रायपुर लौटते समय ट्रेन में दूरदराज गांव की एक बुजुर्ग महिला मिली थी, जो बिलासपुर में रहनेवाली उसकी बेटी के लिए नुआखाई के पकवान लेकर जा रही थी। उसने पोटली दिखाते हुए बताया था कि वह उसकी नातिनों के लिए गांव से परसा पीठा बनाकर ले जा रही है। यानी यह परिजनों से मिलने-जुलने का भी अच्छा मौका होता है।

यह त्योहार भाईचारे का भी है, लोग नुआखाई जुहार व भेंटघाट (सांस्कृतिक कार्यक्रम) के लिए एक दूसरे के घर आते-जाते हैं। आपस में मिलकर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं भी देते हैं। सुदूर शहरों मे नौकरीपेशा लोग भी गांव को चले आते हैं, और त्योहार में शामिल होते हैं।

इस त्योहार में जिन खेती के औजारों व बैलों की पूजा होती है, अब उनमें से कईयों का खेती में उपयोग कम हो गया है, या नहीं के बराबर है। हल-बैल की जगह ट्रेक्टर आ गए हैं। जबकि पहले पशुओं के बिना खेती संभव नहीं थी। रासायनिक खेती की अपनी कई समस्याएं है, जो सभी जानते हैं।

हाल ही में पोला त्योहार निकला है, इसमें ग्रामीणों द्वारा बैलों की पूजा की जाती है। पशुपालन के बिना खेती अधूरी है। इसमें एक चक्र बना रहता था। फसलों के ठंडल व भूसा, खेत के चारे को पशु खाते थे, खेतों में उनसे जुताई होती थी, उनके गोबर खाद से खेत की मिट्टी उर्वरक बनती थी। इस तरह टिकाऊ खेती की परंपरा थी।

किसान के घर का बीज होता था, पशुओं की गोबर खाद होती थी, हल-बैल से खेती होती थी, इसलिए किसान की लागत कम होती थी। अब भी प्राकृतिक खेती में यही तौर-तरीके अपनाए जाते हैं। स्थानीय पेड़ पौधों की पत्तियों से जैव कीटनाशक बनाए जाते हैं। जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। इसमें भी कृषि लागत कम हो जाती है।

पिछले कुछ सालों से रासायनिक खेती का संकट साफ तौर पर उभरकर सामने आया है। खेती की लागत बढ़ती जा रही है। किसानों पर कर्ज हो जाता है और धीरे-धीरे वे इस कर्ज से उबर नहीं पाते हैं। क्योंकि खेती की लागत के अलावा और भी अन्य खर्चे बढ़ गए हैं।

हमारी खेती में सैकड़ों सालों की अच्छी परंपराएं रही हैं। कृषि संस्कृति रही है। हमारे अधिकांश त्योहार खेती से जुड़े हैं। दीपावली भी इनमें से एक है। दीवाली पर गाय, बैल आदि सभी पालतू जानवरों को सजाया जाता है। उनकी पूजा की जाती है। यह वह समय होता है, जब किसान के घर खरीफ की फसल आ जाती है। इस दीवाली में समस्त जीव-जगत के पालन का विचार शामिल है।

दीपावली पर भी अन्न व पशु धन की पूजा की जाती है। पहले स्कूलों में भी दीपावली की लम्बी छुट्टी होती थी। इसे फसली छुट्टी भी कहते थे। इस दौरान बच्चे उनके अभिभावकों के साथ खेतों में काम करते थे। खेती के तौर-तरीके सीखते थे। यानी फसल कटाई के लिए अवकाश भी इसे कहा जाता था।

खेती अब कई समस्याओं से घिर गई है। कृषि सभ्यता ठहर गई है। खेती व गांव उजड़ती हुई सभ्यता के प्रतीक बनते जा रहे हैं। हम ऐसे आधुनिक समय में रह रहे हैं, जहां सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। किसान व किसान की पीड़ा हमारी आंखों से ओझल हो रहे हैं।

हमारे देश की जलवायु, मिट्टी-पानी , हवा, जैव विविधता और पर्यावरण खेती के लिए अनुकूल है। नुआखाई जैसे त्योहार खेती की अच्छी आपस में जोड़ने वाली परंपरा, भाईचारा और प्रकृति के साथ समन्वय करने वाली कृषि और उसकी संस्कृति के वाहक है। क्या हम ऐसी संस्कृति को बचाना चाहेंगे ?

बीता सप्ताह

23 अगस्त

- बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग आधार और 11 दस्तावेजों को मान्य करें।
- श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंध को सरकारी धन के दुरूपयोग मामले में सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया।
- भारत में जन्मे ब्रिटेन के प्रमुख उद्योगयम लॉर्ड स्वराज मॉल का निधन हो गया।
- भारतीय महिला क्रिकेटर गौहर सुल्ताना ने सभ फार्मेट से सन्यास लिया।

24 अगस्त

- टैरिफ विवाद के बीच केन्द्र सरकार ने डाक विभाग ने 29 अगस्त से अमेरिका जाने वाले पार्सल की आवाजाही रोकने का फैसला लिया।
- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता सुखरम सुधाकर रेड्डी का निधन हो गया।
- कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंधे को 26 अगस्त के लिए रिमांड पर भेज दिया।
- केन्द्रीय मंत्री जावेद अहमद राणा ने कहा कि दरबार मूव की परंपरा फिर से बहाल की जाएगी।

25 अगस्त

- विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत है।
- फिजी के प्रधानमंत्री सिटीवेनी लिगाया मादा राबुका के भारत पहुंचने पर शानदार स्वागत हुआ।
- भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज चेतश्व र पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास ले लिया।
- चीन में पहलीबार रोबोट को पीएचडी में मिला दाखिला। छात्रों के जैसा करेगा पढ़ाई।

26 अगस्त

- भारत और फिजी के रक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार, निवेश, संस्कृति, खेल, शिक्षा तथा कौशल विकास के सात क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
- सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई में कहा कि मौत की सजा को दी जा सकती है चुनौती।
- छग के दो शिक्षक डॉ. प्रज्ञा सिंह और संतोष कुमार चौरसिया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
- एलन मस्क की नेतृत्व वाली स्पेसएक्स ने ग्राउंड सिस्टम की समस्या के कारण अपने विशाल राकैट स्टारशिप की 10वीं परीक्षण उड़ान स्थगित कर दी।

27 अगस्त

- टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता और पूर्व विश्व चैंपियन मीरा बाई चानू ने अहमदाबार में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता।
- दुनिया में दौड़ेगी मेड इन इंडिया ईवी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुजुकी के पहले वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वालन ई-विटारा को झंडी दिखाई।
- भारत पर आज से अमेरिका का 50 फीसदी टैरिफ शुरू हुआ।
- छत्तीसगढ़ के रायपुर के आलोक अराधे सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे।

28 अगस्त

- संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि दुनिया भर में 2-1 अरब लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है।
- दिग्गज क्रिकेटर आर. आश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बाद अब आईपीएल से भी सन्यास ले लिया।
- ओलंपियन अनीश थनवाला ने शिमकेंट कजाकिस्तान 16वीं एशियाई निशनेबाजी में चैंपियनशीप में रजत पदक जीता।
- छग रायपुर की पहली महिला विधायक रजनीताई उपासने का निधन हो गया।

29 अगस्त

- महाराष्ट्र में पालघर जिले के विरार क्षेत्र में इमारत गिरने से 17 की मौत हो गई।
- भारत से निर्यात किये जाने वाले माल पर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू होने से फिरोजाबार में करोड़ों के आर्डर निरस्त हुए।
- छग के मुख्यमंत्री ने दक्षिण कोरिया के निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश करने किया आमंत्रित किया
- शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव झारखंड विस में पारित हुआ।

डोनाल्ड ट्रंप का अब भारत और नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का जुनून

■ सुशील कुट्टी

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब नई दिल्ली के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं, तथा भारत और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। राष्ट्रपति ट्रंप के शब्दों का चयन बीनस्टॉक में किसी मोड़ पर बातचीत करने में मशगूल घोंघे को भी चोट पहुंचाता है। ट्रंप ने भारत को 'घृणित' और 'खराब अर्थव्यवस्था' सहित कई तरह के नामों से पुकारा है और भारत के नंबर एक दुश्मन, पाकिस्तान को खुश करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने उसके पाकिस्तानी जिहादी सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर का ऐसे स्वागत किया है जैसे वह पहले खो गया हो और अब मिल गया हो।

बार-बार के दावे के बाद, अब फिर ट्रंप अपने संदिग्ध दावे पर वापस आ गए हैं कि भारत और पाकिस्तान को 'युद्धविराम' की मेज तक पहुंचाने वाला उनका ही हाथ था। ट्रंप को डायबिटिक फुट अल्सर है, जो कभी रुकता नहीं और उन्हें उनके भटकते मन से हटाना मुश्किल है, जो इन दिनों भारत के रिकॉर्ड पर पूरी तरह से अटका हुआ है।

> 27 अगस्त को ट्रंप की 50 प्रतिशत टैरिफ सीमा लागू हो गई और भारत इसे एक नियति मानकर स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। ट्रंप भारत को उसकी जगह दिखवाने पर अड़े हैं और भारत भी अपनी राह पर अड़ा है, बिना किसी रुकावट के। क्या प्रधानमंत्री मोदी कोई जोखिम उठा रहे हैं ? क्या भारत को अमेरिका को एक अटल दुश्मन बना देना चाहिए ?

राष्ट्रपति ट्रंप भारत के प्रति जुनूनी हैं। एक जर्मन अखबार की रिपोर्ट है कि ट्रंप के व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएमओ को फोन किया और घोषणा की कि ट्रंप मोदी को मनाने के लिए फोन पर हैं! लेकिन मोदी के अधिकारियों ने ट्रंप के अधिकारियों को बताया कि मोदी बहुत व्यस्त हैं। जर्मन अखबार ने ट्रंप के चार कॉल गिने और हर बार बताया गया कि मोदी उपलब्ध नहीं हैं।

लेकिन इसमें संदेह है और दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक झूठ बोल रहे हैं और सच्ची कहानी जानने के लिए ट्रंप के मगासमर्थकों से बात करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में मिगा(भारत को फिर से महान बनाओ) और मगा(अमेरिका को फिर से महान बनाओ) के बीच तुलना किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार अक्षरों वाले मेगागठबंधन की बात की। परन्तु नाम रखने में मोदी के माहिर होने के बावजूद यह चल नहीं पाया।

राष्ट्रपति ट्रंप पांच अक्षरों के चमत्कारी हैं, उनके उपनाम 'ट्रंप' से लेकर उनके 'नोबेल' तक, जिसकी उन्हें चाहत है। ट्रंप सभी देशों के बीच शांति के रक्षक के रूप में पहचाने जाना चाहते हैं। ट्रंप का पसंदीदा हथियार, 'टैरिफ', एक छह अक्षरों वाला भयावह तानाशाही शब्दकोश है। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने 'व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप' करके भारत-पाक के बीच संभावित परमाणु युद्ध को रोका और युद्धविराम लागू करने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल किया।

'मैं एक बहुत ही शानदार इंसान, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहा हूं। मैंने कहा, 'तुम्हारे और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है, नफ़रत बहुत ज़्यादा है,' ट्रंप ने दुनिया को यह समझाने की अपनी ताज़ा कोशिश में कहा कि वह शांति और समृद्धि के आदमी हैं, और समृद्धि सिर्फ़ अमेरिका के लिए है। लेकिन मोदी इस बात से सहमत नहीं हैं, कुछ ऐसा जिसके बारे में ट्रंप ने सोचा भी नहीं था कि मोदी ऐसा कर सकते हैं और अब दोनों 'मेरे दोस्त-मेरे दोस्त' नहीं रहे। ट्रम्प ने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव 'बहुत लंबे समय से, कभी-कभी सैकड़ों सालों से अलग-अलग नामों से' चल रहा है।

'भारत और पाकिस्तान 1947 में ही स्वतंत्र राष्ट्र बने, जब अंग्रेजों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपने 200 साल लंबे शासन को समाप्त करने और इसे दो अलग-अलग राष्ट्रों में विभाजित करने का फैसला किया। इससे पहले, यह क्षेत्र अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित था।'

यह भारत के इतिहास पर ट्रंप की पकड़ है, जिसे वह अपनी आस्तीन पर सम्मान के तमगे की तरह शान से दिखाते हैं, यह जाने बिना कि भारतीय कोबरा, ट्रंप और उनके वयस्क बच्चों को पुरानी दुनिया में अपने पूर्वजों के बारे में जितना पता है, उससे कहीं ज़्यादा भारतीय इतिहास जानता है, जहां से ट्रंप के माता-पिता संयुक्त राज्य अमेरिका आए थे। लेकिन ट्रंप अपने बंद दिमाग की खोली में रहते हैं और अपने राष्ट्रपति पद के कार्यकाल का अध्याय इस एहसास के साथ बंद करना चाहते हैं कि वह अब तक के नंबर 1 राष्ट्रपति हैं, इसलिए सावधान रहें!

ऐसे राष्ट्रपति के बारे में क्या कहा जाए, सिवाय उस दिन पछताने के जब राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस के एक रात्रिभोज में ट्रंप का मज़ाक उड़ाया था और ट्रंप ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और राष्ट्रपति पद के लिए दौड़े, और एक नहीं, बल्कि दो बार सफलता का स्वाद चखा? अब, राष्ट्रपति ट्रंप अपनी ही विकृत मानसिकता की खोज में एक अजीबोगरीब बहादुरी दिखा रहे हैं, उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि कौन सा देश, भारत समेत, हाशिये पर जा रहा है।

27 अगस्त को ट्रंप की 50 प्रतिशत टैरिफ सीमा लागू हो गई और भारत इसे एक नियति मानकर स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। ट्रंप भारत को उसकी जगह दिखाने पर अड़े हैं और भारत भी अपनी राह पर अड़ा है, बिना किसी रुकावट के। क्या प्रधानमंत्री मोदी कोई जोखिम उठा रहे हैं? क्या भारत को अमेरिका को एक अटल दुश्मन बना देना चाहिए? क्या ट्रंप के टैरिफ के गुस्से के बाद आई तमाम परेशानियों के लिए यह उचित है?

सच है, यह एक जुआ है, भारत के इतिहास में एक विराम है और इसे इस ट्रंप ने रचा है जो दावा करता है कि वह भारतीय इतिहास को अपने हाथ की हथेली की तरह जानता है।

ट्रम्प ने कहा, 'मैंने कहा, मैं आपके साथ कोई व्यापार समझौता नहीं करना चाहता...आप लोग परमाणु युद्ध में उलझने वाले हैं...मैंने कहा, मुझे कल फिर से फोन करना, लेकिन हम आपके साथ कोई समझौता नहीं करने वाले हैं।' आप पर टैरिफ इतने ज़्यादा हैं कि आपका सिर घूम जाएगा... लगभग पांच घंटे के अंदर ही ये हो गया... अब शायद ये फिर से शुरू हो जाए। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे रोक दूंगा। हम ऐसी चीज़ें नहीं होने दे सकते।'

इस हफ़्ते की शुरुआत में ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने दुनिया भर में सात युद्ध रोके हैं, जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध भी शामिल है। उन्होंने मीडिया को बताया कि इनमें से चार युद्ध इन संघर्षों में शामिल देशों पर उनके टैरिफ लगाने की वजह से रुके थे। 'मेरे पास टैरिफ और व्यापार दोनों थे, और मैं कह सकता था, अगर आप लड़ने जाते हैं और सबको मारना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप हमारे साथ व्यापार करेंगे तो मैं आप सभी पर 100प्रतिशत टैरिफ लगाऊंगा।उन्होंने सबने हार मान ली। मैंने ये सारे युद्ध रोक दिए हैं। एक बड़ा युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच होता...'

ट्रंप ने कहा कि भारत-पाकिस्तान युद्ध अगले स्तर का, एक परमाणु युद्ध होने वाला है! 'खैर, अब कोई युद्ध नहीं चल रहा है। मैंने कई मौकों पर इसका इस्तेमाल किया है। मैंने व्यापार और जो भी मेरे पास था, सब इस्तेमाल किया।' भारत ट्रंप पर ज़रा भी विश्वास नहीं करता, जो कोई जिहादी जनरल असीम मुनीर के साथ बैठकर व्यापार, टैरिफ, परमाणु हथियार और क्रिप्टोकरेंसी की बातें करते हुए बड़े हैमबर्गर का मज़ाक उड़ा सकता है, उसकी बात सुनने लायक नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया को कहां ले जाएंगे, यह तो भविष्य ही बताएगा। फ़िलहाल, सारा दोष राष्ट्रपति बराक ओबामा पर है, जिन्हें व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में ट्रंप का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए था।

सरकार को परेशान करेगी संघ प्रमुख के 'मन की बात'

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा आम भारतीयों की पहुंच से बाहर हैं। एक बात दोहराने के बावजूद उन्होंने व्यवस्था के सिर पर कील ठोंक दी है। इस महीने की शुरुआत में इंदौर में किफायती कैंसर देखभाल सुविधा के उद्घाटन के दौरान भागवत ने कहा कि 'अच्छी स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सुविधाएं तथा इसकी सभी योजनाएं आज समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यकताएं बन गई हैं लेकिन दुर्भाग्य से दोनों क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं आम आदमी की पहुंच और वित्तीय क्षमता से परे हैं।'

कुछ लोग इसे भाजपा का वैचारिक आधार आरएसएस के प्रमुख द्वारा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की नीतियों और विकास के उसके मॉडल की परोक्ष आलोचना के रूप में देखेंगे। आखिरकार यह टिप्पणी विकास के एक प्रमुख पहलू 'विकासशील भारत' को छूती है जिसे सरकार द्वारा पैक किया और बेचा जा रहा है- 'जिसमें सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य' नहीं है जो विकास को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आवश्यक है।

वैसे किसी भी राजनीतिक सोच से परे होकर देखें तो भागवत और आरएसएस की बुलंद आवाज इस मामले में भाजपा शासन के तहत भारत में एक ज्वलंत मुद्दे को उजागर करने का काम करती है जिसे आम नागरिक दिल की गहराईयों तक महसूस करता है। यह एक सीधा-सादा तथ्य है कि शिक्षा का स्तर बेहतर होने के बजाय वह आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रही है। स्वास्थ्य एक ऐसा व्यवसाय बन गया है जो मरीज की देखभाल की बजाय निवेश, आईपीओ और प्रोत्साहन के संबंध में बोला जाता है। कुछ शर्मनाक प्रथाएं विकास के पैरों तले पनपती हैं। इसके साथ ही भारत में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा में विश्वस्तरीय सुविधाएं भी उपलब्ध हैं ताकि हम आम तौर पर विपन्नता के सागर में विश्वस्तरीय टापुओं के साथ रह सकें।

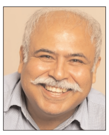

जगदीश रत्तनानी

> कुछ व्यवसायों या सेवाओं को महान सेवाओं के रूप में देखना असामान्य नहीं है क्योंकि यह देखा जाता है कि उनका क्या असर होता है- शिक्षा नागरिकों की एक नई पीढ़ी को प्रभावित करती है और चिकित्सा बीमारों को ठीक करती है। इन दोनों क्षेत्रों को बाजार की गलाकाट स्पर्धा से बाहर रखने इच्छा है, खासतौर पर उस समय जब यह स्पर्धा अन्य क्षेत्रों में जारी है जिसे हम विकास कहते हैं।

कुछ व्यवसायों या सेवाओं को महान सेवाओं के रूप में देखना असामान्य नहीं है क्योंकि यह देखा जाता है कि उनका क्या असर होता है- शिक्षा नागरिकों की एक नई पीढ़ी को प्रभावित करती है और चिकित्सा बीमारों को ठीक करती है। इन दोनों क्षेत्रों को बाजार की गलाकाट स्पर्धा से बाहर रखने इच्छा है, खासतौर पर उस समय जब यह स्पर्धा अन्य क्षेत्रों में जारी है जिसे हम विकास कहते हैं। आरएसएस प्रमुख ने एक तरह से इस बात को दोहराते हुए कहा- च्पहले स्वास्थ्य और शिक्षा एक सेवा के रूप में माने गए थे लेकिन आज दोनों का व्यवसायीकरण हो गया है ज्

दूसरी तरफ नीति में ठोस परिवर्तन के बिना स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों को सर्वसामान्य के लिए आसान बनाने हेतु समाज को जागृत करना, लागत कम रखना या उन्हें मोटे तौर पर डी-मार्केटाइज़ करने की बात करना एक ऐसे समाज में दान और दयालुता की आशा करना है जो अत्यधिक बाजारीकृत हो गया है। प्रसिद्ध अकादमिक और लेखक माइकल सैंडल मार्केट इकॉनामी और मार्केट सोसायटी के बीच अंतर की बात करते हैं- मार्केट सोसायटी दक्षता ला सकती है जबकि मार्केट इकॉनामी हर चीज पर कीमत लगाती है ताकि ऐसा कुछ भी न हो जिसे पैसा नहीं खरीद सकता।

यह तर्क देना संभव है कि भारत लगभग 'कानूनी' तौर पर मार्केट इकॉनामी बन गया है लेकिन 'वास्तव' में एक मार्केट सोसायटी के रूप में काम करता है जो एक ऐसे देश के लिए उल्लेखनीय रूप से उपयोगी नहीं है जिसके संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' शब्द है। शायद ही कुछ ऐसा है जिसे शीर्ष 1 प्रतिशत नहीं खरीद सकते हैं- हिफाजत, सुरक्षा और सफलता के लिए वे इतना कमाते हैं कि अपने खर्चों का खुद भुगतान कर सकते हैं। चूंकि केवल कुछ ही भुगतान कर सकते हैं इसलिए बाकी पीड़ित होंगे, वे शिकायत करेंगे और दुख जाहिर करेंगे कि असमानता हर क्षेत्र में, विशेष रूप से अस्पतालों और स्कूलों में किस तरह का खेल खेलती है।

इस प्रकार की व्यवस्था में स्वास्थ्य बीमा कंपनियां अपनी पाई-पाई क्यों न वसूल करें, चिकित्सा शिक्षा में सक्रिय उद्योग अत्यधिक शुल्क के बिना कैसे जीवित रह सकती है तथा डॉक्टरों या शिक्षकों को कम वेतन के लिए क्यों समझौता करना चाहिए? डॉक्टरों और शिक्षकों को भी आवास, यात्रा, उपकरण, सामग्री और सीखने की आवश्यकता होती है- जो सभी महंगे हैं तथा जिनका बाजारीकरण किया जाता है। क्षेत्र-विशेष में काम करने वाली परोपकारी संस्था (सेक्टोरल चैरिटी) आंशिक रूप से काम करेगी। वास्तव में भारत के कुछ सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों एवं शैक्षणिक संस्थानों को आधिकारिक तौर पर चैरिटी संस्थानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वैसे वास्तविक रूप से बहुत कम संस्थाएं धर्मार्थ हैं। बाजार का आदेशात्मक रुख सारी व्यवस्था को नियंत्रित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि समय के साथ अधिकांश आम भारतीय इस लाभ से दूर रहें।

एक न्यूनीकरणवादी दृष्टिकोण जो कर्तव्य, जिम्मेदारी या सामान्य रूप से एक गैर-आर्थिक मानसिकता के विचार को इंजेक्ट करना चाहता है, चुनिंदा रूप से यह पहचानने से इनकार करता है कि समस्या बहुत व्यापक है। इस मामले में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र की विफलता एक बड़ी समस्या, विकास की काल्पनिक कहानी एवं काल्पनिक विशाल अर्थव्यवस्था का लक्षण हैं जो आंकड़े तो देखती है लेकिन उद्देश्य नहीं, जिसने अपने शानदार हवाई अड्डों और बुलेट ट्रेनों में चमकने की चाह में सीढ़ी के निचले पायदान पर बैठे लोगों की अनदेखी की है।

यह वह नजरिया है जिसके कारण भागवत ने एक मंत्री का बयान उद्धृत किया जिसमें कहा गया है कि शिक्षा 10 खरब डॉलर का व्यवसाय है या वास्तव में नीति आयोग ने एक पेपर में लिखा है जिसमें निम्नलिखित बातें कही गई हैं-'स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में निवेशकों (उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी) की काफी रुचि देखी गई है, जिसमें लेनदेन का मूल्य वर्ष 2011 के 940 लाख अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2016 में 1,2750 लाख अमेरिकी डॉलर हो गया है- जो 13.5 गुना से अधिक की वृद्धि है... वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किए गए निवेशों ने एक आकर्षक स्वास्थ्य सेवा निवेश के गंतव्य के रूप में भारत में बाजार की धारणा को मजबूत किया है।'

इस रास्ते पर बने रहने का मतलब मुसीबत मोल लेना है। कोई भी निजी इक्विटी या उद्यम पूंजी सेवा के उद्देश्य के लिए नहीं आती है। इस जाल से बाहर निकलने के लिए भारत सरकार को पुनर्विचार करना होगा व विकास की कहानी के उद्देश्य को फिर से खोजना होगा। हम कहते हैं कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है लेकिन इसका क्या मतलब है जब भारतीय आबादी के शीर्ष 10 फीसदी के पास कुल राष्ट्रीय धन का 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है जबकि सबसे गरीब आधी आबादी अपनी संपत्ति में केवल 1प्रति सैकड़ा की वृद्धि देखती है। आक्सफैम की हालिया रिपोर्ट में इसका उल्लेख है।

फिर भी हमारे आसपास ऐसे मॉडल हैं जिन्होंने अद्‌भुत काम किया है। वे न केवल भारत को बल्कि दुनिया को धर्म के वास्तविक अर्थ बताते हुए उस पर चलने का रास्ता दिखाते हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध अरविंद आई केयर सिस्टम है, जो एक ऐसा प्रकाशस्तंभ है जो अपनी सेवाओं की मार्केटिंग पर एक रुपया भी खर्च नहीं करता है बल्कि सबसे दूर और सबसे कमजोर लोगों तक पहुंचने के लिए संसाधनों को बाहर निकालता है। यह गांधी की पसंदीदा पुस्तक 'अन टू दिस लास्ट' का एक जीवंत उदाहरण है। अरविंद एक ऐसी प्रणाली है जो जिस तरह चमकती है वैसा ही काम भी करती है। इसे हासिल करने के लिए एक अलग किस्म के संकल्प की आवश्यकता होती है जो उद्देश्य और विनम्रता की उच्च भावना में निहित है न कि प्रचार या प्रभुत्व के अधिकार की अतिरंजित भावना में है जो आज भारत की पहचान बन गई है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। सिंडिकेट : द बिलियन प्रेस)

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

चिंतन

भारतीय अर्थव्यवस्था ने 'डेड' कहने वालों को दिया जवाब

दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था ने डेड कहने वालों को एक बार फिर जोरदार तमाचा लगाया है। सभी अनुमानों को पछाड़ते हुए भारत की जीडीपी 7.8% बढ़ी है। वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.8 फीसदी रही। यह पिछली पांच तिमाहियों में सबसे ज्यारदा है। अर्थशास्त्रियों के एक ईटी पोल ने पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3 प्रतिशत से 7 के बीच रहने का अनुमान लगाया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6.5% का अनुमान लगाया था, लेकिन तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था ने सभी अनुमानों को झटका दे दिया। असल में केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में 52 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जिससे विकास को बढ़ावा मिला। जीएसटी को तर्कसंगत बनाने, आरबीआई की ओर से ब्याज दरों में कटौती और अनुकूल मानसून से आने वाली तिमाहियों में खपत को समर्थन मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तय है कि अगले कुछ महीनों में अर्थव्यवस्था को और भी तेज रफ्तार मिलेगी। यह उनके लिए सबसे बड़ा झटका होगा जो भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड बता रहे थे। यह कथन सिर्फ ट्रंप की अज्ञानता की निशानी भर था। भारत डेड इकॉनमी तो कहीं से नहीं है बल्कि वह वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था में रफ्तार का इंजन है। यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका आकार लगभग 4 ट्रिलियन है। जल्द ही यह जर्मनी को पीछे छोड़ कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। वर्तमान में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है और बीते 10 वर्षों से लगातार इसकी गति बढ़ रही है। वर्ष 2015-25 के बीच भारत की औसत जीडीपी वृद्धि दर 6%-6.5% रही है। जबकि इस बीच भारत ने कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और दूसरे वैश्विक संकट झेले। भारत के मुकाबले चीन इस दौरान 6% या उससे नीचे की ही रफ्तार से बढ़ा है। भारत वर्तमान में वैश्विक जीडीपी वृद्धि में 17 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। यह आगे चलकर इसके 20 होने का अनुमान है। भारत इसी के चलते वैश्विक ग्रोथ का इंजन बना हुआ है। उसकी अर्थव्यवस्था का आकार 2015-25 में 105 फीसदी बढ़ा है, जो पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है। जिस भारत को डोनाल्ड ट्रंप डेड इकॉनमी बता रहे हैं, वह वर्तमान में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है। यह अभी और बढ़ेगी। वर्तमान में भारत का मध्यम वर्ग लगभग 60 करोड़ है। यह मध्यम वर्ग 2047 तक 100 करोड़ पहुंचने के आसार हैं। यही मध्यम वर्ग वर्ष 2030-2031 तक लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर की खपत करेगा। ऐसे में विश्व की कम्पनियों का धंधा भी चीन के अलावा भारत के ही भरोसे होगा। इतना बड़ा मध्यम वर्ग उसे और कहीं नहीं मिलेगा। भारत सिर्फ बड़ा बाजार ही नहीं है बल्कि बहुत ऐसी ऐसी चीजों की फैक्ट्री भी है, जिन पर विश्व निर्भर है। भारत विश्व में जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा सप्लायर है। अमेरिका भी वर्तमान में भारत निर्मित जेनेरिक दवाओं पर निर्भर है। भारत का फार्मा एक्सपोर्ट वर्ष 2030 तक 5.5 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इसके अलावा भारत भले ही कच्चे तेल का बड़ा उत्पादक ना हो लेकिन वह तेल की रिफाइनरी के मामले में बहुत आगे है। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा तेल रिफाइन करने वाला देश है। इसके अलावा गाड़ियां, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक समेत बाकी कई वस्तुओं का भारत बड़ा सप्लायर है। इतना सब होने के बाद भी कोई इसे डेड इकॉनमी कहे तो इसे पागलपन के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता।

मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी

विचार
डॉ. संजय शुक्ला

नेशनल मेडिकल कमिशन 'एनएमसी' के प्रमुख ने हाल ही में उम्मीद जताया है कि चालू शैक्षणिक सत्र में देश में मेडिकल शिक्षा के आठ हजार स्नातक और स्नातकोत्तर सीटें बढ़ सकती है। वर्तमान में देश के मेडिकल कॉलेजों एमबीबीएस की 1,18,098 सीटें हैं जिसमें 59,782 सीटें सरकारी तथा 58,316 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में है। इसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएशन की 53,960 सीटें हैं जिसमें 30,029 सरकारी और 23,931 निजी संस्थानों में है। आशाजनक यह कि बीते 10 सालों में मेडिकल की सीटों में दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है साल 2015 में 56,908 एमबीबीएस की सीटें थीं। केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में चालू साल में मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार सीटें बढ़ाने की घोषणा की है। गौरतलब है कि साल 2011 में जहां 314 मेडिकल कॉलेज थे वहीं 2025 में यह संख्या 780 तक पहुंचने की संभावना है जो वैश्विक सूची के लिहाज से शीर्ष क्रम पर होगा जबकि ब्राजील 389 मेडिकल कॉलेज के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत जैसे कमजोर अर्थव्यवस्था और विशाल जनसंख्या वाले देश में सरकारों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और समाज के अंतिम व्यक्ति तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया बहुत बड़ी चुनौती है।

गौरतलब है कि स्वास्थ्य सेवाओं के केंद्र में डॉक्टर ही होता है लेकिन भारत में मेडिकल कॉलेजों की कमी के चलते दुर्गम ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में डॉक्टरों की किल्लत दशकों से बनी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में देश में 13.86 लाख रजिस्टर्ड एलोपैथी डॉक्टर हैं जिसमें 80 फीसदी चिकित्सक पेशे में सक्रिय हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन 'डब्ल्यूएचओ' द्वारा तय जनसंख्या- डॉक्टर के मुताबिक 1000 आबादी पर एक डॉक्टर की उपलब्धता निर्धारित है जबकि वर्तमान में यह अनुपात 1800 आबादी में एक डॉक्टर का है। इस लिहाज से भारत को साल 2030 तक 20.7 लाख डॉक्टरों की जरूरत होगी। दूसरी ओर संसद के बीते मानसून सत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने बताया है कि यदि देश में पंजीकृत एलोपैथी और आयुष चिकित्सकों के आंकड़े को देखें तो देश में 811 आबादी पर एक चिकित्सक की उपलब्धता होने का अनुमान है जो डब्ल्यूएचओ के निर्धारित मानक से बेहतर है।

देश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और चिकित्सकों की कमी को ध्यान में रखते हुए बीते 10 वर्षों के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा हर जिले में न्यूनतम एक मेडिकल कॉलेज खोलने की कवायद की जा रही है जो समयोचित कदम है। सरकार के मंशानुरूप एनएमसी ने नये मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जरूरी आवश्यक मापदंडों जैसे जमीन, अधोभूत संरचना, मानव संसाधन सहित अन्य में रियायत भी दी गई है। एक दशक पहले मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया 'एमसीआई' के दौर में कौंसिल के सख्त मापदंडों के चलते मेडिकल कॉलेज खोलना टेढ़ी खीर थी। इधर एनएमसी के रियायत और सरकार के प्रोत्साहन के चलते विभिन्न राज्य सरकारों तथा निजी प्रबंधनों में मेडिकल कॉलेज खोलने की होड़ मची हुई है। आलम यह है कि " कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा" की तर्ज पर सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं जहां शिक्षकों से लेकर जरूरी संसाधन अस्थाई तौर पर जुगाड़ा जा रहा है। इस होड़ के चलते सबसे बड़ी चुनौती इन मेडिकल कॉलेजों के शिक्षा की गुणवत्ता की है।

बीते कुछ सालों के दौरान खुले मेडिकल कॉलेजों की बात करें तो अधिकांश कॉलेजों में मेडिकल टीचर्स खासकर हायर फैकल्टी यानि प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की भारी कमी है वहीं संबद्ध अस्पतालों में मरीजों का टोटा है।अनेक कॉलेजों में हास्टल, लायब्रेरी, क्लासरूम, फर्नीचर, प्रायोगिक अध्ययन हेतु उपकरण और रिएजेंट की कमी है तो अस्पतालों में प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ, बिस्तर, इमरजेंसी वार्ड, नैदानिक उपकरणों का आभाव है। खबरों के मुताबिक छत्तीसगढ़ के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों और चिकित्सकों के 48 फीसदी पद खाली हैं। उल्लेखनीय है कि मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता हमेशा से ही नियामक संस्थाओं से लेकर सरकारों के लिए संवेदनशील मुद्दा रहा है क्योंकि यह जनस्वास्थ्य के साथ चिकित्सा अनुसंधान क्षेत्र से जुड़ा मसला है। मेडिकल शिक्षा में छात्रों के लिए जितनी आवश्यकता विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के शिक्षण का है उतनी ही अनिवार्यता अस्पतालों में क्लीनिकल ट्रेनिंग की है। इन परिस्थितियों में यदि कॉलेजों में वरिष्ठ शिक्षकों की कमी हो और अस्पतालों में मरीज तथा जरूरी संसाधनों का टोटा हो तब इसका असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ना लाजिमी है। मेडिकल कॉलेजों में मानव संसाधन से लेकर अन्य संसाधनों के अभाव का खामियाजा भावी डॉक्टरों को ही

उठाना पड़ेगा जिसका असर उनके ज्ञान कौशल और दक्षता पर पड़ना लाजिमी है।

उपरोक्त परिस्थितियों में सरकार और एनएमसी से अपेक्षा है कि वह नये मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति देने के पहले आवश्यक संसाधन और अधोसंरचना की उपलब्धता की पड़ताल सख्ती से करे। देश में नए मेडिकल कॉलेज अथवा पीजी कोर्सेज खोलने तथा सीटों में बढ़ोतरी के लिए निजी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा एमसीआई या एनएमसी के निरीक्षण दल को भारी रिश्वत देने का मामला लगातार उजागर होते रहे हैं। इसी साल जुलाई महीने में सीबीआई ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज सहित मध्यप्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और दिल्ली के 40 मेडिकल कॉलेजों में छापेमारी कर मान्यता के बदले नेशनल मेडिकल कमीशन यानि 'एनएमसी' के निरीक्षण टीम को रिश्वत लेने और देने के आरोप में 3 निरीक्षकों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। लगभग 1300 करोड़ रुपए के घोटाले के इस मामले में देश के 35 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। अलबत्ता संसाधन विहीन मेडिकल कॉलेजों के मान्यता के लिए निरीक्षण के दौरान कॉलेज प्रबंधन द्वारा टीचिंग के लिए घोस्ट फैकल्टी यानि कागज पर शिक्षक तथा अस्पतालों में नकली मरीज भर्ती करने का सिलसिला काफी दिनों से जारी है। साल 2010 में मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया 'एमसीआई' के अध्यक्ष डॉ केतन देसाई पर एक मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने के ऐवज में 20 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा था। जांच के दौरान डॉ. देसाई से डेढ़ किलो सोना और अस्सी किलो चांदी तथा कई आलिशान घर भी मिला था जो घोटाले से हासिल किया गया था।

बहरहाल स्वास्थ्य ही किसी राष्ट्र और समाज के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास का बुनियाद होता है लेकिन भारत में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था सदैव ही दयनीय रहा है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र को कम बजट आबंटन के चलते देश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या कम थी लेकिन निजी मेडिकल कॉलेज के खूब फले- फूले हैं। हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि में डॉक्टरी आज भी सबसे प्रतिष्ठित पेशा है जिसके चलते देश में स्वास्थ्य सेवा का बाजार लगातार गुलजार रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों ने सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के असंतुलन को दूर करने के लिए ही सरकारी कॉलेज खोलने की दिशा में कदम बढ़ाया है फलस्वरूप कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले मेधावी छात्रों और उनके अभिभावकों का डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो रहा है। विचारणीय है कि भारतीय डॉक्टर सिर्फ स्वदेश में ही नहीं बल्कि सात समंदर पार विदेशों में भी अपनी मेधा और दक्षता का लोहा मनवा रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा के बाजार की बात करें तो भारत दुनिया के लिए सबसे बड़ा मेडिकल टूरिज्म का क्षेत्र बन रहा है जहां विदेशों से बड़ी संख्या में लोग उपचार के लिए आ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में मेडिकल टूरिज्म का बाजार 12.3 फीसदी की दर से बढ़ रही है वर्तमान में यह बाजार 18.2 डॉलर की है जो साल 2035 में 18.2 डॉलर पहुंचने की उम्मीद है। बिलाशक भविष्य में भारत पूरी दुनिया के लिए मेडिकल हब बन सकता है लिहाजा यह आवश्यक है कि मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता बरकरार रखने की दिशा में सरकार दृढ़ इच्छाशक्ति प्रदर्शित करे और इस क्षेत्र में जारी विसंगतियों को दूर करे आखिरकार यह देश के साख का मुद्दा है।

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

डिजिटल लाइब्रेरी
संदीप भूषण

युवाओं को डिजिटल संसाधनों के माध्यम से जोड़ने की पहल

फिक्शन और फंतासी की दुनिया में आज धूमकेतु की तरह चमक रही अमेरिकी लेखिका सारा जेनेट मास की प्रसिद्ध कृतियों में 2012 में आईं 'थ्रोन ऑफ ग्लास' सीरीज की किताबें हैं। इसमें वे एक जगह पुस्तकालयों की चर्चा करती हैं। वे कहती हैं कि पुस्तकालय विचारों से भरे रहे हैं, शायद सभी हथियारों में सबसे खतरनाक और शक्तिशाली। यहां हथियार शब्द का इस्तेमाल उन्होंने विचार या मानवीय बुद्धिमत्ता के लिए किया है। सारा के शब्दों को सामने रखते हुए डिजिटल दौर में पुस्तकालयों की जरूरत और भूमिका पर बात करें तो कई रोचक और सराहनीय तथ्य सामने आते हैं। आज सबसे बड़ी चुनौती विचार और ज्ञान को पुराने पड़े पीले पन्नों से उठाकर डिजिटलाइज करने की है। अच्छा लगता है यह जानकर कि यह विवेक आज बिहार जैसे प्रदेश में दिखलाई पड़ रहा है, जहां के समाज और सरकार को लेकर एक खास तरह के पूर्वाग्रह से हम ग्रसित रहे हैं। बिहार सरकार ने इसी दिशा में 'मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना' के नाम से एक बड़ा और दूरदर्शी प्रयास किया है। यह योजना बच्चों और युवाओं को डिजिटल संसाधनों के माध्यम से जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो बिहार के हर कोने में शिक्षा के नए साधन उपलब्ध करा रही है। बिहार के दूरदराज के इलाकों में पढ़ाई के संसाधन सीमित रहे हैं, इस कमी के कारण कई युवाओं के सपने उड़ान भरने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। पर यह स्थिति अब बदल रही है। खासतौर पर जब से डिजिटल लाइब्रेरी की नींव पड़ी है, तब से यह कहीं अधिक सुलभ, समेकित और समकालीन शिक्षा का स्रोत बन गई है। अब हर विधानसभा क्षेत्र, पंचायत और कॉलेज में ऐसे केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं जहां विद्यार्थी ऑनलाइन कोर्स, ई-बुक्स और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए जरूरी सामग्री पा सकते हैं। बिहार सरकार ने इसके लिए 94 करोड़ 50 लाख रुपये स्वीकृत कर इस योजना को एक सशक्त राशि के साथ लॉन्च किया है जिसे देखकर शिक्षा के प्रति उनकी गंभीर प्रतिबद्धता झलकती है। तकनीक के सहारे यह योजना युवा पीढ़ी को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें करियर की बेहतर संभावनाओं के लिए तैयार भी करती है। प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र में कम से कम दस कंप्यूटर के साथ हाई-स्पीड इंटरनेट और पर्याप्त बैठने की जगह होगी। ऐसे केंद्रों की उपस्थिति से छात्र न केवल अपने स्कूल या कॉलेज के कोर्स ऑनलाइन पढ़ सकेंगे, बल्कि जीईई, नीट, क्लैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। साथ ही रोजगार संबंधी ऑनलाइन कोर्स, सरकारी व निजी रोजगार पोर्टल की जानकारी भी मिलेगी, जो युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है। डिजिटल लाइब्रेरी केंद्रों में आधुनिक सुविधा का पूरा इंतजाम है। बिजली, पानी, प्रिंटर, स्कैनर, समाचार पत्र और तकनीकी सहायता से लैस ये केंद्र विद्यार्थियों को एक पूर्ण वातावरण उपलब्ध कराते हैं। पटना में जहां एक मॉडल लाइब्रेरी केंद्र में 60 कंप्यूटर होंगे, वहीं अन्य क्षेत्रीय केंद्रों में भी 50 कंप्यूटर की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई है। अपनी जगह न होने पर पंचायत स्थानीय भवन को 1 रुपये के सालाना किराए पर लेकर लाइब्रेरी चला सकती है। इस तरह यह पहल जितनी आर्थिक रूप से सशक्त है, उतनी ही व्यावहारिक और सभी के लिए उपलब्ध है। गांव-गांव तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए "जीविका दीदी" मॉडल को अपनाया गया है। 7,953 से अधिक नए डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र खोलकर सरकारी प्रयासों ने युवाओं को हाथ थामने का प्रस्ताव रखा है। स्थानीय महिलाओं और समूहों को लाइब्रेरी संचालन में अवसर दिया जाना समाज के लिए भी संरचनात्मक बदलाव लाएगा। जिस तकनीकी क्रांति की बात हम आज करते हैं, इस योजना ने उसे गांव-गांव तक पहुंचाकर शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव की शुरुआत की है। युवा पीढ़ी आज की बदलती दुनिया के लिए जरूरी डिजिटल कौशल सीखने के लिए इस योजना का बड़ा फायदा लेगी। कंप्यूटर की मूल बातें सीखना, ऑनलाइन जानकारी जुटाना, जॉब पोर्टल पर आवेदन करना और डिजिटल माध्यम से करियर की योजना बनाना अब वास्तविकता का हिस्सा बन गए हैं। ऐसे अवसर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर न केवल उनके व्यक्तिगत विकास में सहायता करेंगे, बल्कि राज्य की प्रगति में भी योगदान देंगे। बिहार की यह डिजिटल क्रांति इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान और तकनीक का सही संयोजन नौजवानों को केवल बेहतर आज नहीं देता, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर तैयारी भी कराता है। इस योजना के माध्यम से बिहार का हर युवा डिजिटल युग में अपनी अलग पहचान बना सकेगा और देश की प्रगति में अपने योगदान से इतिहास रचेगा।

(लेखक आर्थिक मामलों के जानकार व वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

सुख की चाह के लिए तप की साधना जरूरी है

संकलित
दर्शन

तप संकल्प की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। जिसे सत्य संकल्प द्वारा सुख की चाह है, उसे तप की साधना अवश्य करनी चाहिए। संकल्प के दृढ़ एवं सत्य न होने का सबसे बड़ा कारण तप की कमी होता है। जो व्यक्ति अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर के द्वारा तप नहीं करता, वह अपने संकल्पों को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। तप से हमें अपने मन और तन, दोनों को पक्का बनाना होता है। जैसे मिट्टी का कच्चा घड़ा पानी डालने पर गल जाता है। वह अग्नि में बिना तपे कभी जल नहीं ला सकता। इसी प्रकार जब तक मनुष्य अपने जीवन को तप द्वारा पक्का नहीं बनाता, तब तक वह कभी भी अपने संकल्पों की सिद्धि को धारण नहीं कर सकता। तप से जीवन की समस्त अशुद्धियां दूर होती हैं। अशुद्धियों के दूर होने से शरीर और इंद्रियों को विशेष सिद्धि मिलती। तभी कहा जाता है कि तप से सभी कुछ साध्य है। वेदों में भी तप की महिमा और आवश्यकता का अनेक स्थानों पर वर्णन किया गया है। कल्याण की कामना करने वाले ऋषिगण भी प्रथम तप और दीक्षा का ही अनुष्ठान करते हैं। श्रीमद्भागवत कथा के द्वितीय स्कंध में श्री भगवान ब्रह्मजी से कहते हैं कि 'मैं इस दृश्यमान अखिल प्रपंच को तप द्वारा रचता हूं और पुनः तप द्वारा ही ग्रसित कर लेता हूं। मैं तप द्वारा ही इस विश्व का भरण-पोषण करता हूं और मेरा अत्यंत तेजस्वी पराक्रम तप ही है। तप द्वारा वह तेज और वह शक्ति प्राप्त की जा सकती है, जो किसी भी संकल्प की प्रतिपूर्ति का आधार बनती है।'

एकाग्रता के बिना मंत्र जप नहीं हो सकता

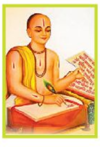

संकलित
प्रेरणा

एक दिन सरयू नदी के किनारे पर गोस्वामी तुलसीदास प्रवचन दे रहे थे। वे अक्सर यहां प्रवचन देते थे। इस दौरान तुलसीदास जी लोगों की समस्याओं का समाधान भी करते थे। एक दिन तुलसीदास जी आंखें बंद करके जप कर रहे थे। एक व्यक्ति ने पूछा कि आप आंखें बंद कर किसे याद कर रहे हैं? तुलसीदास जी बोले कि मेरे राम को। उस व्यक्ति ने फिर पूछा कि तो क्या ये जरूरी है कि भगवान के नाम का जप किया जाए? तुलसीदास जी ने कहा कि हां, ये तो बहुत जरूरी है। नाम जप करने से मन काबू में रहता है। जिन लोगों का मन काबू रहता है, वे शांत रहते हैं। उस व्यक्ति ने फिर पूछा कि जब मैं नाम जप करने बैठता हूं तो मन नहीं लगता है, मुझे क्या करना चाहिए? तुलसीदास जी बोले कि कई लोगों की ये समस्या है, जप में मन नहीं लगता। इस कारण लोग भक्ति करना ही छोड़ देते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखें, मन लगे या न लगे, हमें जप करते रहना चाहिए। हमारा मन एक भूमि की तरह है। भूमि में बीज बोने पर उससे पौधा जरूर उगता है, बीज उल्टा गिरे या सीधा, पौधा तो उगता ही है। ठीक इसी तरह हमें भी मन में भक्ति का बीज बोते रहना चाहिए। जप के लिए सबसे जरूरी है एकाग्रता। सभी को एकाग्रता की जरूरत है। अशांत मन एकाग्र नहीं हो सकता है। जप करते रहेंगे तो मन शांत रहेगा, एकाग्रता बनी रहेगी। जप करने से देर से ही सही, लेकिन इसका सकारात्मक फल जरूर मिलता है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

अंतर्मन

आज की पाती

अब अमेरिका को धूल चटाए

राष्ट्रपिता गांधी जी ने केवल सत्य, अहिंसा और प्यार को आधार बना कर स्वदेशी के अस्त्र से अंग्रेजों को धूल चटा कर निकाल बाहर किया और भारत को स्वतंत्र करवाया। आज जब भारत वैश्विक षड्यंत्रों का शिकार है और अमरीका की आततायी नीति भारत को जख्म दे रही है, ऐसे में भारत केवल स्वदेशी की ढाल से अपनी और जनता की रक्षा कर सकता है। अमरीका, पाकिस्तान जैसे आतंकी राष्ट्र को यूएन में उच्च पद देकर तथा आर्थिक मदद दिलवा कर भारत और चीन दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। चीन का एक गुर्गा हथिया कर भारत व पाकिस्तान को अलग कर शोषण करना चाहता है। रूस की शक्ति क्षीण कर यूक्रेन के संसाधनों को हड़पना उसका लक्ष्य है। - **विवेक जोशी**, बिलासपुर

ट्रेंड

भारत-जापान सहयोग

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और जापान-भारत संघ के अध्यक्ष योशीहिदे सुगा के साथ मेरी बैठक हुई। हमने भारत-जापान सहयोग में प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, व्यापार, निवेश और अन्य क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग बनाने के तरीकों पर चर्चा की।
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

श्रद्धांजलि अर्पित

महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर स्मरण और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन सभी खिलाड़ियों को नमन है जिन्होंने राष्ट्र को गौरवान्वित करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया।
-धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री

परियोजनाओं का लोकार्पण

'आंवला नगरी' प्रतापगढ़ में आज 570 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर जनपद की समृद्धि यात्रा को और गति प्रदान की। लोक-कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक एवं प्रमाण-पत्र के साथ ही विद्यार्थियों को लैपटॉप भी वितरित किए।
-योगी आदित्यनाथ, सीएम, उप्र

अभद्र भाषा का प्रयोग

दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद के मंच से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी स्व. माता जी के विरुद्ध जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, वह अत्यंत अशोभनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूं।
-नीतीश कुमार, सीएम, बिहार

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से aapkepatra.haribhoomi@gmail.com पर भेज सकते हैं।

करंट अफेयर

गाजा में महिलाएं और बच्चे भुखमरी का शिकार हो रहे

संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेंसी की प्रमुख ने कहा कि इस सप्ताह गाजा की उनकी यात्रा के दौरान यह ''बहुत स्पष्ट'' था कि फलस्तीनी क्षेत्र में पर्याप्त भोजन नहीं है तथा उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से और अधिक सहायता की तत्काल जरूरत पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेंसी ने पिछले सप्ताह कहा था कि गाजा पट्टी का सबसे बड़ा शहर अकाल की चपेट में है और यदि युद्धविराम नहीं हुआ या मानवीय सहायता पर प्रतिबंध समाप्त नहीं किए गए तो यह पूरे क्षेत्र में फैल सकता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की कार्यकारी निदेशक सिंडी मैकेन ने बताया कि गाजा में भुखमरी जारी है।

उन्होंने कहा, ''मैंने गाजा में भुखमरी से जूझ रही माताओं और बच्चों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और पूरी स्थिति खुद देखी।'' उन्होंने कहा कि नेतन्याहू '' इस बात से बहुत चिंतित थे कि लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है।'' इससे पहले उन्होंने गाजा में अकाल की बात से इनकार किया था और कहा था कि भुखमरी के दावे हमास का दुष्प्रचार अभियान है। मैकेन ने कहा, ''हम इस बात पर सहमत हुए कि हमें और अधिक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करना होगा। हमारे काफिलों के लिए सुरक्षा और वहां तक पहुंचना जरूरी है।''

ऑफ बीट

शराब छोड़ने पर जिगर के साथ क्या होता है

वास्तव में, क्या लीवर वापस बढ़ सकता है? लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। शराब जैसे विषाक्त पदार्थों का असर कम करने सहित सैकड़ों शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए इसकी आवश्यकता होती है।

चूंकि यह पी गई शराब के संपर्क में आने वाला पहला अंग है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यह शराब के प्रभावों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। हालाँकि, लंबे समय तक भारी शराब के सेवन से मस्तिष्क और हृदय सहित अन्य अंग भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। यह लीवर में वसा जमा होने (फैटी लीवर) से लेकर निशान बनने (सिरोसिस) तक होने वाली बीमारी का एक पहलू है और यह आमतौर पर क्षति के अंतिम चरण तक कोई लक्षण पैदा नहीं करता है। सबसे पहले शराब लिवर को फैटी बनाती है। इस वसा के कारण लीवर में सूजन हो जाती है। जवाब में, यह निशान ऊतक का निर्माण करके खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। यदि इसे अनियंत्रित जारी रखा जाता है, तो पूरा लीवर घावों का एक जाल बन सकता है और बीच में ''अच्छे'' हिस्सों के छोटे-छोटे द्वीप बन सकते हैं, जिसे सिरोसिस कहा जाता है। सिरोसिस के अंतिम चरण में, जब लीवर ख़राब हो जाता है, तो लोगों को पीलिया हो सकता है, सूजन आ सकती है और नींद की कमी और भ्रमित हो सकते हैं।

दैनिक जागरण
मानव जीवन संघर्ष एवं संकल्प की सतत यात्रा है

भारत-चीन संबंध

जापान के बाद चीन पहुंच रहे भारतीय प्रधानमंत्री पर भारत के साथ-साथ विश्व की भी निगाहें होंगी, क्योंकि एक तो वह सात वर्षों बाद वहां जा रहे हैं और दूसरे ऐसे समय जा रहे हैं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मनमानी टैरिफ नीति से विश्व परेशान है। यद्यपि प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन वहां उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से भी होगी और यह स्वाभाविक ही है कि इस दौरान दोनों देशों के संबंधों पर भी बातचीत होगी। यह होनी भी चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दे अनसुलझे हुए हैं और उनके कारण संबंधों में अविश्वास एवं खिंचाव है। देखना यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति के बीच की मुलाकात दोनों देशों के संबंधों में भरोसा और सहयोग कायम करने में सहायक बनती है या नहीं? जो भी हो, भारत को अपने हितों की पूर्ति के लिए चीन से सुधरते संबंधों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए और एससीओ के साथ-साथ ब्रिक्स जैसे मंचों को भी अपने पक्ष में भुनाना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को निशाने पर ले रखा है। वैसे तो चीन भी उनके निशाने पर है, लेकिन भारत के खिलाफ उनकी निगाह कुछ ज्यादा ही टेढ़ी है। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि ट्रंप की बेतुकी टैरिफ नीति के कारण ही चीन ने भारत से संबंध सुधारना बेहतर समझा। समय की मांग को देखते हुए भारत ने भी ऐसा ही करना उचित समझा।

भारत के लिए तेज गति से विकास अनिवार्य है। भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता तीव्र विकास और जितनी जल्दी संभव हो, चीन के बराबर खड़ा होने की कोशिश होनी चाहिए। इससे ही देश वास्तविक महाशक्ति बनेगा। चूंकि चीन के साथ दशकों से अनसुलझे मुद्दे रातों-रात नहीं हल होने वाले, इसलिए भारत की कोशिश यही होनी चाहिए कि वह तेज विकास और विशेष रूप से मैन्यूफैक्चरिंग में समर्थ बनने में चीन से सीख ले। भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि तेज आर्थिक विकास के मामले में चीन उससे कहीं आगे है। वह दुनिया का कारखाना तो बना ही हुआ है, आधुनिक तकनीक के मामले में भी अपनी छाप छोड़ रहा है। कुछ मामलों में तो वह अमेरिका को भी चुनौती दे रहा है। इसी कारण अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ मामले में चीन के प्रति अपेक्षाकृत नरमी दिखाने को विवश हैं। यह ठीक है कि चीन अधिनायकवादी व्यवस्था वाला देश है, लेकिन विकास के मामले में भारत उसके कुछ तौर-तरीकों को तो अपना ही सकता है। अपने द्रुत आर्थिक विकास के लिए भारत को चीन ही नहीं, विश्व के अन्य देशों के श्रेष्ठ उदाहरणों का अनुकरण करने में संकोच नहीं करना चाहिए।

बेटियों का सवाल

झारखंड सरकार और यूनिसेफ द्वारा साल 2025-2030 के लिए तैयार की गई नई कार्ययोजना केवल प्रशासनिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि समाज के सोच को बदलने की एक गहरी वैचारिक पहल है। देश में बाल विवाह कोई मात्र कुप्रथा नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही पितृसत्तात्मक मानसिकता का प्रतीक है, जिसमें बेटियों को बोझ समझा गया और उनकी स्वतंत्रता समय से पहले छीन ली गई। बाल विवाह का संकट यह बताता है कि हम विकास को केवल सड़कों, पुलों और इमारतों से नहीं माप सकते। असली विकास वह है, जहां हर बच्चा चाहे लड़की हो या लड़का अपना बचपन जिए, शिक्षा पाए और अपने भविष्य को खुद गढ़ सके। इसी से स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। बाल विवाह उस संभावना को कुचल देता है और गरीबी, बीमारी तथा असमानता का दुष्चक्र कायम रखता है। यह समझाना है कि बेटी की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता ही उसका वास्तविक दहेज और सुरक्षा है। जब तक समाज इस मूल विचार को आत्मसात नहीं करेगा, तब तक कोई भी सरकारी नीति स्थायी असर नहीं डाल पाएगी। यह केवल बेटियों का सवाल नहीं, बल्कि पूरे समाज की प्रगति का प्रश्न है। आज जरूरत है कि हम बाल विवाह को केवल कानून का उल्लंघन न मानें, बल्कि इसे मानवीय गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ अपराध के रूप में देखें। तभी यह कार्ययोजना सचमुच परिवर्तन का दस्तावेज बनेगी और झारखंड से एक नई चेतना पूरे देश में प्रसारित होगी।

> बेटी की शिक्षा, आत्मनिर्भरता एवं निर्णय लेने की क्षमता ही उसका दहेज और सुरक्षा है

संवाद के साथ सतर्कता भी आवश्यक

श्रीराम चौलिया

सीमा समस्या का समाधान अब भी दूर की कौड़ी लगता है, लेकिन चीन से बातचीत और संपर्क बनाए रखने में कोई हानि नहीं है

सात वर्षों के अंतराल के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 31 अगस्त से एक सितंबर तक चीन के दौरे पर होंगे। वह जापान की यात्रा के बाद चीन पहुंचेंगे। सात वर्षों बाद उनका प्रमुख पड़ोसी देश चीन जाना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि दोनों देशों का रिश्ता कितना जटिल और समस्याओं से भरा है। कूटनीतिक दृष्टिकोण से मोदी की यात्रा द्विपक्षीय नहीं है, क्योंकि वे चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं। इस सम्मेलन के दौरान वे अन्य शासनाध्यक्षों के साथ चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से भी मिलेंगे और यह स्पष्ट ही है कि आपसी विषयों पर भी बातचीत करेंगे। भारत-चीन के लिए यह बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2020 से जारी तनाव से निकल नए सिरे से संबंधों में सुधार लाने के लिए दोनों शीर्ष नेताओं का मिलना आवश्यक है। चीन और भारत के संदर्भ में शीर्ष राजनीतिक स्तर की वार्ता से निकले संकेत हमेशा लाभदायक रहे हैं। 2017 में डोकलाम में दोनों देशों की सेनाओं के आमने-सामने होने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने विवादों को टकराव में बदलने से रोकने के लिए शी के साथ वुहान में अनौपचारिक राजनय के माध्यम से प्रयास किया था, पर अफसोस कि चीन ने तत्पश्चात फिर से आक्रामक रुख अपना लिया। 2020 में गलवान घाटी में हुई सैनिकों की मुठभेड़ में दोनों पक्षों को क्षति पहुंची थी। दोनों देशों ने भारी हथियारों से लैस होकर लगभग साठ हजार सैनिकों को सरहद पर युद्ध की तैयारी के हालात में तैनात कर दिया था।

चीन की चाह एशिया में वर्चस्व और विश्व में अमेरिका के साथ बराबरी की हैसियत पाने की है। इसी कारण जब वह पड़ोसी देशों में कमजोरी देखता है तो उस पर झपट पड़ने और उस पर दबाव बनाने को तत्पर हो जाता है। उसकी इस नीयत को समझकर ही मोदी सरकार ने गलवान घाटी में हुई सैन्य झड़प के बाद चीन के सामने सैन्य बल का प्रदर्शन किया और उसे स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया कि "सीमाओं की स्थिति समग्र संबंधों की स्थिति को परिभाषित करेगी।" भारत का सख्त रुख देखकर चीन को पूर्वी लद्दाख से लगी सीमा के कुछ हिस्सों से अपने सैनिक हटाने पड़े, जहां उसने एकतरफा तरीके से जमीन हड़पने की कोशिश की थी। भारत का अडिग रवैया देखकर ही आज चीन वापस रिश्तों में नरमाहट लाने की कोशिश में है। अक्टूबर 2024 से अब तक चीन ने न केवल अपने सैनिकों को विवादित क्षेत्रों से पीछे हटाया है, बल्कि सीमा पर शांति कायम करने के लिए नई व्यवस्थाओं को भी स्वीकारा है। ऐसी बदली परिस्थितियों में मोदी का शी से मिलना और रिश्तों में सुधार आना समयोचित है। आलोचक कह सकते हैं कि शीर्ष स्तरीय कूटनीति का यह नया दौर भी अंततः विफल रहेगा और चीन भारत पर दबाव बनाता रहेगा, क्योंकि वह भारत को अपने बराबर नहीं आने देना चाहता है, लेकिन जिस पड़ोसी के साथ 3,488 किलोमीटर की सीमा लगती हो और जो एशिया के उन्हीं देशों में अपना दबदबा बना रहा हो, जहां भारत के राष्ट्रीय हित समाहित हैं, उसके साथ कम से कम सम्मानजनक कामकाजी रिश्ता होना तो आवश्यक ही है। एक उत्तरदायी और स्थिरता प्रिय देश होने के नाते भारत कभी भी चीन के साथ पुनः युद्ध नहीं चाहेगा। 'सीमा समस्या' का समाधान अब भी दूर की कौड़ी लगती है, पर बातचीत और संपर्क बनाए रखने में कोई हानि नहीं है।

अवधेश राजपूत

चीन से संवाद बढ़ाने के बाद भी उसके साथ संबंधों में आई नरमी को लेकर भारत अत्यधिक आशावादी नहीं हो सकता। आपरेशन सिंदूर के समय चीन ने पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध सैन्य सहायता दी। शी अपने 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे' को अफगानिस्तान तक विस्तारित करने पर भी जोर दे रहे हैं, जिससे वहां भारत के प्रभाव पर असर पड़ेगा। दक्षिण एशिया और हिंद महासागर के देशों में चीन भारत के विकल्प के तौर पर पेश आ रहा है। इस मामले में भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कम होने की कोई संभावना नहीं है। मोदी और शी का हाथ मिलाना और आपसी हितों पर मंत्रणा करने का यह मतलब नहीं कि 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' का जमाना फिर आ जाएगा। सचेत रहते हुए जिम्मेदारीपूर्वक कूटनीति करना भारत की पहचान है। फिलहाल चीन के साथ रिश्तों में नरमी को इसी नजरिये से देखना चाहिए।

इस समय भारत और चीन संवेदनशीलता के आधार पर तब अपने मतभेदों को सुलझाने में रुचि ले रहे हैं, जब भारत और अमेरिका की सामरिक साझेदारी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार युद्ध के कारण आंच आई है। भारत में चीन के राजदूत ने यह तक दावा किया है कि दोनों देश अमेरिका की धमकी और धौंस के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं, पर तथ्य यही है कि चीन भारत की ऐसी कोई क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता, जो अमेरिका के टैरिफ की वजह से होगी। चीन ने भारत पर कृषि के लिए उर्वरकों, दुर्लभ खनिजों और सुरंग खोदने वाली मशीनों के निर्यात प्रतिबंध को हटाकर भरोसे की बहाली का संकेत तो दिया है, पर असलियत यह है कि चीन को भारत के साथ लगभग 100 अरब डालर का व्यापार अधिशेष प्राप्त है। ऐसे में चीन को अमेरिका का विकल्प मानना अथवा रणनीतिक उलटफेर की आशा करना, जिसमें चीन और भारत एक साथ आकर अमेरिका को चुनौती दें, यथार्थवादी सोच नहीं है। अमेरिका द्वारा छेड़ा गया व्यापार युद्ध कभी न कभी सुलझ जाएगा, लेकिन चीन और भारत के बीच असंतुलित व्यापार का समाधान आसान नहीं दिखता।

चीन चाहता है कि भारत पश्चिमी देशों के साथ अपनी मित्रता तोड़े और उसके खेमे में आ जाए, लेकिन भारत स्वयं महाशक्ति बनने के मार्ग पर है। ऐसे में वह अपनी सामरिक स्वायत्ता पर समझौता नहीं करेगा। करना भी नहीं चाहिए। इन अंतर्विरोधों के बावजूद मोदी का शी के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयास की अहमियत को कम करके नहीं आंकना चाहिए। भारत चीन के साथ सम्मानजनक संबंध चाहता है। यह केवल शक्ति और कूटनीति के संयोजन से ही संभव है।

(लेखक जिंदल स्कूल आफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन हैं)

response@jagran.com

सतह पर आते इतिहास में गुम नायक

शिवेंद्र राणा

राजा पृथु जैसे विस्मृत नायकों का स्मरण भारतीय समाज के इतिहास बोध की चेतना के प्रसार का परिणाम है

पिछले दिनों असम के मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी के एक फ्लाईओवर को राजा पृथु के नाम समर्पित किया। इसके साथ ही 13वीं सदी के कामरूप (आज के असम) के राजा पृथु के बारे में लोगों की जिज्ञासा बढ़ी। इसलिए और बढ़ी, क्योंकि इतिहास में वे गुम से हैं और व्यापक राष्ट्रीय समाज के लिए अनजान। पृथु का पूरा नाम विश्वसुंदरदेव था। वे कामरूप यानी आज के असम के महानतम शासकों में से एक थे। उन्होंने 1185 से 1228 तक शासन किया। उन्होंने अपने शासनकाल में दो आक्रांताओं-बख्तियार खिलजी और नसीरुद्दीन से लोहा लिया। नालंदा को नष्ट करने वाले खिलजी को तो उन्होंने बुरी तरह पस्त किया था। राजा पृथु जैसे न जाने कितने नायकों ने अपनी ही संततियों के समक्ष पहचान का संकट झेला। उनका विस्मरण कुछ ऐसा ही है जैसे सालार मसूद गाजी जैसे उत्पीड़क को मजार और नेजा मेले की शोहरत हासिल हो और उसके त्राण से मुक्ति दिलाने वाले राजा सुहेलदेव को शोध में तलाशने की कोशिश हो रही हो। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि इतिहास का निरूपण सदैव विजेताओं द्वारा किया जाता आया है।

होना यह चाहिए था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय इतिहासकार अपना इतिहास अपनी दृष्टि से लिखते, लेकिन भारत में पहले इस्लामिक आक्रांताओं, यूरोपीय गौरांग महाप्रभुओं के पश्चात वामपंथियों ने इतिहास लेखन में छल किया। कथित सामासिक संस्कृति के आवरण में वामपंथी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास के संदर्भ और संदर्श तक दूषित कर दिए। साहित्य के नोबेल से सम्मानित सोवियत लेखक मिखाइल शोलोखोव अपने उपन्यास 'एंड क्वाइट फ्लोज द डान' में एक कज्जाक गीत का उल्लेख करते हैं, 'हमारी धरती पर हलों की लीकें नहीं हैं। हमारी धरती पर घोड़ों की टापों के निशान हैं और उसमें बीज नहीं, कज्जाकों के शीश बोए जाते हैं।' शोलोखोव जैसी व्यथा भारत के लोगों की भी है। आक्रांताओं के घोड़ों की टापों ने उनका वैभव नष्ट किया और उनकी संस्कृति उजाड़ने का प्रयास किया। 1947 के बाद प्राप्त स्वशासन में भी यह बौद्धिक बेईमानी विद्यमान रही। वर्तमान में इतिहास का वास्तविक निरूपण राष्ट्रीय विचारों एवं सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी एक बानगी एनसीईआरटी की किताबों में दिख रही है। इसकी जरूरत इसलिए है, क्योंकि ऐतिहासिक व्याख्याओं का आधार सांस्कृतिक मूल्यों की वैध मान्यताएं होती हैं।

याद आए खिलजी को मात देने वाले राजा पृथु।

आज यदि हम लचित बरफुकन, सुहेलदेव, झलकारी बाई, दलदेव महाराज, महावीरादेवी भंगी, पन्नाधाय धानुक और अब राजा पृथु जैसे विस्मृत ऐतिहासिक नायकों के चरित्र से साक्षात्कार कर रहे हैं, तो यह भारतीय समाज के सांस्कृतिक जागरण में इतिहास बोध की चेतना के प्रसार का परिणाम है। विस्मृत हुए ये नायक भारत की चैतन्य राष्ट्रीयता का संबल हैं। वर्तमान में इतिहास को नए आयाम सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों ने भी दिया है। ऐसे सामाजिक आंदोलन नहीं होते तो हम उपरोक्त ऐतिहासिक नायक-नायिकाओं का नाम भी नहीं जानते। कुछ समय पहले लखनऊ में अवंती बाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए भाजपा और सपा नेताओं के बीच जो होड़ दिखी, वह इतिहास-बोध की चैतन्यता ही प्रमाणित करती है, भले ही पृष्ठभूमि में राजनीतिक प्रेरणा हो। यह इतिहास बनाने नहीं, उसे जीने का संदर्भ है। यदि इतिहास का सही संदर्भों में यथार्थ निरूपण न हो तो भावी पीढ़ियों को सर सैयद अहमद खान, इकबाल आदि के बारे में वही सब पढ़ने-सुनने को मिले, जो एक खास एजेंडे के तहत लिखा और प्रचारित किया गया। क्या यह किसी से छिपा है कि अलीगढ़ मूवमेंट पाकिस्तान के निर्माण का आधार बना? इतिहास का निर्धारण उचित मानकों पर हो और वह असत्य वाचन का कारक न बने। इतिहास का तो अर्थ ही है-ऐसा ही हुआ था। वामपंथियों ने भारतीय इतिहास पर अपना एजेंडा स्थापित किया और कथित सद्भाव प्रसार के नाम पर कल्पित कथाएं रचीं। डा. राम मनोहर लोहिया कहते थे, जो कत्ल करने वालों को अपना पूर्वज माने, उसका आत्मगौरव झूठा है।

यह आवश्यक है कि कोई भी समाज शत्रु-बोध के भाव का विश्लेषण करे। यह इसलिए आवश्यक है, क्योंकि कभी अनजान स्रोतों से शिवाजी महाराज के बारे में मिथ्या मान्यताएं गढ़ी जाती हैं और कभी धर्मांध औरंगजेब को मंदिरों का संरक्षक बताने की चेष्टा होती है। इस पर आश्चर्य नहीं कि छद्म पंथनिरपेक्ष एवं यथास्थितिवादी वर्ग इतिहास के पुनर्लेखन का विरोधी है। आखिर पहले के इतिहासकारों द्वारा ऐसा क्या छुपाया गया, जिसके प्रकटीकरण से संघर्ष पैदा हो सकता है? इतिहास का यथार्थ विश्लेषण इसलिए और आवश्यक हो जाता है, ताकि दमन-अत्याचार की पीड़ा से गुजर चुका राष्ट्र अपना वास्तविक इतिहास जाने और भावी पीढ़ियों को सचेत करे, ताकि उसे पहले जैसी पीड़ा से न गुजरना पड़े। जनता की समझदारी पर संदेह करने का कोई कारण नहीं। तथ्यों को सत्यता के साथ रख दीजिए, जनता उसका विश्लेषण खुद कर लेगी। इसी संदर्भ में 30 दिसंबर, 1916 को ओहियो में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, 'सिर्फ अपनी आदतों से मुक्ति ही नहीं, बल्कि तमाम गंदे इतिहास से मुक्ति के जरिए ही भविष्य की सभ्यता का परचम उठाया जा सकता है।"

(लेखक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में परियोजना सहयोगी हैं)

response@jagran.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

ऊर्जा

जीवनमुक्त

मुक्ति, मोक्ष आदि पर आध्यात्मिक और दार्शनिक मीमांसकों के मध्य वाद-विवाद चलते रहे हैं। ज्ञान, भक्ति, विवेक, योग इत्यादि अनेक मार्गों के पथिक अपने-अपने तर्क देते रहे हैं, पर उनमें से कितने गंतव्य तक पहुंचे हैं यह विवेचना का विषय है। जो व्यक्ति स्वयं को नित्य-शुद्ध, नित्य-मुक्त, सत्-चित्-आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में जान लेता है, वही जीवनमुक्त कहलाता है। वह व्यक्ति अज्ञान से मुक्त होकर इस अवस्था को प्राप्त करता है।

क्या करें कि हम भी इस यात्रा पर आगे बढ़ सकें। सारा सत्य जानते हुए भी हम संसार के कुचक्र से ग्रस्त होते रहते हैं, जो अंततः सारे कष्टों का मूल कारण है। सबसे पहले मन पर नियंत्रण पाना आवश्यक है, क्योंकि मन ही विषयों का मिथ्या संसार बनाता है, पर क्या सीधे मन पर नियंत्रण संभव है? मन पर नियंत्रण से पहले आवश्यक है प्राण पर विजय। हमारे शरीर में पांच प्रकार के प्राण स्थित हैं- अपान, व्यान, समान, प्राण और उदान। अपान मूलाधार चक्र में स्थित है। व्यान स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित है। समान मणिपुर चक्र में स्थित है। प्राण अनाहत चक्र में स्थित है। और उदान विशुद्धि चक्र में स्थित है। सभी पांचों प्राण शरीर के विभिन्न अंगों, इंद्रियों और प्रणालियों को नियंत्रित करते हैं। इन प्राणों की प्रणाली पर योग और ध्यान द्वारा नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि सारी गतिविधियां इन्हीं के द्वारा क्रियाशील होती हैं। इस प्रक्रिया के बाद ही मन को शांत और एकाग्र किया जाना संभव है।

जिस प्रकार सूर्य के प्रकाशमान होने के बाद भी बादलों के कारण वह अदृश्य प्रतीत होता है, उसी प्रकार अविद्या और चंचल मन के कारण वह चैतन्य रूपी प्रकाश दृश्यमान नहीं होता। अविद्या हटाने का एक मात्र उपाय ज्ञान है, जो सिर्फ एकाग्र, शांत और अंतर्मुखी मन के माध्यम से ही बुद्धि में प्रकट होता है। जो इस मर्म को समझ लेता है वही जीवनमुक्त हो जाता है।

आदित्य नारायण अवस्थी

कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के प्रयास

प्रदीप

शोधकर्ताओं ने पेड़-पौधों से प्रेरित होकर एक ऐसा अणु विकसित किया है, जो प्रकाश से चार आवेशों को संग्रहित कर सकता है

पेड़-पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का निर्माण करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। इसे "प्रकाश संश्लेषण" या "फोटो सिंथेसिस" कहा जाता है। लंबे समय से विज्ञानी इस प्रक्रिया से प्रेरणा लेकर और विशेष प्रोटीनों की मदद से इसे प्रयोगशाला में दोहराने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ऊर्जा का एक स्वच्छ और प्रभावी स्रोत प्राप्त किया जा सके। हाल में स्विट्जरलैंड के बेसल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पेड़-पौधों से प्रेरित होकर एक ऐसा अणु विकसित किया है, जो प्रकाश से चार आवेशों को संग्रहित कर सकता है। इसे कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे कार्बन-तटस्थ ईंधन की खोज में तेजी आने की संभावना है।

कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जटिल है और इसमें बहु-इलेक्ट्रान अभिक्रियाओं की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया मंद प्रकाश में भी कार्य करती है, जिससे तकनीक वास्तविक सौर ईंधन उत्पादन के और करीब पहुंच जाती है। प्रकाश के प्रभाव में अणु एक ही समय में दो धनात्मक और दो ऋणात्मक आवेश संग्रहित करता है। हाल में विकसित किए गए नए अणु में पांच भाग हैं। एक तरफ दो भाग इलेक्ट्रान छोड़कर धनात्मक आवेशित होते हैं, जबकि दूसरी तरफ दो भाग इलेक्ट्रान ग्रहण कर ऋणात्मक आवेशित होते हैं। बीच का भाग सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर इलेक्ट्रान स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करता है। शोधकर्ताओं ने दो प्रकाश स्रोतों के चरणबद्ध उपयोग से चार आवेश उत्पन्न किए। पहला स्रोत एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश बनाता है, जो विपरीत सिरों तक पहुंचते हैं। दूसरे स्रोत से यही प्रक्रिया दोहराई जाती है, जिससे अणु में कुल चार आवेश हो जाते हैं। चरणबद्ध उत्तेजना से काफी मंद प्रकाश का उपयोग संभव हो जाता है, जिसका अर्थ है कि यह सूर्य के प्रकाश की तीव्रता के करीब पहुंचता है। पहले के शोधों में शक्तिशाली लेजर प्रकाश की आवश्यकता होती थी।

इस अध्ययन के निष्कर्ष कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण इलेक्ट्रान स्थानांतरण की समझ में सुधार करने में मदद करेंगे। शोध के प्रमुख लेखक प्रोफेसर ओलिवर वेंगर के अनुसार, "हमने दिखाया है कि सूर्य के प्रकाश से विभिन्न आवेशों को कुशलतापूर्वक कैसे संग्रहित किया जा सकता है। इन इलेक्ट्रान स्थानांतरणों को समझने से हम सौर ऊर्जा को भंडारण योग्य, टिकाऊ ईंधन में बदलने के और करीब पहुंचते हैं।" कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल ईंधनों की कुंजी बन सकती है। इसमें हाइड्रोजन, मेथनाल और सिंथेटिक पेट्रोल जैसे तथाकथित 'सौर ईंधन' शामिल हैं। जलाए जाने पर ये ईंधन केवल उतनी ही कार्बन डाइआक्साइड उत्पन्न करेंगे जितनी उपयोगी ईंधन बनाने के लिए आवश्यक है। ये पूरी तरह से कार्बन-तटस्थ होंगे।

(लेखक विज्ञान संचारक हैं)

मेलबाक्स

अदालतों में लंबित मामलों का सवाल

'सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला अटका हो तो' शीर्षक से लिखे आलेख में राजीव सचान ने सही सवाल उठाया है कि यदि राज्यपालों-राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर तय समय में फैसला लेना जरूरी है तो हाई कोर्ट-सुप्रीम कोर्ट के लिए क्यों नहीं? इस तरह लेखक ने एक गहन और गंभीर विषय पर प्रकाश डाला है। इस प्रकरण में संवैधानिक, व्यावहारिक और राजनीति के प्रश्न निहित हैं। प्रायः देखा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रहित में उन विषयों पर भी आदेश देता है, जिसके लिए संविधान में कोई स्पष्ट प्रविधान नहीं है। कभी-कभी न्यायालय के आदेशों से विधायिका की शक्तियों का भी कार्य संपन्न हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, दो जजों की पीठ संसद द्वारा विधेयक पेश करने, पारित करने अथवा न करने का कार्य कर देती है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, फिर भी इस प्रकार के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। जबकि इंग्लैंड में लिखित संविधान न होने पर भी ऐसे विवाद देखने को नहीं मिलते। हमारे देश में ऐसे प्रश्न कई बार उठते हैं और जनता भी असमंजस में रहती है। एक ओर तो अनेक आवश्यक और त्वरित मामलों के निर्णय वर्षों तक लंबित रहते हैं, दूसरी ओर कभी-कभी रात में ही न्यायालय की पीठ गठित होकर तुरंत सुनवाई करती है और फैसला भी हो जाता है। इन परिस्थितियों में न्यायालय की कार्यप्रणाली पर चर्चा अवश्य बनती है। क्या सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों में एकरूपता लाने का प्रयास करेगा? क्या वरिष्ठ अधिवक्ताओं की तरह सामान्य वकीलों की बात भी इसी गंभीरता से सुनी जाएगी? समय की आवश्यकता है कि इन सवालों पर सामंजस्य, एकरूपता हो और राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित विषयों पर व्यापक मंथन किया जाए।

भूषण शरण महेश, एडवोकेट, मुजफ्फरनगर

सहयोग से बनेगी बात

संपादकीय 'भारत की तैयारी' पढ़ा। भारत और अमेरिका की दोस्ती के बीच आई दरार लगातार बढ़ती ही जा रही है। इन दोनों मुल्कों के बीच रिश्तों में आई खटास के पीछे कुछ गलतफहमियां हैं, तो कुछ हालात जिम्मेदार हैं। ट्रंप सरकार द्वारा भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाने और भारत-पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों हुए युद्ध पर मध्यस्थता करने के मामलों की वजह से अमेरिका से हमारे रिश्तों में कड़वाहट पैदा हुई है। भारत कश्मीर के मुद्दे पर कोई मध्यस्थता नहीं चाहता। भारत इस मुद्दे को हमेशा से द्विपक्षीय मुद्दा मानता रहा है। अब ऐसे समय में अमेरिकी वित्त मंत्री स्काट बेसेंट का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक सकारात्मक संदेश देकर कहा है कि अमेरिका द्वारा भारत पर एकतरफा टैरिफ लगाने और कुछ तीखे बयानों के बावजूद अभी बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। उन्होंने कहा है कि वाशिंगटन और नई दिल्ली बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझा सकते हैं। भारत और अमेरिका दुनिया के दो बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। दोनों मुल्कों की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस कारण भारत से चिढ़ गए लगते हैं कि आपरेशन सिंदूर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने उनके अहं को तुष्ट नहीं किया। इस समय पूरी दुनिया की नजर इन दोनों मुल्कों पर है, इसलिए समय की नजाकत को पहचानते हुए दोनों मुल्कों को बातचीत के जरिए आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने के प्रयास करने चाहिए। निर्यातकों और कामगारों को राहत देने के लिए सरकार को ठोस उपाय करने होंगे। सरकार ने अमेरिकी टैरिफ लागू हो जाने के बाद भारतीय वस्त्रों के लिए अनेक ऐसे देशों की पहचान की है, जिन्हें निर्यात बढ़ाया जा सकता है।

हितेंद्र डेढ़ा, चिल्ला गांव, दिल्ली

आफत की वर्षा

जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। कम समय ज्यादा बारिश जगह-जगह डरावनी तस्वीर पेश कर रही है। इससे कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। वर्षा के बाद जलभराव से लोगों को परेशानी हो रही है। शहरों में वाहनों की रफ्तार थम गई है। फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन से भारी तबाई हुई है। इस समस्या का समाधान निकालना होगा।

कांतिलाल मांडोत, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****